

September 2021 Baba's Monthly **CURRENT AFFAIRS MAGAZINE**

हिंदी

IN
NEW
AVATAR

Revamped With Revolutionary Aspects

- Easy To Remember Tabular Format
- Practice Mcq's At The End
- Top Editorial Summaries Of The Month
- A Comprehensive Compendium Of News Sourced From More Than 5 Reputed Sources



TLP+ Mains Answer Writing Program



22 UPSC Level Mocks
(8 Sectional, 6 Essay, 2 FLT's)



1:1 Mentorship



**Discussion Classes
After Test**



Detailed Synopsis



Flexible Tests



Mainspedia –

Access Important Issues Of Last 1 Year In
Answer Writing Format At One Place

**Toppers
Recommended**

REGISTER NOW

Scan here to



know more

राज्यव्यवस्था एवं शासन

- NEET परीक्षा में उपस्थित होने वाले एनआरआई छात्रों के लिए SC, ST और OBC कोटा नहीं
- ASER रिपोर्ट
- झारखंड सदन ने स्थानीय लोगों के लिए 75% कोटा बिल को मंजूरी दी
- बैठने का अधिकार (Right to Sit)
- एनआईआरएफ रैंकिंग (नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क) 2021
- एनसीएलटी और आईटीएटी के बारे में
- स्वामित्व योजना
- वन अधिकार अधिनियम, 2006
- हिंदी दिवस
- अपराध पर NCRB की रिपोर्ट
- एक नया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (NCF) विकसित करने के लिए कस्तूरीरंगन समिति
- केंद्रीय सतर्कता आयोग
- भारत की धार्मिक संरचना पर प्यू स्टडी (Pew Study)
- सांकेतिक भाषा दिवस
- पिछड़ा वर्ग की जाति जनगणना
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'FASTER' टेक्नोलॉजी
- प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(2)
- विकलांगों के लिए पदोन्नति कोटा की समय सीमा
- प्रगति (PRAGATI - Pro-Active Governance and Timely Implementation)
- नेशनल फ्लोरेस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2020

अर्थव्यवस्था

- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की बैठक
- कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (IFAD)
- GST अपीलित न्यायाधिकरण
- खनिज अन्वेषण
- आयात टैग के बिना SEZ इकाइयों द्वारा स्थानीय बिक्री
- भारत से कर विवाद खत्म करेगी केयर्न एनर्जी
- कोयला आधारित हाइड्रोजन
- कपड़ा क्षेत्र की पीएलआई योजना मंजूर
- डिजिटल गांवों में 100 प्रतिशत डिजिटल साक्षरता के लिए पीएमजी दिशा शुरू
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)
- कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र
- स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021
- परिवहन और विपणन सहायता (TMA) योजना
- आदिवासी कला को बढ़ावा देने को आत्मानिर्भर भारत कॉर्नर
- पेट्रोल-डीजल जीएसटी के दायरे में

- थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति
- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और PayNow को लिंक करना
- प्रतिभूतियों के लिये 'T+1' निपटान प्रणाली
- इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)
- कृषि पर समझौता: विश्व व्यापार संगठन (WTO)
- विश्व बैंक ने बंद की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट
- रेल कौशल विकास योजना
- राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक: FSSAI
- SPIN योजना
- भारत योजना से सेवा निर्यात
- पेटेंट (संशोधन) नियम, 2021
- चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने की योजना अधिसूचित
- एंटी-डॉपिंग ड्यूटी
- स्थानीय मूल्य संवर्धन, विनिर्माण और निर्यात के लिए संचालन समिति (SCALE)
- असम की जुडिमा वाइन राइस को मिला GI टैग
- भारत के रजिस्ट्रार-जनरल और जनगणना आयुक्त
- सेबी ने गोल्ड एक्सचेंज के लिए नियमों को मंजूरी दी
- आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) का विघटन
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) का विस्तार

पर्यावरण

- लद्दाख ने राजकीय पशु और पक्षी घोषित किया
- छत्तीसगढ़ का राज्य पशु, जंगली भैंस विलुप्त होने के करीब
- नीलकुरिंजी (Neelakurinji)
- कछुआ संरक्षण
- IUCN ने प्रजातियों की लाल सूची अपडेट की
- मेक्सिको की खाड़ी में तेल रिसाव
- असम 2030 तक जीवाश्म ईंधन आधारित वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करेगा
- भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व
- पराग कैलेंडर (Pollen calendar)
- जलवायु परिवर्तन के कारण 216 मिलियन लोग स्थानांतरित कर सकते हैं: विश्व बैंक
- 'शून्य' अभियान की शुरुआत
- खाद्य श्रृंखला में आर्सेनिक (arsenic) की उपस्थिति
- भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड
- केराटिन अपशिष्ट को परिवर्तित करने का उपाय
- 27वां वैश्विक ओजोन दिवस
- ग्लोबल मीथेन प्लेज
- मुरा-द्रवा-डेन्यूब (MDD) को दुनिया का पहला 'फाइव-कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व' घोषित
- ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का मंच
- भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र डिजाइन
- हम्बोल्ट पेंगुइन

- समुद्री खीरा
- जनजातीय क्षेत्रों में मोती की खेती
- अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन
- WHO ने 2005 के बाद पहली बार वायु गुणवत्ता मानदंडों में संशोधन किया
- विश्व राइनो दिवस
- आर्कटिक सागर की बर्फ में कमी
- चावल की हर्बीसाइड-टोलरेंट किस्म

भूगोल और समाचारों में स्थान

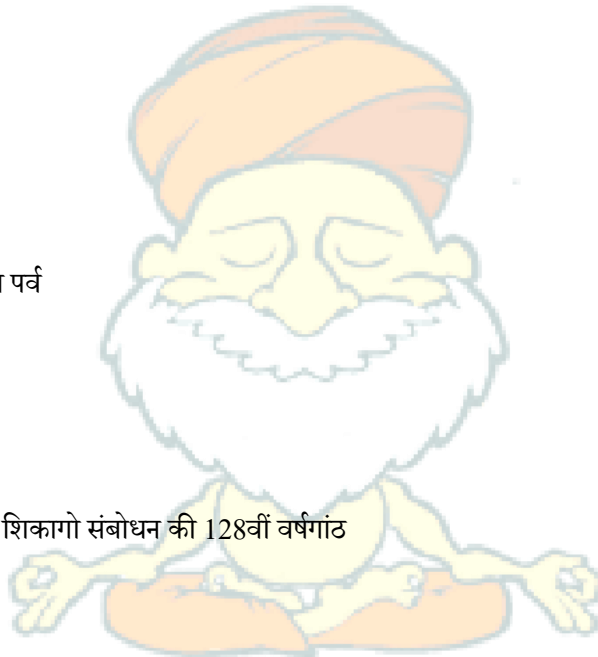
- तूफान 'इडा'
- बैरा-स्यूल पावर स्टेशन
- ब्राह्मणी नदी
- समाचारों में स्थान: क्यूकरताक अवन्नारलेक
- डायनासोर की तीन प्रजातियों के पदचिह्न: राजस्थान
- मणिपुर: कुकी
- विष्णुओनीक्स
- पैटानल आर्द्रभूमि
- जोजिला सुरंग कार्य

संस्कृति और इतिहास

- वी. ओ. चिदंबरम पिल्लै
- श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पर्व
- नुखाई
- सुब्रमण्यम भारती
- आचार्य विनोबा भावे
- थमिराबरानी सभ्यता: तमिलनाडु
- स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक शिकागो संबोधन की 128वीं वर्षगांठ
- सारागढ़ी के युद्ध
- चेरामन मस्जिद
- शंखलिपि
- रामधारी सिंह दिनकर
- नाताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान और विरासत
- कथा प्रसंगम

विज्ञान प्रौद्योगिकी

- मिल्की सी प्रभाव (Milky seas effect)
- रूस में व्यायाम ZAPAD 2021
- ब्लू स्ट्रैगलर
- 2025 तक टीबी मुक्त भारत
- डिफेंस एक्सपो-2022
- म्यू वेरिएंट
- हंसा विमान
- निपाह वायरस



- प्रेरणा 4
- सिम्बेक्स
- ई-आईएलपी प्लेटफॉर्म: मणिपुर
- ऑसिन्डेक्स
- कुपोषण दूर करने के लिए पोषण वाटिका
- सी-295 एयरक्राफ्ट डील
- नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड
- चंद्रयान-2
- सेलाइन गार्गल आरटी-पीसीआर तकनीक
- भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता
- शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास 2021
- रेक्स एमकेआईआई
- हेलिना मिसाइल
- प्लैनेट नाइन पर नया अध्ययन
- भारत जल्द शुरू करेगा कोरोना वैक्सीन का निर्यात
- 'समुद्र शक्ति' अभ्यास
- व्यायाम सूर्य किरण
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (Global Innovation Index) 2021
- डार्क एनर्जी
- भारत-अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता 2021
- रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC)
- हाइपरसोनिक मिसाइल
- केरल में चमगादड़ के नमूनों में मिले निपाह एंटीबॉडी
- जांच से पता चलता है कि पटाखों में जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल होता है
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन

अंतरराष्ट्रीय संबंध

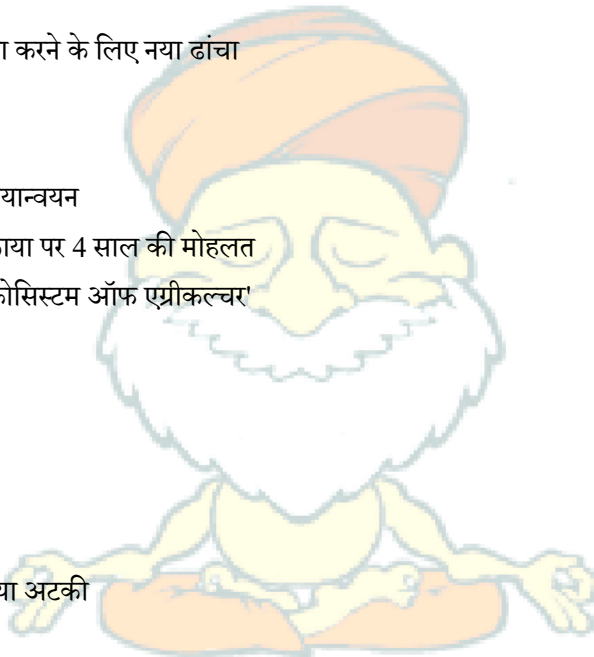
- आईएलओ (ILO)
- रूस के साथ रसद समझौता
- सीएससी और पासपोर्ट सेवाएं
- यूएई का ग्रीन वीजा
- भारत, ऑस्ट्रेलिया 2+2 बैठक आयोजित करेंगे
- यूएस-इंडिया स्ट्रेटजिक क्लिन एनर्जी पार्टनरशिप (SCEP)
- संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) पुरस्कार
- क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग (CAFMD)
- भारत - संयुक्त अरब अमीरात सीईपीए
- भारत, ऑस्ट्रेलिया ने 'संदर्भ की शर्तों' पर हस्ताक्षर किए
- यूएस-इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम
- भारत-आसियान की सामरिक साझेदारी

मुख्य फोकस (MAINS)

- पंजाब में मोनोकल्चर



- ब्रिक्स को बेहतर बनाने का समय
- मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान
- फर्जी पत्रकारों को बाहर निकालने पर
- अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्व एशिया से अमेरिका की वापसी
- हिमालय हाइड्रो अटैक सह नहीं सकता
- अंतरिक्ष जंक खतरा
- भारत की आरक्षण प्रणाली को पुनर्जीवित करने की कुंजी
- बिडेन की विदेश नीति सिद्धांत
- तालिबान और चीन
- बाजरा की खेती का महत्व
- सेमी-कंडक्टर की कमी
- उच्च शिक्षा के सपनों के लिए वास्तविकता की जाँच
- उच्च शिक्षा नामांकन का विस्तार करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए
- 9/11 के दो दशक
- खाता एग्रीगेटर: वित्तीय डेटा साझा करने के लिए नया ढांचा
- वैश्विक तापन एवं स्थायी तुषार
- इंटरनेट शटडाउन
- स्थानीय आरक्षण और उसका क्रियान्वयन
- दूरसंचार राहत पैकेज: AGR बकाया पर 4 साल की मोहलत
- आईडिया - 'इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर'
- बैड बैंक: NARCL-IDRCL
- ई-श्रम पोर्टल
- AUKUS
- फेडरल रिजर्व का रुख और भारत
- साइबर सुरक्षा और बैंक
- नगा समझौते के लिए शांति प्रक्रिया अटकी
- विवाह पंजीकरण
- कार्टेलाइजेशन: बीयर कंपनियों पर CCI जुर्माना
- लेखा परीक्षकों के लेखा परीक्षक: NFRA



प्रैक्टिस MCQs

NEET परीक्षा में उपस्थित होने वाले एनआरआई छात्रों के लिए SC, ST और OBC कोटा नहीं	संदर्भ: हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण कि NEET (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) के इच्छुक उम्मीदवार केवल एक कोटा श्रेणी का विकल्प चुन सकते हैं। इसके बारे में ● एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों से संबंधित एनआरआई छात्र अब आगामी एनईईटी परीक्षाओं में उन्हें प्रदान किए गए आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। ● इच्छुक NRI छात्रों ने यह भी बताया है कि अगर वे 'भारतीय' को अपनी राष्ट्रीयता के रूप में चुनते हैं तो उन्हें केंद्रीय, राज्य और डीम्ड संस्थानों में NRI कोटे के तहत सीटों से कैसे वंचित कर दिया जाता है। ● वर्गीकरण की ऐसी पद्धति NRI के साथ भेदभाव करती है, भले ही वे भारतीय नागरिकता रखते हों नॉन रेजिडेंट किसे माना जाता है? ● भारत का निवासी वह व्यक्ति होता है जो एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 182 दिनों के लिए देश में रहता है, या पिछले चार वर्षों के दौरान 365 दिनों या उससे अधिक के साथ एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 60 दिन रहता है। ● यदि कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक भी है, विदेश में भी रोजगार लेता है, तो 60 दिनों की अवधि को 182 दिनों से बदल दिया जाता है। ● यदि कोई व्यक्ति भारत का कर निवासी नहीं है, तो वह अनिवासी है नीट परीक्षा के बारे में ● NEET भारतीय मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में MBBS और BDS कार्यक्रमों के लिए योग्यता परीक्षा है। ● यह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाती है।
ASER रिपोर्ट	संदर्भ: शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (Annual Status of Education Report-ASER), जिसे इस वर्ष केवल कर्नाटक में मार्च 2021 में तैयार किया गया था, विशेष रूप से प्राथमिक कक्षाओं के लिए, पढ़ने और अंकगणित सीखने के स्तर में भारी गिरावट पाई गई। ● वर्तमान रिपोर्ट के लिए प्रथम ने 24 जिलों के 13,365 घरों के पांच से 16 वर्ष की आयु के 18,385 बच्चों का सर्वेक्षण किया। यह इस साल की शुरुआत में, COVID-19 महामारी के बाद पहली बार किया गया था। असर (ASER) क्या है? ● ASER, शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति के लिए है। ● यह प्रथम NGO द्वारा सुगम भारत में सबसे बड़ा नागरिक-नेतृत्व वाला सर्वेक्षण है। ● NGO यह एक वार्षिक सर्वेक्षण है, जो 2005 से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक जिले और राज्य के लिए बच्चों के नामांकन और बुनियादी सीखने के स्तर का विश्वसनीय अनुमान प्रदान करना है। ● आज यह भारत में उपलब्ध बच्चों के सीखने के परिणामों के बारे में जानकारी का एकमात्र वार्षिक स्रोत है ● ASER स्कूल-आधारित सर्वेक्षण के बजाय घर-आधारित है। ● यह डिजाइन सभी बच्चों को शामिल करने में सक्षम बनाता है - वे जो कभी स्कूल नहीं गए हैं या जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, साथ ही वे जो सरकारी स्कूलों, निजी स्कूलों, धार्मिक स्कूलों में हैं।
झारखंड सदन ने स्थानीय लोगों के लिए 75% कोटा बिल को मंजूरी दी	संदर्भ: झारखंड विधानसभा ने एक बिल पारित किया। इससे प्राइवेट सेक्टर में प्रति माह 40 हजार रुपए तक की सभी मौजूदा नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण मिलेगा। ● एक बार अधिसूचित होने के बाद, झारखंड ऐसा कानून पारित करने वाला आंध्र प्रदेश और हरियाणा के बाद तीसरा राज्य बन जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ● 'झारखंड राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक, 2021' मार्च में सदन में पेश किया गया था, लेकिन बाद में इसे छह सदस्यीय चयन समिति के पास भेज दिया गया। ● इसे 'निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का झारखंड राज्य रोजगार विधेयक, 2021' नाम दिया गया था। ● संशोधित विधेयक में वेतन सीमा को पूर्व के 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दिया गया। ● विधेयक में कहा गया, "प्रत्येक नियोक्ता इस अधिनियम के लागू होने के तीन महीने के अंदर निर्दिष्ट पोर्टल पर

	सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सीमा के रूप में 40 हजार रुपये प्रतिमाह से कम वेतन लेने वाले कर्मचारियों का पंजीकरण कराएगा। बिल को लेकर चिंता ● यदि हाथ में काम के लिए कुशल कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं, तो ये औद्योगिक इकाइयाँ कहीं और से मजदूरों को 'आयात' नहीं कर सकती हैं; स्थानीय लोगों को आवश्यक कौशल प्रदान करने और उन्हें रोजगार देने का भार इकाइयों पर पड़ेगा। ● यह निश्चित रूप से ऐसी भौगोलिक संस्थाओं में व्यवसाय करने की लागत को बढ़ा देगा जो इस नीति को अपनाते हैं, और 'इंडियन कॉमन मार्केट' की अवधारणा का मजाक उड़ाते हैं, जो कि निर्बाध श्रम गतिशीलता के मूलभूत आधार पर टिकी हुई है। ● महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थानीय आबादी के लिए आरक्षण प्रत्येक नागरिक के देश के भीतर काम करने, रहने और स्वतंत्र रूप से घूमने के संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार का भी उल्लंघन है।
बैठने का अधिकार (Right to Sit)	संदर्भ: हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1947 में संशोधन के लिये एक विधेयक पेश किया है। ● इस विधेयक में कर्मचारियों के लिये अनिवार्य रूप से बैठने की सुविधा प्रदान करने हेतु एक उपधारा जोड़ने की मांग की गई है। विधेयक की मुख्य विशेषताएं ● प्रस्तावित संशोधन: अधिनियम की प्रस्तावित धारा 22-A में कहा गया है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान के परिसर में सभी कर्मचारियों के बैठने की उपयुक्त व्यवस्था होगी ताकि वे अवसर पड़ने पर बैठने का लाभ उठा सकें। ● विधेयक की आवश्यकता: दुकानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान खड़े रहने के लिये मजबूर किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ● महत्त्व: इससे बड़े और छोटे प्रतिष्ठानों के हजारों कर्मचारियों, विशेष रूप से कपड़ा और आभूषण शोरूम में काम करने वालों को लाभ होगा। ● समान विधान: कुछ वर्ष पहले केरल में कपड़ा शोरूम के कर्मचारियों ने 'बैठने के अधिकार' की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। ○ इसने केरल सरकार को उनके लिये बैठने की व्यवस्था करने हेतु वर्ष 2018 में केरल दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम (Kerala Shops and Establishments Act) में संशोधन करने के लिये प्रेरित किया।
एनआईआरएफ रैंकिंग (नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क) 2021	प्रसंग: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा स्थापित 'इंडिया रैंकिंग्स, 2021' जारी की है। इंडिया रैंकिंग्स 2021 की मुख्य विशेषताएँ: ● शीर्ष 10 में से सात स्थानों पर कब्जा करते हुए, IIT ने समग्र रैंकिंग पर अपना दबदबा बनाया। ● इस वर्ष भी ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास को देश का बेस्ट शैक्षणिक संस्थान चुना गया है। ● ओवरऑल टॉपर्स: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc), बेंगलुरु को दूसरा स्थान मिला, उसके बाद IIT में बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की और गुवाहाटी को स्थान मिला। ● शीर्ष गैर-IIT विश्वविद्यालय: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) नौवें और दसवें स्थान पर थे। ● शीर्ष विश्वविद्यालय: (1) IISc; (2) JNU; (3) BHU; (4) कलकत्ता विश्वविद्यालय; (5) अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर; (6) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली। एनआईआरएफ क्या है? ● एनआईआरएफ देश में उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) के प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट कार्ड है। ● 'राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क' (NIRF) को सितंबर 2015 में शिक्षा मंत्रालय (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा अनुमोदित किया गया था। ● एनआईआरएफ पांच मानकों के आधार पर संस्थानों की रैंकिंग करता है:

	○ शिक्षण, शिक्षा और संसाधन (Teaching, Learning and Resources), ○ अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास (Research and Professional Practices), ○ स्नातक परिणाम (Graduation Outcomes), ○ आउटरीच और समावेशिता (Outreach and Inclusivity) ○ अनुभूति (Perception)
एनसीएलटी और आईटीएटी के बारे में	संदर्भ: सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में 31 लोगों को न्यायिक, तकनीकी और लेखाकार सदस्यों के रूप में नियुक्त किया है। ● हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न न्यायाधिकरणों में रिक्तियों के बारे में चिंता व्यक्त की थी। पृष्ठभूमि: ● गौरतलब है कि एनसीएलटी, डीआरटी, टीडीसैट और एसएटी (सैट) जैसे विभिन्न प्रमुख न्यायाधिकरणों और अपीलीय न्यायाधिकरणों में लगभग 250 पद खाली पड़े हैं। एनसीएलटी के बारे में: ● यह भारत में एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो भारत में कंपनियों से संबंधित मुद्दों का न्यायनिर्णयन करता है। ● 1 जून, 2016 को स्थापित (कंपनी अधिनियम, 2013)। ● न्यायमूर्ति एराडी समिति की सिफारिशों के आधार पर गठित। ● यह मुख्य रूप से कंपनी कानून और दिवाला कानून से संबंधित मामलों से संबंधित है। ● सदस्यों का कार्यकाल: एनसीएलटी में नियुक्तियां पदभार संभालने की तारीख से 5 साल की अवधि तक या 65 साल की आयु तक या अगले आदेश तक के लिए होंगी। आईटीएटी के बारे में: ● यह आयकर मामलों से संबंधित है। ● यह प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक वैधानिक निकाय है और तथ्य के निष्कर्षों पर इसके आदेशों को अंतिम रूप में स्वीकार किया जाता है। ● ITAT 25 जनवरी, 1941 को बनाया जाने वाला पहला ट्रिब्यूनल था और इसे 'मदर ट्रिब्यूनल' के नाम से भी जाना जाता है। ● आईटीएटी की स्वतंत्रता के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह कानून और न्याय मंत्रालय में कानूनी मामलों के विभाग के तहत कार्य करता है और वित्त मंत्रालय द्वारा किसी भी प्रकार के नियंत्रण से दूर रखा जाता है। ● आईटीएटी द्वारा पारित आदेशों को संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष, कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, अपीलीय चुनौती के अधीन किया जा सकता है।
स्वामित्व योजना	हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करने के लिये फ्रेमवर्क जारी किया है। ● SVAMITVA का पूर्ण रूप “Survey of Villages And Mapping with Improvised Technology In Village Areas” है। ● यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है (केंद्र सरकार द्वारा 100%) केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है। ● ग्रामीण भारत हेतु एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान (Integrated Property validation Solution) प्रदान करना। ● सरकार का लक्ष्य देश भर के प्रत्येक गांव में अगले तीन से चार वर्षों में प्रत्येक परिवार को ऐसे संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। ● GIS मानचित्रों का उपयोग कर बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (Gram Panchayat Development Plan- GPDP) तैयार करने में सहायता करना।
वन अधिकार अधिनियम, 2006	संदर्भ: जम्मू और कश्मीर सरकार ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 को लागू करने का निर्णय लिया है। ● जो गुज्जर सहित आदिवासियों और खानाबदोश समुदायों की 14 लाख-मजबूत आबादी के एक बड़े हिस्से की

	सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊंचा करेगा। ● यह कदम आदिवासी लोगों की लंबे समय से चली आ रही पीड़ा को दूर करेगा और वन संरक्षण को भी सुनिश्चित करेगा। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के बारे में ● कानून वन-निवास समुदायों के भूमि और अन्य संसाधनों के अधिकारों से संबंधित है, जो भारत में औपनिवेशिक वन कानूनों की निरंतरता के परिणामस्वरूप दशकों से उन्हें वंचित कर दिया गया था। ● यह पात्रता उन लोगों तक ही सीमित है जो "मुख्य रूप से जंगलों में रहते हैं" और आजीविका के लिए जंगलों और वन भूमि पर निर्भर हैं। ● इसके अलावा, या तो उस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए या 75 वर्षों से जंगल में रहना चाहिए।
हिंदी दिवस	● भारत की केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में हिंदी भाषा की घोषणा को चिह्नित करते हुए हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। ● सन 1949 में 14 सितंबर के दिन ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था जिसके बाद से अब तक हर साल यह दिन 'हिंदी दिवस' के तौर पर मनाया जाता है।
अपराध पर NCRB की रिपोर्ट	संदर्भ: हाल ही में भारत में अपराध पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट लॉन्च की गई थी। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष ● कोरोनावायरस महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के परिणामस्वरूप 2020 में परंपरागत अपराधों जैसे चोरी, डकैती और महिलाओं और बच्चों पर हमले में कमी आई है। ● 2019 की तुलना में 2020 में मामलों के पंजीकरण में 28% की वृद्धि हुई, हालांकि इनमें ज्यादातर मामले कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन के थे। ● लोक सेवकों द्वारा विधिवत रूप से घोषित आदेश की अवज्ञा के मामलों में लगभग 21 गुना उछाल दर्ज किया गया था। ● अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों में 9.4% की वृद्धि देखी गई। ● अनुसूचित जनजाति समुदायों के खिलाफ अपराधों में 2019 की तुलना में 9.3% की वृद्धि देखी गई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के बारे में ● मुख्यालय: नई दिल्ली ● स्थापित: 1986 ● मंत्रालय: गृह मंत्रालय ● उद्देश्य: NCRB की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में इस उद्देश्य से की गई थी कि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएं प्रदान करके समर्थ बनाया जा सके। ● यह राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) और गृह मंत्रालय के कार्य बल (1985) की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था।
एक नया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (NCF) विकसित करने के लिए कस्तूरीरंगन समिति	संदर्भ: देश में एक नया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (Develop a New National Curriculum Framework-NCF) तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 12 सदस्यीय राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के कस्तूरीरंगन करेंगे। ● डॉ. कस्तूरीरंगन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के लिए मसौदा समिति की भी अध्यक्षता की जिसने एक नए NCF के विकास की सिफारिश की। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ● संचालन समिति को अपना कार्य पूरा करने के लिए तीन वर्ष का कार्यकाल दिया गया है। ● NCF देश भर के स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यक्रम और शिक्षण प्रथाओं के विकास के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज है।

	● समिति चार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करेगी - स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएं ● नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। ● खेल, कला, वाणिज्य, विज्ञान जैसे सह-पाठ्यक्रम और व्यावसायिक विषयों को समान स्तर पर माना जाएगा। ● जहां भी संभव हो, स्कूलों में शिक्षा का माध्यम कम से कम कक्षा 5 तक, लेकिन अधिमानतः कक्षा 8 और उससे आगे तक, घरेलू भाषा या मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। ● पोर्टेबल क्रेडिट के साथ बहु-विषयक उच्च शिक्षा ढांचा और प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री के साथ कई निकास। ● चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India -HECI) का गठन किया जाएगा। ● शिक्षा, मूल्यांकन, योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान-प्रदान हेतु 'राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच' (National Educational Technology Forum-NETF) नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी।
केंद्रीय सतर्कता आयोग	प्रसंग: भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने हाल ही में देखा है कि रेलवे का सतर्कता निदेशालय केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर काम कर रहा है। रेलवे सतर्कता निदेशालय के बारे में ● सतर्कता निदेशालय भारतीय रेलवे में प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ● यह शिकायतों तथा नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप उनकी अनुरूपता निर्धारित करने के लिए प्रबंधकीय निर्णयों के संबंध में नमूना जांच करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के बारे में ● CVC को सरकार द्वारा फरवरी, 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति (Committee on Prevention of Corruption) की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था। ● संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 द्वारा इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। ● शासनादेश: यह लोकसेवकों की कुछ श्रेणियों द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (Prevention of Corruption Act), 1988 के तहत किये गए भ्रष्टाचारों की जाँच कराने की शक्ति रखता है। ● संरचना: आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) होगा; और दो से अधिक सतर्कता आयुक्त (सदस्य) नहीं होंगे। ● नियुक्ति: उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री (अध्यक्ष), गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है।

भारत की धार्मिक संरचना पर प्यू स्टडी (Pew Study)	संदर्भ: विभाजन के बाद से भारत की जनसंख्या की धार्मिक संरचना पर एक नया अध्ययन हाल ही में प्यू स्टडी द्वारा किया गया था। ● प्यू रिसर्च सेंटर वाशिंगटन, डी.सी. में स्थित एक गैर-पक्षपाती अमेरिकी थिंक टैंक है। ● यह संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया को आकार देने वाले सामाजिक मुद्दों, जनमत और जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष ● संरचना में सीमांत परिवर्तन: हिंदुओं और मुसलमानों के "गिरावट और अभिसरण प्रजनन पैटर्न" के कारण, 1951 के बाद से जनसंख्या की समग्र धार्मिक संरचना में केवल मामूली परिवर्तन हुए हैं। ● कुल प्रजनन दर (1992 से 2015): मुसलमानों के लिए, यह 4.4 से घटकर 2.6 हो गई, जबकि हिंदुओं की 3.3 से 2.1 तक गिर गई। यह इंगित करता है कि भारत के धार्मिक समूहों के बीच बच्चे पैदा करने में अंतराल पहले की तुलना में बहुत कम है। ○ मध्य भारत में महिलाओं में अधिक बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति थी। ○ तमिलनाडु और केरल में क्रमशः 1.7 और 1.6 के TFR के विपरीत, बिहार और उत्तर प्रदेश ने TFR क्रमशः 3.4 और 2.7 दिखाया। ● सकारात्मक समग्र विकास: लेकिन सभी छह प्रमुख धार्मिक समूहों - हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन में पूर्ण संख्या में वृद्धि हुई है। ● इस प्रवृत्ति का एकमात्र अपवाद पारसी हैं, जिनकी संख्या 1951 और 2011 के बीच 110,000 से 60,000 हो गई है। ● लड़के को वरीयता: लिंग-चयनात्मक गर्भपात के कारण अनुमानित रूप से 20 मिलियन लड़कियों की कमी हुई। यह प्रथा मुसलमानों और ईसाइयों की तुलना में भारतीय हिंदुओं में अधिक सामान्य है। ● प्रवास का प्रभाव: 1950 के दशक से, प्रवासन का भारत की धार्मिक संरचना पर केवल मामूली प्रभाव पड़ा है। ● हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों के भारत छोड़ने की अधिक संभावना है जबकि मुस्लिम-बहुल देशों से भारत में आने वाले अप्रवासी अनुपातहीन रूप से हिंदू हैं। ● धार्मिक परिवर्तन: इसका भारत की समग्र संरचना पर भी नगण्य प्रभाव पड़ा है, 98% भारतीय वयस्क अभी भी उस धर्म से पहचान रखते हैं जिसमें उनका पालन-पोषण हुआ था।
सांकेतिक भाषा दिवस	● संयुक्त राष्ट्र की घोषणा का अनुसरण करते हुए बधिरी के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के हिस्से के रूप में दुनिया भर में हर साल 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। ● भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (ISLRTC), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का एक स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान है। ● संयुक्त राष्ट्र ने 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में घोषित किया, ISLRTC ने प्रत्येक वर्ष इसे मनाया है - आम जनता को भारतीय सांकेतिक भाषाओं के महत्व और सुनने में अक्षम व्यक्तियों के लिए सूचना और संचार सुलभता के बारे में संवेदनशील बनाना है। ● सांकेतिक भाषा न केवल लोगों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बल्कि सुनने में अक्षम व्यक्तियों के लिए रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सृजन में भी महत्वपूर्ण है।
पिछड़ा वर्ग की जाति जनगणना	संदर्भ: केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना "प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर" है। केंद्र द्वारा प्रमुख तर्क ● केंद्र ने तर्क दिया कि आजादी से पहले जब जातियों की जनगणना की गई थी, तब भी "पूर्णता और सटीकता" के संबंध में डेटा का नुकसान हुआ था। ● सरकार ने यह भी कहा है कि 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) में शामिल जाति के आंकड़े आधिकारिक उद्देश्यों के लिए "अनुपयोगी" हैं क्योंकि वे "तकनीकी खामियों से भरे हुए हैं"।

	○ केंद्र ने कहा कि 2011 का कच्चा जाति/जनजाति डेटा अनुपयोगी था। उदाहरण के लिए, केरल के मालाबार क्षेत्र में मप्पीला को 40 अलग-अलग तरीकों से लिखा गया था, जिसके परिणामस्वरूप 40 विभिन्न जातियों की सूची बनाई गई थी। ○ SECC जाति डेटा को रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में संग्रहीत किया जाता है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है (SECC का आर्थिक डेटा प्रकाशित होता है)। ● सरकार ने कहा कि जनगणना में जाति-वार गणना 1951 से नीति के रूप में छोड़ दी गई थी। इसने कहा कि “जाति के आधिकारिक हतोत्साह” की नीति थी। जनगणना क्या है? ● जनगणना (दशवार्षिक जनगणना) में, जनसांख्यिकीय और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मापदंडों जैसे शिक्षा, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, धर्म, भाषा, विवाह, प्रजनन क्षमता, विकलांगता, व्यवसाय और व्यक्तियों के प्रवास पर डेटा एकत्र किया जाता है। ● गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तहत महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, भारत का कार्यालय जनगणना करने के लिए जिम्मेदार होता है। ● यह देश की आबादी के आकार, वितरण और सामाजिक-आर्थिक, जनसांख्यिकीय और अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ● भारत में पहली समकालिक जनगणना 1881 में हुई थी। तब से, प्रत्येक दस वर्ष में एक बार बिना किसी रुकावट के जनगणना की जाती रही है। ● आधिकारिक राजपत्र के अनुसार, जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जनगणना में एकत्र किए गए व्यक्तिगत डेटा को अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक नहीं किया जाता है। ○ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर सहित किसी अन्य डेटाबेस को तैयार करने के लिए व्यक्तिगत डेटा का उपयोग नहीं किया जाता है। ● विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर केवल समेकित जनगणना डेटा जारी किया जाता है। ● COVID-19 महामारी के प्रकोप के कारण, जनगणना 2021 और अन्य जनगणना से संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'FASTER' टेक्नोलॉजी	संदर्भ: जुलाई में CJI की अगुवाई वाली एक विशेष बेंच के एक आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का तेज़ और सुरक्षित ट्रांसमिशन" (FASTER) सिस्टम पेश किया है। ● इस प्रणाली के माध्यम से जमानत पर आदेश और गिरफ्तारी पर रोक सहित सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों को एक सुरक्षित माध्यम से जेल अधिकारियों और जांच एजेंसियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जा सकता है। ● सुप्रीम कोर्ट के अभ्यास और प्रक्रिया पर नियम और हैंडबुक निर्णय या आदेश की प्रमाणित प्रति को भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रसारित करने में सक्षम बनाता है। 'FASTER' टेक्नोलॉजी का महत्व ● 'FASTER' का मतलब है Fast and Secured Transmission of Electronic Records ● यह एक सुरक्षित संचार माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के तत्काल वितरण को सक्षम बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के कार्यान्वयन में कोई देरी न हो। ● इस नए सिस्टम के जरिए जांच एजेंसियों, जेल अथॉरिटीज और हाइकोर्ट्स जैसी जगहों पर समन, कोर्ट के अंतरिम, स्टे, जमानत ऑर्डर, जमानत के परवाने आदि फौरन भेजे जा सकेंगे। उससे कैदियों की रिहाई समय रहते हो सकेगी। ● अदालत द्वारा पहले ही उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के बाद भी यह प्रणाली लोगों की अनावश्यक गिरफ्तारी और हिरासत को भी रोकेगी। ● यह अंतिम अदालत द्वारा समय पर दिए गए निष्पादन पर रोक लगाने की सूचना भी दे सकता है। ● यह जीवन के मौलिक अधिकारों, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है।

प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन	संदर्भ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर को 'प्रधान मंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन' के राष्ट्रव्यापी रोल-आउट की घोषणा की। ● इसके तहत आम लोगों को एक यूनिट हेल्थ आईडी भी मिलेगी, जिसके जरिए उनके स्वास्थ्य का पूरा ब्योरा रखा जाएगा। ○ जब भी कोई डॉक्टर या किसी फार्मसी में जाता है, तो इस कार्ड में सब कुछ दर्ज हो जाएगा। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट से लेकर दवा तक, हेल्थ प्रोफाइल में सब कुछ उपलब्ध होगा। ● यह न केवल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करेगा बल्कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं की एक रजिस्ट्री भी प्रदान करेगा। ● इस मिशन को पुडुचेरी, चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली सहित छह केंद्र शासित प्रदेशों में पायलेट प्रॉजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। ● कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ● NDHM केंद्र के राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मानकों का एक कोर ई-स्वास्थ्य डेटाबेस स्थापित करके कागज पर रोगियों को अपने स्वास्थ्य डेटा पर नियंत्रण रखने की अनुमति देकर स्वास्थ्य सेवा वितरण को बढ़ाना है। ● अपने प्रमुख बिल्डिंग ब्लॉक्स (building blocks) या एप्लिकेशन, हेल्थआईडी, डिजीडॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, टेलीमेडिसिन और ई-फार्मसी के साथ यह मिशन अलग-अलग हितधारकों को एक साथ लाएगा और मौलिक रूप से मजबूत करेगा, इस प्रकार यह भारत के स्वास्थ्य सेवा वितरण परिदृश्य को बदल देगा।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(2)	संदर्भ : हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने फैसला सुनाया कि किसी संस्था को दी जाने वाली सरकारी सहायता नीति का विषय है, यह मौलिक अधिकार नहीं है। ● भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 (शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिये अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित) अपने स्वयं के प्रतिबंधों के अधीन है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ● कोई भी संस्था चाहे वह बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित हो, सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार नहीं है। दोनों ही मामलों में सहायता के नियमों और शर्तों का समान रूप से पालन करना होगा। ● बेंच ने कहा कि अगर सरकार ने सहायता वापस लेने के लिए कोई नीतिगत कॉल की, तो कोई संस्था "अधिकार के मामले" के रूप में निर्णय पर सवाल नहीं उठा सकती है। एक संस्था शर्तों के साथ अनुदान स्वीकार करने या अपने तरीके से जाने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 30(2) के बारे में ● इसमें कहा गया है सरकार को आर्थिक सहायता देते समय अल्पसंख्यक द्वारा प्रबंधित किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिये।
विकलांगों के लिए पदोन्नति कोटा की समय सीमा	संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से विकलांग व्यक्तियों (PwD) को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए “जल्द से जल्द और चार महीने से अधिक नहीं” निर्देश जारी करने को कहा। ● 14 जनवरी, 2020 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में “स्पष्टीकरण” की मांग की गई थी जिसमें पुष्टि की गई थी कि पीडब्ल्यूडी को पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। इस फैसले को सिद्धाराजू बनाम कर्नाटक राज्य के नाम से जाना जाता है। ● इसमें कहा गया है कि निर्देश विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के अनुसार जारी किए जाने चाहिए। ○ यह प्रावधान करता है कि "प्रत्येक उपयुक्त सरकार बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों से भरे जाने वाले पदों के प्रत्येक समूह में कैडर संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या का कम से कम 4% प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में नियुक्त करेगी। सिद्धाराजू बनाम कर्नाटक राज्य मामले के बारे में

	● सिद्धाराजू बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के आरक्षण की पुष्टि की। दिए गए मामले में, इंदरा साहनी के मामले के तहत दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार किया गया था। ● न्यायालय का विचार था कि पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षण प्रदान करने का आधार शारीरिक अक्षमता है और अनुच्छेद 16(1) के तहत निषिद्ध कोई भी मानदंड नहीं है। ● इसके अलावा, विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण का 50% की सीमा से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए, इंदिरा साहनी में निर्धारित आरक्षण पदोन्नति के नियम का स्पष्ट और मानक रूप से विकलांग व्यक्तियों पर कोई लागू नहीं है। पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में अन्य ऐतिहासिक निर्णय ● इंदिरा साहनी मामले (1992) में, SC ने कहा कि आरक्षण नीति को पदोन्नति तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। ● हालांकि, 77वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 16 में खंड 4A को शामिल किया और पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान को बहाल किया। ● नागराज फैसले (2006) में, कोर्ट ने तीन नियंत्रण शर्तों को निर्धारित किया जो राज्य को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले पूरा करना होगा: ○ राज्य को वर्ग का पिछड़ापन दिखाना होगा। ○ वर्ग को स्थिति या सेवा में अपर्याप्त रूप से दर्शाया गया है। ○ आरक्षण प्रशासनिक दक्षता के हित में है। ● जरनैल सिंह मामले (2018) में, इसने नागराज फैसले से पिछड़ेपन के प्रावधान के प्रदर्शन को रद्द कर दिया।
प्रगति (PRAGATI - Pro-Active Governance and Timely Implementation)	● वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया यह एक बहु उद्देश्यीय मंच है जो प्रधानमंत्री को विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिये केंद्र एवं राज्य के अधिकारियों के साथ चर्चा करने में सक्षम बनाता है। ● द्वारा डिज़ाइन किया गया: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Center- NIC) की मदद से प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) की टीम। ● इस त्रिस्तरीय प्रणाली में पीएमओ, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव शामिल हैं। ● उद्देश्य: ○ शिकायत निवारण; ○ कार्यक्रम कार्यान्वयन; ○ परियोजना निगरानी ● महत्व: ○ यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। ○ यह मंच रियल टाइम उपस्थिति और प्रमुख हितधारकों के बीच विनिमय के साथ ई-पारदर्शिता एवं ई-जवाबदेही हेतु एक मजबूत प्रणाली है। ○ यह ई-शासन और सुशासन हेतु एक अभिनव परियोजना है।
नेशनल फ्लोरेस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2020	सुर्खियों में: राष्ट्रपति द्वारा 51 पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय फ्लोरेस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। ● नर्सों द्वारा समाज को दी गई मेधावी सेवाओं के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1973 में फ्लोरेस नाइटिंगेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की बैठक	संदर्भ: हाल ही में वित्त मंत्री ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) के बारे में ● यह 2010 में कार्यकारी आदेश द्वारा गठित गैर-सांविधिक शीर्ष परिषद है। ● यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ● वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर रघुराम राजन समिति (2008) ने सबसे पहले FSDC के निर्माण का प्रस्ताव रखा। ● इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं और इसके सदस्यों में सभी वित्तीय क्षेत्र नियामकों (RBI, SEBI, PFRDA और IRDA) के प्रमुख, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव (DEA), वित्तीय सेवा विभाग के सचिव (DFS) शामिल हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IBBI) के अध्यक्ष और राजस्व सचिव को शामिल किया जाता है। ● FSDC उप-समिति की अध्यक्षता RBI के गवर्नर करते हैं। ● परिषद आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों को अपनी बैठक में आमंत्रित कर सकती है। ● कार्य: ○ परिषद का कार्य वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर-नियामक समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन तथा बड़ी वित्तीय कंपनियों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था से जुड़े छोटे-छोटे मुद्दों का विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण करना है। ○ इसके अतिरिक्त इस परिषद को अपनी गतिविधियों के लिये अलग से कोई कोष आवंटित नहीं किया जाता है।
कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (IFAD)	संदर्भ: हाल ही में कृषि विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय कोष (IFAD) ने वर्ष 2030 तक अपने जलवायु वित्त का 30% ग्रामीण लघु-स्तरीय कृषि में प्रकृति-आधारित समाधानों के समर्थन पर केंद्रित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। IFAD के बारे में: ● वर्ष 1974 के वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस के परिणामस्वरूप वर्ष 1977 में इसका गठन किया गया था। ● आईएफएडी एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है और विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने वाली विशिष्ट संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो संबद्ध परियोजनाओं के लिए कम ब्याज के साथ अनुदान और ऋण प्रदान करती है। ● मुख्यालय: रोम, इटली ● यह हर साल ग्रामीण विकास रिपोर्ट लाता है। ● इसके 177 सदस्य देश हैं। भारत भी एक सदस्य देश है। ● उद्देश्य: ○ गरीब लोगों की उत्पादक क्षमता में वृद्धि करना। ○ बाजार भागीदारी से उनके लिए लाभ बढ़ाना। ○ उनकी आर्थिक गतिविधियों की पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु अनुकूलता को मजबूती प्रदान करना। ● यह हाशिए पर जीवन व्यतीत कर रहे लोगों और कमजोर समूहों (जैसे कि छोटी जोत वाले किसान, वनवासी, पशुचारक, मछुआरे तथा छोटे पैमाने के उद्यमी) को आपदा की तैयारी, मौसम की जानकारी तक पहुँच, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं सामाजिक शिक्षा आदि प्रदान करने का कार्य करता है।
GST अपीलीय न्यायाधिकरण	प्रसंग: सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि सरकार के पास वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ● 2016 में केंद्रीय जीएसटी कानून पारित होने के चार साल बाद भी जीएसटी न्यायाधिकरण का गठन नहीं किया गया है। ● जीएसटी अधिनियम की धारा 109 ट्रिब्यूनल के गठन को अनिवार्य करती है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण क्या है?

	● GST अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा पारित किसी भी असंतोषजनक आदेश के लिए GST के तहत दूसरा अपील मंच है। ● केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण भी पहला आम मंच है। ● एक साझा मंच होने के नाते, जीएसटी के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों के निवारण में एकरूपता सुनिश्चित करना जीएसटीएटी का कर्तव्य है। ● यह न्यायालय के समान अधिकार रखता है और किसी मामले की सुनवाई के लिए दीवानी न्यायालय समझा जाता है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन ● राष्ट्रीय पीठ: राष्ट्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली में स्थित है, जिसमें 2 तकनीकी सदस्यों (प्रत्येक केंद्र और राज्य से 1) के साथ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष (प्रमुख) का गठन होता है। ● क्षेत्रीय बेंच: जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर सरकार आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय बेंच (अधिसूचना द्वारा) गठित कर सकती है। ○ अभी तक, भारत में 3 क्षेत्रीय बेंच (मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में स्थित) हैं। ● स्टेट और एरिया बेंच
खनिज अन्वेषण	सुर्खियों में : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने नीलामी के लिए भूगर्भीय रूप से संभावित 100 खनिज ब्लॉकों को चित्रित किया है। ● इन 100 रिपोर्टों को राज्य सरकारों को सौंपने से देश में खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी और अधिक संख्या में खनिज ब्लॉकों को नीलामी के तहत लाकर राज्य सरकारों को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। MMDR संशोधन अधिनियम, 2021 ● MMDR संशोधन अधिनियम, 2015 ने पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे के संदर्भ में खनिज रियायतों के आवंटन में पारदर्शिता की शुरुआत की। ● इस निरंतर प्रयास में मार्च 2021 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम को और अधिक स्वतंत्र बनाया गया है। ● हाल के संशोधन से खनन क्षेत्र में रोजगार और निवेश में वृद्धि, राज्यों को राजस्व में वृद्धि, खनिजों के उत्पादन में वृद्धि और खदानों का समयबद्ध संचालन, पट्टेदार के परिवर्तन के बाद खनन कार्यों में निरंतरता बनाए रखने, खनिज संसाधनों की खोज और नीलामी की गति में वृद्धि होने की उम्मीद है।
आयात टैग के बिना SEZ इकाइयों द्वारा स्थानीय बिक्री	संदर्भ: सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Special Economic Zones- SEZ) में उत्पादकों को आयात के रूप में इलाज किए बिना घरेलू बाजार में अपना उत्पादन बेचने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यह निर्यात के लिए हाल ही में अधिसूचित टैक्स रिफंड स्कीम से निर्यात-उन्मुख इकाइयों (EOU) और SEZ के बहिष्करण की भी समीक्षा कर रहा है। ● हाल ही में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि माल भाड़ा दरों और इनपुट लागत में वृद्धि के बावजूद, एसईजेड और ईओयू इकाइयों को निर्यात उत्पादों पर करों और शुल्कों की छूट (RoDTEP) योजना के तहत लाभ नहीं दिया गया था। RoDTEP योजना क्या है? ● भारत सरकार द्वारा निर्यात उत्पादों (आरओडीटीईपी) योजना पर शुल्क और करों की छूट की घोषणा 2019 में की गई थी और यह 1 जनवरी 2021 को प्रभावी हो गई। ● यह निर्यातकों को उन करों और शुल्कों पर रिफंड प्राप्त करने की अनुमति देता है जिन्हें किसी अन्य योजना के तहत छूट या रिफंड नहीं किया गया है। ● उद्देश्य: उन सामानों के निर्यात को बढ़ावा देना जो मात्रा में खराब थे। ● यह मर्चेडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (MEIS) का स्थान लेता है। ● यह MEIS तथा राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (RoSCTL) की छूट का एक संयोजन है। ● इस योजना के तहत निर्यात के फ्रेट ऑन बोर्ड (FOB) मूल्य के प्रतिशत के रूप में रिफंड का दावा किया जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) क्या हैं?

	● यह एक विशेष रूप से चित्रित शुल्क-मुक्त एन्क्लेव है, जिसे व्यापार संचालन और कर्तव्यों और शुल्कों के प्रयोजनों के लिए विदेशी क्षेत्र माना जाता है। ● घरेलू टैरिफ क्षेत्र (SEZ को छोड़कर पूरे भारत) से SEZ क्षेत्र में जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को निर्यात माना जाएगा और SEZ क्षेत्र से DTA में आने वाली वस्तुओं को आयात माना जाएगा। ● SEZ इकाइयां सामान के निर्माण और सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित की जाती हैं। ● व्यापार और ट्रेड्स लॉ देश के बाकी हिस्सों से अलग हैं। ● SEZs देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर स्थित हैं। ● उनके उद्देश्यों में व्यापार संतुलन बढ़ाना, रोजगार, निवेश में वृद्धि, रोजगार सृजन और प्रभावी प्रशासन शामिल हैं। ● SEZ इकाइयों को नियंत्रित करने वाला वर्तमान नियम यह है कि SEZ इकाइयाँ आयात शुल्क के भुगतान के बिना DTA से सामान और सेवाओं का आयात / खरीद कर सकती हैं। लेकिन जब SEZ डीटीए में सामान बेच रहे हैं तो आयात/सीमा शुल्क लगाया जाता है।
भारत से कर विवाद खत्म करेगी केयर्न एनर्जी	संदर्भ : यूके स्थित केयर्न एनर्जी पूर्वव्यापी करों के 1.06 बिलियन डॉलर के "दस्तावेजीकरण और धनवापसी के भुगतान" में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के साथ काम कर रही है। ● अपनी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में, केयर्न ने कहा कि भारत सरकार से अपेक्षित टैक्स रिफंड में से, विशेष लाभांश और बायबैक (buybacks) के माध्यम से शेयरधारकों को 70 करोड़ डॉलर वापस करने की योजना है। भारत सरकार द्वारा I-T कानूनों में हालिया संशोधन ● हाल ही में सरकार ने 2012-13 में पेश किए गए पूर्वव्यापी कर प्रावधानों को रद्द करने के लिए आयकर कानूनों में संशोधन किया, जिसके अंतर्गत 2006-07 में किए गए कॉर्पोरेट पुनर्गठन के लिए 2014 में केयर्न पर कर लगाया गया था। ● कर विभाग ने बाद में कार्यवाही के हिस्से के रूप में फर्म के शेयरों को फ्रीज कर दिया और दावा किए गए कर बकाया की वसूली के लिए उन्हें बेच दिया। ● यदि प्रभावित करदाता सभी लंबित मुकदमों को और किसी भी ब्याज तथा नुकसान के दावों को छोड़ देते हैं, तो परिवर्तन पूर्वव्यापी रूप से लगाए गए करों को वापस करने का प्रस्ताव है। ट्रिब्यूनल का फैसला ● कर विवाद की जांच कर रहे एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने पिछले साल केयर्न के पक्ष में फैसला सुनाया और कंपनी को 1.2 अरब डॉलर का हर्जाना दिया। जबकि सरकार ने फैसले के खिलाफ अपील दायर की है, केयर्न ने ट्रिब्यूनल के फैसले को लागू करने के लिए कई विदेशी न्यायालयों में मुकदमे दायर किए हैं। पृष्ठभूमि ● सन्दर्भित वर्ष 2006-07, एक ऐसा समय था जिसमें केयर्न एनर्जी में बड़े कॉर्पोरेट परिवर्तन और विकास हुए। ● यह वह वर्ष था जिसमें उसने न केवल एक कॉर्पोरेट पुनर्गठन किया, बल्कि एक भारतीय सहायक, केयर्न इंडिया भी शुरू किया, जो 2007 की शुरुआत में भारतीय बाजारों में सूचीबद्ध हुई। ● कॉर्पोरेट पुनर्गठन प्रक्रिया के माध्यम से, केयर्न एनर्जी ने अपनी सभी भारतीय संपत्तियों को स्थानांतरित कर दिया था, जो तब तक विभिन्न देशों में नौ सहायक कंपनियों के पास थी, नवगठित केयर्न इंडिया को। ● लेकिन कर अधिकारियों ने दावा किया कि इस पुनर्गठन की प्रक्रिया में, केयर्न एनर्जी ने 24,500 करोड़ रुपये का पूंजीगत लाभ कमाया था। यह विभाग ने जोर देकर कहा, 1.6 बिलियन अमरीकी डालर की कर मांग का आधार था। ● वर्ष 2011 में, यूके स्थित वेदांत रिसोर्सेज ने केयर्न इंडिया में लगभग 60% हिस्सेदारी खरीदी। दरअसल, इसके चार साल बाद, केयर्न इंडिया को अपनी पूर्व मूल कंपनी को होने वाले लाभ के लिए कर नहीं रोकने के लिए एक कर नोटिस मिला।
कोयला आधारित हाइड्रोजन	सुर्खियों में : कोयला मंत्रालय ने दो समितियों का गठन किया है, ये समितियां देखरेख के साथ-साथ मंत्रालय का मार्गदर्शन करेंगी। इसका उद्देश्य सही तरीके से हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। कोयले के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्पादन ● इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से प्राकृतिक गैस (ग्रे हाइड्रोजन) और नवीकरणीय ऊर्जा (ग्रीन हाइड्रोजन) के अलावा

	कोयला हाइड्रोजन बनाने (ब्राउन हाइड्रोजन) के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। अक्षय ऊर्जा (हरित हाइड्रोजन) के मामले में अधिशेष सौर ऊर्जा का उपयोग पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए किया जाता है। ● तरल ईंधन के स्थान पर हाइड्रोजन (वाहनों में ईंधन के रूप में), अधिशेष अक्षय ऊर्जा का हाइड्रोजन के रूप में भंडारण (क्योंकि बिजली को लागत प्रभावी मूल्य पर संग्रहीत नहीं किया जा सकता है) और उत्सर्जन में कटौती पर वैश्विक जोर दिया जा रहा है। ● हालांकि कोयले को अन्यत्र प्रोत्साहित नहीं किया गया है क्योंकि इस भय से कि कोयले के माध्यम से हाइड्रोजन निकालते समय (कोयले में निहित नमी से) कार्बन उत्सर्जन हो सकता है। ● भारत में उत्पादित लगभग 100% हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस के माध्यम से होता है। चुनौतियाँ ● कोयले से हाइड्रोजन के उत्पादन में उच्च उत्सर्जन के मामले में चुनौतियाँ होंगी और 'कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज' (CCUS) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालाँकि जब कोयले से हाइड्रोजन प्रक्रिया के दौरान बनने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ तरीके (CCUS) में फंसाया और संग्रहीत किया जाता है, भारतीय कोयला भंडार हाइड्रोजन का एक बड़ा स्रोत बन सकता है। ● उत्पादित प्रत्येक टन ब्राउन हाइड्रोजन के लिए, हमें कम से कम 10 से 12 टन CO₂ के बीच मिलता है। इसमें प्रक्रिया को चलाने वाले ऊर्जा स्रोत द्वारा उत्पादित CO₂ या ग्राहक को हाइड्रोजन के परिवहन में उत्पादित CO₂ भी शामिल नहीं है। कुल मिलाकर ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन और परिवहन पर्यावरण के लिए बहुत खराब है। ● इस्पात निर्माण में हाइड्रोजन के उपयोग से इस्पात के उत्पादन पर बहुत काम किया गया है। हालांकि हाइड्रोजन के माध्यम से लोहे की कमी एक एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया है और इसके लिए बहुत अधिक गर्मी की आवश्यकता होगी। कोयला गैसीकरण प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली सिंक गैस में CO की उपस्थिति के कारण DRI संयंत्रों में यह ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है।
कपड़ा क्षेत्र की पीएलआई योजना मंजूर	प्रसंग: हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी। इसके लिए 10,683 करोड़ रुपये बजट का आवंटन किया गया है। ● उद्देश्य: वैश्विक कपड़ा व्यापार में भारत को अपना ऐतिहासिक प्रभुत्व हासिल करने में मदद करना। योजना की मुख्य विशेषताएं ● इस योजना में एमएमएफ (मानव निर्मित फाइबर) परिधान, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के 10 खंडों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। ● इस योजना से 19,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नया निवेश आकर्षित होगा और कुल कारोबार 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बो जाएगा साथ ही इससे इस क्षेत्र में 7.5 लाख से ज्यादा अतिरिक्त नौकरियां मिलेंगी। ● विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों के साथ निवेश के दो स्तर होंगे। ○ पहला: कोई भी व्यक्ति या कंपनी जो एमएमएफ फैब्रिक, गारमेंट्स और तकनीकी टेक्स्टाइल के उत्पादों के उत्पादन के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और सिविल कार्यों (भूमि और प्रशासनिक भवन लागत को छोड़कर) में न्यूनतम 300 करोड़ रुपए का निवेश करने का इच्छुक है, भाग लेने के लिए पात्र होगा। ○ दूसरा: उन्हीं शर्तों के तहत (जैसे पहले चरण के मामले में) न्यूनतम 100 करोड़ रुपए खर्च करने के इच्छुक निवेशक आवेदन करने के पात्र होंगे। ● साथ ही आकांक्षी जिलों, टियर-3, टियर-4 कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी और इसके माध्यम से उद्योग को पिछड़े क्षेत्रों में ले जाने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा। ● इस योजना से गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों को लाभ होने की उम्मीद है। ● आवेदकों के पास निवेश अवधि के रूप में दो वर्ष होंगे और 2024-2025 'प्रदर्शन' वर्ष होगा। प्रोत्साहन प्रवाह 2025-2026 में शुरू होगा और पांच साल तक चलेगा। कपड़ा क्षेत्र का महत्व ● कपड़ा और वस्त्र उद्योग एक श्रम प्रधान क्षेत्र है जो भारत में 45 मिलियन लोगों को रोजगार देता है।

	● यह रोजगार के मामले में कृषि क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर है। ● यह भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन का 7%, भारत की निर्यात आय में 12% का योगदान देता है और कुल रोजगार का 21% से अधिक रोजगार देता है। ● भारत 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ तकनीकी वस्त्रों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो दुनिया में कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ● तकनीकी वस्त्र कार्यात्मक कपड़े होते हैं जिनका ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण जैसे उद्योगों में अनुप्रयोग होता है, ● भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है और दुनिया में हाथ से बुने हुए कपड़े का 95% भारत से आता है। ● भारत का दो-तिहाई कपड़ा निर्यात अब कपास आधारित है जबकि वस्त्र और परिधान में विश्व व्यापार का 66-70% एमएमएफ आधारित और तकनीकी वस्त्र है।
डिजिटल गांवों में 100 प्रतिशत डिजिटल साक्षरता के लिए पीएमजी दिशा शुरू	मुखियों में: डिजिटल गांवों में 100 प्रतिशत डिजिटल साक्षरता के लिए 'प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharata Abhiyan – PMGDISHA) अभियान शुरू किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार की एक प्रमुख डिजिटल साक्षरता योजना है। ● इस अभियान के अंतर्गत सितंबर 2021 में कुछ दिनों के लिए ग्रामीण नागरिकों विशेषकर महिलाओं और वंचित समुदायों के लिए तीन दिवसीय प्रमाणन अभियान चलाया जाएगा। ● उसके बाद, पीएमजीदिशा योजना के लिए इसी तरह से एक प्रमाणन अभियान चलाया जाएगा। ● इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) ने सभी डिजिटल गांवों को शत-प्रतिशत डिजिटल साक्षर बनाने का भी प्रस्ताव रखा। ● डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने में पीएमजी दिशा और सीएससी अहम भूमिका अदा करने वाले पक्षों के रूप में उभरे हैं और वे आम लोगों के जीवन को बदलने और डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार और नागरिकों के बीच की खाई को पाटने के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पीएमजीदिशा कार्यक्रम के बारे में ● इस योजना के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में छह करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने की परिकल्पना की गई है। इससे लगभग 40% ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जा सकेगा। ● डिजिटल रूप से साक्षर व्यक्ति: डिजिटल रूप से साक्षर व्यक्ति कंप्यूटर/डिजिटल एक्सेस डिवाइस (जैसे टैबलेट, स्मार्ट फोन, आदि) संचालित करने, ईमेल भेजने और प्राप्त करने, इंटरनेट ब्राउज़ करने, सरकारी सेवाओं तक पहुंचने, जानकारी की खोज करने, कैशलेस लेनदेन करने आदि में सक्षम होंगे। और इसलिए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आईटी का उपयोग करें।
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)	मुखियों में : PLFS में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2020 का त्रैमासिक बुलेटिन जारी किया गया है। एक निश्चित व छोटे समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) शुरू किया था। ● केवल 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (CWS) में शहरी क्षेत्रों के लिए तीन महीने के कम समय अंतराल में प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतक (अर्थात श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर) का अनुमान लगाने के लिए। ● ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सालाना 'सामान्य स्थिति' (ps+ss) और CWS दोनों में रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाने के लिए। त्रैमासिक बुलेटिन के लिए प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का वैचारिक ढांचा: ● आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) श्रम बल भागीदारी दर (LFPR), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR), बेरोजगारी दर (UR) आदि जैसे प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान देता है। ये संकेतक 'वर्तमान' साप्ताहिक स्थिति को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

	● श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर): एलएफपीआर को कुल आबादी में श्रम बल के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों (अर्थात कहीं कार्यरत या काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध) के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। (पुरुष: 73.6, महिला: 20.6; कुल: 47.3) ● श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR): डब्ल्यूपीआर को कुल आबादी में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। (पुरुष: 66.7, महिला: 17.9; कुल: 42.4) ● बेरोजगारी दर (यूआर): इसे श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। (पुरुष: 9.5, महिला: 13.1; कुल: 10.3)
कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र	सुर्खियों में: हैदराबाद में BHEL R & D केंद्र ने 2016 में नीति आयोग की सहायता से 0.25 टन प्रति दिन मेथनॉल का उत्पादन करने के लिए भारतीय उच्च राख कोयला (जिस कोयले में राख की अधिक मात्रा होती है) गैसीकरण पर काम करना शुरू किया। ● इस परियोजना को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 10 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ समर्थित किया गया था। ● BHEL ने '1.2 टन प्रति दिन फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर' (1.2 TPD Fluidized bed gasifier) का उपयोग करके उच्च राख वाले भारतीय कोयले से 0.25 टन प्रति दिन मेथनॉल बनाने की सुविधा को सफलतापूर्वक डिजाइन किया। ● भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र (high ash coal gasification based methanol production plant) का उद्घाटन BHEL अनुसंधान एवं विकास केंद्र, हैदराबाद में किया गया है। ● इस उत्पादित कच्चे मेथनॉल की मेथनॉल शुद्धता 98 से 99.5 फीसदी के बीच है। ● इस प्रयास से बीएचईएल में अधिक क्षमता वाली कोयला गैसीकरण सुविधाओं को डिजाइन करने के लिए इन-हाउस डिजाइन विशेषज्ञता का निर्माण हुआ, जो 'आत्म निर्भर भारत' के दृष्टिकोण को आवश्यक गति प्रदान करेगा। यह आंतरिक क्षमता भारत के कोयला गैसीकरण मिशन और हाइड्रोजन मिशन के लिए हाइड्रोजन उत्पादन के लिए कोयले की सहायता करेगी। ● इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद बीएचईएल कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं जैसे कि सिनगैस का मेथनॉल में कैटेलिटिक रूपांतरण घर में विकसित कर रहा है। मेथनॉल के बारे में ● इसका उपयोग मोटर ईंधन के रूप में, जहाज के इंजनों को बिजली देने और पूरे विश्व में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किया जाता है। ● मेथनॉल का उपयोग 'डाइ-मिथाइल ईथर' (di-methyl ether: DME) के उत्पादन करने के लिए भी किया जाता है। यह एक तरल ईंधन है, जो डीजल की तरह होता है। मौजूदा डीजल इंजनों को डीजल की जगह DME का उपयोग करने के लिए मामूली रूप से बदलने की जरूरत होती है। ● मेथनॉल हल्के-फुल्के वाहनों के लिए प्राकृतिक गैस आधारित ईंधन के बड़े पैमाने पर बाजार में प्रवेश के लिए सबसे आशाजनक विकल्प हो सकता है क्योंकि इसकी कम ईंधन लागत और गैसोलीन के साथ एक वाहन को चलाने की तुलना में कम अतिरिक्त लागत है। ● मेथनॉल, इथेनॉल की तरह लेकिन हाइड्रोकार्बन ईंधन के विपरीत, पानी में घुलनशील है। परिणामस्वरूप यह हाइड्रोकार्बन की तुलना में बहुत तेज गति से पर्यावरण में प्रसार और संवहन के माध्यम से ले जाया जाता है। तेजी से प्रवास के कारण हाइड्रोकार्बन की तुलना में मेथनॉल बायो-डिग्रेड बहुत तेजी से होता है। तेजी से परिवहन और गिरावट के परिणामस्वरूप इसका जीवनकाल कम होता है। दूसरी तरफ हाइड्रोकार्बन में कई स्थिर यौगिक होते हैं, जिनमें सुगंधित पदार्थ शामिल हैं जो जैव-जीवों के लिए अत्यधिक विषैले होते हैं और धीरे-धीरे खराब हो जाते हैं। ● सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (SATAT) पहल के तहत प्रचारित। ● विश्वव्यापी मेथनॉल उत्पादन का अधिकांश भाग प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है, जो अपेक्षाकृत आसान प्रक्रिया है। चूंकि भारत में प्राकृतिक गैस का अधिक भंडार नहीं है, इसलिए आयातित प्राकृतिक गैस से मेथनॉल का उत्पादन

	करने से विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह होता है और कभी-कभी प्राकृतिक गैस की अत्यधिक कीमतों के कारण यह गैर-आर्थिक होता है। अगला सबसे अच्छा विकल्प भारत के प्रचुर मात्रा में कोयले का उपयोग करना है। हालांकि, भारतीय कोयले के उच्च राख प्रतिशत के कारण, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुलभ तकनीक मांगों के लिए पर्याप्त नहीं होती है।
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021	संदर्भ: हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण- II के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 या ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की शुरुआत की। - इसका उद्देश्य देश खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस का दर्जा देने की केंद्र की पहल के एक हिस्से के रूप में यह ग्रामीण भारत में स्वच्छता, सफाई और स्वच्छता की स्थिति का आकलन करता है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (एसएसजी), 2021 के बारे में - सर्वेक्षण 2021 के संचालन के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी को काम पर रखा गया है। - सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में, गांवों, जिलों और राज्यों को प्रमुख मानकों का उपयोग करके रैंक किया जाएगा। - ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में देश भर के 698 जिलों के 17,475 गांवों को कवर किया जाएगा जहां सर्वेक्षण के लिए स्कूलों, आंगनबाड़ियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों, हाट/बाजारों/धार्मिक स्थलों का दौरा किया जाएगा। - इसके अलावा नागरिकों को इस उद्देश्य के लिए विकसित एक एप्लिकेशन का उपयोग करके स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर ऑनलाइन प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। SSG की पृष्ठभूमि क्या है? - इसे जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS) द्वारा कमीशन किया गया था। - यह जनांदोलन (जन आंदोलन) बनाने का एक माध्यम रहा है। - प्रमुख गुणवत्ता और मात्रात्मक मानकों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर जिलों की रैंकिंग की जाती है। - SSG 2021 के विभिन्न तत्वों का भार नीचे दिया गया है: - सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता का प्रत्यक्ष निरीक्षण- 30% - नागरिकों की प्रतिक्रिया - 35% - स्वच्छता संबंधी मानकों पर सेवा स्तर की प्रगति - 35% स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण- II क्या है? - जल शक्ति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2020 में SBM (G) चरण- II को मंजूरी दी गई थी और इसे 2020-21 से 2024-25 तक मिशन मोड में 1,40,881 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा। - यह चरण- I के तहत उपलब्धियों की स्थिरता और ग्रामीण भारत में ठोस / तरल और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने पर जोर देता है। - उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिये केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न 90:10, अन्य राज्यों के लिये 60:40 और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में 100% वित्तपोषण केंद्र द्वारा किया जाएगा। - खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ), ओडीएफ+, ओडीएफ++ स्थिति (नगर और शहरों के लिए) के बारे में ODF: दिन के किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते नहीं पाया जाता है। ODF+: दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति खुले में शौच और/या पेशाब करते हुए नहीं पाया जाता है, और सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक और अच्छी तरह से बनाए हुए हैं। ODF++: यदि क्षेत्र पहले से ही ओडीएफ+ है और मल कीचड़/सेप्टेज और सीवेज को सुरक्षित रूप से प्रबंधित और उपचारित किया जाता है।
परिवहन और विपणन सहायता (TMA) योजना	मुखियों में: हाल ही में केंद्र ने निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए "परिवहन और विपणन सहायता" (टीएमए) योजना को संशोधित किया। पृष्ठभूमि: वाणिज्य विभाग ने माल ढुलाई के अंतरराष्ट्रीय घटक के साथ सहायता करने के लिए, कृषि उत्पादों के भारतीय निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली उच्च माल ढुलाई लागत के नुकसान को कम करने के लिए फरवरी 2019 में निर्दिष्ट

	कृषि उत्पाद योजना के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) शुरू की थी। संशोधित योजना में निम्नलिखित बड़े बदलाव किए गए हैं: ● डेयरी उत्पाद, जो पहले की योजना के अंतर्गत शामिल नहीं थे, संशोधित योजना के तहत सहायता के पात्र होंगे। ● सहायता की दरों में समुद्र द्वारा निर्यात के लिये 50% और हवाई मार्ग हेतु 100% की वृद्धि की गई है। लाभ: संशोधित योजना के तहत बढ़ी हुई सहायता से कृषि उत्पादों के भारतीय निर्यातकों को बढ़ती माल ढुलाई और लोजिस्टिक्स लागत को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
आदिवासी कला को बढ़ावा देने को आत्मानिर्भर भारत कॉर्नर	संदर्भ : India@75 के हिस्से के रूप में, जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED) एक आत्मानिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करने जा रहा है। आत्मानवीर भारत कॉर्नर के बारे में ● यह कॉर्नर प्राकृतिक और जैविक उत्पादों के अलावा जीआई टैग वाले आदिवासी कला और शिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष स्थान होगा। ● TRIFED "वोकल फॉर लोकल" पर फोकस के साथ "आत्मनिर्भर भारत" के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में जुटा है। ● TRIFED कई मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है जैसे: ○ संस्कृति मंत्रालय ○ उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य मंत्रालय ○ भारतीय डाक ○ पर्यटन मंत्रालय ○ प्रधान मंत्री का कार्यालय ● TRIFED विदेश मंत्रालय के सहयोग से अगले 90 दिनों में विश्व भर में 75 भारतीय मिशनों / दूतावासों में एक आत्मानिर्भर भारत कॉर्नर भी स्थापित कर रहा है। ● स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बैंकॉक, थाईलैंड में भारतीय दूतावास में पहले आत्म निर्भर भारत कोने का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया गया। ट्राइफेड (TRIFED) क्या है? ● यह भारत सरकार द्वारा अगस्त 1987 में बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत स्थापित किया गया था। ● मुख्य उद्देश्य: लघु वन उत्पादों (MFP) के व्यापार को संस्थागत बनाना और भारत के आदिवासियों को उनके द्वारा उत्पादित अधिशेष कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य प्रदान करना। ● यह राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था है। ● मंत्रालय: जनजातीय मामलों के मंत्रालय। ● ट्राइफेड को उनके द्वारा एकत्रित/खेती की गई लघु वनोपज और अधिशेष कृषि उत्पाद (SAP) के व्यापार को संस्थागत रूप देकर देश के आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है।
पेट्रोल-डीजल जीएसटी के दायरे में	संदर्भ : जीएसटी परिषद पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों पर एकल राष्ट्रीय जीएसटी व्यवस्था के तहत कर लगाने पर विचार कर सकती है। ● जीएसटी के बजाय, अभी तक पेट्रोल, डीजल, एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF), प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल जैसे पेट्रोलियम सामानों पर 'उत्पाद शुल्क' और 'वैट' जैसे कर लगाए जा रहे हैं। ● 2017 में जब GST लागू किया गया था, तब राज्यों ने इन वस्तुओं को GST में शामिल करने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें इन वस्तुओं पर भारी राजस्व (VAT के माध्यम से) मिल रहा था। ● उन्होंने सोचा कि अगर इन पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में शामिल कर लिया गया तो वे इन वस्तुओं पर कर की दर तय करने की स्वतंत्रता खो देंगे। ● तो उस समय इस बात पर सहमति बनी थी कि 5 साल के भीतर अर्थात 2022 तक इन पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में शामिल कर लिया जाएगा। जीएसटी परिषद के बारे में

	● GST परिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। ● यह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें करता है। ● जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। ● इसके अन्य सदस्य केंद्रीय राजस्व या वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं।																		
थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति	संदर्भ: थोक कीमतों में मुद्रास्फीति अगस्त में बढ़कर 11.39% हो गई, जो लगातार पांचवें महीने दोहरे अंकों में रही। प्रमुख मुद्रास्फीति डेटा ● विनिर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति: 11.4% ● विनिर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति: 26.1% ● खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति: 3.43% ● एलपीजी, पेट्रोल और डीजल मुद्रास्फीति क्रमशः 48.1%, 61.5% और 50.7% है। WPI और CPI के बीच अंतर <table><tr><th>संदर्भ</th><th>WPI (थोक मूल्य सूचकांक)</th><th>CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक)</th></tr><tr><td>परिभाषा</td><td>थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन की मात्रा।</td><td>खुदरा स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को दर्शाता है।</td></tr><tr><td>प्रकाशन कार्यालय</td><td>आर्थिक सलाहकार का कार्यालय (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)</td><td>केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) और श्रम ब्यूरो</td></tr><tr><td>सामान</td><td>केवल सामान</td><td>सामान और सेवाएं दोनों</td></tr><tr><td>आधार वर्ष</td><td>2011-12</td><td>2012 नोट: आधार वर्ष संशोधित किया जाना है।</td></tr><tr><td>प्रकाशित</td><td>महीने के</td><td>महीने के</td></tr></table>	संदर्भ	WPI (थोक मूल्य सूचकांक)	CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक)	परिभाषा	थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन की मात्रा।	खुदरा स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को दर्शाता है।	प्रकाशन कार्यालय	आर्थिक सलाहकार का कार्यालय (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) और श्रम ब्यूरो	सामान	केवल सामान	सामान और सेवाएं दोनों	आधार वर्ष	2011-12	2012 नोट: आधार वर्ष संशोधित किया जाना है।	प्रकाशित	महीने के	महीने के
संदर्भ	WPI (थोक मूल्य सूचकांक)	CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक)																	
परिभाषा	थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन की मात्रा।	खुदरा स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को दर्शाता है।																	
प्रकाशन कार्यालय	आर्थिक सलाहकार का कार्यालय (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) और श्रम ब्यूरो																	
सामान	केवल सामान	सामान और सेवाएं दोनों																	
आधार वर्ष	2011-12	2012 नोट: आधार वर्ष संशोधित किया जाना है।																	
प्रकाशित	महीने के	महीने के																	
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और PayNow को लिंक करना	संदर्भ : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (MAS) ने अपने संबंधित तेज भुगतान प्रणालियों - एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) और PayNow को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की। ● PayNow सिंगापुर की तेज भुगतान प्रणाली है जो पीयर-टू-पीयर फंड-ट्रांसफर सेवा को सक्षम बनाती है। ● यह लिंक सिस्टम जुलाई 2022 से काम करेगा। ● इसके तहत भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और सिंगापुर का 'PayNow' एक साथ जुड़ेंगे और इसके जरिए दोनों देशों के बीच फास्ट पेमेंट की सुविधा मिलेगी। ● इससे उपयोगकर्ताओं को काफी फायदा होगा क्योंकि वे पारस्परिक आधार पर तत्काल एवं कम लागत के साथ पैसों का हस्तांतरण कर सकेंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) क्या है? ● यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक अंतर बैंक फंड ट्रांसफर की सुविधा है, जिसके जरिए स्मार्टफोन पर फोन नंबर और वर्चुअल आईडी की मदद से पेमेंट की जा सकती है। ● यह इंटरनेट बैंक फंड ट्रांसफर के मकैनिज्म पर आधारित है। एनपीसीआई के द्वारा इस सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। ● यूजर्स यूपीआई से चंद मिनटों में ही घर बैठे ही पेमेंट के साथ मनी ट्रांसफर करते हैं। ● यूपीआई एक ग्राहक को कार्ड या बैंक विवरण टाइप करने की परेशानी के बिना, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के विभिन्न व्यापारियों को सीधे बैंक खाते से भुगतान करने की अनुमति देता है। ● यह "पीयर टू पीयर" संग्रह अनुरोध को भी पूरा करता है जिसे शेड्यूल किया जा सकता है और सुविधा के अनुसार																		

	भुगतान किया जा सकता है। ● पिछले 5 वर्षों में 100 मिलियन से अधिक UPI QR बनाए गए हैं। ● 2020-21 में BHIM UPI ने 41 लाख करोड़ रुपये के 22 अरब लेनदेन को संसाधित किया है।
प्रतिभूतियों के लिए 'T+1' निपटान प्रणाली	प्रसंग : सिक््योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने स्टॉक मार्केट एक्सचेंजों के लिए टी + 1 निपटान प्रणाली की पेशकश की है। ● यदि स्टॉक एक्सचेंज प्रस्ताव पर सहमत हो जाता है, तो निवेशकों को उनके द्वारा अपने खातों में बेचे या खरीदे गए शेयरों के लिए तेजी से और सुरक्षित तथा जोखिम मुक्त माहौल में पैसा मिलेगा। T+1 (T+2, T+3) चक्र क्या है? ● T+1 (T+2, T+3) संक्षिप्त रूप हैं जो सुरक्षा लेनदेन की निपटान तिथि को संदर्भित करते हैं। ● “T” का अर्थ लेन-देन की तारीख है, जिस दिन लेन-देन होता है। ● संख्या 1, 2, या 3 दर्शाती है कि लेन-देन की तारीख के कितने दिन बाद निपटान-या धन का हस्तांतरण और सुरक्षा स्वामित्व-होता है। ● स्टॉक और म्यूचुअल फंड आमतौर पर T+1 होते हैं और बॉन्ड तथा मनी मार्केट फंड T+1, T+2, और T+3 के बीच भिन्न होते हैं।
इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)	संदर्भ: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वस्तु और सेवा कर व्यवस्था के उल्टे शुल्क ढांचे के तहत इनपुट सेवाओं के लिए टैक्स क्रेडिट के रिफंड का दावा नहीं किया जा सकता है। ● SC ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले की पुष्टि की है जिसमें इनपुट सेवाओं के कारण संचित अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की वापसी को निष्पादित करने के लिए केंद्रीय वस्तु और सेवा कर नियमों में शामिल एक राजकोषीय सूत्र को बरकरार रखा गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्या है? ● ITC करों के कैस्केडिंग से बचने के लिए एक तंत्र है। करों का कैस्केडिंग, सरल भाषा में, 'कर पर कर' है। ● इनपुट टैक्स क्रेडिट से तात्पर्य उस कर से है जो किसी व्यक्ति द्वारा वस्तु या सेवाओं की खरीद के समय पहले ही चुकाया जा चुका है और जो देय कर से कटौती के रूप में उपलब्ध है। ● एक पंजीकृत व्यक्ति को जीएसटी के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ है, सीजीएसटी, एसजीएसटी/यूटीजीएसटी या आईजीएसटी किसी भी वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाया गया। ● इसमें आयात पर लगने वाला IGST और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत देय कर शामिल है। ● जब कोई पंजीकृत डीलर से कोई उत्पाद/सेवा खरीदता है तो हम खरीद पर कर का भुगतान करते हैं। ● बेचने पर, हम टैक्स वसूल करते हैं। ● हम खरीद के समय भुगतान किए गए करों को आउटपुट टैक्स (बिक्री पर कर) की राशि के साथ समायोजित करते हैं और कर की शेष देयता (बिक्री पर कर घटाकर खरीद पर कर) का भुगतान सरकार को करना होता है। ● इस तंत्र को इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग कहा जाता है। ● यदि इनपुट पर दिया गया टैक्स आउटपुट पर टैक्स से अधिक है, तो अतिरिक्त रिफंड के रूप में दावा किया जा सकता है। अपवाद: कंपोजीशन स्कीम के तहत एक व्यवसाय इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकता है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए या छूट प्राप्त सामानों के लिए ITC का दावा नहीं किया जा सकता है।
कृषि पर समझौता: विश्व व्यापार संगठन (WTO)	प्रसंग: G-33 वर्चुअल अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। ● बैठक में, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में बताया है कि विश्व व्यापार संगठन (WTO) में कृषि समझौता गहरे असंतुलन से भरा हुआ है, जो विकसित देशों का पक्ष लेता है और कई विकासशील देशों के खिलाफ नियमों को झुकाता है। G-33 क्या है? ● G-33 (या कृषि में विशेष उत्पादों के मित्र) विकासशील देशों का एक गठबंधन है। ● यह 2003 कैनकन (Cancun) मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से पहले स्थापित किया गया था।

	● यह समूह ऐसे देशों की मदद करने के लिये बनाया गया था जो समान समस्याओं का सामना कर रहे थे। G-33 ने विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं में विकासशील देशों हेतु विशेष नियम प्रस्तावित किये हैं, जैसे कि उन्हें अपने कृषि बाजारों तक पहुँच को प्रतिबंधित करना जारी रखने की अनुमति देना। ● वर्तमान में 47 सदस्य राष्ट्र हैं। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है? ● एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर (AoA) विश्व व्यापार संगठन की एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। ● यह टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते के उरुग्वे दौर के दौरान बातचीत की गई थी , और 1 जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के साथ लागू हुई। ● विकासशील देशों में आय का एक प्रमुख स्रोत, छोटे किसानों के लिए टैरिफ सुरक्षा को कम करने के लिए नागरिक समाज समूहों द्वारा समझौते की आलोचना की गई है, साथ ही साथ अमीर देशों को घर पर कृषि पर सब्सिडी जारी रखने की अनुमति दी गई है।
विश्व बैंक ने बंद की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट	संदर्भ : विश्व बैंक अपनी 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट के वर्ष 2018 और 2020 संस्करणों (क्रमशः 2017 और 2019 में जारी) में बैंक कर्मचारियों के 'नैतिक मामलों' से संबंधित 'डेटा अनियमितताओं' की जाँच के बाद इसके प्रकाशन को बंद कर देगा। ● यह व्यापार और निवेश के माहौल का आकलन करने के लिए एक नए दृष्टिकोण पर काम करेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में ● इस रिपोर्ट को पहली बार वर्ष 2003 में जारी किया गया था ताकि व्यापार नियमों के उद्देश्य और उपायों का आकलन किया जा सके तथा 190 अर्थव्यवस्थाओं के जीवन चक्र एवं उनके अंतर्गत आने वाले व्यवसाय को प्रभावित करने वाले दस मापदंडों के आधार पर मापा जा सके। ● विशेष रूप से वर्ष 2017, 2018 और 2019 में जारी तीन रिपोर्टों में भारत "सबसे उल्लेखनीय सुधार" दिखाते हुए शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में स्थान पाने में सफल रहा। विश्व बैंक के बारे में ● यह 1944 में अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतराष्ट्रीय बैंक (IBRD) के रूप में बनाया गया था। ● IBRD बाद में विश्व बैंक बन गया। ● यह स्थायी समाधान के लिए काम करता है जो गरीबी को कम करता है और विकासशील देशों में साझा समृद्धि का निर्माण करता है। ● प्रमुख रिपोर्ट: ○ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ○ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ○ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ● विश्व बैंक पाँच प्रमुख विकास संस्थान: ○ अंतराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD): यह लोन, ऋण और अनुदान प्रदान करता है। ○ अंतराष्ट्रीय विकास संघ (IDA): यह निम्न आय वाले देशों को कम या बिना ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है। ○ अंतराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC): यह कंपनियों और सरकारों को निवेश, सलाह तथा परिसंपत्तियों के प्रबंधन संबंधी सहायता प्रदान करता है। ○ बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA): यह ऋणदाताओं और निवेशकों को युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। ○ निवेश विवादों के निपटारे के लिये अंतराष्ट्रीय केंद्र (ICSID): यह निवेशकों और देशों के मध्य उत्पन्न निवेश-विवादों के सुलह और मध्यस्थता के लिये सुविधाएँ प्रदान करता है।
रेल कौशल विकास योजना	संदर्भ: हाल ही में रेल मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अंतर्गत रेल कौशल विकास योजना (RKVY) की शुरुआत की है।

	रेल कौशल विकास योजना (RKVY) क्या है? ● यह एक कौशल विकास कार्यक्रम है, जहां युवाओं को रेलवे के लिए प्रासंगिक नौकरियों पर विशेष ध्यान देने के साथ प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ● प्रशिक्षण चार ट्रेडों में प्रदान किया जाएगा अर्थात् इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर एवं अन्य ट्रेडों को क्षेत्रीय रेलवे के साथ-साथ उत्पादन इकाइयों द्वारा क्षेत्रीय मांगों तथा आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर जोड़ा जाएगा। ● अपरेंटिस अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ● उद्देश्य: ○ गुणात्मक सुधार लाने के लिए युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण कौशल प्रदान करना। ○ इसके तहत अगले तीन वर्षों में 50 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ● पात्रता: इसके लिये 10वीं पास और 18-35 वर्ष के बीच के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे। ● महत्व: यह योजना न केवल युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करेगी, बल्कि स्वरोजगार हेतु कौशल को भी उन्नत करेगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है? ● यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो वर्ष 2015 में शुरू किया गया। ● उद्देश्य: इसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने और देश की जरूरतों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रमाणन को संरेखित करने के उद्देश्य से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रेरित करना है। महत्वपूर्ण तथ्य : ○ अल्पावधि प्रशिक्षण: राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुसार प्रशिक्षण उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो या तो स्कूल/कॉलेज छोड़ चुके हैं या बेरोजगार हैं। ○ पूर्व शिक्षा की मान्यता (RPL): एक निश्चित कौशल वाले या पूर्व शिक्षण अनुभव वाले व्यक्ति का मूल्यांकन NSQF के अनुसार, ग्रेड के साथ RPL के तहत किया जाता है और प्रमाणित किया जाता है। ○ विशेष परियोजनाएं: यह घटक सरकारी निकायों और कॉर्पोरेट के विशेष क्षेत्रों एवं परिसरों में प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर व हाशिये पर स्थित समूहों को प्रशिक्षण के लिये प्रोत्साहित करना है। ○ प्रशिक्षण भागीदारों (TPs) के लिये हर छह महीने में कौशल और रोजगार मेलों का आयोजन करना तथा प्रमाणित लोगों को प्लेसमेंट सहायता प्रदान करना अनिवार्य है।
राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक: FSSAI	प्रसंग: हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (Food Safety Index-FSSAI) जारी किया है। ● इसके अलावा, देश भर में खाद्य सुरक्षा परिवेश को मजबूत करने के लिये 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन (फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। सूचकांक के बारे में: ● खाद्य सुरक्षा के पांच महत्वपूर्ण मानकों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा सूचकांक विकसित किया गया है। ● 7 जून, 2019 को वर्ष 2018-19 के लिये पहला राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर घोषित किया गया था। राज्यों की रैंकिंग: ● बड़े राज्यों में, गुजरात शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य था, उसके बाद केरल और तमिलनाडु थे। ● छोटे राज्यों में, गोवा पहले स्थान पर रहा, उसके बाद मेघालय और मणिपुर का स्थान रहा। ● केंद्रशासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और नई दिल्ली शीर्ष स्थान पर रहे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के बारे में ● यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSS अधिनियम) के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक

	निकाय है। ● इस अधिनियम का उद्देश्य बहु-स्तरीय, बहु-विभागीय नियंत्रण से एकल कमांड लाइन में स्थानांतरित करके, खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित सभी मामलों के लिए एकल संदर्भ बिंदु स्थापित करना है। ● मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ● इसमें एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं जिनमें से एक-तिहाई महिलाएं होती हैं। तथा FSSAI के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ● प्रवर्तन की प्राथमिक जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों की होती है।
SPIN योजना	संदर्भ: हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने SPIN (Strengthening the Potential of India- भारत की क्षमता को मजबूत करना) नामक एक विशिष्ट योजना शुरू की। स्पिन योजना के बारे में ● SPIN योजना का उद्देश्य भारतीय मिट्टी के बर्तनों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का संचार करना है। ● यह एक बिना सब्सिडी वाला कार्यक्रम है, जो पंजीकृत कुम्हारों को प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत बैंकों से सीधे ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ● स्पिन योजना के तहत, KVIC आरबीएल बैंक के माध्यम से कुम्हारों को वित्तीय सहायता के लिए एक सुविधादाता के रूप में कार्य कर रहा है और इस योजना को चुनने वाले कारीगरों को प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है। ● राजकोष पर कोई वित्तीय बोझ नहीं होगा और कुम्हार द्वारा ऋण आसान किस्तों में चुकाया जाएगा। ● योजना के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड के 780 कुम्हारों ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से वित्तीय सहायता के लिए पंजीकरण कराया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? ● गैर कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्तीय सुविधाओं की औपचारिक पहुंच प्रदान करने के लिए अप्रैल, 2015 में योजना शुरू की गई। ● उद्देश्य: भारतीय अर्थव्यवस्था के गैर-वित्तपोषित क्षेत्रों के लिए बैंक वित्त को बढ़ावा देना और सुनिश्चित करना। ● इन ऋणों को PMMY के तहत MUDRA ऋणों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ● ये ऋण वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी, लघु वित्त बैंक, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा दिए जाते हैं। ● ऋण के प्रकार: ऋण लाभार्थी सूक्ष्म इकाई की वृद्धि और वित्त पोषण की जरूरतों के चरण के अनुसार दिए जाते हैं। ○ शिशु: 50,000 रुपये तक के ऋण को कवर किया जाता है। ○ किशोर: 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण को कवर किया जाता है। ○ तरुण: 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक के ऋण को कवर किया जाता है।
भारत योजना से सेवा निर्यात	संदर्भ: सेवा निर्यातकों को कुछ राहत देते हुए सरकार ने भारत योजना से सेवा निर्यात (SEIS) के अंतर्गत 2019-20 में किए गए निर्यात के लिए दिए जाने वाले लाभों को अधिसूचित किया है। ● इसने प्रति निर्यातक 5 करोड़ रुपये की पात्रता निर्धारित की है। ● लाभों की अधिसूचना से फर्मों के ऋण का बोझ कम होगा, विशेष रूप से यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में खिलाड़ियों के लिए जो महामारी में सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। भारत योजना से सेवा निर्यात (SEIS) के बारे में ● सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (SEIS) का उद्देश्य पात्र निर्यातों के लिए शुल्क स्क्रिप्ट क्रेडिट प्रदान करके भारत से सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना है। ○ एक ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी किए गए क्रेडिट प्रमाणपत्र की तरह है इसका उपयोग केंद्र सरकार को विभिन्न शुल्कों/करों का भुगतान करने के लिए किया जाता है। ● पात्र सेवाओं के सेवा प्रदाता अर्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा पर अधिसूचित दरों पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के हकदार होंगे। ● शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्ट का उपयोग सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवाओं की खरीद पर जीएसटी आदि के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

	● इसके अलावा, SEIS योजना ने वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त में छूट दी है और शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का उपयोग करके आयात किए गए सामान स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय हैं। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी होने की तारीख से 18 महीने की अवधि के लिए वैध होगा। ● यह योजना विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के सहयोग से सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित और प्रशासित है।
पेटेंट (संशोधन) नियम, 2021	मुख्तियारों में: सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों पर लगने वाले एकस्व क्रम-स्थापन (पेटेंट फाइलिंग) एवं प्रक्रिया शुल्क को 80% तक कम कर दिया है। पेटेंट के लिए आवेदन करते समय, नवोन्मेषकों (innovators) को इन पेटेंटों को उन संस्थानों के नाम पर आवेदन करना होता है, जिन्हें बड़े आवेदकों के लिए बहुत अधिक शुल्क देना पड़ता है। इस संबंध में देश के नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिक्षण संस्थानों की और अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये पेटेंट नियम, 2003 के तहत विभिन्न अधिनियमों के संबंध में उनके द्वारा देय आधिकारिक शुल्क को पेटेंट (संशोधन) नियम, 2021 के माध्यम से घटा दिया गया है। ● नए परीक्षकों की भर्ती करके जनशक्ति का संवर्धन करना। ● पेटेंट आवेदन करने और देने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करना। ● त्वरित और संपर्क रहित कार्यवाही के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेटेंट में मामलों की सुनवाई। ● वेबसाइटों की गतिशील पुनः अभिकल्पना एवं हितधारकों को आईपी सूचना का सद्य अनुक्रिया (वास्तविक समय) आधारित परेशानी मुक्त प्रसार। ● उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) ने अपने आवेदनों को दाखिल करने और प्रसंस्करण के साथ सुविधा प्रदान करने के लिए स्टार्ट-अप बौद्धिक संपदा संरक्षण (SIPP) की सुविधा प्रदान करने के लिए योजना शुरू की। ● फीडबैक/सुझाव/शिकायत दर्ज करने के लिए तंत्र स्थापित किया गया है। ● एक त्वरित परीक्षा प्रणाली शुरू की गई है जिसमें पेटेंट प्रदान करने के लिए एक आवेदन पर इस तरह के अनुरोध को दाखिल करने के एक वर्ष के भीतर निर्णय लिया जा रहा है।
चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने की योजना अधिसूचित	प्रसंग : हाल ही में केंद्र सरकार ने चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा और विनिर्माण लागत में भी बहुत कमी आएगी। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 400 करोड़ रुपये है तथा इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020-2021 से लेकर वित्त वर्ष 2024-2025 तक है। महत्वपूर्ण तथ्य ● इस योजना का उद्देश्य परीक्षण और बुनियादी सुविधाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। ● उम्मीद है कि इससे चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन की लागत में कमी आएगी, जिससे वे घरेलू उपभोग के लिए अधिक किफायती हो जाएंगे। ● चयनित किए गए मेडिकल डिवाइस पार्क को सामान्य बुनियादी सुविधाओं की परियोजना लागत का 70 % वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों के मामले में वित्तीय सहायता परियोजना लागत का 90 % होगी। ● हालांकि इस योजना के अंतर्गत एक मेडिकल डिवाइस पार्क को अधिकतम 100 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चिकित्सा उपकरण के बारे में ● चिकित्सा उपकरण उद्योग इंजीनियरिंग और चिकित्सा का एक अनूठा मिश्रण है। इसमें मशीनों का निर्माण करना शामिल है जिनका उपयोग जीवन बचाने के लिये किया जाता है। ● चिकित्सा उपकरणों में सर्जिकल उपकरण, डायग्नोस्टिक उपकरण जैसे- कार्डिएक इमेजिंग, सीटी स्कैन, एक्स-रे, मॉलिक्यूलर इमेजिंग, एमआरआई और हाथ से प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों सहित लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट जैसे- वेंटिलेटर आदि के साथ-साथ इम्प्लांट्स एवं डिस्पोजल तथा अल्ट्रासाउंड इमेजिंग शामिल हैं। क्या आप जानते हैं?

	● उद्योग के अनुमानों के अनुसार, भारतीय चिकित्सा उपकरणों का बाजार 2025 तक बढ़कर 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। ● स्वचालित मार्ग के माध्यम से चिकित्सा उपकरणों में 100% FDI की अनुमति है। ● आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड (AMTZ), सुल्तानपुर गांव (तेलंगाना) में एक पार्क तथा तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में HLL लाइफकेयर मेडिपार्क सहित पूरे भारत में मेडिकल डिवाइस पार्क की योजना बनाई गई है।
एंटी-डंपिंग ड्यूटी	प्रसंग: वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce) की जांच शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय (Directorate General of Trade Remedies-DGTR) DGTR ने घरेलू विनिर्माताओं को सस्ते इम्पोर्ट से बचाने के लिए चीन के कुछ एल्युमीनियम प्रोडक्ट्स पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। ● सेफ्ट्रिजोन (Ceftriaxone) सोडियम स्टेराइल रसायन या कच्चा माल है जिसका उपयोग पेटों के अंदर संक्रमण, त्वचा संक्रमण और श्वसन संबंधी संक्रमण जैसी बीमारियों के इलाज में किया जाता है। ● शुल्क लगाने पर अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय लेगा। DGTR प्राधिकरण के बारे में ● DGTR वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है। ● DGTR एंटी-डंपिंग, काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) और रक्षोपाय उपायों से संबंधित है। ● यह घरेलू उद्योग और निर्यातकों को अन्य देशों द्वारा उनके खिलाफ लागू किये गए व्यापार उपायों की जाँच के बढ़ते मामलों से निपटने में सहायता प्रदान करता है। ● DGTR अनुचित व्यापार प्रथाओं के प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ घरेलू उद्योग को एक समान अवसर प्रदान करता है। एंटी-डंपिंग ड्यूटी के बारे में ● एंटी-डंपिंग ड्यूटी एक संरक्षणवादी शुल्क है जो एक घरेलू सरकार विदेशी आयातों पर लगाती है जिसे वह मानता है कि डंप किया गया है। ● विश्व व्यापार संगठन के शासन के अंतर्गत एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने की अनुमति है। ● इसका उद्देश्य निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करना और स्थानीय उत्पादकों के लिए विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए समान अवसर प्रदान करना है। ● इन शुल्कों से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए उच्च कीमतें भी हो सकती हैं। सक्रिय फार्मास्यूटिकल संघटक (API) क्या है? ● किसी भी दवा का हिस्सा जो अपना प्रभाव पैदा करती है। ● रोग के निदान, इलाज, शमन, उपचार या रोकथाम में औषधीय गतिविधि या अन्य प्रत्यक्ष प्रभाव प्रस्तुत करने का इरादा है।
स्थानीय मूल्य संवर्धन, विनिर्माण और निर्यात के लिए संचालन समिति (SCALE)	संदर्भ: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने विनिर्माण को पुनर्जीवित करने के लिए 'स्थानीय मूल्य संवर्धन, विनिर्माण और निर्यात के लिए संचालन समिति' (Steering Committee for Local Value Addition, Manufacturing and Exports: SCALE) का गठन किया है। महत्वपूर्ण तथ्य ● उद्देश्य: COVID-19 महामारी द्वारा उजागर किए गए आयात-निर्भरता के नुकसान से भारतीय विनिर्माण को दूर करना। ● SCALE में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के सदस्य सचिव मनमीत कौर नंदा के साथ तीन उद्योग निकायों- सीआईआई, फिक्की और एसोचैम तथा सरकार के तीन प्रतिनिधि शामिल हैं। ● समूह अब 17 क्षेत्रों के लिए ऐसे विचारों पर काम कर रहा है, जिनमें खिलौने, वस्त्र, फर्नीचर और ई-साइकिल से लेकर ड्रोन और यहां तक कि मत्स्य पालन तक शामिल हैं। ● इस समिति की कोई समय सीमा नहीं है और यह कई स्तरों पर अलग-अलग एजेंडा के साथ उद्योग के विभिन्न दलों के साथ परामर्श की एक कठोर प्रक्रिया का पालन करेगा।
असम की जुडिमा	संदर्भ: जुडिमा (Judima), असम में डिमासा जनजाति द्वारा बनाई गई शराब को भौगोलिक संकेत (geographical

वाइन राइस को मिला GI टैग	indication - GI) टैग से सम्मानित किया गया है। ● यह शराब चावल और एक खास जड़ी-बूटी से बनाई जाती है। ● इस लेबल को अर्जित करने वाला यह उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का पहला पेय है। ● जुडिमा डिमासो के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अंतर्निहित है। ● इस पेय के लिए जीआई टैग निकटवर्ती कार्बी आंगलोंग जिले के अदरक को भौगोलिक संकेत मिलने के 14 साल बाद आया है। ● एक सप्ताह पहले मणिपुर ने देखा कि उसके दो स्वदेशी उत्पादों को जीआई टैग मिला है। ये क्रमशः तामेंगलोंग संतरा और पहाड़ियों में उगाई जाने वाली हथी (Hathei) मिर्ची।
भारत के रजिस्ट्रार-जनरल और जनगणना आयुक्त	संदर्भ : हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) में वर्णित जाति डेटा "अनुपयोगी" था, लेकिन 2016 में, भारत के रजिस्ट्रार-जनरल और जनगणना आयुक्त ने स्थायी समिति को सूचित किया था। ग्रामीण विकास पर कि व्यक्तिगत जाति और धर्म के आंकड़ों का 98.87 प्रतिशत "त्रुटि मुक्त" था। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त क्या हैं? ● भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त की स्थापना 1961 में भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी। ● भूमिका: यह भारत की जनगणना और भारत के भाषाई सर्वेक्षण सहित भारत के जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण के परिणामों की व्यवस्था, संचालन और विश्लेषण करता है। ● रजिस्ट्रार का पद आमतौर पर संयुक्त सचिव के रैंक वाले एक सिविल सेवक के पास होता है। सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) क्या है? ● सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC), जिसने 1931 के बाद से जाति पर पहला आंकड़ा एकत्र किया यह जाति की गणना का सबसे बड़ा अभ्यास है। ● SECC आवास, शैक्षिक स्थिति, भूमि जोत, विकलांग, व्यवसाय, संपत्ति का कब्जा, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों, आय आदि के आधार पर परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अंतर करने के लिए डेटा की आपूर्ति करता है। ● इस प्रकार जनगणना भारतीय आबादी का एक चित्र प्रदान करती है, जबकि SECC राज्य के समर्थन के लाभार्थियों की पहचान करने का एक उपकरण है।
सेबी ने गोल्ड एक्सचेंज के लिए नियमों को मंजूरी दी	संदर्भ: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) ने गोल्ड एक्सचेंज के लिए फ्रेमवर्क को भी अनुमति दी गई है, जिससे सोने से जुड़ी प्रतिभूतियों में व्यापार की सुविधा हुई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ● अन्य प्रतिभूतियों के मामले में 'इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट' (EGRs) में ट्रेडिंग के लिए गोल्ड एक्सचेंज स्थापित किए जाएंगे। ● मौजूदा स्टॉक एक्सचेंजों को EGRs के व्यापार के लिए मंच प्रदान करने की अनुमति होगी। ● EGRs के व्यापार और सोने में बदलने का मूल्यवर्ग SEBI के अनुमोदन से एक्सचेंजों द्वारा तय किया जाएगा। ● EGRs धारक, अपने विवेक से ईजीआर को सरेंडर करने के बाद वाल्ट से अंतर्निहित सोना निकाल सकते हैं। ● सेबी से मान्यता प्राप्त वाल्ट मैनेजर सोने की जमा राशि के भंडारण और सुरक्षित रखने, ईजीआर के निर्माण, सोने की निकासी, शिकायत निवारण और डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड के साथ फिजिकल गोल्ड (physical gold) के आवधिक मिलान के लिए जिम्मेदार होंगे। ● वाल्ट मैनेजर (vault manager) के पास कम से कम रु. 50 करोड़। ● महत्व: यह एक्सचेंज पारदर्शी मूल्य खोज, निवेश लिक्विडिटी और सोने की गुणवत्ता में आश्वासन को सक्षम करेगा।
आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) का विघटन	संदर्भ : हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) को भंग करने का आदेश जारी किया है। विघटन के पश्चात, इसकी परिसंपत्तियां, कर्मचारियों एवं प्रबंधन को सात नवगठित रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (DPSUs) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

	● एक बार लागू होने के बाद, ओएफबी का वजूद खत्म हो जाएगा। ● कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। ● 16 जून को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने OFB को निगमित करने के लिए एक लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार योजना को मंजूरी दी थी, जिसमें 41 कारखाने हैं, DPSUs की तर्ज पर सात पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में। ● लाभ ○ देश को रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर बनाएं। ○ आयुध कारखानों को उत्पादक और लाभदायक संपत्तियों में बदलना। ○ उत्पाद श्रृंखला में गहन विशेषज्ञता। ○ बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। ○ बेहतर गुणवत्ता। ○ अक्षम आपूर्ति श्रृंखलाओं को समाप्त करने जैसी विभिन्न मौजूदा कमियों को दूर करने में मदद करना। आयुध निर्माणी बोर्ड के बारे में ● आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) में भारतीय आयुध कारखाने शामिल थे। ● यह एक संगठन था, जो रक्षा उत्पादन विभाग (DDP), रक्षा मंत्रालय (MoD), भारत सरकार के नियंत्रण में था। ● यह वायु, भूमि और समुद्री प्रणालियों के क्षेत्रों में एक उत्पाद श्रृंखला के अनुसंधान, विकास, उत्पादन, परीक्षण, विपणन और रसद में लगा हुआ था। ● OFB दुनिया का सबसे बड़ा सरकार द्वारा संचालित उत्पादन संगठन था और भारत में सबसे पुराना संगठन था।
आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) का विस्तार	प्रसंग: सरकार ने “Covid -19 महामारी से प्रभावित (pandemic’s adverse effects) विभिन्न व्यवसायों का समर्थन करने के लिए (continued support to eligible sectors), ईसीएलजीएस की समयसीमा को 31 मार्च, 2022 तक या योजना के तहत 4.5 लाख करोड़ की राशि स्वीकृत होने के समय तक (इनमें जो भी पहले हो) बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) क्या है? ● भारत सरकार द्वारा COVID-19 संकट को देखते हुए एक विशेष योजना के रूप में शुरू किया गया। ● उद्देश्य: इस योजना के तहत 100 प्रतिशत संपार्श्विक (Collateral) मुक्त ऋण की गारंटी राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा प्रदान की जा रही है, जबकि बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs) योजना के तहत ऋण प्रदान करती हैं। ● फरवरी 29, 2020 तक व्यावसायिक उद्यमों / एमएसएमई को दी जाने वाली आपातकालीन क्रेडिट लाइन की राशि कुल बकाया का 20% तक होगी। ● आपातकालीन क्रेडिट लाइन योजना के अंतर्गत स्वीकृत अतिरिक्त धनराशि के लिए 100% गारंटी कवरेज। ● पात्र उधारकर्ता: इस योजना के तहत वे उधारकर्ता ऋण प्राप्त करने के लिये पात्र होंगे जिनकी- ● बकाया राशि 29 फरवरी, 2020 तक 50 करोड़ रुपए तक है। ● वार्षिक कारोबार 250 करोड़ रुपए तक है। ● ब्याज दर: बैंकों के लिए ब्याज दर 9.25% और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies- NBFCs) के लिए 14% तक सीमित है। ● कोई शुल्क या गारंटी शुल्क नहीं होगी।

TLP Connect 2022

Integrated Prelims & Mains Test Series cum Mentorship Program



Comprehensive Program
(Prelims +Mains+ Interview)



1:1 Mentorship



30 Mains Tests
(14 Sectional + 6 Essay + 10 FLT's)



**Detailed Synopsis Along
With Strategy Classes**



50 Prelims Tests
(40 GS + 10 CSAT)



**Discussion Classes
/Videos after Test**



Babapedia
(Prelimspedia + Mainspedia)

**Toppers
Recommended**

**Available Online and Offline
(Delhi, BANGALORE and Lucknow)**

**The Program Begins On
30th October**

REGISTER NOW

Scan here to



know more

लद्दाख ने राजकीय पशु और पक्षी अपनाया



सन्दर्भ : हाल ही में लद्दाख ने हिम तेंदुए और काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पशु और राज्य पक्षी के रूप में अपनाया।

- काली गर्दन वाली क्रेन, जो केवल लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है, 5 अगस्त, 2019 से पहले जम्मू-कश्मीर का राज्य पक्षी था।
- वफादार जोड़े माने जाने वाले काले गर्दन वाले सारस केवल लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में पाए जाते हैं।

हिम तेंदुए के बारे में-

- हिम तेंदुआ या 'स्नो लेपर्ड' को 'पहाड़ों का भूत' (Ghost of the Mountains) भी कहा जाता है
- हिम तेंदुए (पैंथेरा यूनिया) खाद्य शृंखला में शीर्ष शिकारी के रूप में अपनी स्थिति के कारण उस पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के संकेतक के तौर पर कार्य करते हैं जिसमें वे रहते हैं।
- **आवास:** जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में उच्च हिमालयी और ट्रांस-हिमालयी परिदृश्य।
- विश्व की हिम तेंदुआ राजधानी: हेमिस, लद्दाख।
- **खतरे:** शिकार की आबादी में कमी, अवैध शिकार और प्रजातियों के आवास में मानव आबादी की घुसपैठ में वृद्धि और वन्यजीवों के अंगों और उत्पादों का अवैध व्यापार।
- **भारत द्वारा संरक्षण के प्रयास:**
 - **हिमाल संरक्षक (Himal Sanrakshak) :** यह एक सामुदायिक स्वयंसेवी कार्यक्रम है, जो हिम तेंदुओं की रक्षा के लिए 23 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया है।
 - 2019 में, हिम तेंदुए की जनसंख्या के आकलन पर पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल भी लॉन्च किया गया था।
 - **सुरक्षित हिमालय (SECURE Himalaya) :** वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)-UNDP वित्त पोषित परियोजना उच्च ऊंचाई वाली जैव विविधता के संरक्षण पर।
 - प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वर्ष 2009 में लॉन्च किया गया था।
 - पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के लिए हिम तेंदुआ 21 सूक्ष्म रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में है।

काली गर्दन वाली क्रेन के बारे में-

- इसके सिर पर एक विशिष्ट रेड क्राउन मौजूद होता है।
- नर और मादा दोनों लगभग एक ही आकार के होते हैं लेकिन नर मादा से थोड़ा बड़ा होता है
- इस पक्षी को छोटे दलाई लामा (त्सांगयांग ग्यात्सो) के अवतार के रूप में मोनपास (अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख बौद्ध जातीय समूह) के समुदाय द्वारा सम्मानित किया जाता है।
- **आवास और प्रजनन क्षेत्र :** तिब्बती पठार, सिचुआन (चीन) और पूर्वी लद्दाख (भारत) की उच्च ऊंचाई वाली आर्द्रभूमि भूमि इन प्रजातियों के मुख्य प्रजनन स्थल हैं। यह पक्षी सर्दी का मौसम कम ऊंचाई वाले स्थानों पर बिताता है।
- भूटान और अरुणाचल प्रदेश में यह केवल सर्दियों के दौरान आता है।
- **खतरा:** जंगली कुत्तों के कारण अंडे और चूजों को नुकसान, आर्द्रभूमि पर बढ़ते मानव दबाव (विकास परियोजनाएं) के कारण आवास का नुकसान, आर्द्रभूमि के पास सीमित चरागाहों पर बढ़ता चराई का दबाव।
- **उनके संरक्षण के लिए स्टेप्स :** वन्यजीव विभाग के सहयोग से वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया (WWF-इंडिया)।
- संरक्षण, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख क्षेत्र में एक प्राथमिकता वाली प्रजाति के रूप में काली गर्दन वाले सारस के साथ उच्च ऊंचाई वाली आर्द्रभूमि के संरक्षण की दिशा में काम कर रहा है।

छत्तीसगढ़ का राज्य पशु, जंगली भैंस विलुप्त होने के करीब	प्रसंग: छत्तीसगढ़ के सीतानदी-उदंती टाइगर रिजर्व में एक संरक्षण केंद्र में एकमात्र मादा जंगली भैंस की हाल ही में मृत्यु हो गई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ● छत्तीसगढ़ में प्रजातियों के 20 से कम व्यक्तियों के बचे होने के साथ राज्य पशु विलुप्त होने के कगार पर है। ● संरक्षण केंद्र में केवल एक मादा और तीन नर थे और अब रिजर्व में कोई मादा जंगली भैंस नहीं बची है। ● यह अभयारण्य ओडिशा राज्य के खरियार वन प्रभाग से सटा हुआ है और सुनबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य के लिए बफर के रूप में कार्य करता है। जंगली पानी भैंस के बारे में ● जंगली जल भैंस (बुबलस अर्नी), जिसे एशियाई भैंस भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया का एक बड़ा गोजातीय मूल निवासी है। ● इसमें ऐश-ग्रे से काली त्वचा होती है। वे दिनचर और निशाचर दोनों हैं। इनमें दोनों लिंगों के सींग होते हैं। ● यह सबसे भारी जीवित जंगली बोविड प्रजातियों में से एक है, और गौर से थोड़ा छोटा है। ● यह नमी वाली घास के मैदानों, दलदलों, बाढ़ के मैदानों और घनी वनस्पति वाली नदी घाटियों से जुड़ा है। ● यह CITES परिशिष्ट III में शामिल है। ● यह भूटान, भारत, नेपाल और थाईलैंड में कानूनी रूप से संरक्षित है। ● IUCN रेड लिस्ट स्थिति: 1986 से संकटग्रस्ता। ● शेष जनसंख्या कुल 4,000 से कम है, जिसमें से लगभग 91% भारत में रहते हैं, जो अधिकतर असम में पायी जाती है। ● CITES यह निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में पाया जाता है: ○ असम: काजीरंगा, मानस और डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य और बुरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य। ○ अरुणाचल प्रदेश: डीरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य। ○ मेघालय: बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान। ○ छत्तीसगढ़: इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और उदंती वन्यजीव अभयारण्य।
नीलकुरिंजी (Neelakurinji)	प्रसंग: कर्नाटक के कोडगू जिले में 12 साल बाद नीलकुरिंजी के फूल खिले हैं। इस प्रकार के सामूहिक पुष्पन को ग्रीगेरियस फ्लावरिंग के रूप में जाना जाता है। इस फूल के बारे में ● यह एक झाड़ी है जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के शोला जंगलों में पाई जाती है। ● स्थानीय रूप से यह कुरिंजी के रूप में जाना जाता है, ये 1300 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर खिलते हैं और इसका पौधा 30-60 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। ● नीलगिरि हिल्स, जिसका शाब्दिक अर्थ है नीले पहाड़, का नाम नीलाकुरिंजी के बैंगनी नीले फूलों से मिला है जो 12 वर्षों में केवल एक बार खिलते हैं। ● कुरिंजिमाला अभयारण्य केरल के इडुक्की जिले के कोट्टाकंबूर और वट्टावडा गांवों में लगभग 32 वर्ग किमी मुख्य निवास स्थान में कुरिंजी की रक्षा करता है। ● अंदावर में स्थित मंदिर कोडईकनाल पर तमिलनाडु के लिए समर्पित तमिल भगवान मुरुगन भी Strobilanthes पौधों को संरक्षित रखता है। ● तमिलनाडु में रहने वाले पलियान आदिवासी लोगों ने इसे अपनी उम्र की गणना के लिए एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया। ● कर्नाटक में नीलकुरिंजी की लगभग 45 प्रजातियां हैं और प्रत्येक प्रजाति 6 , 9 , 11 या 12 वर्षों के अंतराल पर खिलती है। ● पश्चिमी घाटों के अलावा, नीलकुरिंजी कर्नाटक में बेल्लारी जिले के पूर्वी घाट, संदुरु पहाड़ियों के शेवरॉय में भी देखे जाते हैं।

कछुआ संरक्षण	संदर्भ : हाल ही में भारतीय जीवविज्ञानी शैलेन्द्र सिंह को तीन गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Critically Endangered) कछुए की प्रजातियों को उनके विलुप्त होने की स्थिति से बाहर लाने हेतु बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार (Behler Turtle Conservation Award) से सम्मानित किया गया है। ● 'बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार' कछुआ संरक्षण में शामिल कई वैश्विक निकायों जैसे 'टर्टल सर्वाइवल एलायंस (TSA), IUCN/SSC कच्छप और मीठे पानी के कछुआ विशेषज्ञ समूह, कछुआ संरक्षण तथा 'कछुआ संरक्षण कोष' द्वारा प्रदान किया जाता है। ● वर्तमान संदर्भ में तीन गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुओं को देश के विभिन्न हिस्सों में टीएसए इंडिया के अनुसंधान, संरक्षण प्रजनन और शिक्षा कार्यक्रम के एक भाग के रूप में संरक्षित किया जा रहा है। ● कुछ प्रजातियों के लिए जैसे रेड - क्राउन रूफ टर्टल (बटागुर कचुगा), उत्तरी नदी भूभाग (बटागुर बस्का) और ब्लैक सॉफ्टशेल टर्टल (निल्सोनिया नाइग्रिकन्स-Nilssonina Nigricans), डॉ. सिंह और उनकी टीम के प्रयास देश में उनके जंगली अस्तित्व की आखिरी उम्मीद हैं।
IUCN ने प्रजातियों की लाल सूची अपडेट की	संदर्भ: इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) ने 4 सितंबर, 2021 को फ्रांस के मार्सिले में विश्व संरक्षण कांग्रेस में प्रजातियों की लाल डेटा सूची (रेड लिस्ट) को अपडेट किया है। प्रमुख अपडेट: ● आईयूसीएन रेड लिस्ट ये भी पता चलता है कि 30 प्रतिशत प्रजातियों (38,543) का मूल्यांकन किया गया जिसमें से (138,374) विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहा है। ● पृथ्वी से लगभग 902 प्रजातियां आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गईं। ● जंगलों में लगभग 80 प्रजातियां विलुप्त हैं, और 8,404 गंभीर रूप से संकटग्रस्त, 14,647 लुप्तप्राय, 15,492 संवेदनशील और 8,127 खतरे में हैं। ● टूना मछली: सात सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से काम में आने वाली टूना मछली प्रजातियों में से चार ने ठीक होने के संकेत दिखाए हैं। ● विश्व की सबसे बड़ी जीवित छिपकली, कोमोडो ड्रैगन (वरनस कोमोडोएन्सिस), को कमजोर से लुप्तप्राय में स्थानांतरित कर दिया गया है। ○ ये प्रजाति इंडोनेशिया के लिए स्थानिक है और केवल वर्ल्ड हैरिटेज साइट कोमोडो नेशनल पार्क और उसके पड़ोसी फ्लोर्स में होती है। ● दुनिया की 37% शार्क और रे प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा था। IUCN के बारे में संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची ● यह 1964 में IUCN द्वारा स्थापित किया गया था और यह जानवरों, कवक और पौधों की प्रजातियों के वैश्विक विलुप्त होने के जोखिम की स्थिति पर दुनिया का सबसे व्यापक सूचना स्रोत बनने के लिए विकसित हुआ है। ● IUCN रेड लिस्ट विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। ● यह हजारों प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक मानदंडों के एक सेट का उपयोग करता है। ● यह सीमा, जनसंख्या आकार, आवास और पारिस्थितिकी, उपयोग और या व्यापार, खतरों और संरक्षण कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो आवश्यक संरक्षण निर्णयों को सूचित करने में मदद करेगा। ● इसका उपयोग सरकारी एजेंसियों, वन्यजीव विभागों, संरक्षण से संबंधित गैर सरकारी संगठनों, प्राकृतिक संसाधन योजनाकारों, शैक्षिक संगठनों, छात्रों और व्यावसायिक समुदाय द्वारा किया जाता है। ● यह सूचकांक पांच समूहों के लिए उपलब्ध है: पक्षी, स्तनधारी, उभयचर, मृंगा और साइकाडा।

	CRITERIA A Population reduction B Restricted geographic range C Small population size & decline D Very small or restricted population E Extinction probability analysis THREATENED CATEGORIES Critically Endangered (CR) Endangered (EN) Vulnerable (VU)
मेक्सिको की खाड़ी में तेल रिसाव	संदर्भ : क्लीन-अप क्रू और यूएस कोस्ट गार्ड घातक तूफान हरिकेन (Hurricane) इडा के बाद मैक्सिको की खाड़ी में देखे गए तेल रिसाव के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। - नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) द्वारा हाल की उपग्रह तस्वीरों में पोर्ट फोरचॉन, लुइसियाना से लगभग दो मील (3 किमी) दूर स्लिक दिखाया गया है। रिसाव का स्रोत क्या है? - मीलों लंबे तेल रिसाव का स्रोत मेक्सिको की खाड़ी के मारचंद खाड़ी क्षेत्र में माना जाता था। मेक्सिको की खाड़ी महासागर बेसिन और अटलांटिक महासागर का एक सीमांत समुद्र है, जो बड़े पैमाने पर उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से घिरा हुआ है। - ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक अपतटीय ड्रिलिंग साइट पर पानी के भीतर एक स्रोत से आ रहा है। - खाड़ी में क्षतिग्रस्त पाइपलाइन स्पिल के संभावित कारण हैं। तेल रिसाव क्या है? - एक तेल रिसाव पर्यावरण में कच्चे तेल, गैसोलीन, ईंधन या अन्य तेल उप-उत्पादों के किसी भी अनियंत्रित रिलीज को संदर्भित करता है। - तेल रिसाव के हानिकारक प्रभाव - तेल रिसाव भूमि, वायु या जल को प्रदूषित करता है। - यह पर्याप्त मात्रा में सूर्य के प्रकाश को सतह में प्रवेश करने से रोकता है। - यह घुलित ऑक्सीजन के स्तर को भी कम करता है। - तेल से लिपटे पक्षी और समुद्री स्तनधारी हाइपोथर्मिया से मर सकते हैं। - अंतर्ग्रहण तेल प्रभावित जानवरों के लिए विषाक्त हो सकता है और उनके आवास और प्रजनन दर को नुकसान पहुंचा सकता है। तेल रिसाव की सफाई- कंटेनमेंट बूम (Containment Booms) : फ्लोटिंग बैरियर, जिन्हें बूम कहा जाता है, का उपयोग तेल के प्रसार को प्रतिबंधित करने और इसकी वसूली हटाने या फैलाव की अनुमति देने के लिए किया जाता है। स्किमर्स (Skimmers) : ये ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग पानी की सतह से गिराए गए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। सॉर्बेंट्स (Sorbents) : पानी से तेल को अवशोषित करने वाले विभिन्न सॉर्बेंट्स (जैसे-पुआल, ज्वालामुखी राख और पॉलिएस्टर-व्युत्पन्न प्लास्टिक की छीलन) का उपयोग किया जाता है। फैलाने वाले घटक (Dispersing agents): ये ऐसे रसायन होते हैं जिनमें सर्फैक्टेंट या यौगिक होते हैं जो तेल जैसे तरल पदार्थों को छोटी बूंदों में तोड़ने का काम करते हैं। जैविक घटक (Biological agents): पोषक तत्व, एंजाइम या सूक्ष्मजीव जैसे अल्केनिवॉरेक्स बैक्टीरिया या मिथाइलोसेला सिल्वेस्ट्रिस जो उस दर को बढ़ाते हैं जिस पर तेल का प्राकृतिक बायोडिग्रेडेशन होता है।
असम 2030 तक जीवाश्म ईंधन	संदर्भ : असम सरकार ने 2030 तक जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति का अनावरण किया है।

आधारित वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करेगा	योजना की मुख्य विशेषताएं ● इस मिशन में सभी सरकारी वाहनों और सार्वजनिक बसों के बेड़े को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करना और अगले 5 वर्षों के अंदर 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को खड़ा करना शामिल है। ● यह नीति लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहन का एक सेट भी प्रदान करती है। ● इनमें रजिस्ट्रेशन चार्ज और रोड टैक्स में 100% छूट शामिल है। ● EV स्टेशन स्थापित करने वाले उद्यमियों को बिजली शुल्क से 90% छूट का आश्वासन दिया गया है। सरकार की पहल क्या हैं ? ● सरकार ने 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की कारों और दोपहिया वाहनों की नई बिक्री का 30% आज 1% से कम करने का लक्ष्य रखा है। ● एक स्थायी EV पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए जैसे - नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP) और भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से अपनाना और विनिर्माण (फेम इंडिया) भारत द्वारा शुरू किया गया है।
भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व	संदर्भ : तमिलनाडु राज्य सरकार ने पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। संरक्षण रिजर्व के बारे में ● यह संरक्षण रिजर्व 500 किमी के क्षेत्र को कवर करेगा। ● प्रस्तावित संरक्षण क्षेत्र में देश में डुगोंग का उच्चतम संकेंद्रण है। ● यह अभ्यारण्य आदिरामपट्टिनम से अमापट्टिनम तक पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में फैला होगा। ● कैम्पा-डुगोंग रिकवरी प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में, नवंबर 2016 से मार्च 2019 तक पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में विभिन्न सर्वेक्षण किए गए। ● मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी छोर और पश्चिमी श्रीलंका के बीच एक उथला खाड़ी क्षेत्र है। डुगोंग के बारे में ● डुगोंग जिसे आमतौर पर समुद्री गायों के रूप में जाना जाता है, एक लुप्तप्राय समुद्रीय स्तनपायी है। ● डुगोंग, जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, एक शाकाहारी स्तनपायी है। ● यह एक बार के विविध परिवार डुगोंगिडे का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि है। ● वे समुद्री घास खाते हैं और सांस लेने के लिए सतह पर आते हैं। ● वे 30 से अधिक देशों में पाए जाते हैं और भारत में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक खाड़ी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ● भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के अनुमान के अनुसार, जंगल में केवल 200-250 डुगोंग बचे हैं, जिनमें से 150 तमिलनाडु में पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। ● खतरा : ○ समुद्री घास के आवासों का नुकसान। ○ जल प्रदूषण। ○ विकासात्मक गतिविधियों के कारण तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का हास मछली पकड़ने के जाल में आकस्मिक उलझावा। ○ नावों, ट्रॉलरों से टकराना। ● संरक्षण की स्थिति ○ IUCN- सुभेद्य (Vulnerable) ○ CITES: परिशिष्ट I ○ वन्य (जीवन) संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-I ● भारत सरकार भी 1983 से प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण (CMS) के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता है जहां उसने

	साइबेरियन क्रेन (1998), समुद्री कछुए (2007), डुगोंग (2008) और रैप्टर्स (2016) के संरक्षण और प्रबंधन पर गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। डुगोंग को विलुप्त होने से बचाने का एकमात्र तरीका उचित संरक्षण है।
पराग कैलेंडर (Pollen calendar)	संदर्भ : हाल ही में चंडीगढ़ को अपना पहला पराग कैलेंडर मिला, यकीनन भारत के किसी भी शहर के लिए यह पहला होगा। पराग कैलेंडर क्या है? - पराग कैलेंडर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद हवाई/वायुजनित पराग के समय की गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। - वे एक ही चित्र में पूरे वर्ष में मौजूद विभिन्न वायुजनित परागों के बारे में आसानी से सुलभ दृश्य विवरण प्राप्त करते हैं। ‘पराग कैलेंडर’ प्रायः स्थान-विशिष्ट होते हैं, जिसमें पराग की सांद्रता स्थानीय रूप से वितरित वनस्पतियों से निकटता से संबंधित होती है। - यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा ‘एलर्जिक राइनाइटिस’/‘हे फीवर’ को रोकने तथा निदान करने एवं पराग के मौसम के समय एवं गंभीरता का अनुमान लगाने के लिये क्षेत्रीय पराग कैलेंडर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। पराग कैलेंडर का महत्व? - पराग कैलेंडर चिकित्सकों के साथ-साथ एलर्जी वाले लोगों को संभावित एलर्जी ट्रिगर की पहचान करने और उच्च पराग भार के मौसम के दौरान उनके जोखिम को सीमित करने में मदद करने के लिए एक स्पष्ट समझ प्रदान करता है। - प्रारंभिक परामर्श तैयार किया जा सकता है और मीडिया चैनलों के माध्यम से नागरिकों को प्रसारित किया जा सकता है। चंडीगढ़ के पराग कैलेंडर के बारे में - चंडीगढ़ के लिए पराग कैलेंडर लगभग दो वर्षों तक वायुजनित पराग और इसके मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन करके तैयार किया गया था। - अध्ययन विभिन्न मौसमों में महत्वपूर्ण पराग प्रकारों की परिवर्तनशीलता पर प्रकाश डालता है। वसंत और पतझड़ दो मौसम होते हैं जब वायुजनित पराग हावी होते हैं। पराग और मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव - परागकण नर जैविक संरचनाएं हैं जिनमें निषेचन की प्राथमिक भूमिका होती है, लेकिन जब मनुष्यों द्वारा साँस ली जाती है, तो वे श्वसन प्रणाली पर दबाव डाल सकते हैं और एलर्जी का कारण बन सकते हैं। - हवा में निलंबित पाया गया पराग व्यापक ऊपरी श्वसन पथ और अस्थमा, मौसमी राइनाइटिस और ब्रोन्कियल जलन जैसी अभिव्यक्तियों के साथ नासोब्रोन्कियल एलर्जी का कारण बन सकता है। - भारत में लगभग 20-30% आबादी एलर्जिक राइनाइटिस/हे फीवर से पीड़ित है, और लगभग 15% लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। - पराग को एक प्रमुख बाहरी वायुजनित एलर्जेन माना जाता है जो मनुष्यों में एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा और एटोपिक जिल्द की सूजन के लिए जिम्मेदार है। - ताड़, बिछुआ, सफेदा, सफेद शहतूत (शहतूत), कांग्रेस घास, चीड़ जैसे पेड़ों में पराग का प्रकोप अधिक होता है।
जलवायु परिवर्तन के कारण 216 मिलियन लोग स्थानांतरित कर सकते हैं: विश्व बैंक	संदर्भ : हाल ही में विश्व बैंक ने ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट प्रकाशित की है। - विश्व बैंक ने चेतावनी दी कि कम कृषि उत्पादन, पानी की कमी, समुद्र के बढ़ते स्तर और जलवायु परिवर्तन के अन्य प्रतिकूल प्रभावों के कारण 2050 तक 216 मिलियन लोग अपने ही देशों में स्थानांतरित कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष - जलवायु परिवर्तन अगले तीन दशकों में 200 मिलियन से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने और प्रवासन हॉटस्पॉट बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है जब तक कि वैश्विक उत्सर्जन को कम करने और विकास अंतराल को भरने के लिए तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है।

	● रिपोर्ट में विश्लेषण किए गए छह क्षेत्रों में 216 मिलियन लोगों के अपने देशों के अंदर जाने का अनुमान लगाया गया है। ○ वे क्षेत्र लैटिन अमेरिका हैं; उत्तरी अफ्रीका; उप सहारा अफ्रीका; पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया; दक्षिण एशिया; और पूर्वी एशिया और प्रशांत। ● सबसे अधिक जलवायु-अनुकूल परिदृश्य में, उत्सर्जन के निम्न स्तर और समावेशी, सतत विकास के साथ, दुनिया अभी भी 44 मिलियन लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होते हुए देख सकती है। ● दक्षिण एशिया: दक्षिण एशिया में बांग्लादेश विशेष रूप से बाढ़ और फसल खराब होने से प्रभावित है, जो अनुमानित जलवायु प्रवासियों का लगभग आधे के लिए जिम्मेदार है। ● अफ्रीकी क्षेत्र के संबंध में निष्कर्ष: ○ उप-सहारा अफ्रीका: मरुस्थलीकरण, नाजुक तटरेखा और कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता के कारण सर्वाधिक कमजोर क्षेत्र में सबसे अधिक प्रवासी दिखाई देंगे, जिसमें 86 मिलियन लोग राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर जा रहे हैं। ○ उत्तरी अफ्रीका में जलवायु प्रवासियों का सबसे बड़ा अनुपात होने की भविष्यवाणी की गई है, जिसमें 19 मिलियन लोग प्रवास कर रहे हैं। ○ पूर्वोत्तर ट्यूनीशिया, उत्तर-पश्चिमी अल्जीरिया, पश्चिमी और दक्षिणी मोरक्को तथा मध्य एटलस तलहटी में पानी की कमी बढ़ जाएगी।
‘शून्य’ अभियान की शुरुआत	अभियान के बारे में: यह उपभोक्ताओं और उद्योग के एक साथ मिलकर शून्य-प्रदूषण वितरण वाहनों (Zero-Pollution Delivery Vehicles) को बढ़ावा देने की एक पहल है। ● इस अभियान का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में डिलीवरी के मामले में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने में तेजी लाना और शून्य-प्रदूषण वितरण के लाभों के बारे में उपभोक्ताओं के मध्य जागरूकता पैदा करना है। ● शहरी मालवाहक-वाहन भारत में माल परिवहन से संबंधित CO2 उत्सर्जन के 10% हिस्से के लिये उत्तरदायी हैं और वर्ष 2030 तक इसके उत्सर्जन में 114% की बढ़ोतरी की आशंका है। ● EV से कोई टेलपाइप उत्सर्जन नहीं होता है, जो बेहतर वायु गुणवत्ता में अत्यधिक योगदान कर सकता है। यहाँ तक कि अपने निर्माण के समय भी वे आंतरिक दहन इंजन समकक्षों की तुलना में 15-40% कम उत्सर्जन करते हैं और उनकी परिचालन लागत भी कम होती है।
खाद्य श्रृंखला में आर्सेनिक (arsenic) की उपस्थिति	प्रसंग: बिहार में किये गए एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि आर्सेनिक (arsenic) न केवल भूजल को बल्कि खाद्य श्रृंखला को भी दूषित करता है। ● यह शोध ‘नेचर एंड नरचर इन आर्सेनिक इन्ड्यूस्ड टॉक्सिसिटी ऑफ बिहार’ परियोजना का एक हिस्सा था, जिसे यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटिश काउंसिल और भारत में ‘विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग’ द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया गया था। प्रमुख निष्कर्ष: ● खाद्य श्रृंखला में आर्सेनिक की उपस्थिति दर्ज की गई है- मुख्य रूप से चावल, गेहूं और आलू में। ● भूजल में आर्सेनिक मौजूद है और इसका उपयोग किसानों द्वारा सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। अतः खाद्य श्रृंखला में इसकी उपस्थिति का भी यही कारण है। ● शोध के मुताबिक पीने योग्य जल की तुलना में भोजन में आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई गई, वहीं पीने योग्य जल में आर्सेनिक का मौजूदा स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर (µg/L) के अंतिम गाइड मूल्य से भी ऊपर है। आर्सेनिक क्या है? ● यह एक गंधहीन और स्वादहीन उपधातु (Metalloid) है जो व्यापक रूप से पृथ्वी की भूपर्पटी पर विस्तृत है। ● यह कई देशों के भूपर्पटी और भूजल में उच्च स्तर पर स्वाभाविक रूप से मौजूद है। यह अपने अकार्बनिक रूप में अत्यधिक विषैला होता है। ● आर्सेनिकोसिस, आर्सेनिक विषाक्तता के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला एक शब्द है, जो शरीर में बड़ी मात्रा में आर्सेनिक के जमा होने के कारण होता है।

	पीने के पानी और भोजन के माध्यम से आर्सेनिक के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर और त्वचा पर घाव हो सकते हैं। इसे हृदय रोग और मधुमेह से भी संबद्ध माना जाता है।
भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड	सुर्खियों में: पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC), बिजली क्षेत्र में अग्रणी NBFC ने सफलतापूर्वक अपना पहला यूरो 300 मिलियन 7-वर्षीय यूरो ऋण पत्र (बॉन्ड) जारी किया है। 7 साल के यूरो 300 मिलियन बॉन्ड की कीमत 1.841 फीसदी रखी गई है। - यह भारत की ओर से प्रचलित (जारी होने वाला) अब तक का प्रथम यूरो मूल्यवर्ग का हरित ऋण पत्र (ग्रीन बॉन्ड) है। इसके अतिरिक्त, यह किसी भारतीय एनबीएफसी द्वारा जारी किया जाने वाला प्रथम ऋण पत्र एवं 2017 के बाद से भारत द्वारा जारी प्रथम ऋण पत्र है।
केराटिन अपशिष्ट को परिवर्तित करने का उपाय	सुर्खियों में: भारतीय वैज्ञानिकों ने मानव बाल, ऊन और मुर्गी के पंखों जैसे केराटिन कचरे को उर्वरक, पालतू और पशु आहार में परिवर्तित करने के लिए एक स्थायी और किफायती समाधान विकसित किया है। - नवीन प्रौद्योगिकी पेटेंट, आसानी से मापनीय, पर्यावरण के अनुकूल, ऊर्जा-कुशल है, और यह वर्तमान में विपणन उत्पादों की तुलना में अमीनो एसिड युक्त तरल उर्वरकों को अधिक किफायती बना देगी। - इसके पीछे प्रमुख तकनीक में हाइड्रोडायनामिक कैविटेशन नामक तकनीक का उपयोग करके केराटिन के हाइड्रोलिसिस के बाद पूर्व-उपचार शामिल है, जिसमें बहते तरल में वाष्पीकरण, बुलबुला निर्माण और बुलबुला प्रत्यारोपण शामिल है।
27वां वैश्विक ओजोन दिवस	- विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। - जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, जो आज ही के दिन 1987 में लागू हुई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन में भारत की उपलब्धियां (जून 1992 से) - मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सभी दायित्वों को पूरा किया। - भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुरूप नियंत्रित उपयोग के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हैलोनस, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है। - वर्तमान में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के त्वरित कार्यक्रम के अनुसार हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है। - हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन फेज आउट मैनेजमेंट प्लान (HPMP) स्टेज- II वर्तमान में 2017 से लागू किया जा रहा है और 2023 तक पूरा हो जाएगा। - हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को समाप्त करने की प्रबंधन योजना (एचपीएमपी) चरण- III की तैयारी शीघ्र ही शुरू की जाएगी, जो एचसीएफसी-22 के उपयोग को समाप्त करने के बारे में विचार करेगी, जो रेफ्रिजेशन और एयर कंडीशनिंग निर्माण और सेवा क्षेत्रों में उपयोग किया जाने वाला रेफ्रिजेंट है। 2016 के दौरान पार्टियों द्वारा अंतिम रूप दिए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी) के गैर-ओजोन क्षयकारी विकल्प के रूप में पेश किए गए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) की खपत और उत्पादन को धीरे-धीरे कम करेगा, जिसमें 12 से 14000 तक उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है। - कम ग्लोबल वार्मिंग क्षमता और ऊर्जा-दक्ष प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से किगाली संशोधन के तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को समाप्त करने की दिशा में कार्यान्वयन से ऊर्जा दक्षता लाभ और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी - एक "जलवायु सह-लाभ" प्राप्त होगा। - इसके अलावा, पर्यावरण लाभ के अलावा, आर्थिक और सामाजिक सह-लाभों को अधिकतम करने के उद्देश्य से भारत सरकार के चल रहे सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ तालमेल को बढ़ावा दिया जाएगा।
ग्लोबल मीथेन प्लेज	संदर्भ: हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने 'ग्लोबल मीथेन प्लेज' (Global Methane Pledge) की घोषणा की है, जो इस दशक के अंत तक मीथेन उत्सर्जन में एक तिहाई की कटौती करने हेतु 'संयुक्त राज्य अमेरिका-यूरोपियन संघ' के नेतृत्व वाला प्रयास है।

- यह घोषणा ऊर्जा और जलवायु (MEF) पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के फोरम में की गई थी, जिसकी मेजबानी हाल ही में व्हाइट हाउस ने की थी, जिसमें कई देशों और यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और (भारत के) पर्यावरण मंत्री भाग लिया।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- प्लेज ग्लोबल वार्मिंग की दर को तेजी से कम करने में मदद करेगी।
- यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि उत्पादन में सुधार जैसे एक बहुत ही मूल्यवान पक्ष लाभ भी उत्पन्न करेगा।

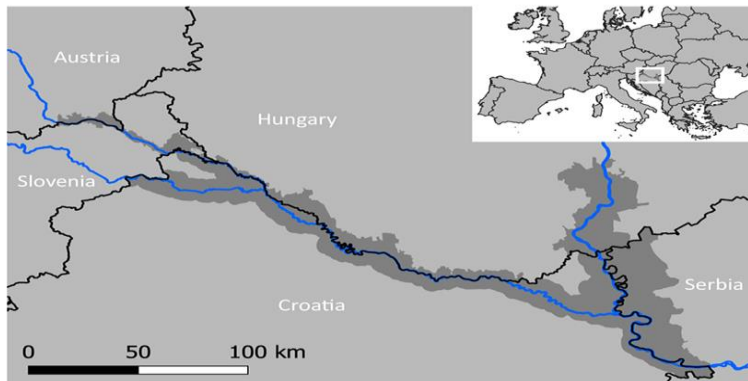
मीथेन के बारे में

- मीथेन एक ग्रीनहाउस गैस है।
- यह अपनी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना अधिक शक्तिशाली है।
- मीथेन का लगभग 40% प्राकृतिक स्रोतों से और लगभग 60% मानव-प्रभावित स्रोतों से उत्सर्जन होता है, जिसमें पशुधन खेती, चावल कृषि, बायोमास जलाना आदि शामिल हैं।

क्या आप जानते हैं?

- पार्टियों का 26वां सम्मेलन (COP26), ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन, नवंबर 2021 में आयोजित किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य जलवायु पर पेरिस समझौते (2015) के बाद से प्रगति की समीक्षा करना है, कुछ देशों ने 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है।
- पेरिस समझौता देशों को उत्सर्जन में कटौती के लिए प्रतिबद्ध करके तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से ऊपर 2 डिग्री सेल्सियस (और 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे की वृद्धि को सीमित करने के लक्ष्य का पीछा) तक बनाए रखने का प्रयास करता है।

मुरा-द्रवा-डेन्यूब (MDD) को दुनिया का पहला 'फाइव-कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व' घोषित



संदर्भ : हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा मुरा-द्रवा-डेन्यूब (Mura-Drava-Danube- MDD) को विश्व का प्रथम 'पाँच देशों का बायोस्फीयर रिजर्व' (Five-Country Biosphere Reserve) घोषित किया गया है।

MDD के बारे में:

- यह बायोस्फीयर रिजर्व मुरा, द्रवा और डेन्यूब नदियों के 700 किलोमीटर के क्षेत्र और ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी तथा सर्बिया में फैला हुआ है।
- रिजर्व का कुल क्षेत्रफल एक मिलियन हेक्टेयर है जिसे तथाकथित रूप से 'यूरोप का अमेज़न' (Amazon of Europe) कहा जाता है तथा यह अब यूरोप में सबसे बड़ा नदी संरक्षित क्षेत्र है।
- बायोस्फीयर रिजर्व ने यूरोपीय ग्रीन डील (जलवायु कार्य योजना) में अपना महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व किया और मुरा-द्रवा-डेन्यूब क्षेत्र में यूरोपीय संघ की जैव विविधता रणनीति के कार्यान्वयन में योगदान दिया।
- इस रणनीति का उद्देश्य नदियों को (25,000 किमी) पुनर्जीवित करना है और वर्ष 2030 तक यूरोपीय संघ के 30% भूमि क्षेत्र की रक्षा करना है।

एमडीडी का महत्व:

- यह क्षेत्र प्रजातियों की विविधता के मामले में यूरोप में सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है।

	● यह बाढ़ के मैदानों के जंगलों, बजरी और रेत के किनारों, नदी के द्वीपों, ऑक्सबो (यू-आकार की झील) और घास के मैदानों का क्षेत्र है। ● यह क्षेत्र सफेद पूंछ वाले चील और लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे- लिटिल टर्न, ब्लैक स्टॉक, ऊदबिलाव, बीवर और स्टर्जन के जोड़ों के प्रजनन हेतु यूरोप का उच्चतम सघन क्षेत्र है। ● यह हर वर्ष यहाँ आने वाले 2,50,000 से अधिक प्रवासी जलपक्षियों का महत्वपूर्ण गंतव्य स्थान है।
ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का मंच	संदर्भ: मेजर इकोनॉमीज फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट (MEF) का उद्देश्य विकसित और विकासशील दोनों प्रमुख उत्सर्जक देशों के बीच स्पष्ट संवाद की सुविधा प्रदान करना है। ● COP26 से पहले संवाद और चर्चा को सक्षम बनाने तथा आम सहमति बनाने का भी लक्ष्य है, जो आने वाले वर्षों में जलवायु प्रयासों के लिए एक मिसाल कायम करेगा। भारत का रुख ● जलवायु परिवर्तन का सामना करना एक साझा वैश्विक चुनौती है और हमारी प्रतिक्रिया समानता और सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। ● यद्यपि विश्व जनसंख्या में भारत का हिस्सा 17% है, लेकिन संचयी ऐतिहासिक उत्सर्जन में देश का हिस्सा सिर्फ 4% है और यहां तक कि वर्तमान वार्षिक उत्सर्जन भी वैश्विक उत्सर्जन का केवल 5.2% है और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत का लगभग एक तिहाई है। ● भारत का लक्ष्य 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का है। ● अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से सदस्य देशों की सहयोगी भावना पर आधारित भारत की सौर क्षमता पिछले छह वर्षों में पंद्रह गुना बढ़ गई है।
भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र डिजाइन	सुर्खियों में: भारत ने उच्च राख वाले भारतीय कोयले को मेथनॉल में बदलने के लिए एक स्वदेशी तकनीक विकसित की है और हैदराबाद में अपना पहला पायलट प्लांट स्थापित किया है। ● देश को स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। ● परिवहन ईंधन (पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण) के रूप में मेथनॉल के उपयोग को बढ़ावा देगा, इस प्रकार कच्चे तेल के आयात को कम करेगा। प्रक्रिया और चुनौती: ● कोयले को मेथनॉल में बदलने की व्यापक प्रक्रिया में कोयले का संश्लेषण (सिनगैस) गैस, सिनगैस सफाई और कंडीशनिंग, सिनगैस से मेथनॉल रूपांतरण, और मेथनॉल शुद्धिकरण शामिल हैं। ● अधिकांश देशों में कोयले से मेथनॉल संयंत्र कम राख वाले कोयले से संचालित होते हैं। इस उच्च मात्रा में राख को पिघलाने के लिए आवश्यक उच्च राख और गर्मी को संभालना भारतीय कोयले के मामले में एक चुनौती है, जिसमें आम तौर पर उच्च मांग सामग्री होती है। ● वर्तमान में, प्रायोगिक संयंत्र 99% से अधिक शुद्धता के साथ मेथनॉल का उत्पादन कर रहा है। इसे बढ़ाने से देश के ऊर्जा भंडार के इष्टतम उपयोग में मदद मिलेगी और आत्मनिर्भरता की दिशा में इसकी यात्रा में तेजी आएगी। ● लाइट-ड्यूटी वाहनों के लिए प्राकृतिक गैस-आधारित ईंधन के बड़े पैमाने पर बाजार में प्रवेश के लिए मेथनॉल सबसे आशाजनक विकल्प हो सकता है क्योंकि इसकी कम ईंधन लागत और गैसोलीन के साथ वाहन को चलाने के सापेक्ष कम अतिरिक्त लागत है। मेथनॉल अगले कुछ वर्षों में भारत के तेल आयात बिल में अनुमानित 20 प्रतिशत की कटौती करेगा।
हम्बोल्ट पेंगुइन	संदर्भ : मुंबई के भायखला चिड़ियाघर (Byculla Zoo) ने इस साल दो नए नन्हें हम्बोल्ट पेंगुइन (Humboldt penguin) को शामिल करने की घोषणा की। हम्बोल्ट पेंगुइन के बारे में ● हम्बोल्ट पेंगुइन (स्फेनिस्कस हम्बोल्टी) एक मध्यम आकार की प्रजाति है जिसकी औसत ऊँचाई सिर्फ 2 फीट तक होती है। ● इनका नाम हम्बोल्ट पेंगुइन इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका आवास हम्बोल्ट धारा के पास स्थित है, जो ठंडे जल की विशेषता वाली एक महासागरीय जल धारा है।



- हम्बोल्ट करंट, जिसे पेरू करंट भी कहा जाता है, एक ठंडी, कम लवणता वाली महासागरीय धारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ उत्तर की ओर बहती है।
- **पर्यावास:** 'हम्बोल्ट पेंगुइन' चिली और पेरू के प्रशांत तटों के लिये स्थानिक हैं।
- जंगलों में उनके प्रजनन का मौसम उनकी कॉलोनी के स्थान के आधार पर मार्च-अप्रैल या सितंबर- अक्तूबर हो सकता है।
- IUCN स्थिति: संवेदनशील

समुद्री खीरा



संदर्भ : हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी (Palk Bay) क्षेत्रों में दो टन समुद्री खीरा, जो कि एक प्रतिबंधित समुद्री प्रजाति है, को ज़ब्त किया।

समुद्री खीरा क्या है?

- समुद्री खीरे समुद्री अकशेरुकीय हैं जो आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तल पर पाए जाते हैं। उनका नाम उनके असामान्य आयताकार आकार के आधार पर रखा गया है जो एक मोटे खीरे जैसा दिखता है।
- **महत्व:**
 - वे समुद्र के आवासों के संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
 - वे प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र के अभिन्न अंग हैं क्योंकि समुद्री खीरा चयापचय के बाद मुख्य उपोत्पाद के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट मुक्त करता है जो कि प्रवाल भित्तियों के अस्तित्व के लिये आवश्यक है।
 - वे समुद्री दुनिया के अपशिष्ट संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करते हैं और पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करते हैं।
- **खतरा:** अवैध व्यापार और तस्करी
- **संरक्षण:**
 - **IUCN रेड लिस्ट:** ब्राउन समुद्री खीरा (लुप्तप्राय), ब्लैकस्पॉटेड समुद्री खीरा (कम चिंतनीय), नीला समुद्री खीरा (डेटा की कमी) आदि।
 - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 :** अनुसूची-I
 - **संरक्षण के प्रयास:** वर्ष 2020 में लक्षद्वीप प्रशासन ने 239 वर्ग किमी. में समुद्री खीरे के लिये विश्व का पहला संरक्षण क्षेत्र बनाया।

जनजातीय क्षेत्रों में मोती की खेती

संदर्भ: हाल ही में TRIFED (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ) ने आदिवासी क्षेत्रों में मोती की खेती को बढ़ावा देने के लिये झारखंड स्थित 'पूर्ति एग्रीटेक' के साथ एक समझौता किया है।

समझौते के बारे में

- समझौते के तहत विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अलावा 'पूर्ति एग्रीटेक' द्वारा 141 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स के माध्यम से मोती बेचे जाएंगे।
- 'पूर्ति एग्रीटेक' के केंद्र को 'वन धन विकास केंद्र क्लस्टर' (VDVKC) के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड में मोती की खेती के लिये ऐसे 25 'वन धन विकास केंद्र क्लस्टर' विकसित करने की योजना है।
- सीपों का प्रजनन एवं मोतियों का विकास व्यवसाय की एक सतत् विधि है और इसे प्रायः उन आदिवासियों द्वारा अभ्यास में लाया जा सकता है, जिनकी आस-पास के जल निकायों तक पहुँच है।
- यह आने वाले समय में आदिवासियों की आजीविका के लिये गेम-चेंजर साबित होगा।

मोती की खेती के बारे में

- मोती दुनिया में एकमात्र ऐसा रत्न है, जो किसी जीवित प्राणी से प्राप्त होता है।
- सीप और मसल्स जैसे मोलस्क इन कीमती रत्नों का उत्पादन करते हैं
- पर्ल सीप की खेती दुनिया के कई देशों में सुसंस्कृत मोतियों के उत्पादन के रूप में की जाती है।
- मीठे पानी के मोती को मसल्स का उपयोग करके खेतों में उगाया जाता है।
- चूँकि मसल्स ऑर्गेनिक होस्ट होते हैं, इसलिये मोती प्राकृतिक रूप से खारे पानी की सीपों की तुलना में 10 गुना बड़े हो सकते हैं और ताज़े पानी के मोती की चमक भी अधिक होती है।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED) के बारे में

	● बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत 1987 में स्थापित यह वैधानिक निकाय देश के आदिवासी लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काम करता है। ● मंत्रालय: जनजातीय मामलों के मंत्रालय। ● इसे देश के सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया है। ● यह आदिवासी लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए स्थायी आधार पर उत्पादों का निर्माण करने में मदद करता है और स्वयं सहायता समूहों के गठन तथा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने में भी सहायता करता है।
अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन	खबरों में : विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको-लेबल "ब्लू फ्लैग" ने इस वर्ष 2 नए समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया है - तमिलनाडु में कोवलम (Kovalam) और पुडुचेरी में ईडन (Eden) हैं। ● फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन (Foundation for Environment Education - FEE), डेनमार्क, जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान करता है, ने आठ नामित समुद्र तटों - शिवराजपुर-गुजरात, घोघ्ला-दीव, कसकोद और पदुबिदरी -कर्नाटक, काप्पाड-केरल, रुशिकोंदा-आंध्र प्रदेश, गोल्डन-ओडिशा के लिए पुनः प्रमाणन भी दिया है और राधानगर- अंडमान और निकोबार, जिन्हें पिछले साल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया था। ● समुद्र तट पर्यावरण और सौंदर्यशास्त्र प्रबंधन सेवाएं (BEAMS): ○ संसाधनों के समग्र प्रबंधन के माध्यम से प्राचीन तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और संरक्षण करना। ○ BEAMS कार्यक्रम के उद्देश्य हैं: तटीय जल प्रदूषण को न्यून करना, समुद्र तट सुविधाओं के सतत विकास को बढ़ावा देना, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण, स्वच्छता के उच्च मानकों को मजबूत करना और उन्हें बनाए रखना और तटीय वातावरण और नियमों के अनुसार समुद्र तट के लिये स्वच्छता और सुरक्षा।
WHO ने 2005 के बाद पहली बार वायु गुणवत्ता मानदंडों में संशोधन किया	संदर्भ : विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 2005 के बाद से अपने पहले अपडेट में वैश्विक वायु प्रदूषण मानकों को कड़ा किया है क्योंकि पिछले एक दशक में यह माना गया है कि स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का प्रभाव पहले की तुलना में कहीं अधिक गंभीर है। ● एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक वर्ष वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से 7 मिलियन लोगों की मृत्यु समय से पूर्व हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप लोगों के जीवन के लाखों स्वस्थ वर्षों का नुकसान होता है। नए मानदंड ● डब्ल्यूएचओ ने पीएम 2.5 सहित कई प्रदूषकों के लिए स्वीकार्य सीमा कम कर दी है। अब, पीएम 2.5 सांद्रता $15\mu\text{g}/\text{m}^3$ से नीचे रहनी चाहिए। ● नई सीमा के अनुसार, औसत वार्षिक PM2.5 सांद्रता 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ● 4 घंटे की अवधि में अनुशंसित PM2.5 सांद्रता 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, जबकि WHO के वर्ष 2005 के दिशा-निर्देशों में 25 माइक्रोग्राम की सलाह दी गई है। भारत पर प्रभाव ● इस कदम का भारत पर तुरंत प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (National Ambient Air Quality Standards- NAAQS) WHO के मौजूदा मानकों को पूरा नहीं करते हैं। ● सरकार का अपना एक समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक वर्ष 2017 के स्तर को आधार वर्ष मानते हुए 122 शहरों में कणों की सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी लाना है। राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS) क्या है? ● राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा निर्धारित परिवेशी वायु गुणवत्ता के मानक हैं। ● CPCB को यह शक्ति वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 द्वारा प्रदान की गई है। ● परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों में 12 प्रदूषक होते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) क्या है? ● इसे MoEFCC द्वारा जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था।

	● समयबद्ध कमी लक्ष्य के साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का देश में यह पहला प्रयास है। ● यह तुलना के लिए आधार वर्ष 2017 के साथ अगले पांच वर्षों में मोटे (पीएम10) और महीन कणों (पीएम 2.5) की सांद्रता में कम से कम 20% की कटौती करना चाहता है। ● योजना में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 गैर-प्राप्ति शहर शामिल हैं, जिनकी पहचान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने 2011 और 2015 के बीच उनके परिवेशी वायु गुणवत्ता डेटा के आधार पर की थी। ● गैर-प्राप्ति वाले शहर: ये वे शहर हैं जो पांच वर्षों से अधिक समय से राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) से कम हैं।
विश्व राइनो दिवस	संदर्भ : राइनो की सभी पांच प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाने और उन्हें बचाने के लिए किए जा रहे कार्य के लिए 22 सितंबर को संदर्भ विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। ● विश्व राइनो दिवस पहली बार 2010 में विश्व वन्यजीव कोष-दक्षिण अफ्रीका (World Wildlife Fund-South Africa) द्वारा घोषित किया गया था। ● आवास के क्षतिग्रस्त होने और अवैध शिकार के कारण राइनो की प्रजातियों पर विलुप्त होने का संकट मंडरा रहा है। ● थीम 2021: कीप द फाइव अलाइव (Keep the five Alive)। ● उद्देश्य: सुरक्षा को मजबूत करना, विचरण क्षेत्र का विस्तार, अनुसंधान और निगरानी, पर्याप्त एवं निरंतर वित्तपोषण। गैंडे की प्रजातियों के बारे में ● गैंडे की पाँच प्रजातियाँ इस प्रकार हैं- अफ्रीका में सफेद और काले राइनो (White and Black Rhinos in Africa), एक सींग वाले गैंडे (Greater one-Horned), एशिया में जावा और सुमात्रन गैंडे/राइनो (Javan and Sumatran Rhino) की प्रजातियाँ। ● IUCN लाल सूची की स्थिति: ○ व्हाइट राइनो: खतरे या संकट के करीब। ○ ब्लैक राइनो: गंभीर रूप से संकटग्रस्त। ○ एक सींग वाले गैंडे: सुभेद्य। ○ जावन: गंभीर रूप से संकटग्रस्त। ○ सुमात्रा राइनो: गंभीर रूप से संकटग्रस्त। एक सींग वाले गैंडे ● इसे इंडियन राइनो के रूप में भी जाना जाता है, यह राइनो प्रजातियों में सबसे बड़ा है। ● भारत विश्व में एक सींग वाले गैंडे की सर्वाधिक संख्या वाला देश है। ● वर्तमान में भारत में लगभग 2,600 इंडियन राइनो हैं, जिनकी 90% से अधिक आबादी असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में केंद्रित है। ● पर्यावास: यह प्रजाति इंडो-नेपाल तराई क्षेत्र, उत्तरी पश्चिम बंगाल और असम तक सीमित है। ● भारत में गैंडे मुख्य रूप से पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, असम के काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान तथा उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। ● खतरा: ○ सींगों का अवैध शिकार। ○ प्राकृतिक वास का नुकसान। ○ जनसंख्या घनत्व। ○ घटती आनुवंशिक विविधता। ● संरक्षण स्थिति:

	○ IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य ○ CITES: परिशिष्ट-I ○ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची- I भारत द्वारा संरक्षण प्रयास: ● न्यू डेलही डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज: भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया ने प्रजातियों के संरक्षण और संरक्षण के लिए एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। ● सभी गैंडों का डीएनए प्रोफाइल: यह परियोजना अवैध शिकार को रोकने और गैंडों से जुड़े वन्यजीव अपराधों में सबूत इकट्ठा करने में मदद करेगी। ● राष्ट्रीय राइनो संरक्षण रणनीति: इसे 2019 में एक-सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया था। ● इंडियन राइनो विज़न 2020: इसे वर्ष 2005 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य एक सींग वाले गैंडों की आबादी को वर्ष 2020 तक भारतीय राज्य असम के सात संरक्षित क्षेत्रों में 3,000 से अधिक करना था।
आर्कटिक सागर की बर्फ में कमी	संदर्भ : हाल ही में आर्कटिक समुद्र की बर्फ पिघलकर 4.72 मिलियन वर्ग मील की न्यूनतम सीमा तक पहुंच गई है। ● यह अब तक रिकॉर्ड आर्कटिक समुद्री बर्फ का 12वाँ सबसे कम स्तर है, अभी तक वर्ष 2012 में बर्फ के पिघलने का न्यूनतम रिकॉर्ड दर्ज है। ● ग्रीनलैंड के उत्तर में आर्कटिक की बर्फ में स्थित 'लास्ट आइस एरिया' (Last Ice Area- LIA) भी वैज्ञानिकों की अपेक्षा से कहीं अधिक पिघलने लगा है। महत्वपूर्ण तथ्य ● मानव गतिविधियों के चलते कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 1980 के दशक से समुद्री बर्फ का आवरण पिघलकर लगभग आधा हो गया है। ● बर्फ के पिघलने के इस चरण में सी आइस पैक (Sea Ice Pack) सबसे कमजोर होता है और किसी निश्चित दिन या सप्ताह की मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है। इसमें सूक्ष्म परिवर्तनों का बड़ा प्रभाव हो सकता है। बर्फ के तेजी से पिघलने वाले कारक ● एल्बेडो फीडबैक लूप: बर्फ, जमीन या पानी की सतहों की तुलना में अधिक परावर्तक (उच्च एल्बीडो) होती है। ● वामावर्त बर्फ परिसंचरण: साइबेरिया से आर्कटिक में प्रवेश करने वाले चक्रवातों ने वामावर्त हवाओं और बर्फ के बहाव को उत्पन्न किया जिससे ग्रीनलैंड के पूर्व में फ्रैम स्ट्रेट के माध्यम से आर्कटिक से बाहर निकलने वाली समुद्री बर्फ की मात्रा कम हो गई। इसने ग्रीनलैंड सागर में देखी गई कम गर्मी की समुद्री बर्फ की स्थिति को रिकॉर्ड करने में योगदान दिया। ● निम्न दाब प्रणाली: निम्न दबाव प्रणाली आर्कटिक के ऊपर बादल निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाती है जो सतह से खोई हुई गर्मी को भी रोक सकती है।
चावल की हर्बिसाइड-टोलैरेंट किस्म	संदर्भ : हाल ही में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) ने देश की पहली गैर-जीएम (आनुवंशिक रूप से संशोधित) हर्बिसाइड-टोलैरेंट चावल की किस्में (पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985) विकसित की है। ● इन किस्मों को सीधे बोया जा सकता है और पारंपरिक रोपाई की तुलना में पानी और श्रम की काफी बचत होती है। ● ICAR-IARI एक डीमंड यूनिवर्सिटी है। चावल की नई किस्मों के बारे में: ● नई किस्मों में एक उत्परिवर्तित एसिटोलैक्टेट सिंथेज (ALS) जीन होता है, जिससे किसानों के लिए खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड इमाज़ेथापायर का छिड़काव करना संभव बनाता है। ○ 'इमाज़ेथापायर' चौड़ी पत्ती, घास और खरपतवारों के विरुद्ध प्रभावी होता है, हालाँकि सामान्य धान की किस्मों पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह फसल और आक्रामक पौधों के बीच अंतर नहीं करता है। ● इससे पौधे हर्बिसाइड के अनुप्रयोग को 'टोलैरेंट' कर सकते हैं और इस प्रकार हर्बिसाइड केवल खरपतवार एवं

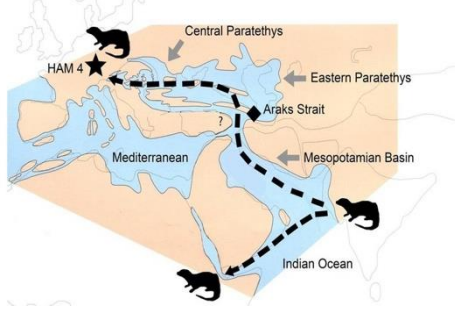
आक्रामक पौधों के लिये विनाशकारी है।

- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, चूँकि इस प्रक्रिया में कोई विदेशी जीन शामिल नहीं है, इसलिये हर्बिसाइड-टोलरेंट का गुण उत्परिवर्तन प्रजनन के माध्यम से उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह किस्म आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्म नहीं है।



तूफान 'इडा'	प्रसंग : हाल ही में तूफान इडा ने अमेरिका के लुइसियाना तटीय क्षेत्र में में दस्तक दी। यह एक अत्यंत खतरनाक श्रेणी-4 का तूफान है और अमेरिका में अब तक के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में नाम: ● टाइफून: चीन सागर और प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून के रूप में जाना जाता है। ● हरिकेन : कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में पश्चिम भारतीय द्वीपों में। ● विली-विलीज़: उत्तर-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ● उष्णकटिबंधीय चक्रवात: हिंद महासागर क्षेत्र में। तूफान का वर्गीकरण: ● तूफान को सैफिर-सिम्पसन (Saffir-Simpson) तूफान पवन पैमाने पर वर्गीकृत किया जाता है, जो हवा की गति के आधार पर उन्हें 1 से 5 के पैमाने पर रेट करता है। ● श्रेणी तीन या उससे अधिक तक पहुंचने वाले तूफान को बड़े तूफान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 
बैरा-स्यूल पावर स्टेशन	संदर्भ: नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) लिमिटेड ने अपने 180 मेगावाट बैरा-स्यूल पावर स्टेशन का स्वदेशी रूप से नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया है तथा वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है। ● यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा में है। ● बैरा-स्यूल पावर स्टेशन एनएचपीसी का पहला पावर स्टेशन है जो 1 अप्रैल 1982 से वाणिज्यिक संचालन के अधीन था और इसका 35 वर्षों का अपना जीवनकाल पूरा हो गया। ● बैरा-स्यूल पावर स्टेशन के जीवनकाल को अब 25 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। NHPC के बारे में ● NHPC सभी पहलुओं में जलविद्युत शक्ति के एकीकृत और कुशल विकास की योजना बनाने, बढ़ावा देने और व्यवस्थित करने के उद्देश्य से शामिल केंद्र सरकार का उद्यम है। ● स्थापित: 1975 ● इसके अलावा, जलविद्युत ऊर्जा कंपनी ने सौर, भूतापीय, ज्वार, पवन आदि जैसे ऊर्जा के अन्य स्रोतों को शामिल करने के लिए अपनी वस्तुओं का विस्तार किया है। ● वर्तमान में NHPC केंद्र सरकार का एक मिनी रत्न श्रेणी-I उद्यम है जिसकी अधिकृत शेयर पूंजी रु. 1,50,000 मिलियन है।
ब्राह्मणी नदी	संदर्भ: पर्यावरणविदों ने ब्राह्मणी नदी बेसिन से ताजे पानी के बड़े पैमाने पर पथांतरण (diversion) पर चिंता व्यक्त की है, जो ओडिशा में प्रसिद्ध मैंग्रोव वनस्पति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। ● तालचर-अंगुल कोयला खदानों, इस्पात और बिजली संयंत्र के साथ-साथ कलिंगनगर स्टील और पावर हब द्वारा ब्राह्मणी नदी से भारी मात्रा में इस ताजे पानी का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बारे में: ● ब्राह्मणी पूर्वी भारत के ओडिशा राज्य में एक प्रमुख मौसमी नदी है। ● ब्राह्मणी का निर्माण शंख और दक्षिण कोयल नदियों के संगम से हुआ है।

	● बैतरणी नदी के साथ मिलकर यह धामरा में बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले एक बड़ा डेल्टा बनाती है। ● 195 वर्ग किमी. में फैली भितरकनिका रामसर आर्द्रभूमि 62 मैंग्रोव प्रजातियों का घर है। इसके अलावा, भितरकनिका मैंग्रोव वन के दलदल में 1600 खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। ● ब्राह्मणी और खारसरोटा नदियों के निचले किनारों के पास समुद्री जल के साथ मीठे पानी के मिश्रण से मैंग्रोव के लिए आदर्श 'खारे पानी' का उत्पादन होता है।
समाचारों में स्थान: क्यूकरताक अवन्नारलेक	● यह एक छोटा, निर्जन और पहले से अज्ञात द्वीप है जिसे हाल ही में ग्रीनलैंड के तट पर खोजा गया था। ● 60×30 मीटर मापने वाला और समुद्र तल से तीन मीटर की चोटी के साथ, यह अब पृथ्वी पर भूमि का नया सबसे उत्तरी भाग बन गया है। ● इससे पहले, Oodaaq को पृथ्वी के सबसे उत्तरी इलाके के रूप में चिह्नित किया गया था। ● यह खोज आर्कटिक राष्ट्रों, अमेरिका, रूस, कनाडा, डेनमार्क और नॉर्वे के बीच उत्तरी ध्रुव और आसपास के समुद्र तल, मछली पकड़ने के अधिकार और जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ पिघलने से उजागर होने वाले शिपिंग मार्गों के नियंत्रण के लिए एक लड़ाई के रूप में सामने आई है।
डायनासोर की तीन प्रजातियों के पदचिह्न: राजस्थान	प्रसंग: हाल ही में एक बड़ी खोज में राजस्थान के जैसलमेर जिले के थार मरुस्थल में डायनासोर की 3 प्रजातियों के पैरों के निशान मिले हैं। ● यह राज्य के पश्चिमी भाग में विशाल सरीसृपों की उपस्थिति को प्रमाणित करता है, जो मेसोजोइक युग के दौरान टेथिस महासागर के समुद्र तट का निर्माण करते थे। इस खोज के बारे में: ● डायनासोर के पैरों के निशान वाली 3 प्रजातियां इस प्रकार हैं - यूब्रोंटेस सीएफ (Eubrontes cf), गिगेंटस (Giganteus), यूब्रोंट्स ग्लेनरोसेंसिस (Eubrontes glenrosensis) और ग्रेलेटर टेनुइस (Grallator tenuis)। ● ये पैरों के निशान 200 मिलियन वर्ष पुराने थे। ● डायनासोर की प्रजाति को थेरोपोड (Theropod) प्रकार का माना जाता है, जिसमें खोखली हड्डियों और तीन-पैर वाले अंगों (उंगलियों जैसी) की विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं। ● थेरोपोडा डायनासोर उपसमूह के थेरोपोड वर्ग में वे सदस्य शामिल हैं जो मांसाहारी डायनासोर की श्रेणी में आते हैं। ● 'डायनासोर युग' (मेसोजोइक युग- 252-66 मिलियन वर्ष पूर्व- MYA) अनुगामी तीन भूगर्भिक समय सारणी (ट्राइसिक (Triassic), जुरासिक (Jurassic) और क्रेटेशियस (Cretaceous) के अंतर्गत शामिल था। इन तीन अवधियों में से प्रत्येक के दौरान विभिन्न डायनासोर प्रजातियाँ पाई जाती थीं। थार रेगिस्तान के बारे में ● थार नाम 'थुल' से लिया गया है जो कि इस क्षेत्र में रेत की लकीरों के लिये प्रयुक्त होने वाला एक सामान्य शब्द है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ● अवस्थिति: यह उत्तर-पश्चिमी भारत के राजस्थान राज्य में तथा पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित पंजाब और सिंध प्रांत तक विस्तृत है। ● यह पश्चिम में सिंचित सिंधु नदी के मैदान, उत्तर और उत्तर-पूर्व में पंजाब के मैदान, दक्षिण-पूर्व में अरावली शृंखला और दक्षिण में कच्छ के रण से घिरा हुआ है। ● यह एक लहरदार सतह प्रस्तुत करता है, जिसमें रेतीले मैदानों और निचली बंजर पहाड़ियों, या भाकरों द्वारा अलग किए गए उच्च और निम्न रेत के टीले हैं। ● 'बरचन' जिसे 'बरखान' भी कहते हैं, मुख्य रूप से एक दिशा से आने वाली हवा द्वारा निर्मित अर्द्धचंद्राकार आकार के रेत के टीले हैं। ● कई 'प्लाया' (खारे पानी की झीलें), जिन्हें स्थानीय रूप से 'धंड' के रूप में जाना जाता है, पूरे क्षेत्र में विस्तृत हैं। ● थार मरुस्थल एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है तथा इस मरुस्थल में मुख्य रूप से तेंदुए, एशियाई जंगली बिल्ली (Felis silvestris Ornata), चाउसिंगा (Tetracerus Quadricornis), चिंकारा (Gazella Bennettii), बंगाली रेगिस्तानी लोमड़ी (Vulpes Bengalensis), ब्लैकबक (Antelope) और सरीसृप की

	कई प्रजातियाँ निवास करती हैं।
मणिपुर : कुकी	● मणिपुर में कुकी जनजाति ने सोमवार को मणिपुर में कथित रूप से एक सशस्त्र नागा समूह द्वारा कुकी नागरिकों के नरसंहार की 28वीं वर्षगांठ मनाई। ● कुकी लोग मिजो हिल्स (पूर्व में लुशाई) के मूल निवासी एक जातीय समूह हैं, जो भारत में मिजोरम के दक्षिणपूर्वी भाग में एक पहाड़ी क्षेत्र है। ● कुकी भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर कई पहाड़ी जनजातियों में से एक है। ● पूर्वोत्तर भारत में, वे अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में मौजूद हैं। ● भारत में कुकी लोगों की लगभग पचास जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है, जो उस विशेष कुकी समुदाय द्वारा बोली जाने वाली बोली के साथ-साथ उनके मूल क्षेत्र के आधार पर हैं।
विष्णुओनीक्स	प्रसंग : विष्णुओनीक्स के नए पाए गए जीवाश्म जर्मनी के बवेरिया में एक जीवाश्म स्थल हैमरस्चिमीडे के क्षेत्र में पाए गए हैं। ● 12.5 मिलियन से 14 मिलियन वर्ष पहले, विष्णुओनीक्स नामक ऊदबिलाव के एक जीनस के सदस्य दक्षिणी एशिया की प्रमुख नदियों में रहते थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ● अब विलुप्त हो चुके इन ऊदबिलावों के जीवाश्म सबसे पहले हिमालय की तलहटी में पाए जाने वाले अवसादों में खोजे गए थे। ● अब, नया पाया गया जीवाश्म इंगित करता है कि उसने जर्मनी तक यात्रा की थी। ● नए खोजे गए जीवाश्मों का नाम विष्णुनीक्स नेपच्यूनी रखा गया है, जिसका अर्थ है 'नेपच्यून का विष्णु'। ● यह यूरोप में विष्णुओनीक्स जीनस के किसी सदस्य की पहली खोज है। ● यह अब तक का सबसे उत्तरी और पश्चिमी रिकॉर्ड भी है। विष्णुओनीक्स के बारे में ● विष्णुओनीक्स मध्यम आकार के शिकारी थे जिनका वजन औसतन 10-15 किलोग्राम था। ● इससे पहले, जीनस केवल एशिया और अफ्रीका में ही जाना जाता था। ● विष्णुओनीक्स पानी पर निर्भर थे और जमीन पर लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकता थे। इसने यूरोप तक की यात्रा कैसे की? ● शोधकर्ताओं के अनुसार, 6,000 किमी से अधिक की यात्रा संभवतः 12 मिलियन वर्ष पहले के भूगोल से संभव हुई थी, जब हाल ही में आल्प्स का गठन हुआ था। ● ये आल्प्स और ईरानी एल्ब्रस पर्वत एक बड़े महासागर बेसिन द्वारा अलग किए गए थे, जिससे ऊदबिलाव को इसे पार करना आसान हो जाता था। 
पैंटानल आर्द्रभूमि	प्रसंग: लंबे समय से सूखे के बाद विनाशकारी जंगल की आग ने पैंटानल जगुआर के लिए खतरा पैदा कर दिया है। पंतनल आर्द्रभूमि के बारे में ● पैंटानल दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के भौगोलिक केंद्र में स्थित है। ● पैंटानल आर्द्रभूमि(Pantanal wetlands), विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि/ दलदली भूमि (world's largest tropical wetlands) वाला क्षेत्र है। ● पैंटानल आर्द्रभूमि का क्षेत्र मुख्य रूप से ब्राजील में स्थित है। हालांकि इस आर्द्रभूमि का कुछ क्षेत्र बोलीविया और पराग्वे देशों में भी आता है। ● पैंटानल आर्द्रभूमि का क्षेत्रफल 1,50,000 वर्ग किमी से भी अधिक है। ● यह एक विशाल आंतरिक नदी डेल्टा का निर्माण करता है, जिसमें आसपास के पठार से बहने वाली कई नदियाँ विलीन हो जाती हैं, अपने तलछट और कटाव अवशेषों को जमा करती हैं। ● पंतनल की वनस्पति, जिसे अक्सर "पंतनल परिसर" के रूप में जाना जाता है, पौधों के समुदायों का मिश्रण इस

	प्रकार है- नम उष्णकटिबंधीय अमेजोनियन वर्षावन पौधे, अर्ध-शुष्क वुडलैंड पौधे, ब्राजीलियाई सेराडो सवाना पौधे और बोलीविया और पराग्वे के चाको सवाना के पौधे। ● सेब का घोंघा पैटानल के पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख प्रजाति है। ● पैटानल पृथ्वी पर सबसे बड़ी और स्वास्थ्यप्रद जगुआर (पैंथेरा ओन्का) आबादी का घर है। ● पंतनाल की आर्द्रभूमि में निवास करने वाले दुर्लभ जानवरों में दलदली हिरण, विशाल नदी ऊदबिलाव, जलकुंभी एक प्रकार का तोता, क्रोनेड सोलिटरी ईगल, मॅनेड (maned) भेड़िया, दक्षिण अमेरिकी तपीर (tapir) और विशालकाय चींटी हैं।
जोजिला सुरंग कार्य	संदर्भ : हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने जोजिला सुरंग में निर्माण कार्य की समीक्षा की, जिसके सितंबर 2026 तक तैयार होने की संभावना है। जोजिला सुरंग के बारे में ● यह सुरंग श्रीनगर घाटी और लेह के बीच एनएच-1 पर हर मौसम में संपर्क मुहैया कराएगी और जम्मू-कश्मीर का चारोंतरफ से आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक एकीकरण करेगी। ● श्रीनगर और लद्दाख के बीच यात्रा करने में 3.5 घंटे लगते हैं। यह सुरंग यात्रा के समय को घटाकर 15 मिनट कर देगी। ● 14.15 किलोमीटर लंबी यह सुरंग एशिया की सबसे लंबी द्वि-दिशात्मक सुरंग होगी।



TLP+ Mains Answer Writing Program - 2022

Mains Test - Based Mentorship Program.



30 UPSC Level Mocks
(14 Sectional, 6 Essay, 10 FLT's)



1:1 Mentorship



Discussion Classes After Test



Detailed Synopsis



Flexible Tests

Toppers Recommended

**The Program Begins On
31st October**

REGISTER NOW

Scan here to



know more

वी. ओ. चिदंबरम पिल्लै	सुर्खियों में: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी वी.ओ.चिदंबरम पिल्लै की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वी ओ चिदंबरम पिल्लै के बारे में ● 5 सितंबर, 1872 को जन्मे पिल्लै को लोकप्रिय कप्पलोटिया थमिज़ान (तमिल खेवनहार) और "चेक्किलुथथा चेम्मल"के रूप में जाने जाते थे। ● चिदंबरम पिल्लै ने कैलडवेल कॉलेज, तूतीकोरिन से स्नातक किया। अपनी कानून की पढ़ाई शुरू करने से पहले उन्होंने एक संक्षिप्त अवधि के लिये तालुक कार्यालय में क्लर्क के रूप में काम किया। ● न्यायाधीश के साथ उनके विवाद ने उन्हें 1900 में तूतीकोरिन में नए काम की तलाश करने के लिये मजबूर किया। ● वर्ष 1905 तक वे पेशेवर और पत्रकारिता गतिविधियों में संलग्न रहे। ● 1906 तक चिदंबरम पिल्लै ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी (एसएसएनसीओ) के नाम से एक स्वदेशी मर्चेन्ट शिपिंग संगठन स्थापित करने के लिये तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली में व्यापारियों एवं उद्योगपतियों का समर्थन हासिल किया। ● चिदंबरम पिल्लै और शिवा को उनके प्रयासों हेतु तिरुनेलवेली स्थित कई वकीलों द्वारा सहायता प्रदान की गई, जिन्होंने स्वदेशी संगम या 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक' नामक एक संगठन का गठन किया। ● भारत के तेरह प्रमुख बंदरगाहों में से एक तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। ● वी. ओ. चिदंबरम पिल्लै पर खेल: देसभक्तर चिदंबरनार। ● उनके जीवन पर फिल्म: कपालोटिया तमिज़ान।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पर्व	सुर्खियों में : प्रधानमंत्री ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर लोगों को बधाई दी है। ● यह अवसर सिखों के पवित्र ग्रंथ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पांचवें गुरु अर्जन देव जी की देखरेख में 1604 में गुरुद्वारा रामसर साहिब में पूरा होने का प्रतीक है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के बारे में ● सर्वप्रथम प्रकाश पर्व उत्सव ने 1604 में हरमंदिर साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना को चिह्नित किया, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। ● गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद, उनके भजनों और अन्य लेखों को दशम ग्रंथ के नाम से जाना जाने वाला एक पुस्तक में संकलित किया गया था। ● करतारपुर साहिब कॉरिडोर: हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के सिखों की सबसे प्रसिद्ध परियोजना है । ● भारत से तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान में गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जाने की सुविधा प्रदान करता है। गुरुदासपुर में डेरा बाबा नानक को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के अंतिम विश्राम स्थल करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब से जोड़ने के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ● सभी धर्मों के भारतीय तीर्थयात्री और भारतीय मूल के व्यक्ति कॉरिडोर का उपयोग कर सकते हैं। ● यह यात्रा वीजा मुक्त होगी; तीर्थयात्रियों को केवल एक वैध पासपोर्ट ले जाने की आवश्यकता है ● तीर्थयात्रियों को कृपाण (खंजर) ले जाने की अनुमति होगी, जो सिखों द्वारा पहनी जाने वाली आस्था की पांच वस्तुओं में से एक है। ● गतका (Gatka): एक पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट है।
नुखाई	● यह पश्चिमी ओडिशा और झारखंड में सिमडेगा के आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है। ● यह एक कृषि त्योहार है, जिसे मौसम के नए चावल के स्वागत के लिए मनाया जाता है।

	- यह भाद्रपद या भाद्र महीने (अगस्त-सितंबर) के चंद्र पखवाड़े के पांचवें दिन, गणेश चतुर्थी त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है। - लोग अनुष्ठान के एक भाग के रूप में अपने संबंधित पीठासीन देवताओं को नबन्हा (Nabanha) नामक नई फसल की पेशकश करते हैं
सुब्रमण्यम भारती	संदर्भ: प्रधानमंत्री ने सुब्रमण्यम भारती को उनकी 100वीं पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि दी। सुब्रमण्यम भारती के बारे में - एक तमिल लेखक, कवि, पत्रकार, भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, समाज सुधारक और बहुभाषाविद थे। - इन्हें लोकप्रिय रूप से "महाकवि भारती" ("महान कवि भारती") के रूप में जाना जाता है, वह आधुनिक तमिल कविता के अग्रणी थे और उन्हें अब तक के सबसे महान तमिल साहित्यकारों में से एक माना जाता है। - उनकी कई कृतियों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशभक्ति जगाने वाले ज्वलंत गीत शामिल थे। - उन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी, बाल विवाह के खिलाफ, ब्राह्मणवाद और धर्म में सुधार के लिए खड़े हुए। वह दलितों और मुसलमानों के साथ भी एकजुटता में थे।
आचार्य विनोबा भावे	संदर्भ: प्रधानमंत्री ने आचार्य विनोबा भावे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। 11 सितंबर, 1895 को उनका जन्म महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गागोड गांव में हुआ था। उनका नाम विनायक नरहरि भावे था। उनके पिता का नाम नरहरि शम्भू राव और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। - वह एक धर्मगुरु के साथ-साथ एक समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। - वह गांधीजी की तरह ही अहिंसा के पुजारी थे। - उन्हें अधिकतर आचार्य (संस्कृत का शिक्षक) कहा जाता है, उन्हें भूदान और ग्रामदान आंदोलन के लिए जाना जाता है। - उन्हें भारत का राष्ट्रीय शिक्षक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। - वे एक प्रख्यात दार्शनिक थे। उनके द्वारा गीता का मराठी भाषा में अनुवाद भी किया गया है, जिसका नाम गीताई यानी मां गीता है।
थमिराबरानी सभ्यता: तमिलनाडु	प्रसंग: तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के शिवकलाई में पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त कार्बनिक पदार्थों पर की गई कार्बन डेटिंग से पता चला है कि थमिराबरानी सभ्यता कम-से-कम 3,200 साल पुरानी है। कार्बन डेटिंग: कार्बन के समस्थानिक कार्बन-12 और कार्बन-14 के सापेक्ष अनुपात से कार्बनिक पदार्थ की आयु या तिथि के निर्धारण को कार्बन डेटिंग कहते हैं। थमिराबरानी नदी के बारे में - तमिलनाडु की सबसे छोटी नदी का उद्गम थमिराबरानी अंबासमुद्रम तालुके में पश्चिमी घाट की पोथिगई पहाड़ियों से होता है, यह तिरुनेलवेली और थूथुकुडी जिलों से होकर बहती है तथा कोरकाई (तिरुनेलवेली जिले) में मन्नार की खाड़ी (बंगाल की खाड़ी) में गिरती है। निष्कर्षों का महत्व/परिणाम: - यह इस बात का प्रमाण दे सकता है कि दक्षिण भारत में 3,200 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक शहरी सभ्यता [पोरुनाई नदी (थमिराबरानी) सभ्यता] थी। - साथ ही, तमिल मूल की खोज के लिए अन्य राज्यों और देशों में पुरातात्विक उत्खनन किया जाएगा। - पहले चरण में चेर साम्राज्य की प्राचीनता और संस्कृति को स्थापित करने के लिये केरल में मुजिरिस के प्राचीन बंदरगाह, जिसे अब पट्टनम के नाम से जाना जाता है, पर अध्ययन किया जाएगा। - इन देशों के साथ तमिलों के व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए मिस्र में कुसीर अल-कादिम और पर्निका अनेके, जो कभी रोमन साम्राज्य का हिस्सा थे, और साथ ही ओमान में खोर रोरी में अनुसंधान किया जाएगा। - इन देशों में तमिल लिपियों वाले बर्तन पाए गए हैं। - इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी अध्ययन किया जाएगा, जहां राजा राजेंद्र चोल ने वर्चस्व स्थापित किया था। क्या आप जानते हैं?

- तमिल भारत के तीन शासक घरानों, पांड्य, चेर और चोल ने दक्षिणी भारत और श्रीलंका के वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ी।
- इन राजवंशों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रारंभिक साहित्य को बढ़ावा दिया और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों का निर्माण किया।
- संगम साहित्य, जो छह शताब्दियों (3rd BCE – 3rd CE) की अवधि में लिखा गया था, विभिन्न चोल, चेर और पांड्य राजाओं के संदर्भ है।



स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक शिकागो संबोधन की 128वीं वर्षगांठ

संदर्भ : 11 सितंबर, 1893 को, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित 'विश्व धर्म संसद' (Parliament of the World's Religions) में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसमें उनके लिए महासभा में सम्मिलित व्यक्ति पूरे दो मिनट तक खड़े होकर तालियाँ बजाते रहे।

- इस ऐतिहासिक भाषण के पश्चात उन्हें 'भारत का चक्रवाती भिक्षु' (Cyclonic Monk of India) का उपनाम दिया गया।
- इस वर्ष स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक शिकागो संबोधन की 128वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।

इस आयोजन का महत्व क्या है?

- शिकागो में दिए गए भाषण में हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का विस्तार से वर्णन गया था, और इस भाषण के शब्द आज भी गुंजायमान हैं।
- विश्व धर्म संसद में अपने प्रसिद्ध भाषण के बाद स्वामी विवेकानंद पश्चिमी दुनिया में काफी लोकप्रिय हो गए।
- उन्हें भारत में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और 19वीं शताब्दी के अंत में एक प्रमुख विश्व धर्म का दर्जा दिलाने के लिए एक प्रमुख शक्ति माना जाता है।
- 1893 में शिकागो में विश्व "धर्म संसद" में उनके भाषण ने दुनिया का ध्यान वेदांत के प्राचीन भारतीय दर्शन की ओर भी आकर्षित किया।

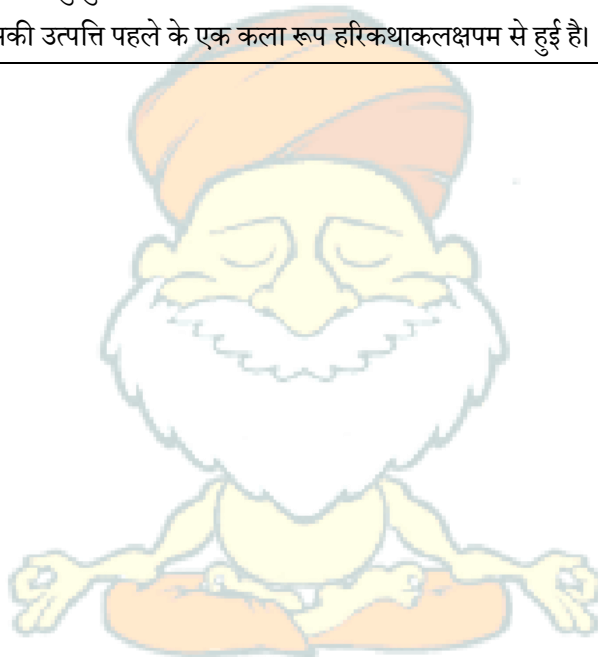
स्वामी विवेकानंद के बारे में:

- वह वास्तविक रूप से एक तेजस्वी व्यक्ति थे, और इनके लिए पश्चिमी जगत को हिंदू धर्म से परिचित कराने का श्रेय दिया जाता है।
- वह श्री रामकृष्ण परमहंस के एक उत्साही शिष्य और भारत में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार में एक प्रमुख शक्ति थे।
- उन्होंने औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया, और उन्होंने वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपना सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषण दिया था।

	वर्ष 1984 में भारत सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को 'राष्ट्रीय युवा दिवस' के रूप में घोषित किया गया था।
सारागढ़ी के युद्ध	संदर्भ: 12 सितंबर को सारागढ़ी की लड़ाई की 124वीं वर्षगांठ है। - सारागढ़ी की लड़ाई ब्रिटिश राज और अफगान आदिवासियों के बीच तिराह अभियान से पहले लड़ी गई एक अंतिम लड़ाई थी। - सारागढ़ी फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान के बीच संचार टावर था। - बीहड़ उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत (NWFP) में दो किलों का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह द्वारा किया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने उनका नाम बदल दिया। 12 सितंबर 1897 को, अनुमानित 12,000-24,000 ओरकजई और अफरीदी आदिवासियों ने सारागढ़ी की चौकी पर हमला किया, जिससे फोर्ट लॉकहार्ट से गुलिस्तान का किला कट गया। - हवलदार ईशर सिंह के नेतृत्व में 36वें सिख के सैनिकों ने अंतिम सांस तक संघर्ष किया, जिसमें 200 आदिवासियों की मौत हो गई और 600 घायल हो गए। 2017 में, पंजाब सरकार ने 12 सितंबर को छुट्टी के रूप में सारागढ़ी दिवस मनाने का फैसला किया।
चेरामन मस्जिद	संदर्भ: केरल के त्रिसूर जिले के कोडुनगालुर तालुका में देश की पहली व भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी चेरामन जुमा मस्जिद के जीर्णोद्धार का काम पूरा हो गया है। जल्द ही मस्जिद मुस्लिम धर्म के साथ आम लोगों के लिए खोली जाएगी, जिससे लोग इस ऐतिहासिक धार्मिक इमारत का दीदार कर सकेंगे। मस्जिद 629 ईस्वी की है। - केरल सरकार ने मुजिरिस के पौराणिक बंदरगाह के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को बहाल करने के लिए मुजिरिस विरासत परियोजना शुरू की है। - मुजिरिस विरासत परियोजना भारत में सबसे बड़ी संरक्षण परियोजनाओं में से एक है, जहां राज्य और केंद्र सरकारें एक समृद्ध संस्कृति के संरक्षण के लिए एक साथ आई हैं जो 3000 साल या उससे अधिक पुरानी है। - यह क्षेत्र बीते युग के कई स्मारकों से युक्त है जो एक विशाल और विशद अतीत को दर्शाते हैं। - यह पूरी परियोजना को सभी इच्छित विकासात्मक पहलों में स्थानीय समुदाय को शामिल करने और एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
शंखलिपि	संदर्भ: हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के पुरातत्वविदों को उत्तर प्रदेश के एटा जिले में गुप्त काल के एक प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों पर 'शंखलिपि' शिलालेख मिला है। - एटा-उत्तर प्रदेश में बिलसड़, जहां अवशेष पाए गए थे, औपनिवेशिक काल से एक संरक्षित स्थल रहा है और यह गुप्त काल की एक ज्ञात बस्ती है। मुख्य निष्कर्ष 'शंखलिपि' अभिलेखों को पुरातत्वविदों ने गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि 'श्री महेंद्रादित्य' कहकर गूँथ लिया था। - यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि गुप्त युग से अब तक केवल दो अन्य संरचनात्मक मंदिर पाए गए हैं - दशावतार मंदिर (देवगढ़) और भितरगांव मंदिर (कानपुर देहात)। शंखलिपि के बारे में - यह लिपि ब्राह्मी व्युत्पन्न मानी जाती है जो शंख की तरह दिखती है। - वे पूरे उत्तर-मध्य भारत के शिलालेखों में पाए जाते हैं और चौथी तथा आठवीं शताब्दी के बीच के हैं। - शिलालेखों में कम संख्या में वर्ण होते हैं, जो यह सुझाव देते हैं कि शैल शिलालेख नाम या शुभ प्रतीक या दोनों का संयोजन है। - लिपि की खोज 1836 में अंग्रेजी विद्वान जेम्स प्रिंसेप द्वारा उत्तराखंड के बाराहाट में पीतल के त्रिशूल पर की गई थी। - शैल शिलालेखों के साथ प्रमुख स्थलों में बिहार में मुंडेश्वरी मंदिर, मध्य प्रदेश में उदयगिरी गुफाएं, महाराष्ट्र में मानसर और गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ गुफा स्थल शामिल हैं। - इंडोनेशिया के जावा और बोर्नियो में भी शैल शिलालेखों की सूचना दी गई है।

	गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम ● गुप्त रूप से संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण करने वाले पहले व्यक्ति थे, जो प्राचीन रॉक-कट मंदिरों से अलग थे। ● कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और गुप्त वंश के महान समुद्रगुप्त का पोता था। ● उन्होंने विश्व प्रसिद्ध प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। ● गुप्त राजाओं में उसने सबसे बड़ी किस्म के सिक्के जारी किए।
रामधारी सिंह दिनकरी	● 1908 में बिहार के सिमरिया में जन्मे दिनकर की कविता स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेरणादायी मानी जाती थी। ● भारतीय स्वतंत्रता से पहले के दिनों में लिखी गई उनकी राष्ट्रवादी कविता के परिणामस्वरूप विद्रोह के कवि के रूप में फिर से जुड़ गए। ● उनकी कविता में वीर रस का संचार हुआ और उनकी प्रेरक देशभक्ति रचनाओं के कारण उन्हें राष्ट्रकवि ('राष्ट्रीय कवि') के रूप में सम्मानित किया गया। ● सरकार के प्रकोप से बचने के लिए दिनकर की कविताओं को छद्म नाम "अमिताभ" के तहत प्रकाशित किया गया था। ● दिनकर ने शुरू में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन बाद में गांधीवादी बन गए। ● इन्हें 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ● उनका कुरुक्षेत्र महाभारत के शांति पर्व पर आधारित एक कथात्मक कविता है। ● कृष्ण की चैतवाणी उन घटनाओं के बारे में रचित एक कविता है जिसके कारण महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ। उनकी समाधेनी कविताओं का एक संग्रह है जो कवि की सामाजिक सरोकार को राष्ट्र की सीमाओं से परे दर्शाती है। ● उनकी रश्मिरथी को हिंदू महाकाव्य महाभारत के सर्वश्रेष्ठ संस्करणों में से एक माना जाता है।
नाताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान और विरासत	मुख्तियारों में: नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और योगदान पर डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। ● भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो बार निर्वाचित अध्यक्ष, (1938-हरिपुर और 1939-त्रिपुरी)। ● राजनीतिक मतभेदों के कारण, उन्होंने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और बंगाल में कांग्रेस के अंदर एक अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ● कलकत्ता में, बोस ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसे नजरबंद कर दिया गया, जहां से वह फरार हो गये। आजाद हिंद फौज ● आजाद हिंद फौज के नेता। ● सुभाष चंद्र बोस को इस बात का दृढ़ विश्वास था कि सशस्त्र संघर्ष ही भारत को स्वतंत्र करने का एकमात्र तरीका है। 1920 और 1930 के दशक में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कट्टरपंथी दल के नेता रहे, 1938-1939 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने की राह पर आगे बढ़ रहे थे लेकिन महात्मा गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के साथ मतभेदों के बाद उन्हें हटा दिया गया। ● सुभाष चंद्र बोस 1941 में भारत से भाग गए थे और भारत की आजादी के लिए जर्मनी गए थे। 1943 में, वह भारतीय स्वतंत्रता लीग का नेतृत्व करने और भारतीय राष्ट्रीय सेना (आजाद हिंद फौज) का पुनर्निर्माण करने के लिए सिंगापुर आए ताकि इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए एक प्रभावी साधन बनाया जा सके। ● नेताजी अंडमान गए जिस पर जापानियों का कब्जा था और वहां भारत का झंडा फहराया। 1944 की शुरुआत में, आजाद हिंद फौज (INA) की तीन इकाइयों ने भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्सों पर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए हमले में भाग लिया। ● आजाद हिंद फौज, 'दिल्ली चलो' के नारे और जय हिंद के नारे के साथ, देश के अंदर और बाहर भारतीयों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया में रहने वाले सभी धर्मों और क्षेत्रों के भारतीयों को एक साथ लामबंद किया।

	● आजाद हिंद फौज की एक महिला रेजिमेंट का गठन किया गया, जो कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन की कमान में थी। इसे रानी झांसी रेजिमेंट कहा जाता था। आजाद हिंद फौज भारत के लोगों के लिए एकता और वीरता का प्रतीक बन गई। ● बोस की मृत्यु को आजाद हिंद आंदोलन के अंत के रूप में देखा गया। ध्यान दें: ● नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप: अंडमान और निकोबार द्वीप का रॉस द्वीप। ● नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
कथा प्रसंगम	● कथाप्रसंगम या कथावाचन प्रदर्शन एक लोकप्रिय कला रूप है जिसमें संगीत और संभाषण कला की परंपराएं मिश्रित हैं। ● केरल की प्रदर्शन कला कथाप्रसंगम की प्रस्तुति काथिकन (कथाप्रसंगम के कलाकार) द्वारा की जाती है जो एक साथ एक प्रतिभाशाली गायक, अभिनेता और वक्ता होते हैं। ● पोशाक, मेकअप या सेटिंग्स का उपयोग नहीं किया जाता है। ● मुख्य कलाकार, काथिकन, दो या तीन वादकों के साथ कहानी सुनाता है, अभिनय करता है और गाता है। ● विषयवस्तु मुख्यतः शास्त्रीय और लोकप्रिय साहित्य से हैं। ● इसकी उत्पत्ति पहले के एक कला रूप हरिकथाकलक्षपम से हुई है।



मिल्की सी प्रभाव (Milky seas effect) संदर्भ: चमकीले दूधिया समुद्रों/मिल्की सी (Milky Seas) को खोजने के लिये वैज्ञानिक नई उपग्रह प्रौद्योगिकी डे/नाइट बैंड का उपयोग कर रहे हैं।	मिल्की सी इफेक्ट के बारे में ● मिल्की सी इफेक्ट समुद्र में एक असामान्य समुद्री घटना को संदर्भित करता है जिसमें रात में समुद्र के पानी की एक बड़ी मात्रा चमकदार (भयानक नीली चमक) दिखाई देती है। ● इसे मारेल (Mareel) भी कहा जाता है, यह समुद्री बायोलुमिनसेंस (Bioluminescence) का एक दुर्लभ रूप है जहां रात के समय समुद्री सतह एक व्यापक, समान और स्थिर सफेद चमक उत्पन्न करती है। ● कुछ लोगों का कहना है कि मारेल आमतौर पर नोक्टिलुका स्कैंडिलन्स (लोकप्रिय रूप से "समुद्री चमक" के रूप में जाना जाता है) के कारण होता है, एक डिनोफ्लैगलेट जो परेशान होने पर चमकता है और दुनिया के अधिकांश हिस्सों में महासागरों में पाया जाता है। ● बायोलुमिनसेंस एक जीवित जीव (Living Organism) के भीतर एक रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न प्रकाश है। जो मुख्य रूप से समुद्र के पानी, समुद्री तलछट, सड़ने वाली मछलियों की सतह और समुद्री जानवरों की आंत में मौजूद होते हैं। ● समुद्र और लहरों की गति के कारण होने वाला तनाव, प्लवक को कुछ फायरफ्लाइज़ के समान ही एक रक्षा तंत्र के रूप में प्रकाश या बायोलुमिनसेंस का उत्सर्जन करने के लिए प्रेरित करता है। ● इस तरह की घटनाएं रात में इतनी तेज चमकती हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों से दिखाई देती हैं। ● 2005 में, वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि पहली बार उन्होंने इस चमक के फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त किए हैं। ● दुनिया भर में प्रतिवर्ष लगभग दो या तीन मिल्की सी/दूधिया समुद्र देखे जाते हैं, ज्यादातर की उत्पत्ति उत्तर-पश्चिमी हिंद महासागर के जल में इंडोनेशिया के तट से दूर होती हैं। ● ल्यूमिनसेंट चमक समुद्र की सतह पर केंद्रित होती है और पूरे जल स्तंभ में समान रूप से मिश्रित नहीं होती है।
रूस में व्यायाम ZAPAD 2021	सुर्खियों में: भारतीय सेना का 200 सैनिकों का एक दल दिनांक 03 से 16 सितंबर 2021 तक रूस के निझनी में आयोजित होने वाला एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास ZAPAD 2021 में भाग लेगा। अभ्यास ZAPAD 2021 के बारे में: ● ZAPAD 2021 रूसी सशस्त्र बलों के थिएटर स्तर के अभ्यासों में से एक है और यह मुख्य रूप से आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन पर केंद्रित होगा। ● इस युद्धाभ्यास में यूरेशियन और दक्षिण एशियाई क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक देश भाग लेंगे। ● अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाना है, भाग लेने वाले देश इस अभ्यास की योजना और निष्पादन करते हैं। ● भारतीय दल को एक कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद रखा गया है जिसमें मशीनीकृत, हवाई और हेलीबोर्न, आतंकवाद रोधी, कॉम्बैट कंडीशनिंग एवं फायरिंग समेत पारंपरिक अभियानों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। ● अभ्यास में भाग लेने वाले NAGA बटालियन समूह में सभी शस्त्रों का संयुक्त कार्यबल होगा।
ब्लू स्ट्रैगलर	संदर्भ : ब्लू स्ट्रैगलर्स खुले या गोलाकार समूहों में सितारों का एक ऐसा वर्ग हैं जो अन्य सितारों की तुलना में अपेक्षाकृत बड़े और नीले रंग के होने के कारण अलग ही दिखाई देते हैं। ● ये उन वैज्ञानिकों को चिंतित करते हैं जिन्होंने लंबे समय से इन तारों की उत्पत्ति का अध्ययन किया है। ● ब्लू स्ट्रैगलर का पहला व्यापक विश्लेषण करते हुए भारतीय शोधकर्ताओं ने पाया है कि उनके द्वारा देखे गए नमूनों में से आधे ब्ल्यू (नीले) स्ट्रैगलर एक करीबी द्वि-ध्रुवीय (बाइनरी) साथी तारे से बड़े पैमाने पर द्रव्य स्थानांतरण के माध्यम से बनते हैं। ब्लू स्ट्रैगलर क्या है? ● एक ही बादल से एक ही निश्चित अवधि में जन्मे तारों का कोई एक समूह अलग से दूसरा समूह बना लेता है। ● मानक तारकीय विकास के तहत जैसे-जैसे समय बीतता है, प्रत्येक तारा अपने द्रव्यमान के आधार पर अलग-अलग विकसित होने लगता है।

	● ब्लू स्ट्रैगलर विकसित होने के बाद मुख्य अनुक्रम से हट जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप उनके मार्ग में एक विपथन आ जाता है जिसे टर्नऑफ के रूप में जाना जाता है। ● चूँकि ब्लू स्ट्रैगलर इस इस वक्र से दूर रहते हैं, इसलिये वे असामान्य तारकीय विकास क्रम से गुजर सकते हैं। ● वे एक अधिक शांत, लाल रंग की अवस्था प्राप्त करने के विकास क्रम में अपने समूह के अधिकांश अन्य सितारों से पिछड़ते हुए दिखाई देते हैं। ● एलन सैंडेज (कैलिफोर्निया के पासाडेना में कार्नेगी ऑब्जर्वेटरीज के एक खगोलशास्त्री) ने वर्ष 1952-53 में गोलाकार क्लस्टर M3 में ब्लू स्ट्रैगलर की खोज की थी। ● प्रारंभ में, ये नीले तारे जो अभी भी टर्नऑफ के ऊपर संघर्ष कर रहे थे, इन समूहों का हिस्सा नहीं थे। ● हालांकि, बाद के अध्ययनों ने पुष्टि की कि ये सितारे वास्तव में क्लस्टर सदस्य हैं, और उन्हें "ब्लू स्ट्रैगलर्स" कहा गया। भारतीय शोधकर्ताओं के हालिया निष्कर्ष ● शोधकर्ताओं ने 2013 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित (लॉन्च) किए गए गैया टेलीस्कोप का उपयोग अपनी उत्कृष्ट स्थिति सटीकता के साथ समूहों में ब्लू स्ट्रैगलर का चयन करने और यह समझने के लिए किया था कि अभी ऐसे कितने सितारे हैं, कहां पर हैं और कैसे बनते हैं? ● उन्होंने पाया कि जिन समूहों को उन्होंने देखा और स्कैन किया उन 868 में से कुल 228 ब्लू स्ट्रैगलर्स हैं। ● ब्लू स्ट्रैगलर का यह पहला व्यापक विश्लेषण रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मासिक नोटिस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। ● इससे पता चला कि ये तारे मुख्य रूप से पुराने और बड़े तारा समूहों में ही मौजूद हैं और उनके अधिक द्रव्यमान के कारण वे समूहों के केंद्र की ओर अलग कर दिए गए हैं। ● शोधकर्ताओं ने नीले स्ट्रैगलर्स के द्रव्यमान की तुलना उन टर्नऑफ सितारों के द्रव्यमान से की जो क्लस्टर में सबसे बड़े पैमाने पर 'सामान्य' सितारे हैं। साथ ही उन्होंने इनके संभावित निर्माण तंत्र का भी पूर्वानुमान लगाया। ● हाल के निष्कर्षों का महत्व: यह अध्ययन विभिन्न आकाशगंगाओं सहित बड़ी तारकीय आबादी के अध्ययन में रोमांचक परिणामों को उजागर करने के साथ ही इन तारकीय प्रणालियों की जानकारी की समझ में और सुधार लाने में सहायक होगा।
2025 तक टीबी मुक्त भारत	सुर्खियों में: ● केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने क्षय रोग के खिलाफ सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ की समीक्षा के लिए सभी राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक से मुख्य निष्कर्ष: ● मंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार 2025 तक टीबी मुक्त भारत के प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के अपने मिशन में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी सुझावों के लिए तैयार है। ● उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को COVID के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य कार्यक्रमों तथा पहलों पर सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया। ● कोविड-19 के कारण टीबी से होने वाले लाभ के खतरे पर, उन्होंने हाल के दिनों में कोविड टीकाकरण में तेजी लाने पर बात की और 5 सितंबर तक सभी शिक्षकों को टीकाकरण के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जिसके लिए राज्यों को अतिरिक्त खुराक प्रदान की जा रही है। ● उन्होंने राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया कि देश में बेहतर स्थिति के कारण COVID प्रोटोकॉल का पालन किया जाए और कोई ढिलाई नहीं दिखाई जाए। ● उन्होंने टीबी उन्मूलन के इस मिशन में आम लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। इसे लोगों की पहल बनाना होगा। टीबी और COVID-19: ● विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) उन सदस्य देशों को सलाह दे रहा है जो सामने आ रही COVID-19 महामारी की प्रतिक्रिया का नेतृत्व कर रहे हैं।

	- WHO ग्लोबल टीबी प्रोग्राम ने, WHO के क्षेत्रीय और देश के कार्यालयों के साथ, हितधारकों के सहयोग से एक सूचना नोट विकसित किया है। - इस नोट का उद्देश्य राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रमों और स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 महामारी के दौरान टीबी से प्रभावित लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने में मदद करना है, जो अभिनव जन-केंद्रित दृष्टिकोणों द्वारा संचालित है, साथ ही दोनों बीमारियों से निपटने के लिए संयुक्त समर्थन को अधिकतम करना है। - यह महत्वपूर्ण है कि टीबी की रोकथाम और देखभाल में की गई प्रगति COVID19 महामारी से विपरीत न हो जाए। टीबी से पीड़ित लोगों का पता लगाना और उनका इलाज करना टीबी की रोकथाम और देखभाल के मूलभूत स्तंभ हैं और उन पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
डिफेंस एक्सपो-2022	सुर्खियों में: - रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी ने 02 सितंबर, 2021 को केवडिया, गुजरात में संयुक्त रूप से DefExpo-2022 की तैयारियों की समीक्षा की। - डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण, जो भारत का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें थल, नौसेना, वायु और साथ ही मातृभूमि सुरक्षा प्रणालियों को प्रदर्शित किया जाता है, यह आयोजन अगले साल 11-13 मार्च के बीच होगा। - गुजरात सरकार का लक्ष्य अपने एयरोस्पेस और रक्षा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और विदेशी निवेश प्राप्त करने के अवसर का उपयोग करना है। - फरवरी 2021 में, भारत पहला देश था जिसने सख्त COVID-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन में, बेंगलुरु में एक हाइब्रिड एयरोस्पेस प्रदर्शनी, एयरो इंडिया-2021 आयोजित की। रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में जबरदस्त वैश्विक प्रतिक्रिया देखी गई थी। डिफेंस एक्सपो-2022 - अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस और रक्षा कैलेंडर में प्रमुख आयोजन डिफेंस एक्सपो में भागीदारी की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में साल-दर-साल वृद्धि देखी गई है। - DefExpo-2022 का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' को प्राप्त करने और 2024 तक पांच अरब अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात लक्ष्य तक पहुंचने के दृष्टिकोण पर निर्माण करना है। - इसका उद्देश्य भारत को थल, नौसेना, वायु और मातृभूमि सुरक्षा प्रणालियों और रक्षा इंजीनियरिंग का एक प्रमुख स्थान बनाना है। - भविष्य के युद्ध को ध्यान में रखते हुए इस आयोजन का उद्देश्य संघर्षों पर विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के प्रभाव और आवश्यक उपकरणों तथा प्लेटफार्मों पर इसके परिणामी प्रभाव को पहचानना है। - DefExpo-2022 का आयोजन COVID-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और इसका उद्देश्य अधिकतम अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भागीदारी सुनिश्चित करना है। - नियोजित कार्यक्रमों में कॉन्क्लेव, हाइब्रिड कार्यक्रम, लाइव प्रदर्शन और व्यावसायिक सेमिनार शामिल हैं।
म्यू वेरिएंट	संदर्भ: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेरिएंट ऑफ़ इंटरैस्ट (Variants of Interest- VOI) की सूची में कोविड-19 का एक नया वेरिएंट जोड़ा है और इसे Mu (B.1.621) नाम दिया है। इसने C.1.2 को एक नए VOI के रूप में भी जोड़ा है। इसके बारे में - वेरिएंट की पहली बार जनवरी, 2021 में कोलंबिया में पहचान की गई थी। - अनुक्रमित मामलों में म्यू संस्करण के वैश्विक प्रसार में गिरावट आई है और वर्तमान में यह 0.1% से कम है। हालांकि कोलंबिया (39%) और इक्वाडोर (13%) में प्रसार लगातार बढ़ा है। - दक्षिण अमेरिका और यूरोप के देशों से बड़े प्रकोप की सूचना मिली थी। - यूके, यूएस और हांगकांग में भी मामले सामने आए हैं। SARS-CoV-2 प्रकार के वर्ग वेरिएंट ऑफ़ इंटरैस्ट - विशिष्ट आनुवंशिक मार्करों वाला एक प्रकार जो रिसेप्टर बाइंडिंग में परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है जो इसके क्लिनिकल को प्रभावित करता है और अद्वितीय प्रकोप समूहों का कारण बनने की उम्मीद है।

	● यह संप्रेषणीयता में वृद्धि की भविष्यवाणी के लिए जाना जाता है। ● इसे आनुवंशिक परिवर्तन जैसे कारकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो वायरस की विशेषताओं को प्रभावित करने के लिए जाने जाते हैं या ज्ञात होते हैं जैसे संक्रमण, रोग की गंभीरता, प्रतिरक्षा से बचना आदि। ● यह चिंता के एक प्रकार (VOC) की तुलना में निम्न स्तर की चिंता का प्रतिनिधित्व करता है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न ● एक प्रकार जिसके लिए संचरण क्षमता में वृद्धि, गंभीर बीमारी (जैसे-अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु में वृद्धि) का प्रमाण है। ● यह पिछले संक्रमण या टीकाकरण के दौरान उत्पन्न एंटीबॉडी द्वारा बेअसर करने में महत्वपूर्ण कमी, उपचार या टीकों की कम प्रभावशीलता या नैदानिक पहचान विफलताओं के लिए जाना जाता है। ● उदाहरण - SARS-CoV-2 के अल्फा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट।
हंसा विमान	सुखियों में: हंसा न्यू जनरेशन (NG) विमान ने सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भरी। हंसा न्यू जनरेशन (NG) विमान: ● हंसा न्यू जनरेशन (NG) विमान सीएसआईआर-एनएएल द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया एक विमान है। ● ट्रेनर विमान स्मार्ट मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले, एक ग्लास कॉकपिट और बबल कैनोपी डिजाइन के साथ IFR-कंप्लेंट एवियोनिक्स से लैस है। ● सीएसआईआर-एनएएल ने पहले ही एक निजी भागीदार की पहचान कर ली है और श्रृंखला का उत्पादन जल्द ही शुरू हो जाएगा। NAL के बारे में ● राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाएं (NAL) भारत की पहली और सबसे बड़ी एयरोस्पेस फर्म है। ● इसकी स्थापना वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) द्वारा 1959 में दिल्ली में की गई थी और इसका मुख्यालय 1960 में बंगलूर में स्थानांतरित कर दिया गया था। ● यह देश के नागरिक क्षेत्र में एकमात्र सरकारी एयरोस्पेस अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है। ● यह फर्म HAL, DRDO और ISRO के साथ मिलकर काम करती है तथा भारत में नागरिक विमान विकसित करने की प्रमुख जिम्मेदारी है। ● CSIR-NAL का अधिदेश मजबूत विज्ञान सामग्री के साथ एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों को विकसित करना, छोटे और मध्यम आकार के नागरिक विमानों का डिजाइन और निर्माण करना तथा सभी राष्ट्रीय एयरोस्पेस कार्यक्रमों का समर्थन करना है।
निपाह वायरस	प्रसंग: तीन साल से अधिक के अंतराल के बाद केरल में जूनोटिक निपाह वायरस के संक्रमण का एक मामला सामने आया, जिसमें एक निजी अस्पताल में एक 12 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। निपाह वायरस के बारे में ● मनुष्यों के बीच निपाह वायरस का पहला प्रकोप मलेशिया (1998) और सिंगापुर (1999) से दर्ज किया गया था। ● इस वायरस का नाम मलेशिया के उस गांव से लिया गया है जहां जिस व्यक्ति में वायरस को सबसे पहले अलग किया गया था और और उसकी बीमारी से मृत्यु हो गई। ● यह एक जूनोटिक वायरस है, जिसका अर्थ है कि यह जानवरों से इंसानों में फैल गया है। ● फ्रूट बैट्स, जिसे आमतौर पर उड़ने वाली लोमड़ी के रूप में जाना जाता है, को वायरस का एक प्राकृतिक भंडार माना जाता है। फ्रूट बैट्स इस वायरस को अन्य जानवरों जैसे- सूअर, कुत्तों, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों और भेड़ों में भी फैलते हैं। ● मनुष्य मुख्य रूप से इन जानवरों के सीधे संपर्क में आने से संक्रमित हो जाते हैं। यह वायरस इन संक्रमित जानवरों के लार या मूत्र से दूषित भोजन के माध्यम से या सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है।

	● लक्षणों में तीव्र एन्सेफलाइटिस और श्वसन संबंधी बीमारियां शामिल हैं। ● निपाह वायरस SARS-CoV-2 की तुलना में कहीं अधिक धीरे-धीरे फैलने के लिए जाना जाता है। हालाँकि यह इसकी मारने की क्षमता है जो सबसे बड़ी चिंता है।
प्रेरणा 4	प्रसंग: स्पेसएक्स ने घोषणा की कि 'प्रेरणा 4', इसकी पहली सर्व-नागरिक, गैर-सरकारी अंतरिक्ष उड़ान, 15 सितंबर को लॉन्च होने की राह पर है। प्रेरणा 4 के बारे में ● इंस्पिरेशन 4 कक्षा में जाने वाला दुनिया का पहला सर्व-नागरिक मिशन है। ● उड़ान को स्पेसएक्स (यूएस प्राइवेट स्पेस कंपनी) द्वारा निजी तौर पर पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किए गए क्रू ड्रैगन कैप्सूल का उपयोग करके निजी तौर पर संचालित किया जाएगा। ● इंस्पिरेशन 4, 15 सितंबर को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। ● इस मिशन में तीन दिनों तक पृथ्वी का चक्कर लगाना और फिर अटलांटिक महासागर में गिरना शामिल है। ● इंस्पिरेशन 4 अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (408 किमी) और हबल स्पेस टेलीस्कोप (547 किमी) की तुलना में 575 किमी की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ● 2009 के बाद से, जब अंतरिक्ष यात्री पिछली बार हबल की मरम्मत के लिए गए थे, यह किसी कर्मीदल मिशन द्वारा तय की गई सबसे दूर की दूरी होगी। ● यह मिशन अमेरिका में सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल के लिए जागरूकता और धन जुटाएगा। क्या आप जानते हैं? ● स्पेसएक्स कंपनी का एक्स-1 मिशन, जिसे 2021 के अंत के लिए भी नियोजित किया गया है, चार निजी अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल की मेजबानी करता है, जो ISS की आठ-दिवसीय यात्रा के लिए प्रत्येक को \$55 मिलियन का भुगतान करता है। ● 2018 में, एलोन मस्क ने यह भी घोषणा की कि जापानी अरबपति युसाकु मेजावा स्पेसएक्स के नए रॉकेट सिस्टम स्टारशिप पर चंद्रमा के चारों ओर एक सवारी करेंगे, जो विकास के अधीन है। ● फाल्कन 9 एक पुनः प्रयोज्य, दो चरणों वाला रॉकेट है जिसे स्पेसएक्स द्वारा लोगों और पेलोड के विश्वसनीय तथा सुरक्षित परिवहन के लिए पृथ्वी की कक्षा और उससे आगे तक डिजाइन और निर्मित किया गया है।
सिम्बेक्स	सुर्खियों में: 2 से 4 सितंबर 2021 के मध्य भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास 'सिम्बेक्स (SIMBEX), 2021' का 28 वां संस्करण आयोजित किया गया। सिम्बेक्स के बारे में ● इसे वर्ष 1994 में प्रारंभ किया गया था। ● सिम्बेक्स, किसी भी विदेशी नौसेना के साथ, भारतीय नौसेना का सबसे लंबा चलने वाला निर्बाध द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों का महत्व ● चल रही महामारी की चुनौतियों के बावजूद इस महत्वपूर्ण जुड़ाव की निरंतरता को बनाए रखा। ● इस योजना के चरणों के दौरान इन बाधाओं के बावजूद, दोनों नौसेनाएं कई चुनौतीपूर्ण विकासों के निर्बाध और सुरक्षित निष्पादन को प्राप्त कर सकीं, जिसमें लाइव हथियार फायरिंग और उन्नत नौसैनिक युद्ध धारावाहिक शामिल हैं, जिनमें पनडुब्बी रोधी, हवा-विरोधी और सतह-विरोधी युद्ध अभ्यास शामिल हैं। ● अभ्यास का पैमाना और जटिलता दोनों नौसेनाओं के बीच हासिल की गई अंतःक्रियाशीलता का पर्याप्त प्रमाण है।
ई-आईएलपी प्लेटफॉर्म : मणिपुर	प्रसंग : हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक इनर लाइन परमिट (ILP) काउंटरो का शुभारंभ किया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ● इंफाल, जिरिबाम और माओ केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। ● इस पोर्टल के अंतर्गत राज्य के बाहर से कोई व्यक्ति e-ILP के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और

	ऑनसाइट सत्यापन के बाद जारी करने वाले केंद्रों से परमिट प्राप्त कर सकता है। ● e-ILP ट्रेकिंग प्रणाली को परमिट जारी करने और इसकी ट्रेकिंग प्रणाली में अपनाई गई प्रक्रियाओं में खामियों को दूर करने के लिए विकसित किया गया है। ● इसमें एक व्यापक डैशबोर्ड सिस्टम है जो सक्रिय रूप से जानकारी दिखाएगा जैसे कि किसी विशेष तिथि और समय पर राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या और विभिन्न प्रवेश द्वारों के माध्यम से आने वाले लोगों की ग्राफिकल ब्रेक-अप आधारित प्रस्तुति। ● यह सिस्टम उन लोगों की डिफॉल्ट सूची की स्वचालित पीढ़ी के साथ भी सक्षम है, जो परमिट के अनुसार अनुमत दिनों की संख्या से अधिक समय तक रहे हैं। ● ILP प्रणाली 1 जनवरी, 2020 को मणिपुर में लागू हुई। इनर लाइन परमिट सिस्टम क्या है? ● इनर लाइन परमिट (ILP) एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है, जिसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्यों में प्रवेश करने के लिये अन्य राज्यों के भारतीय नागरिकों के पास ILP होना आवश्यक है। ● यह पूर्णतः यात्रा के प्रयोजन से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ● वर्तमान में, संरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में स्थित हैं: ○ संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश ○ हिमाचल प्रदेश के हिस्से ○ जम्मू और कश्मीर के हिस्से ○ संपूर्ण मणिपुर ○ संपूर्ण मिजोरम ○ संपूर्ण नागालैंड ○ राजस्थान के हिस्से ○ संपूर्ण सिक्किम (आंशिक रूप से संरक्षित और आंशिक रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र में) ○ उत्तराखंड के हिस्से ● कोई भी व्यक्ति प्रत्येक छह महीने में अपने परमिट को नवीनीकृत करने का हकदार है यदि वह इन राज्यों में मूल निवासी नहीं है, और इसके बावजूद कि वह एक दीर्घकालिक निवासी है। ● यह भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास स्थित कुछ क्षेत्रों में आवाजाही को भी नियंत्रित करता है। ● यह ILP के संरक्षण में आने वाले संबंधित राज्यों द्वारा जारी किया जाता है।
ऑसिन्डेक्स	मुखियों में: भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास AUSINDEX का चौथा संस्करण 06 सितंबर, 2021 से शुरू हो गया है, AUSINDEX के बारे में ● 2015 में द्विपक्षीय IN-RAN समुद्री अभ्यास के रूप में शुरू हुआ, AUSINDEX पिछले कुछ वर्षों में जटिलता में बढ़ गया है। ○ और 2019 में बंगाल की खाड़ी में आयोजित अभ्यास के तीसरे संस्करण में पहली बार पनडुब्बी रोधी अभ्यास शामिल हैं। ● यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं को अंतर-संचालन को मजबूत करने, सर्वोत्तम प्रथाओं से लाभ उठाने और समुद्री सुरक्षा संचालन के लिए प्रक्रियाओं की एक सामान्य समझ विकसित करने का अवसर प्रदान करेगा। ● कोविड संबंधी प्रतिबंधों के बावजूद इस अभ्यास का आयोजन भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच मौजूदा तालमेल का प्रमाण है। ● यह अभ्यास दोनों देशों के बीच '2020 व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के साथ जुड़ा हुआ है और इसका उद्देश्य भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने वाली क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के प्रति साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। ● AUSINDEX के इस संस्करण में भाग लेने वाली नौसेनाओं के जहाजों, पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टरों और लंबी

	दूरी के समुद्री गश्ती विमानों के बीच जटिल सतह, उप-सतह और हवाई संचालन शामिल हैं। इसमें भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत (Kadmatt) क्रमशः नवीनतम स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट और एंटी-सबमरीन कार्वेट हैं।
कुपोषण दूर करने के लिए पोषण वाटिका	सुखियों में: कुपोषण उन्मूलन के लिए आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से 'पोषण वाटिका' (न्यूट्री गार्डन) के महत्व पर एक वेबिनार का आयोजन किया। पोषण वाटिका के बारे में - ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त जगह है और पोषक उद्यान/पोषण वाटिका स्थापित करना कहीं ज्यादा आसान है क्योंकि किसान परिवार कृषि से जुड़े होते हैं। - पोषण वाटिका के अंतर्गत पौषणिक और जड़ी-बूटियों के वृक्षारोपण से बाहरी निर्भरता कम होगी और समुदायों को उनकी पोषण सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। - आयुष मंत्रालय पोषण वाटिका की स्थापना के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए 3,000 आंगनवाड़ियों के साथ मिलकर काम करेगा और वहां लगाए जाने वाले पौष्टिक और औषधीय पौधे भी तय करेगा। - पोषण वाटिका में लगाने के लिए मोरिंगा (सहजन), अमरूद, केला और तुलसी जैसे पौधे पोषण वाटिका में लगाए जा सकते हैं क्योंकि ये महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करते हैं। पोषण वाटिका का महत्व - पोषण अभियान शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कुपोषण की समस्या का समाधान करना है। आंगनवाड़ी ऐसे 50 प्रतिशत लोगों को कवर करती है जो गरीब हैं और उन्हें उचित पोषण नहीं मिलता है, जबकि पोषण अभियान में बाकी 50 प्रतिशत लोगों को शामिल किया गया है जो गरीब नहीं हैं लेकिन उन्हें उचित पोषण के बारे में जानकारी चाहिए। - परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त फल और सब्जियों की निरंतर आपूर्ति के माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करके आहार विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जो घरेलू या सामुदायिक स्तर पर कुपोषण से निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा और विविधता प्रदान करने के लिए एक स्थायी मॉडल साबित हो सकता है।
सी-295 एयरक्राफ्ट डील	संदर्भ : सुरक्षा मामलों संबंधी समिति (CCS) ने एयरोस्पेस क्षेत्र में मेक-इन-इंडिया पहल के तहत भारतीय वायु सेना के लिये 56 सी-295 मेगावाट (56 C-295 MW) क्षमता वाले मध्यम परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है। 56 सी-295 एमडब्ल्यू (C-295 MW) विमान को एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एस.ए. स्पेन से खरीदा जाएगा। - यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अंतर्गत भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा और इसकी लागत करीब 3 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य 56 सी-295 एमडब्ल्यू समकालीन तकनीक के साथ 5-10 टन क्षमता का परिवहन विमान है। इसमें तेजी से प्रतिक्रिया और सैनिकों एवं कार्गो की पैरा ड्रॉपिंग के लिये एक रियर रैंप (Rear Ramp Door) है। - परिवहन विमान धीरे-धीरे भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो बेड़े की जगह लेगा। IAF के पास 1960 के दशक में 56 एवरोस खरीदे गए थे और उन्हें तत्काल बदलने की आवश्यकता है। - सभी 56 विमानों को स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के साथ स्थापित किया जाएगा। - यह परियोजना भारत में एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगी जिसमें देश भर में फैले कई MSMEs विमान के कुछ हिस्सों के निर्माण में शामिल होंगे। - यह कार्यक्रम "आत्मनिर्भर भारत" के अनुरूप है और घरेलू विमानन निर्माण को बढ़ावा देगा जिसके परिणामस्वरूप आयात पर निर्भरता कम होगी और निर्यात में अपेक्षित वृद्धि होगी। - इस कार्यक्रम से एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र में रोजगार सृजन भी होगा।
नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड	संदर्भ : भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा जल्द ही राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (National Intelligence Grid-NATGRID) का शुभारंभ किए जाने की उम्मीद है। इसका लक्ष्य भारत की आतंकवाद-रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदान करना है।

	● महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस का अंतिम परीक्षण किया जा रहा है, ताकि इसे शुरू किया जा सके। नेटग्रिड क्या है? ● नेटग्रिड एक ऑनलाइन डेटाबेस है जो दूरसंचार, कर रिकॉर्ड, बैंक, आप्रवास आदि के क्षेत्र में 20 से अधिक संगठनों से सूचना के बिखरे हुए टुकड़ों को एकत्रित करने के लिए खुफिया जानकारी उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। ● NATGRID आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिये एक कार्यक्रम है ● 26/11 के बाद इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर NATGRID की स्थापना की गई। ● इस हमले का मास्टरमाइंड डेविड हेडली वर्ष 2006 से 2009 के बीच हमले की योजनाओं को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु कई बार भारत आया लेकिन उसके आवागमन की किसी भी सूचना का विश्लेषण नहीं किया जा सका। ● NATGRID विभिन्न खुफिया और प्रवर्तन एजेंसियों के डेटा का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए बिग डेटा और एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करेगा ● कम से कम 10 केंद्रीय एजेंसियों जैसे आईबी, राँ और अन्य के पास आतंकवाद विरोधी जांच के लिए डेटा तक पहुंच होगी। ● यह समझौता NATGRID को 'अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम' (Crime and Criminal Tracking Network and Systems- CCTNS) के माध्यम से डेटाबेस/सूचना तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ऐसा मंच है जो लगभग 14,000 पुलिस स्टेशनों को आपस में जोड़ता है। ● एनसीटीसी या एनआईए के विपरीत, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, नेटग्रिड अनिवार्य रूप से एक उपकरण है जो सुरक्षा एजेंसियों को देश में विभिन्न संगठनों और सेवाओं के एकत्रित डेटा सेट से आतंकवादी संदिग्धों पर प्रासंगिक जानकारी का पता लगाने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ● यह आतंकवादियों की पहचान करने, उन्हें पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने में मदद करेगा और आतंकी साजिशों को रोकने में मदद करेगा। ○ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र (एनसीटीसी) 2008 के मुंबई हमलों के बाद स्थापित दो संगठन हैं। ● NATGRID के लिए डेटा रिकवरी सेंटर बेंगलुरु में है। ● NATGRID खुफिया और जांच एजेंसियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा। क्या आप जानते हैं? ● नेटग्रिड को धारा 24 की उप-धारा (2) के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से छूट प्राप्त है। ● इस परियोजना को 31 दिसंबर 2020 तक लाइव होना था, लेकिन COVID-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था।
चंद्रयान-2	प्रसंग: चंद्रयान -2 मिशन के ऑर्बिटर और अन्य उपकरणों ने दो वर्षों में, नई जानकारी का खजाना इकट्ठा किया है जिसने चंद्रमा और उसके पर्यावरण के बारे में हमारे ज्ञान को जोड़ा है। चंद्रयान-2 का क्या हुआ? ● चंद्रयान -2, चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन, चंद्र सतह पर सॉफ्ट-लैंडिंग करने में विफल रहा था। ● लैंडर और रोवर अंतिम क्षणों में खराब होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। यह मिशन अभी भी प्रासंगिक क्यों है? ● विफलता के बावजूद, मिशन का ऑर्बिटर और अन्य भाग सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और जानकारी एकत्र कर रहे हैं। ● हाल ही में, इसरो ने अब तक वैज्ञानिक पेलोड द्वारा एकत्र की गई जानकारी जारी की, जिनमें से कुछ का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाना बाकी था। चंद्रयान-2 से जुटाई अहम जानकारियां ● चंद्रमा पर पानी के अणुओं की उपस्थिति जो पानी के बारे में अब तक की सबसे सटीक जानकारी है।

	● सूक्ष्म तत्वों की उपस्थिति: क्रोमियम, मैंगनीज और सोडियम का पहली बार सुदूर संवेदन के माध्यम से पता लगाया गया है। ● सोलर फ्लेयर्स के बारे में जानकारी: सक्रिय क्षेत्र के बाहर बड़ी संख्या में माइक्रोफ्लेयर पहली बार देखे गए हैं। यह सौर कोरोना को गर्म करने के पीछे के तंत्र को समझने में मदद करेगा। चंद्रयान-2 मिशन के बारे में अधिक जानकारी ● वैज्ञानिकों ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए सितंबर 2019 में चंद्रयान-2 पर सोलर एक्स-रे मॉनिटर (XSM) का इस्तेमाल किया। ● चंद्रयान 2 का प्राथमिक उद्देश्य: चंद्र सतह पर सॉफ्ट-लैंड करने की क्षमता प्रदर्शित करना और सतह पर रोबोटिक रोवर संचालित करना। ● मिशन में चंद्रमा का एक ऑर्बिटर, विक्रम (विक्रम साराभाई के बाद) - लैंडर और प्रज्ञान (ज्ञान) - रोवर शामिल थे, सभी चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों से लैस थे।
सेलाइन गार्गल आरटी-पीसीआर तकनीक	सुर्खियों में: COVID-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक उल्लेखनीय कदम में, नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) ने COVID-19 नमूनों के परीक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली स्वदेशी रूप से विकसित सलाइन गार्गल RT-PCR तकनीक की जानकारी को स्थानांतरित कर दिया है। ● सेलाइन गार्गल आरटी-पीसीआर तकनीक सरल, तेज, किफायती, रोगी के अनुकूल और आरामदायक है। ● सलाइन गार्गल से टेस्ट के नतीजे तत्काल आते हैं। ● यह ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसके लिए न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। ● इससे इस नई तकनीक के व्यावसायीकरण और निजी, सरकारी और सहित सभी सक्षम पार्टियों को इसके उत्पादन का लाइसेंस प्राप्त करने में मदद मिलेगी। लाइसेंसधारकों से कहा गया है कि वे इस तकनीक का आसानी से इस्तेमाल करने के लिए कॉम्पैक्ट किट के रूप में व्यावसायिक उत्पादन की सुविधाएं स्थापित करें। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सलाइन गार्गल आरटी पीसीआर टेस्ट से महामारी के परीक्षण की सस्ती व सुलभ तकनीक से जल्दी जांच हो सकेगी।
भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता	सुर्खियों में: भारत सरकार ने द्विवार्षिक DefExpo सैन्य प्रदर्शनी के मौके पर आयोजित होने वाले एक नियमित कार्यक्रम के रूप में भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता को संस्थागत बनाने का प्रस्ताव दिया है। ● भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता के नियमितीकरण से अफ्रीकी देशों और भारत के बीच मौजूदा साझेदारी को और मजबूत करने में मदद मिलेगी और क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों सहित आपसी जुड़ाव के लिए अभिसरण के नए क्षेत्रों का पता लगाने में मदद मिलेगी। ● नई दिल्ली में मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस (Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses) दोनों देशों के बीच बढ़े हुए रक्षा सहयोग के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने में सहायता करने के लिए भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का ज्ञान भागीदार होगा। ● पृष्ठभूमि: भारत और अफ्रीका के बीच घनिष्ठ और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत-अफ्रीका रक्षा संबंधों की नींव 'सागर', क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास' और 'वसुधैव कुटुम्बकम्', द वर्ल्ड इज वन फैमिली जैसे दो मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित है। ● नोट: 'लखनऊ घोषणा': भारत और अफ्रीका के बीच एक संयुक्त घोषणा को पहली बार भारत-अफ्रीका रक्षा मंत्री सम्मेलन (IADMC) के समापन के बाद अपनाया गया था।
शांतिपूर्ण अभ्यास 2021 मिशन	संदर्भ: हाल ही में भारतीय सेना ने SCO अभ्यास 'शांतिपूर्ण मिशन' 2021 में भाग लिया। शांतिपूर्ण मिशन के बारे में ● संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन एक बहुपक्षीय अभ्यास है, जो शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों के बीच सैन्य कूटनीति के हिस्से के रूप में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। ● एससीओ सदस्य देशों के मध्य घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना एवं सैन्य नेतृत्वों के मध्य की बहु-राष्ट्रीय सैन्य टुकड़ियों को कमान देने की क्षमता को बढ़ाना। ● द्वारा होस्ट किया गया: रूस द्वारा दक्षिण-पश्चिम रूस के ऑरेनबर्ग (Orenburg) क्षेत्र में 13 से 25 सितंबर,

	2021 तक आयोजित किया जा रहा है। 2021 में, द्विवार्षिक बहुपक्षीय अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन का छठा संस्करण शुरू किया जा रहा है। ● दो आईएल-76 विमानों द्वारा एक भारतीय दल को अभ्यास क्षेत्र में शामिल किया गया था। ● अभ्यास के दायरे में पेशेवर बातचीत, अभ्यास और प्रक्रियाओं की आपसी समझ, संयुक्त कमान और नियंत्रण संरचनाओं की स्थापना और आतंकवादी खतरों का उन्मूलन शामिल है।
रेक्स एमकेआईआई	प्रसंग: हाल ही में इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) ने एक रिमोट-नियंत्रित सशस्त्र रोबोट REX MKII का अनावरण किया है। रेक्स एमकेआईआई के बारे में ● यह रोबोट युद्ध क्षेत्रों में गश्त करने, घुसपैठियों पर नज़र रखने और दुश्मन के ठिकानों पर गोलियां चलाने में सक्षम है। ● यह एक इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट द्वारा संचालित होता है और इसे दो मशीनगनों, कैमरों और सेंसर से लैस किया जाता है। ● यह गोला-बारूद की आपूर्ति, महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण, पानी और भोजन के साथ-साथ स्ट्रेचर पर घायल कर्मियों को निकालने के द्वारा सैनिकों को लिगिस्टिक्स सहायता प्रदान करेगा। ● यह सिस्टम स्थिति-जागरूकता प्रणाली के माध्यम से भी खुफिया जानकारी एकत्र कर सकता है। ● मानवरहित वाहन ड्रोन प्रौद्योगिकी की दुनिया में नवीनतम जोड़ है, जो आधुनिक युद्धक्षेत्र को तेजी से नया आकार दे रहा है। ● ये अर्ध-स्वायत्त मशीनें सेनाओं को अपने सैनिकों की रक्षा करने की अनुमति देती हैं, जबकि आलोचकों को डर है कि यह जीवन या मृत्यु के निर्णय लेने वाले रोबोटों की ओर एक और खतरनाक कदम है।
हेलिना मिसाइल	संदर्भ : हेलिना (नाग पर आधारित हेलीकॉप्टर) एक तीसरी पीढ़ी की 'दागो और भूल जाओ' टैंक रोधी मिसाइल (ATGM)) प्रणाली है, जिसे आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) पर स्थापित किया गया है। हेलिना के बारे में ● हेलिना तीसरी पीढ़ी की, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च (एलओबीएल) फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) प्रणाली है। ● यह प्रणाली, सभी मौसम में दिन और रात के समय सक्षम है तथा पारंपरिक कवच के साथ ही साथ विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच के साथ युद्धक टैंकों को नष्ट कर सकती है। ● हेलिना मिसाइल सीधे हिट मोड के साथ ही साथ टॉप अटैक मोड दोनों में टार्गेट्स पर निशाना लगा सकती है। नाग मिसाइल के बारे में ● भारत ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा बनाई गई नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। ● यह दिन और रात की क्षमताओं के साथ और न्यूनतम 500 मीटर और अधिकतम 4 किमी की सीमा के साथ एक सभी मौसम की स्थिति है। ● नाग को जमीन और हवा आधारित प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है। भूमि संस्करण वर्तमान में नाग मिसाइल वाहक (NAMICA) पर एकीकरण के लिए उपलब्ध है। ● DRDO ने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नाग मिसाइल विकसित की है। इस कार्यक्रम के तहत विकसित पांच मिसाइलें (P-A-T-N-A) हैं: ○ पृथ्वी: कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। ○ अग्नि: विभिन्न रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें, अर्थात अग्नि (I, II, III, IV, V)। ○ त्रिशूल: कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। ○ नाग: तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइल। ○ आकाश: मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल।

प्लैनेट नाइन पर नया अध्ययन	भाग: प्रारंभिक और जीएस III - अंतरिक्ष में जागरूकता संदर्भ: हमारे सौर मंडल में काल्पनिक नौवें ग्रह की निरंतर खोज में, माइकल ब्राउन, खगोलविद, जिन्होंने 2006 में प्लूटो को एक बौने ग्रह के रूप में स्थानांतरित कर दिया था, ने एक नए अध्ययन का सह-लेखन किया है जो इस क्षेत्र को संभावित रूप से सीमित करने का दावा करता है। नया ग्रह स्थित हो सकता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ● अध्ययन का प्रस्ताव है कि "प्लैनेट नाइन" नेपच्यून से परे मौजूद है और पृथ्वी के द्रव्यमान का छह गुना है। ● नए अध्ययन में ग्रह की संभावित कक्षा का "खजाने का नक्शा" भी शामिल है, जो वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह लगभग 7,400 पृथ्वी वर्षों तक रहता है और 2016 के अध्ययन की तुलना में सूर्य के करीब है। ● सूर्य की नजदीकी कक्षा ग्रह को उज्ज्वल और देखने में आसान बना देगी। ● प्लैनेट नाइन शायद नेपच्यून की तरह एक ठंडी गैस का विशालकाय ग्रह होगा, जो सूर्य से सौर मंडल का सबसे दूर ज्ञात ग्रह है। ● नासा के अनुसार, नेपच्यून की सतह ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बनी है।
भारत जल्द शुरू करेगा कोरोना वैक्सीन का निर्यात	संदर्भ : इंडिया COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access) के प्रति प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अपने 'वैक्सीन मैत्री' कार्यक्रम के तहत COVID-19 टीकों के निर्यात को फिर से शुरू करेगा। COVAX (COVID-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस) क्या है? ● COVAX कार्यक्रम का नेतृत्व यूनिसेफ, वैक्सीन निर्माताओं और विश्व बैंक के साथ साझेदारी में वैक्सीन गठबंधन GAVI, WHO और गठबंधन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन (CEPI) द्वारा किया जाता है। ● उद्देश्य: विश्व स्तर पर COVID-19 टीकों का समान वितरण सुनिश्चित करना। ● यह इतिहास में सबसे बड़ा वैक्सीन खरीद और आपूर्ति संचालन माना जाता है। ● कार्यक्रम 92 एडवांस मार्केट कमिटमेंट (AMC) देशों में लगभग 20 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण करना चाहता है, जिसमें मध्यम और निम्न-आय वाले देश शामिल हैं जो COVID-19 टीकों के लिए भुगतान नहीं कर सकते हैं। ● 4000 अमेरिकी डॉलर से कम प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) वाले देशों और विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) के अंतर्गत पात्र कुछ अन्य देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। Gavi, Vaccine Alliance क्या है? ● इसे 2000 में बनाया गया था। ● Gavi एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है - एक वैश्विक वैक्सीन एलायंस, जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में रहने वाले बच्चों के लिए नए और कम इस्तेमाल किए गए टीकों तक समान पहुंच बनाने के साझा लक्ष्य के साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को एक साथ लाता है। ● इसके मुख्य भागीदारों में डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन शामिल हैं।
'समुद्र शक्ति' अभ्यास	सुखियों में: भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना ने 'समुद्र शक्ति' अभ्यास में भाग लिया। ● द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए। ● दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री संचालन में आपसी समझ और अंतरसंचालनीयता बढ़ाना। ● सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और समुद्री सुरक्षा संचालन की एक सामान्य समझ विकसित करने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करना। नोट : सुंडा जलडमरूमध्य- जावा और सुमात्रा के इंडोनेशियाई द्वीपों के बीच जलडमरूमध्य। यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है।
व्यायाम सूर्य किरण	खबरों में: भारत-नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण पिथौरागढ़ (यूके) में शुरू हुआ। ● भारतीय और नेपाली सेना की एक-एक इन्फैंट्री बटालियन इंटर-ऑपरेबिलिटी विकसित करने और आतंकवाद विरोधी अभियानों तथा आपदा राहत कार्यों के अपने अनुभव को साझा करने के लिए एक साथ प्रशिक्षण देगी।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (Global)	● विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization - WIPO) द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (Global Innovation Index) 2021 में भारत को 46वें स्थान पर रखा गया है। भारत

Innovation Index) 2021	पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर चढ़ गया है। - पिछले कुछ वर्षों में देश की रैंक लगातार बढ़ रही है। 2015 में 81 से, यह 2021 में 46 हो गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII): - GII वैश्विक नवाचार की स्थिति पर नया डेटा और विश्लेषण प्रदान करता है, और पाठकों और नीति निर्माताओं को 130 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के प्रदर्शन को बेंचमार्क करने की अनुमति देता है। - जीआईआई रैंकिंग में लगातार सुधार विशाल ज्ञान पूंजी, स्टार्ट-अप और सार्वजनिक और निजी अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए अद्भुत काम के कारण था। - परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और अंतरिक्ष विभाग जैसे वैज्ञानिक विंग ने राष्ट्रीय नोवशन इकोसिस्टम को समृद्ध करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।"
डार्क एनर्जी	संदर्भ : हाल ही में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पहली बार डार्क एनर्जी का प्रत्यक्ष रूप से पता लगाया है। XENON1T प्रयोग और प्रमुख निष्कर्ष - XENON1T एक डार्क मैटर रिसर्च प्रोजेक्ट है, जो इटैलियन ग्रेन सासो नेशनल लेबोरेटरी में संचालित (Italian Gran Sasso National Laboratory) है। यह एक गहरी भूमिगत अनुसंधान सुविधा है जिसकी विशेषता प्रयोगों द्वारा तीव्रता के साथ महत्वाकांक्षी डार्क मैटर कणों का पता लगाना है। - खोज से यह भी पता चलता है कि XENON1T जैसे प्रयोग, जिन्हें डार्क मैटर का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, का उपयोग डार्क एनर्जी का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। डार्क एनर्जी क्या है? - डार्क एनर्जी ऊर्जा का एक अज्ञात रूप है जो ब्रह्मांड को सबसे बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। - इसके अस्तित्व का पहला प्रेक्षणात्मक प्रमाण सुपरनोवा के मापन से प्राप्त हुआ, जिससे पता चला कि ब्रह्मांड एक स्थिर दर से विस्तार नहीं करता है, बल्कि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। डार्क मैटर क्या है? - सबसे पहले, यह अंधेरा है, जिसका अर्थ है कि यह सितारों और ग्रहों के रूप में नहीं है जो हम देखते हैं। - प्रेक्षणों से पता चलता है कि ब्रह्मांड में प्रेक्षणों के लिए आवश्यक 27% को बनाने के लिए बहुत कम दृश्यमान पदार्थ है। - दूसरा, यह सामान्य पदार्थ के काले बादलों के रूप में नहीं होता है, यह पदार्थ बेरियोन नामक कणों से बना होता है। - तीसरा, डार्क मैटर एंटीमैटर नहीं है, क्योंकि हम उस अद्वितीय गामा किरणों को नहीं देखते हैं जो तब उत्पन्न होती हैं जब एंटीमैटर पदार्थ के साथ समाप्त हो जाता है। - डार्क मैटर आकाशगंगाओं को एक साथ आकर्षित (Attracts) और धारण (Holds) करता है, जबकि डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड के विस्तार का कारण बनती है। क्या डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों एक ही हैं? - ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी है। - जबकि डार्क मैटर आकाशगंगाओं को एक साथ आकर्षित कर धारण करता है, डार्क एनर्जी पीछे हटती है और ब्रह्मांड के विस्तार का कारण बनती है। - दोनों घटकों के अदृश्य होने के बावजूद डार्क मैटर के बारे में बहुत कुछ ज्ञात है, क्योंकि 1920 के दशक में डार्क मैटर के अस्तित्व के बारे में बताया गया, जबकि 1998 तक डार्क एनर्जी की खोज नहीं की गई थी।
भारत-अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता 2021	ख़बरों में: दो दिवसीय संवाद दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में चल रहे कई सहयोगों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में लाभान्वित हुआ। दो दिवसीय संवाद के दौरान महामारी विज्ञान अनुसंधान और निगरानी, वैक्सीन विकास, स्वास्थ्य, जूनोटिक और वेक्टर जनित रोगों, स्वास्थ्य प्रणालियों और स्वास्थ्य नीतियों आदि को मजबूत करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

	● स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को शामिल करते हुए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। बचाव और सुरक्षा; संचारी रोग और गैर संचारी रोग; स्वास्थ्य प्रणाली; और स्वास्थ्य नीति। ● वैश्विक स्वास्थ्य खतरों की अग्रिम वैज्ञानिक खोज और प्रबंधन में सहायता के लिए अच्छी तरह से डिजाइन और मान्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण और देशों के बीच सहयोग पर निर्भर संक्रामक रोगों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए इन उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ● सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को एक साथ काम करना चाहिए और नवाचारों के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों की असमानताओं से लड़ने में अपनी ताकत को मिलाना चाहिए।
रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC)	संदर्भ: रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 13,165 करोड़ रुपये मूल्य के प्रस्तावों को मंजूरी दी ● प्रमुख प्रस्तावों में हेलीकॉप्टर, निर्देशित युद्ध सामग्री और रॉकेट गोला बारूद शामिल हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद क्या है? ● रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) तीन सेवाओं (सेना, नौसेना और वायु सेना) और भारतीय तटरक्षक बल के लिए नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेने के लिए रक्षा मंत्रालय में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। ● रक्षा मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ● कारगिल युद्ध (1999) के बाद 2001 में 'राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार' पर मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के बाद इसका गठन किया गया था।
हाइपरसोनिक मिसाइल	प्रसंग : उत्तर कोरिया ने एक नई हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है? ● हाइपरसोनिक को ध्वनि की गति से कम से कम पांच गुना गति से यात्रा करने में सक्षम होने के रूप में परिभाषित किया गया है - मच 5, या प्रति घंटे 6,100 किलोमीटर (3,800 मील) से अधिक। ● वे मध्य-उड़ान में भी पैंतरेबाजी कर सकते हैं, जिससे उन्हें पारंपरिक प्रक्षेप्यों की तुलना में ट्रैक करना और अवरोधन करना अधिक कठिन हो जाता है। ● उड़ान के समय में कटौती करके, वे प्रतिक्रिया देने के अवसर को भी कम कर देते हैं। ● डिजाइन के आधार पर, वे केवल परमाणु आयुध या पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम हो सकते हैं, और रणनीतिक संतुलन को बदलने की क्षमता रखते हैं। कौन से देश के पास हैं? ● रूस, अमेरिका और चीन ● रूस को आम तौर पर अब तक प्रौद्योगिकी में विश्व नेता के रूप में देखा जाता है, जो नए हाइपरसोनिक हथियारों की एक श्रृंखला विकसित कर रहा है ● जुलाई में इसने जिरकोन (Zircon) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो एक जहाज से प्रक्षेपित हाइपरसोनिक मिसाइल है जो ध्वनि की गति से सात गुना अधिक गति से यात्रा करती है। ● इसके शस्त्रागार में पहले से ही अवांगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन और हवा से प्रक्षेपित किंगजल (Dagger) मिसाइलें हैं।
केरल में चमगादड़ के नमूनों में मिले निपाह एंटीबॉडी	संदर्भ : नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) पुणे के इकट्ठे किए गए चमगादड़ों के सैंपल्स में निपाह वायरस एंटीबॉडी (IgG एंटीबॉडी) का पता लगा है। कोझीकोड जिले के कोडियाथूर और थमारसेरी से ये नमूने लिए गए, यहां पिछले महीने निपाह वायरस का प्रकोप देखा गया था। निपाह के प्रकोप में बाद एनआईवी पुणे ने ये सैंपल इकट्ठे किए थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ● थमारसेरी से एकत्र किए गए टेरोपस प्रजाति से संबंधित एक नमूने में निपाह एंटीबॉडी पाए गए, जबकि कोडियाथूर से एकत्र किए गए रूसेटस प्रजाति के एक अन्य नमूने में इसका पता चला था। ● वर्तमान प्रमाणों को देखते हुए, यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत होगा कि कोझीकोड में निपाह का प्रकोप चमगादड़ से उत्पन्न हुआ था, भले ही चमगादड़ से मनुष्यों में वायरस के संचरण का मार्ग अभी भी अज्ञात है।

	● इस बीच, 4 सितंबर को कोझीकोड में निपाह का अकेला मामला सामने आने के बाद से राज्य में 21 दिनों के बाद तक निपाह का कोई नया मामला सामने नहीं आया। ● अगले 21 दिन तक अगर निपाह का कोई नया मामला सामने नहीं आता है तो ये घोषित करना सुरक्षित होगा कि प्रकोप पूरी तरह से नियंत्रण में है। निपाह क्या है? ● यह एक जूनोटिक वायरस है, जिसका अर्थ है कि यह जानवरों से इंसानों में फैल गया है। ● फ्रूट बैट्स, जिसे आमतौर पर उड़ने वाली लोमड़ी के रूप में जाना जाता है, को वायरस का एक प्राकृतिक भंडार माना जाता है। ● संचरण: मनुष्य मुख्य रूप से इन जानवरों के सीधे संपर्क में आने से संक्रमित हो जाते हैं। वायरस इन संक्रमित जानवरों के लार या मूत्र से दूषित भोजन के माध्यम से या सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है। ● लक्षणों में तीव्र एन्सेफलाइटिस और श्वसन संबंधी बीमारियां शामिल हैं। ● निपाह वायरस SARS-CoV-2 की तुलना में कहीं अधिक धीरे-धीरे फैलने के लिए जाना जाता है। हालाँकि, यह इसकी मारने की क्षमता है जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है।
जांच से पता चलता है कि पटाखों में जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल होता है	संदर्भ : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु सहित पटाखा उद्योग में CBI द्वारा प्रारंभिक जांच में बेरियम और इसके लवण जैसे जहरीले तत्वों के उपयोग पर प्रतिबंध के बड़े पैमाने पर उल्लंघन का पता चला है। पृष्ठभूमि ● मार्च 2020 में एक आदेश में, अदालत ने चेन्नई में सीबीआई के संयुक्त निदेशक को "विस्तृत" जांच करने का आदेश दिया। ● सीबीआई को 2018 में अदालती प्रतिबंध के उल्लंघन के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था। जांच के प्रमुख निष्कर्ष ● तैयार और अर्ध-निर्मित पटाखों के नमूनों और निर्माताओं से लिए गए कच्चे माल के रासायनिक विश्लेषण में बेरियम की मात्रा दिखाई दी। ● कोर्ट ने कहा कि बेरियम की अस्पष्ट मात्रा बाजार से खरीदी गई थी। ● पटाखों के कवरों में निर्माण या समाप्ति तिथि नहीं दिखाई गई थी। बेरियम क्या है? ● बेरियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 56 है। ● यह एक सॉफ्ट, चांदी जैसी क्षारीय पृथ्वी धातु है। ● इसकी उच्च रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण, बेरियम प्रकृति में कभी भी एक मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है। ● अनुप्रयोग: ○ उच्च तापमान वाले सुपरकंडक्टर्स और इलेक्ट्रोसेरेमिक्स के एक घटक के रूप में। ○ कार्बन ग्रेन्स के आकार को कम करने के लिए स्टील और कच्चा लोहा में जोड़ा गया। ○ ग्रीन कलर देने के लिए पटाके में जोड़ा गया। ○ मानव जठरांत्र संबंधी मार्ग की इमेजिंग के लिए एक्स-रे रेडियोकॉन्ट्रास्ट एजेंटों के रूप में। ○ कृतकनाशकों के रूप में। ● हानिकारक प्रभाव: ○ घुलनशील बेरियम यौगिक जहरीले होते हैं। ○ अधिक मात्रा में, वे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिससे हृदय संबंधी अनियमितताएं, कंपकंपी, कमजोरी, चिंता आदि होती हैं। ○ हालांकि, बेरियम कार्सिनोजेनिक नहीं है और बायोकेम्युलेट नहीं करता है।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन	संदर्भ: हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (Ayushman Bharat Digital Mission) की शुरुआत की।

	● आयुष्मान भारत, भारत की एक प्रमुख योजना है जिसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार शुरू किया गया था। इस मिशन को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) के रूप में भी जाना जाता है। ● नागरिकों की सहमति से देशांतरीय स्वास्थ्य अभिलेखों तक पहुंच और विनिमय को सक्षम बनाना। ● भुगतान प्रणाली में आए क्रांतिकारी बदलाव में यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) द्वारा निभाई गई भूमिका के समान डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करने में साहयक। महत्वपूर्ण भाग ● स्वास्थ्य आईडी: यह प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया जाएगा जो उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में भी काम करेगा। इस स्वास्थ्य खाते में हर परीक्षण, हर बीमारी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, ली गई दवाओं और निदान का विवरण होगा। ● स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ और पेशेवर रजिस्ट्री: ○ कार्यक्रम के अन्य प्रमुख घटकों- हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (HPR) और हेल्थकेयर फैसिलिटीज रजिस्ट्री (HFR) को निर्मित किया गया है, जिससे मेडिकल प्रोफेशनल्स और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तक आसान इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस की अनुमति मिलती है। ○ HPR चिकित्सा की आधुनिक और पारंपरिक दोनों प्रणालियों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले सभी स्वास्थ्य पेशेवरों का एक व्यापक डिजिटल भंडार होगा।
--	--

अंतरराष्ट्रीय संबंध

आईएलओ (ILO)	संदर्भ : हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की 'वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22' से पता चला है कि वैश्विक स्तर पर 4.1 बिलियन लोगों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। ● दुनिया में आधे से अधिक लोगों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, ● सामाजिक सुरक्षा में विशेष रूप से वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता, काम में चोट, मातृत्व या परिवार में मुख्य कमाने वाले की हानि से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल और आय सुरक्षा उपायों तक पहुंच के साथ-साथ बच्चों वाले परिवारों के लिए अतिरिक्त सहायता शामिल है। ● रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में वैश्विक आबादी के केवल 46.9% (सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले) लोगों को एक ही प्रकार की सुरक्षा का लाभ प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में ● ILO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है। यह 187 सदस्य राज्यों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को श्रम मानकों को स्थापित करने, नीतियों को विकसित करने तथा सभी महिलाओं एवं पुरुषों के लिये अच्छे काम को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु एक साथ लाती है। ● 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। ● 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली संबद्ध विशिष्ट एजेंसी बनी। ● मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड ● संस्थापक मिशन: सार्वभौमिक और स्थायी शांति के लिए सामाजिक न्याय आवश्यक है। ● अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देता है।
--------------------	--

रूस के साथ रसद समझौता	संदर्भ: भारत जल्द ही रूस के साथ द्विपक्षीय रसद समझौते को समाप्त करने के लिए तैयार है, जबकि यूके के साथ समझौता समापन के अंतिम चरण में है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य - लॉजिस्टिक्स के पारस्परिक आदान-प्रदान समझौते (RELOS) पर भारत द्वारा अगले दो महीनों में हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। - समझौता एक प्रशासनिक व्यवस्था है जो ईंधन के आदान-प्रदान और आपसी समझौते के प्रावधानों के लिए सैन्य सुविधाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है। - यह सहयोग लॉजिस्टिक सहायता को सरल करता है और भारत से दूर संचालन करते समय सेना के संचालन में बदलाव को बढ़ाता है। - भारत ने सभी क्वाड देशों, फ्रांस, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के साथ समान रसद समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी शुरुआत 2016 में यू.एस. के साथ LEMOA से हुई थी। LEMOA के बारे में: लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट - लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) पर भारत ने वर्ष 2016 में हस्ताक्षर किये थे। - यह समझौता भारत एवं अमेरिकी सेनाओं की एक-दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुंच को आसान बनाता है लेकिन यह इसे स्वचालित या अनिवार्य नहीं बनाता है। - यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं को मुख्य रूप से चार क्षेत्रों जैसे - पोर्ट कॉल, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत में सुविधाएं प्रदान करता है। - LEMOA का सबसे बड़ा लाभार्थी भारतीय नौसेना है, जो विदेशी नौसेनाओं के साथ सबसे ज्यादा सूचना का आदान-प्रदान और अभ्यास करती है। - सीधे शब्दों में कहें तो, यह एक दोस्त के गैरेज और वर्कशॉप में जाकर अपनी कार में ईंधन भरने और मरम्मत करवाने जैसा है। लेकिन, ऐसा करके व्यक्ति अपनी कार और तकनीक को मित्र के सामने उजागर कर रहा है, और इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। - यदि LEMOA पर हस्ताक्षर करने के लिए विश्वास की आवश्यकता है, तो इसका आवेदन विश्वास को बढ़ाता है। LEMOA पर बातचीत करने में लगभग एक दशक का समय लगा।
सीएससी और पासपोर्ट सेवाएं	संदर्भ: हाल ही में सामान्य सेवा केंद्रों/कॉमन सर्विस सेंटर (Common Services Centres-CSC) को ग्रामीण क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा केंद्र कियोस्क (Passport Seva Kendra kiosks) के प्रबंधन और संचालन की मंजूरी प्राप्त हुई है। महत्वपूर्ण तथ्य - CSC का संचालन करने वाले ग्राम-स्तरीय उद्यमियों (VLEs) को पासपोर्ट प्रक्रिया के साथ-साथ प्रारंभिक गैर-पुलिस सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज, फोटो और अन्य विवरण एकत्र करने का काम सौंपा जाएगा। - इसके लिए 100 रुपये तक का मामूली शुल्क लिया जाता है। - कार्यक्रम के लिए पायलट हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ सीएससी में शुरू किया गया था। - पूर्ण सेवाओं को जल्द ही पूरे देश में शुरू किया जाएगा। CSC क्या है? - यह इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) की एक पहल है। - CSC भारत सरकार की ई-सेवाओं को ग्रामीण और दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने के लिए भौतिक सुविधाएं हैं जहां कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता नगण्य थी या अधिकतर अनुपस्थित थी। - वे एक भौगोलिक स्थान पर एकाधिक लेनदेन के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए बहु-सेवा-एकल-बिंदु मॉडल हैं। - CSC का वर्तमान कार्य - वर्तमान में, CSC को केवल दूसरों के लिए आवेदन पत्र भरने और अपलोड करने की अनुमति है, एक आवेदक की ओर से एक लागू शुल्क का भुगतान करें, और उनके लिए एक नियुक्ति निर्धारित करें। - पिछले तीन वर्षों में इसने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में, पूरे देश में अपनी उपस्थिति का लाभ उठाकर,

	भागीदारों के साथ करार किया है। ● उन्होंने घरेलू और बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ-साथ टाटा, पेप्सिको, यूनीबिक फूड्स आदि के साथ संबंध स्थापित किया है। ● लॉकडाउन के दौरान, VLEs ने गांवों, ग्राम पंचायतों और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं की आसान डिलीवरी के लिए ग्रामीण ई-स्टोर भी खोला।
यूई का ग्रीन वीजा	संदर्भ: संयुक्त अरब अमीरात ने देश में नए 'ग्रीन वीजा' सिस्टम का ऐलान किया है। अब इसके जरिए कंपनी की तरफ से स्पांसर किए बगैर कामगारों को वीजा के लिए आवेदन जमा करने का इजाजत देता है। देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात ने सिस्टम की शुरुआत की है। नए वीजा की मुख्य विशेषताएं ● ग्रीन वीजा के अंतर्गत विदेशियों को किसी नियुक्ता द्वारा प्रायोजित किए बिना संयुक्त अरब अमीरात में काम करने की अनुमति दी जाएगी। ● ग्रीन वीजा धारक की परमिट पर उसके माता-पिता और 25 साल की उम्र तक के बच्चे भी यूई की यात्रा कर पाएंगे। ● यह कार्यक्रम धारक को अपनी पुरानी नौकरी खोने पर नई नौकरी की तलाश करने के लिए तीन महीने तक की छूट अवधि की भी अनुमति देगा।
भारत, ऑस्ट्रेलिया 2+2 बैठक आयोजित करेंगे	संदर्भ : भारत और ऑस्ट्रेलिया नई दिल्ली में उद्घाटन '2+2' मंत्रिस्तरीय बैठक करेंगे। ● बैठक क्षेत्रीय साझेदारों के साथ ऑस्ट्रेलिया की व्यस्तताओं का हिस्सा होगी क्योंकि मंत्री इंडो-पैसिफिक परामर्श के लिए इंडोनेशिया, भारत, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करेंगे। ● ये उद्घाटन 2+2 चर्चाएं ऑस्ट्रेलिया-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की आधारशिला हैं, जो एक सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। ● चर्चा में आर्थिक मुद्दों, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं को शामिल किया जाएगा। ● रक्षा सहयोग संबंधी बैठक भी भारतीय रक्षा मंत्री के साथ होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंध ● हाल के वर्षों में भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ● ऑस्ट्रेलिया में संघीय और राज्य दोनों स्तरों पर ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के लिए भारत की बढ़ती आर्थिक प्रोफाइल और व्यावसायिक प्रासंगिकता को मान्यता दी गई है। ● ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात 2016 में लगभग 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (A\$6.1 बिलियन) था, जबकि इसी अवधि के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत का आयात 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर (A\$14.6 बिलियन) था। ● ऑस्ट्रेलिया को भारत का मुख्य निर्यात मोटर वाहन और मशीनरी, मोती, रत्न और आभूषण, दवाएं और परिष्कृत पेट्रोलियम हैं, जबकि भारत का प्रमुख आयात कोयला, गैर-मौद्रिक सोना, तांबा, ऊन, उर्वरक और शिक्षा संबंधी सेवाएं हैं।
यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप (SCEP)	संदर्भ: हाल ही में अमेरिकी ऊर्जा मंत्रालय के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान संशोधित 'यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप' (SCEP) को लॉन्च किया गया। ● SCEP को वर्ष 2021 की शुरुआत में आयोजित 'लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट' में दोनों देशों द्वारा घोषित 'यूएस-इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप' के तहत लॉन्च किया गया था। बैठक की मुख्य बातें ● इस बैठक में दोनों पक्षों ने प्रगति और प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा की और कई स्तंभों में सहयोग के लिए नए क्षेत्रों को प्राथमिकता दी। ● SCEP के तहत, दोनों देश पांच स्तंभों में सहयोग करने पर सहमत हुए - बिजली और ऊर्जा दक्षता; नवीकरणीय ऊर्जा; जिम्मेदार तेल और गैस; सतत वृद्धि; और उभरते ईंधन।

	○ उन्होंने उभरते ईंधन पर पांचवें स्तंभ को जोड़ने की भी घोषणा की क्योंकि दोनों देश स्वच्छ ऊर्जा ईंधन को बढ़ावा देना चाहते हैं। ● एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के तहत क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग भी 13 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा जो कि अमेरिका और भारत के द्विपक्षीय ऊर्जा संवाद पर आधारित है जिसने ऊर्जा सुरक्षा और नवाचार को गति दी है। ● दोनों देश स्वच्छ ऊर्जा-अनुसंधान (PACE-R) को आगे बढ़ाने के लिए लंबे समय से चली आ रही अमेरिका-भारत भागीदारी के माध्यम से अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास को जारी रखने पर सहमत हुए, जिसमें उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान को प्राथमिकता दी गई। ● वे असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्य समूह सहित विभिन्न सहयोगी कार्यक्रमों के माध्यम से नेट-शून्य समाधान के रूप में असैन्य परमाणु ऊर्जा में नवाचार को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। ● तकनीकी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों को स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को तैनात करने में मदद के लिए लगाया जाएगा। ● भारत-यू.एस. जैव ईंधन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए जैव ईंधन पर कार्य बल की भी घोषणा की गई। ● नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर एकीकरण का समर्थन करने के लिए भारत में विद्युत ग्रिड को मजबूत किया जाएगा। ● उन्होंने गैस टास्क फोर्स का नाम बदलकर भारत-अमेरिका निम्न उत्सर्जन गैस टास्क फोर्स (India-US Low Emissions Gas Task Force) करने की भी घोषणा की। यह टास्क फोर्स भारत की गैस आधारित अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को समर्थन प्रदान करने के लिए नवीन परियोजनाओं पर भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच सहयोग को जारी रखेगी। उभरते ईंधन क्या हैं? ● उभरते ईंधन वैकल्पिक ईंधन हैं जो विकास के अधीन हैं या पहले से उपयोग में हैं। ● लाभ: ये ईंधन ऊर्जा सुरक्षा बढ़ा और उत्सर्जन कम कर सकते हैं, वाहन के प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं तथा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ● उदाहरणों में बायोबुटानॉल (ब्यूटाइल अल्कोहल), जैव ईंधन, मेथनॉल आदि शामिल हैं।
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) पुरस्कार	प्रसंग: मध्यप्रदेश के निवाड़ी जिले के लढपुरा खास गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने (UNWTO) 'सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव' की श्रेणी में नामित किया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन इस गांव को पुरस्कृत करेगा। ● लढपुरा खास गांव पर्यटन नगर ओरछा के पास स्थित है। 'ग्रामीण पर्यटन परियोजना' के बारे में ● 'ग्रामीण पर्यटन परियोजना' लढपुरा खास सहित मध्य प्रदेश के गांवों में शुरू की गई है। ● उद्देश्य: नए आयाम जोड़कर ग्राम पर्यटन की अवधारणा को आकार देना। ● अगले पांच वर्षों में ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से 100 गांवों का विकास किया जाएगा। ● इनमें से ओरछा, खजुराहो, मांडू, सांची, पचमढी, तामिया, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सहित पर्यटन स्थलों के आसपास उपयुक्त स्थलों का चयन और विकास किया जाएगा। ● मप्र पर्यटन बोर्ड सामुदायिक भागीदारी से पर्यटन से संबंधित उत्पादों को विकसित करने का प्रशिक्षण भी दे रहा है। ● महत्व: ग्रामीण पर्यटन स्थानीय लोगों को स्थानीय संस्कृति और परंपरा के महत्व को बनाए रखते हुए पर्यटकों के हितों और जरूरतों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करेगा। ○ स्थानीय समुदाय को रोजगार सृजन के माध्यम से अपने क्षेत्र में पर्यटन के विकास से सीधा लाभ होगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) क्या है? ● संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जिसे जिम्मेदार, टिकाऊ और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सौंपा गया है, जिसमें

	● इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में है। ● यह सामाजिक-आर्थिक विकास में पर्यटन के योगदान को अधिक करने के लिए वैश्विक आचार संहिता के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है, जबकि इसके संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम करता है।
क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनैस मोबिलाइजेशन डायलॉग (CAFMD)	सुर्खियों में : 13 सितंबर, 2021 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनैस मोबिलाइजेशन डायलॉग (जलवायु कार्यवाही एवं वित्तीय संग्रहण संवाद) का शुभारंभ किया। ● क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनैस मोबिलाइजेशन डायलॉग (सीएएफएमडी) अप्रैल, 2021 में जलवायु पर लीडर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लांच भारत-अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा-2030 भागीदारी के दो ट्रैक में से एक है। ● भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, "भारत-अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी" के तहत एक रचनात्मक जुड़ाव के लिए संलग्न होंगे। ये मंच जलवायु कार्यों के लिए एक साथ काम करने के अधिक अवसर प्रदान करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि भारत स्वच्छ ऊर्जा पर अमेरिका के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ● यह संवाद न केवल जलवायु और पर्यावरण पर भारत-अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा बल्कि यह प्रदर्शित करने में भी मदद करेगा कि कैसे दुनिया राष्ट्रीय परिस्थितियों और सतत विकास प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए समावेशी और लचीला आर्थिक विकास के साथ तेजी से जलवायु कार्रवाई को संरेखित कर सकती है। ● आर्थिक विकास और स्वच्छ ऊर्जा कैसे साथ-साथ हो सकते हैं, यह प्रदर्शित करने में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका की सराहना की और कहा कि तत्काल वैश्विक जलवायु कार्रवाई समय की आवश्यकता है। ● शुभारंभ से पूर्व संपन्न बैठक में दोनों पक्षों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस (अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन-आईएसए), एग्रीकल्चर इनोवेटिव मिशन फॉर क्लाइमेट (एआईएम 4 सी) सहित सीओपी-26, जलवायु महत्वाकांक्षा, जलवायु वित्त, वैश्विक जलवायु से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
भारत - संयुक्त अरब अमीरात सीईपीए	सुर्खियों में : हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने औपचारिक रूप से भारत-यूई व्यापक आर्थिक सहयोग तथा भागीदारी समझौते (CEPA) पर वार्ता शुरू की। ● मौजूदा व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार सहित द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में सुधार लाने के उद्देश्य से ● नए रोजगार सृजित करेगा, जीवन स्तर को ऊंचा करेगा, और दोनों देशों में व्यापक सामाजिक और आर्थिक अवसर प्रदान करेगा। ● एक नए रणनीतिक आर्थिक समझौते के हस्ताक्षर के पांच साल के भीतर द्विपक्षीय व्यापार (माल) के 100 अरब डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है और सेवाओं में यह 15 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। ● विश्व व्यापार संगठन द्वारा सन्निहित नियम-आधारित, पारदर्शी, गैर-भेदभावपूर्ण, खुली और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत करना। ● स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 12वें विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC12) में संतुलित और समावेशी परिणाम की दिशा में काम करने के लिए भी सहमत हुए। संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच संबंध ● 2019-2020 में द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, जिसका मूल्य 59 बिलियन अमरीकी डॉलर है। ● 2019-2020 में लगभग 29 बिलियन अमरीकी डॉलर के निर्यात के साथ, अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। ● भारत में आठवां सबसे बड़ा निवेशक, जिसने अप्रैल 2000 और मार्च 2021 के बीच 11 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया है, जबकि भारतीय कंपनियों द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में निवेश 85 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। ● भारत 2019 में यूई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा, जिसका द्विपक्षीय गैर-तेल व्यापार 41 अरब अमेरिकी डॉलर था।

	● संयुक्त अरब अमीरात को भारत के प्रमुख निर्यात में पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती धातुएं, पत्थर, रत्न और आभूषण, खनिज, खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, चीनी, फल और सब्जियां, चाय, मांस और समुद्री भोजन, कपड़ा, इंजीनियरिंग और मशीनरी उत्पाद और रसायन शामिल हैं। ● संयुक्त अरब अमीरात से आयात की जाने वाली प्रमुख चीजों में शामिल हैं- पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती धातुएं, पत्थर, रत्न और आभूषण, खनिज, रसायन और लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद। 2019-2020 में भारत ने यूएई से 10.9 अरब डॉलर का कच्चा तेल आयात किया।
भारत, ऑस्ट्रेलिया ने 'संदर्भ की शर्तों' पर हस्ताक्षर किए	संदर्भ : भारतीय और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने बुधवार को दोनों देशों के बीच नौसेना-से-नौसेना वार्ता के संचालन के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए। यह इस साल 18 अगस्त को दोनों नौसेनाओं के प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षरित “भारत-ऑस्ट्रेलिया नौसेना के लिए नौसेना संबंध के लिए संयुक्त मार्गदर्शन” दस्तावेज के आलोक में आता है। ● भारतीय नौसेना द्वारा किसी भी देश के साथ हस्ताक्षरित यह पहला ऐसा दस्तावेज है। महत्वपूर्ण तथ्य ● दस्तावेज हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण होगा। ● दस्तावेज ने वार्ता के विशिष्ट परिणामों के आधार पर अलग-अलग समझौतों के कार्यान्वयन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान किया। ● दस्तावेज के मुख्य आकर्षण में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS), पश्चिमी प्रशांत नौसेना संगोष्ठी (WPNS) और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) सहित क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों में घनिष्ठ सहयोग शामिल है।
यूएस-इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम	विजन : 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता भारत ने ● 2022 तक 175 GW RE क्षमता और 2030 तक 450 GW RE क्षमता रखने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करना ● स्थापित सौर और पवन क्षमता में 100 गीगावाट तक पहुंच गया और हाइड्रो क्षमता को भी जोड़ने के बाद, कुल स्थापित अक्षय क्षमता 146 मेगावाट है। ● 63 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता निर्माणाधीन है जो भारत को नवीकरणीय क्षमता वृद्धि के मामले में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के व्यवहार्य उपयोग के लिए अगले 3-4 महीनों में हरित हाइड्रोजन के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियां आयोजित करेगा।
भारत-आसियान की सामरिक साझेदारी	मुखियों में : केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के विकासशील देशों के बीच सीमा पार संपर्क के महत्व को रेखांकित किया है। कनेक्टिविटी पर ● कंबोडिया, लाओस और वियतनाम के लिए त्रिपक्षीय राजमार्ग के विस्तार से भारत के पूर्वोत्तर का अपने पूर्वी पड़ोसियों के साथ ज्यादा संपर्क और आर्थिक एकीकरण सक्षम होगा। ● भारत ने म्यांमार में 1,360 किलोमीटर लंबे त्रिपक्षीय राजमार्ग के दो प्रमुख हिस्सों के निर्माण में मदद की है, लेकिन कई अन्य खंडों पर काम और लगभग 70 पुलों के उन्नयन को कई कारकों द्वारा रोक दिया गया है। यह राजमार्ग आसियान क्षेत्र के बाजारों तक पहुंच की अनुमति देगा और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देगा। ● सीमा पार परिवहन और व्यापार की सुविधा के लिए राष्ट्रीय परिवहन सुविधा समितियों (NTFCs) की स्थापना पर जोर दिया। भौतिक संपर्क सीमा क्षेत्रों में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को नए व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने में सक्षम बनाएगा। डिजिटल और डेटा कनेक्टिविटी पर ● भारत और आसियान तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार हैं - डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के तरीकों का पता लगाने के लिए दो क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण।

- भारत सरकार विभिन्न नीतियों और सुधारों के माध्यम से भारत को "वैश्विक डेटा हब" में बदलने के प्रयास कर रही है। भारत के डेटा सेंटर उद्योग में 2021-23 के दौरान 560 मेगावाट जोड़ने की उम्मीद है, जिससे 6 मिलियन वर्ग फुट की अचल संपत्ति की आवश्यकता होगी। उद्योग के 447 मेगावाट से 2023 तक 1,007 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है।

मुख्य फोकस (MAINS)

पंजाब में मोनोकल्चर

संदर्भ : चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच खासतौर पर पंजाब में धान-गेहूँ की खेती की संवहनीयता पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं।

TABLE 1: CROP-WISE PERCENTAGE SHARE OF TOTAL PLANTED AREA IN PUNJAB

	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2018-19
Wheat	27.3	40.5	41.6	43.6	43.1	44.9
Paddy	4.8	6.9	17.5	26.9	31.3	39.6
Pulses	19.1	7.3	5.0	1.9	0.7	0.4
Cotton	9.4	7.0	9.6	9.3	7.6	5.1
Maize	6.9	9.8	5.6	2.5	2.1	1.4
Oilseeds	3.9	5.2	3.7	1.5	1.1	0.5
Bajra	2.7	3.7	1.0	0.2	0.1	0
Sugarcane	2.8	2.3	1.0	1.3	1.8	1.2
Barley	1.4	1.0	0.9	0.5	0.3	0.1
Vegetables	1.2	0.9	1.1	0.7	1.3	3.3
Fruits	0.6	0.6	0.4	0.8	0.5	1.1
Other crops	17.7	14.8	12.6	10.8	10.1	2.4

Source: Punjab Economic Survey 2019-20

- पंजाब में धान-गेहूँ की मोनोकल्चर की सीमा कितनी है?
- वर्ष 2018-19 में पंजाब का सकल कृषि क्षेत्र तकरीबन 78.30 लाख हेक्टेयर था।
- जिसमें से तकरीबन 35.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र गेहूँ के लिये और तकरीबन 31.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र धान के लिये प्रयोग किया गया, जो कि कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 84.6 प्रतिशत था।
 - यह अनुपात 1960-61 में 32% और 1970-71 में 47.4% था।
- यह दालों (1960-61 के बाद), मक्का, बाजरा और तिलहन (1970-71 के बाद) और कपास (1990-91 के बाद) की कीमत पर रहा है।
- चना, मसूर, सरसों और सूरजमुखी की जगह गेहूँ ने ले ली, जबकि कपास, मक्का, मूंगफली और गन्ना क्षेत्र को धान की ओर मोड़ दिया गया।
- केवल वे फसलें जिन्होंने कुछ रकबा विस्तार दर्ज किया है, वे हैं सब्जियां (विशेषकर आलू और मटर) तथा फल (किन्तु), लेकिन वे शायद ही किसी विविधीकरण के बराबर हों

मोनोकल्चर ऐसी समस्या क्यों है?

- साल-दर-साल एक ही जमीन पर एक ही फसल उगाने से कीट और बीमारी के खतरे की संभावना बढ़ जाती है।
 - फसल और आनुवंशिक विविधता जितनी अधिक होगी, कीटों और रोगजनकों को संक्रमित करना उतना ही कठिन होगा।
 - गेहूँ और धान भी दालों और फलियों के विपरीत वातावरण से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकते।
 - बिना किसी फसल चक्र के उनकी निरंतर खेती से मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। नतीजतन, फसलों को तेजी से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भर रहना पड़ेगा।
 - पंजाब के मामले में, मुद्दा गेहूँ के साथ उतना नहीं है, जो स्वाभाविक रूप से अपनी मिट्टी और कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल है।
 - यह प्राकृतिक रूप से पंजाब की मिट्टी और कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल है। यह एक ठंडे मौसम की फसल है, जिसे उन स्थानों पर उगाया जा सकता है, जहाँ मार्च माह में तापमान 30 डिग्री की रेंज में रहता है।
 - पंजाब में इसकी खेती राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।
 - पंजाब में प्रति हेक्टेयर औसतन 5 टन से अधिक गेहूँ का उत्पादन किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय औसत 3.4-3.5 टन के आसपास है।
- तो, यह मूल रूप से धान है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है?**
- हां, इसके दो कारण हैं।
- पहला यह है कि धान गर्म मौसम की फसल है जो उच्च तापमान तनाव के प्रति बहुत संवेदनशील नहीं है। इसे पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भारत के अधिकांश हिस्सों में उगाया जाता है, जहाँ पानी पर्याप्त रूप से उपलब्ध है।
 - पंजाब ने 2019-20 में कुल केंद्रीय पूल खरीद 52 मिलियन टन में से 10.88 मिलियन टन चावल (पिसा हुआ धान) का योगदान दिया। शायद पंजाब के इस चावल का आधा हिस्सा

पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या असम से खरीदा जाता है।

- धान की खेती के लिये भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। किसान आमतौर पर गेहूं की पांच बार सिंचाई करते हैं। धान में 30 या अधिक सिंचाई दी जाती है।
- पंजाब के भूजल स्तर में औसतन 0.5 मीटर प्रति वर्ष की गिरावट आ रही है - मुख्य रूप से धान की खेती और राज्य की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की आपूर्ति की नीति के कारण।
- सरकार की इस नीति ने राज्य के किसानों को धान की लंबी अवधि की किस्मों जैसे- पूसा-44 की उपज के लिये प्रेरित किया है।
 - पूसा-44 धान की उपज काफी अधिक होती है, किंतु इसकी अवधि काफी लंबी होती है।
 - लंबी अवधि का अर्थ है कि मई माह के मध्य तक इसकी रोपाई की जाती है और अक्तूबर माह तक इसकी कटाई कर ली जाती है, जिससे समय रहते गेहूं की अगली फसल की रोपाई भी हो जाती है। हालाँकि इसमें सिंचाई के लिये पानी की काफी अधिक आवश्यकता पड़ती है।

क्या पंजाब सरकार ने इससे निपटने के लिए कुछ किया है?

- पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉयल वॉटर एक्ट, 2009 के तहत पंजाब के किसानों को प्रत्येक वर्ष 15 मई से पूर्व धान की बुवाई और 15 जून से पूर्व धान की रोपाई करने से मना किया गया है।
- इसलिए पूसा-44 की रोपाई की अनुमति जून के मध्य में मानसून की बारिश आने के बाद ही दी गई थी। यह पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था।
- जब जून के मध्य में बारिश के बाद ही धान की रोपाई की अनुमति दी जाती है, तो धान की कटाई भी अक्तूबर माह के अंत तक होती है, जिससे 15 नवंबर की समय-सीमा से पूर्व गेहूं की बुवाई के लिये काफी कम समय बचता है।

- ऐसे में किसानों के पास कटाई के बाद छोड़े गए धान की पराली को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
- सीधे शब्दों में कहें तो पंजाब में भूजल संरक्षण ने दिल्ली में वायु प्रदूषण का कारण बना।

क्या इस व्यापार-बंद से बचने का कोई तरीका है?

- पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU), लुधियाना के वैज्ञानिकों ने एक काम किया है, वह है कम अवधि की धान की किस्मों। ये पूसा-44 की तुलना में परिपक्व होने में 13 से 37 दिनों के बीच कम समय लेते हैं, जबकि लगभग समान उपज देते हैं (तालिका 2 देखें)।
- PR-126, 2017 में जारी एक किस्म की अवधि मात्र 123 दिनों की है (नर्सरी उगाने के 30 दिनों के बाद सहित) और इसकी उपज 30 क्विंटल प्रति एकड़ है।
- 2012 में पंजाब के गैर-बासमती धान का 39 फीसदी क्षेत्र पूसा-44 के अंतर्गत था। 2021 में यह घटकर 20% रह गया, जबकि छोटी अवधि की किस्मों, मुख्य रूप से PR-121 और PR-126 की हिस्सेदारी 71% को पार कर गई है।
- पूसा-44 में लगभग 31 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि पीआर-126 में यह केवल 23 और पीआर-121 में 26 है। बाढ़ वाले खेतों में रोपाई के विपरीत, यदि किसान धान की सीधी बुवाई को अपनाते हैं तो 3-4 सिंचाई की बचत होती है।
 - एक सिंचाई में प्रति एकड़ लगभग 2 लाख लीटर पानी की खपत होती है।

आगे की राह

- पंजाब के धान क्षेत्र को सीमित करने और केवल कम अवधि की किस्मों के रोपण को सुनिश्चित करने के लिए एक समझदार रणनीति हो सकती है।
- बिजली की मीटरिंग और धान की सीधी बुआई के माध्यम से पानी की और बचत की जा सकती है।

ब्रिक्स को बेहतर बनाने का समय

संदर्भ: 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) 9 सितंबर को, डिजिटल रूप से भारतीय अध्यक्षता में किया जाएगा।

- भारत ने 2012 और 2016 में भी यह पद संभाला था।
- **ब्रिक्स का महत्व:** यह दुनिया की आबादी का 42%, भूमि क्षेत्र का 30%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 16% प्रतिनिधित्व करता है।

ब्रिक्स की सफलताएं

- इसने ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच एक सेतु के रूप में काम करने की कोशिश की।
- इसने दुनिया में बहुध्रुवीयता के लिए सक्रिय रूप से समर्थन किया (अमेरिका के प्रभुत्व के खिलाफ)।
- संगठन ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों की एक विस्तृत शृंखला पर एक सामान्य दृष्टिकोण को विकसित किया है।
- इसने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की।
- 'आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था' के रूप में एक वित्तीय स्थिरता जाल का निर्माण किया गया।

- साथ ही, संगठन एक 'वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्चुअल सेंटर' की स्थापना करने जा रहा है।

समूह की चुनौतियां

- भू-राजनीति में भारत अमेरिका और रूस-चीन के साथ आ रहा है।
- पिछले वर्ष पूर्वी लद्दाख में चीन की आक्रामकता ने भारत-चीन संबंधों को कई दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर ला दिया है।
- ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (राजनीतिक अस्थिरता) दोनों में गंभीर आंतरिक चुनौतियां हैं।
- अपने सदस्य राज्यों के बीच अपर्याप्त व्यापार और निवेश संबंध और चीन की केंद्रीयता और इंटर-ब्रिक्स व्यापार प्रवाह का प्रभुत्व।
- ब्रिक्स देशों ने अपने एजेंडे के लिए अपना इष्टतम समर्थन हासिल करने के लिए ग्लोबल साउथ की सहायता करने के लिए पर्याप्त नहीं किया है।
- वर्तमान अध्यक्ष के रूप में, भारत ने चार प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है
- हालांकि एक नया लक्ष्य नहीं है, भारत चाहता है कि ब्रिक्स संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, आईएमएफ, विश्व व्यापार संगठन और डब्ल्यूएचओ से लेकर बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार करे।

- आतंकवादी समूहों द्वारा कट्टरवाद, आतंकवादी वित्तपोषण और इंटरनेट के दुरुपयोग से लड़ने के लिए विशिष्ट उपायों वाले ब्रिक्स काउंटर टेरिज्म एक्शन प्लान को तैयार करके आतंकवाद का सामना करें।
- सतत विकास लक्ष्यों के लिए तकनीकी और डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देना।
- कोविड महामारी के दौर में डिजिटल उपकरणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उल्लेखनीय है कि शासन सुधार के लिये नवीनतम तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने में भारत सबसे अग्रणी रहा है।

निष्कर्ष

- ब्रिक्स का विचार - चार महाद्वीपों से पांच उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा साझा हितों की एक साझा खोज - मौलिक रूप से मजबूत और प्रासंगिक है।
- ब्रिक्स प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए सरकारों ने भारी राजनीतिक पूंजी का निवेश किया है। इसलिए इसकी प्रासंगिकता को जीवित रखने के लिए समूहीकरण में तनाव को दूर करने की आवश्यकता है।

मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान

संदर्भ: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए मुंबई जलवायु कार्य योजना (MCAP) का मसौदा तैयार कर रहा है। इसके लिए हाल ही में कंपनी ने एक वेबसाइट लॉन्च की है।

क्या आप जानते हैं?

- मुंबई दिसंबर 2020 में C40 सिटीज ग्रुप में शामिल हुआ।
- C40 शहरों में दुनिया भर में 97 शहर जुड़े हुए हैं, जिन्हें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम करके जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए जलवायु कार्य योजनाओं को विकसित करने और लागू करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

मुंबई जलवायु कार्य योजना क्या है?

- शहर में चरम मौसम की घटनाओं के कारण जलवायु परिवर्तन की चेतावनियों के बीच, नागरिक निकाय ने मुंबई जलवायु कार्य योजना (MCAP) तैयार करना शुरू कर दिया है।
- यह छह क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके शमन और अनुकूलन रणनीतियों के साथ जलवायु लचीलापन को देखेगा -
 - स्थाई अपशिष्ट प्रबंधन
 - शहरी हरियाली और जैव विविधता
 - शहरी बाढ़ और जल संसाधन प्रबंधन
 - ऊर्जा दक्षता का निर्माण

- वायु गुणवत्ता
- जलवायु लचीलापन

- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन (COP26) सम्मेलन से पहले नवंबर तक योजना तैयार होने की उम्मीद है।

मुंबई को जलवायु कार्य योजना की आवश्यकता क्यों है?

- विश्व संसाधन संस्थान (WRI) भारत द्वारा मुंबई की भेद्यता मूल्यांकन पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार, शहर को दो प्रमुख जलवायु चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा-
 - तापमान में वृद्धि
 - अत्यधिक बारिश की घटनाएं जो बाढ़ का कारण बनेंगी।
- IPCC ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अगले तीन दशकों में मुंबई सहित कम से कम 12 भारतीय तटीय शहरों में समुद्र में 0.1 मीटर से 0.3 मीटर की वृद्धि होगी।
- इससे पहले फरवरी 2020 में, मैकिन्से इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक मुंबई फ्लड फ्लश फ्लैश की तीव्रता में 25% की वृद्धि और समुद्र के स्तर में 0.5 मीटर की वृद्धि देखी जाएगी, जिसके चलते समुद्र के 1 किमी के भीतर रहने वाले 2-3 मिलियन लोग प्रभावित होंगे।

- 2007 के बाद से, शहर में तापमान में लगातार वृद्धि देखी गई है, मुख्य रूप से कंक्रीटीकरण, हरित आवरण की कमी और आवास घनत्व के कारण। इन 14 वर्षों में तापमान में औसत वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस तक होती है।
- शहर में अत्यधिक भारी वर्षा की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। मुंबई में प्रति वर्ष औसतन छह भारी (64.5 - 115.5 मिमी), पांच बहुत भारी (115.6 - 204.4 मिमी) और चार अत्यंत भारी (> 204.5 मिमी) बारिश की घटनाएं देखी गई हैं।
- मुंबई की जलवायु कार्य योजना इन जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए शमन और अनुकूलन कदमों के साथ एक दृष्टिकोण निर्धारित करने और रणनीतियों को लागू करने में मदद करेगी।

शहर का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन क्या है?

- आंकड़े यह बताते हैं कि 2019 में मुंबई का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 34.3 मिलियन टन था।
 - यह 71% ऊर्जा क्षेत्र से आया है जो मुख्य रूप से कोयले पर आधारित है।

- 24% परिवहन से है,
- शेष 5% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से।
- आंकड़ों के अनुसार, मुंबई की 95 प्रतिशत बिजली कोयला आधारित है और उत्सर्जन को कम करने के लिए इसे अक्षय ऊर्जा में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए BMC की योजना कैसे है?

- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए, MCAP निकट अवधि (2030), मध्यम अवधि (2040) और लंबी अवधि (2050) के लिए क्षेत्रों और खपत पैटर्न द्वारा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- बढ़ते जलवायु जोखिमों को बेहतर ढंग से अपनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:
 - सुभेद्यता मूल्यांकन।
 - कमजोर पड़ोस में सामुदायिक लचीलापन क्षमता बढ़ाना।
 - जलवायु अनुकूल अवसंरचना का निर्माण।
 - मजबूत प्राकृतिक प्रणालियों का पोषण।

फर्जी पत्रकारों को बाहर निकालने पर

संदर्भ: मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सही पत्रकारों के हितों की रक्षा और फर्जी पत्रकारों को बाहर निकालने के लिए तीन महीने के भीतर प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु (PCTN) नामक एक निकाय का गठन करने का निर्देश दिया है।

मामला क्या था?

- सही मामला पत्रकार होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था जिसमें उसने विभिन्न मंदिरों से मूर्तियों की चोरी की जांच कर रहे विशेष दल के खिलाफ आरोप लगाया था।
- इस मामले का निपटारा आइडल विंग सीआईडी (CID) को कानून के अनुसार जांच आगे बढ़ाने के निर्देश के साथ किया गया था।
- चूंकि याचिकाकर्ता की परिचय पर संदेह था, इसलिए पीठ ने फर्जी पत्रकारों की बड़ी समस्या को दूर करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया है।

क्या आप जानते हैं?

- अभी तक, भारतीय प्रेस परिषद सार्वजनिक शिकायतों के बारे में प्रहरी की भूमिका निभाती है, लेकिन बिना किसी ठोस प्रवर्तन शक्ति के।
- पत्रकार निकायों के साथ प्रत्यायन और व्यवहार अब संबंधित सरकारों के कार्य हैं।
- 'समाचार पत्र, किताबें और प्रिंटिंग प्रेस' समवर्ती सूची में हैं।

PCTN की संरचना क्या होगी?

- इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे।
- अनुभवी और प्रतिष्ठित पत्रकार, सेवानिवृत्त सिविल सेवक तथा भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी इसके सदस्य होंगे।

PCTN की शक्तियां और कार्य क्या हैं?

- तमिलनाडु राज्य में प्रेस क्लबों और पत्रकार संघों या यूनियनों को मान्यता देने का एकमात्र अधिकार परिषद के पास होगा।
- यह जाति, समुदाय या राज्य की सीमाओं के आधार पर संघों या संघों के गठन या निरंतरता की अनुमति या मान्यता नहीं देगा।
- परिषद इन क्लबों, यूनियनों और संघों के चुनाव करायेगी और उन्हें मंजूरी देगी। यदि परिषद के निर्देश के तहत चुनाव नहीं होते हैं, तो ऐसे संगठन को PCTN के नियंत्रण में लाया जाएगा।
- इसे प्रत्येक शहर या कस्बे में पत्रकार संघों की संख्या तय करने का भी अधिकार होगा जिन्हें अनुमति दी जा सकती है।
- पत्रकार संघों को अपनी आय के स्रोतों का खुलासा करना चाहिए और राज्य सम्मेलनों तथा बैठकों के आयोजन से पहले परिषद की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।
- PCTN के पास फर्जी पत्रकारों की पहचान करने और उनके खिलाफ अधिकार क्षेत्र की पुलिस में शिकायत दर्ज करने की शक्ति होगी।

- मेंबर ऑफ़ पब्लिक फर्जी पत्रकारों के संबंध में अपनी शिकायतें कल्याण बोर्ड को भेज सकते हैं, जो ऐसे फर्जी पत्रकारों के खिलाफ जांच और आपराधिक कार्रवाई शुरू करेगा, क्योंकि वे नागरिक समाज के लिए सही नहीं हैं,
- यह पहचान और मान्यता कार्डों के वितरण को भी विनियमित करेगा, जो उन्हें कुछ लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है (उदा: बस और रेल पास, कल्याणकारी उपाय आदि)।
- फर्जी पत्रकार आम तौर पर अपने अन्यायपूर्ण संवर्धन के लिए उद्योगपतियों, व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं को ब्लैकमेल करने जैसी अवैध और अनैतिक प्रथाओं में लिप्त होते हैं।
- इसके अलावा, वे लेटर-पैड प्रकाशन चलाते हैं, या अज्ञात पत्रिकाओं की कुछ प्रतियां भी छापते हैं, और निहित स्वार्थों के लिए काम करते हैं।

- PCTN जैसी संस्था होने से ऐसे फर्जी पत्रकारों को बाहर निकालने में मदद मिलेगी और इस प्रकार पत्रकारिता की अखंडता को बढ़ावा मिलेगा।

इससे संबंधित चिंताएं क्या हैं?

- इस तरह के एक निकाय का निर्माण न्यायिक निर्देश द्वारा जनहित याचिका के निपटारे के दौरान किया जा रहा है, जो कि मामले से कुछ हद तक असंबंधित है।
- इस तरह के निकाय का निर्माण आम तौर पर कानून द्वारा और व्यापक परामर्श के बाद किया जाता है, इस प्रकार इसे न्यायिक ओवररीच माना जा सकता है।

अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्व एशिया से अमेरिका की वापसी

संदर्भ: कई दक्षिण पूर्व एशियाई सरकारों को अमेरिकी निर्णयों के परिणामस्वरूप अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को जल्दी से निकालने के लिए मजबूर किया गया था और चिंताएं हैं कि अफगानिस्तान में इस्लामी चरमपंथ की वृद्धि से दक्षिण पूर्व एशिया में आतंकवादी हमलों का खतरा बढ़ सकता है।

दक्षिण पूर्व एशिया के प्रति अमेरिकी नीति का विकास

- वियतनाम युद्ध की समाप्ति के बाद के दशकों में, दक्षिण पूर्व एशिया में अमेरिकी हित को विदेश नीति के दायरे में "सौम्य उपेक्षा" के रूप में दर्शाया गया था।
- हालांकि, इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के उदय के साथ-साथ अधिक मुखर चीन के खतरे के साथ, दक्षिण पूर्व एशिया वाशिंगटन के लिए एक प्रमुख क्षेत्र बन गया, जिसे 2011 में ओबामा प्रशासन की ओर से एशिया नीति की तथाकथित धुरी के रूप में चिह्नित किया गया था।
- संयुक्त राज्य अमेरिका अधिकांश दक्षिण पूर्व एशियाई सरकारों का एक प्रमुख आर्थिक और सुरक्षा भागीदार है और उसका थाईलैंड और फिलीपींस के साथ संधि गठबंधन है, साथ ही सिंगापुर और वियतनाम के साथ घनिष्ठ रक्षा संबंध हैं।
- दक्षिण चीन सागर में क्षेत्र को लेकर चीन के साथ अपने विवादों में वाशिंगटन ने वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया का पक्ष लिया है।

अब क्या चिंता है?

- अफगानिस्तान से जल्दबाजी में वापसी ने कुछ एस.ई.एशियाई (S.E.Asian) देशों को यह सवाल करने के लिए मजबूर किया है कि क्या चीन के साथ हिंसक संघर्ष होने पर अमेरिका उनके बचाव में आएगा।

- हालांकि, दक्षिण पूर्व एशियाई सरकारें इस बात से अवगत हैं कि उनके क्षेत्र में अमेरिका के हित अमेरिका द्वारा कहीं और हासिल करने की कोशिश से काफी अलग हैं।
- जबकि अफगानिस्तान जैसे देशों में अमेरिकी हस्तक्षेप आतंकवाद विरोधी प्रयासों और राष्ट्र-निर्माण के इर्द-गिर्द घूमता है, दक्षिण पूर्व एशिया में, अमेरिका के हित स्थिर राज्यों के साथ पहले से ही घनिष्ठ संबंधों को सुधारने पर केंद्रित हैं।
- इसके अलावा, अफगानिस्तान में यू.एस. ने खुद को देश की अधिकांश सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ एक कमजोर और गरीब राज्य को नियंत्रित करने का काम सौंपा।
- दक्षिण पूर्व एशिया दुनिया की कुछ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का घर है, जिनसे अमेरिकी व्यवसाय लाभ उठा सकते हैं। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण पूर्व एशियाई ब्लॉक अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

क्या दक्षिण पूर्व एशिया पर अब अधिक अमेरिका ध्यान जाएगा?

- कई दक्षिण पूर्व एशियाई सरकारों ने ट्रम्प प्रशासन के अंतिम वर्षों के दौरान भ्रम की स्थिति व्यक्त की, खासकर तब जब उन्होंने 2019 में आसियान शिखर सम्मेलन में एक वरिष्ठ अधिकारी को नहीं भेजकर इस क्षेत्र की उपेक्षा की।
- बाइडेन प्रशासन यह कहते हुए कार्यालय में आया कि उसका इरादा मध्य एशिया और मध्य पूर्व से हिंद-प्रशांत में पुनर्गठन करना है। अफगानिस्तान से वापस लेना इस योजना का हिस्सा था, सिवाय इसके कि इसे बहुत खराब तरीके से अंजाम दिया गया था।

- दक्षिण पूर्व एशियाई सरकारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस संदेश को सुदृढ़ करने के लिए कितनी तेजी से आगे बढ़ता है कि इंडो-पैसिफिक अमेरिकी विदेश नीति के केंद्र में है।
- अमेरिका की उपराष्ट्रपति, कमला हैरिस ने कहा है कि "सिंगापुर में, दक्षिण पूर्व एशिया और पूरे भारत-प्रशांत में अमेरिकी भागीदारी इसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है"।
- यह सच है कि चीन के साथ अमेरिका की प्रतिद्वंद्विता में दक्षिण पूर्व एशिया एक प्रमुख क्षेत्र है।

- अमेरिका के दृष्टिकोण से, दक्षिण पूर्व एशिया को उसके भौगोलिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और सामाजिक संबंधों के साथ छोड़ना सही नहीं है, जो अब चीन के साथ प्रतिस्पर्धा से जटिल हो गए हैं।

निष्कर्ष

- दक्षिण पूर्व एशिया चाहता है कि अमेरिका और चीन उनके ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करें, लेकिन इस क्षेत्र के देशों को दोनों के बीच चयन करने के लिए मजबूर होने से नाराजगी है।

हिमालय सह नहीं सकता हाइड्रो अटैक

संदर्भ: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक मामले में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे में उत्तराखंड हिमालय में सात आंशिक रूप से निर्मित जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण की सिफारिश की गई है।

- हिमालय में जल परियोजनाओं पर विशेषज्ञ समितियां
- 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद, SC के मार्गदर्शन में, एक विशेषज्ञ निकाय (EB-I) का गठन किया गया था जो यह जांच करने के लिए गठित किया गया था कि क्या उत्तराखंड में पनबिजली परियोजनाओं की बढ़ती संख्या आपदा से जुड़ी हुई थी।
- अपने निष्कर्षों में, EB-I ने कहा कि आपदा को तेज करने में इन बांधों का "प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव" था।
- बाद में, केंद्र सरकार ने कुछ डिज़ाइन परिवर्तनों के साथ इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृति मिलने तक समिति का गठन किया।

चिंताएं/आलोचना

- **अल्पकालिक लाभ दीर्घकालिक नुकसान:** हरित ऊर्जा के रूप में जलविद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने वाली बांध लॉबी, जलवायु परिवर्तन के खतरों और पर्यावरणीय चुनौतियों की सख्त चेतावनी के बावजूद अल्पकालिक मौद्रिक लाभ के लिए ऐसी परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ना चाहती है।
- **बांधों की स्थिरता पर सवाल:** जलविद्युत पूरी तरह से पानी की अधिक उपलब्धता पर निर्भर करता है। स्थान छोड़ने वाले ग्लेशियर और बाढ़ और सूखे नदियों के मौसमी प्रवाह को प्रभावित करेंगे।

- तलछट हॉटस्पॉट पैराग्लेशियल ज़ोन का अस्तित्व, जो बादल फटने के समय नदी में भारी मात्रा में मलबा और गाद आता है, जिससे नदी की मात्रा बढ़ जाती है और बांध खतरे में पड़ जाते हैं।

- **सामाजिक विस्थापन:** जलविद्युत परियोजनाएं पूंजी गहन उद्यम हैं जो स्थानीय समुदायों और उनकी आजीविका को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।

- **प्राकृतिक आपदाओं को तेज करता है:** इन पर्यावरण-संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों में जलविद्युत परियोजनाओं के प्रसार से बाद, हिमस्खलन और भूस्खलन की तीव्रता में तेजी आती है। उदाहरण: ऋषि गंगा त्रासदी और 2012 की आपदाएं (बाढ़) बांधों से बढ़ गई थीं।

- **पहाड़ की ढलानों का डूबना:** बिजलीघरों तक पानी ले जाने वाली भूमिगत सुरंगों के एक व्यापक नेटवर्क का निर्माण और रखरखाव पहाड़ की ढलानों की विफलता में योगदान है।

- **आर्थिक संभाव्यता के मुद्दे:** जब तक उनका निर्माण होगा, तब तक उत्पन्न बिजली की लागत भी बहुत अधिक होगी और उसका कोई खरीदार नहीं होगा।

आगे की राह

- समय आ गया है कि MoEFCC एक व्यापक सार्वजनिक चर्चा के बाद जलविद्युत क्षेत्र के संबंध में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर एक लिखित स्थिति तैयार करे।
- इन क्षेत्रों के पर्यावरण और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, यह जरूरी है कि सरकार गंगा के ऊपरी इलाकों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित करे। इसे नदी को निर्बाध और मुक्त बहने देना चाहिए।

अंतरिक्ष जंक खतरा



UPSC OPTIONAL

Mains Test Series

- **History Optional**
- **Public Administration Optional**
- **Anthropology Optional**
- **Geography Optional**
- **Kannada Optional**

REGISTER NOW

Scan here to



know more

संदर्भ: मार्च में एक चीनी सैन्य उपग्रह (युन्हाई 1-02) कक्षा में स्वेच्छया से बिखरता हुआ दिखाई दिया, जिससे पृथ्वी के ऊपर मलबे का एक निशान निकल गया।

- हाल ही में यह समझा गया था कि 1996 के रूसी रॉकेट प्रक्षेपण से बचे हुए कबाड़ के टुकड़े के साथ टकराने के कारण उपग्रह बिखर गया।
- 2009 के बाद से यह पृथ्वी की कक्षा में पहला बड़ा स्मैश-अप (smash-up) था।

स्पेस जंक क्या है?

- यह मृत और अवांछित शिल्प है जो पृथ्वी की कक्षा के परिमित स्थान (finite space) में पीछे छूट गया है।
- अंतरिक्ष कबाड़ के 10 करोड़ से अधिक टुकड़े अब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं।
- हालांकि विशाल समूह रेत के दाने के आकार के छोटे हैं, कम से कम 26,000 हंक (hunks) एक उपग्रह को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं।

स्पेस जंक के साथ प्रमुख चिंता क्या है?

- रॉकेट और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में लागत-बचत प्रगति के कारण, ज्यादा देश और कंपनियां कक्षा में पहले से कहीं अधिक सामान लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं।
 - लगभग 4,000 परिचालित उपग्रह अब कक्षा में हैं; आने वाले वर्षों में, यह संख्या बढ़कर 100,000 से अधिक हो सकती है।
- जैसे-जैसे अधिक संस्थाएं वैज्ञानिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कक्षा में पहुंचेगी, टकराव की संभावना और जोखिम तेजी से बढ़ जायेगा।
- प्रत्येक टकराव से मलबा निकलेगा जिससे और टक्कर होने की संभावना बढ़ जाएगी।
- इसका परिणाम अंतरिक्ष कबाड़ की एक बेल्ट इतनी घनी हो सकती है कि यह कुछ निम्न-पृथ्वी कक्षाओं को अनुपयोगी बना देगी।
- अंतरिक्ष कबाड़ उनके अनुसंधान कार्यों को भी प्रभावित कर सकता है (अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरा सहित)।
- जैसे-जैसे पृथ्वी की कक्षा सैन्य प्रतिद्वंद्विता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनती जा रही है, इस बात का जोखिम है कि टकराव को दुर्घटना के अलावा किसी और चीज के रूप में गलत समझा जा सकता है।
- मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए, नासा ने समस्या से निपटने के लिए एक कक्षीय मलबे कार्यक्रम कार्यालय (ODPO) की स्थापना की।

ODPO का परिणाम क्या था?

- 1995 में, एजेंसी ने दुनिया का पहला मलबा-शमन दिशा-निर्देश जारी किया। अन्य बातों के अलावा, इसने प्रस्तावित किया कि मिशन पूरा होने के 25 वर्षों के अंदर उपग्रहों को पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।
- अन्य अंतरिक्ष यात्रा वाले देशों और संयुक्त राष्ट्र ने अपने-अपने दिशा-निर्देशों का पालन किया।
- लेकिन तात्कालिकता और अनुपालन की कमी थी, आंशिक रूप से विश्व ने 2007 तक अंतरिक्ष यान और मलबे के बीच विनाशकारी टक्कर का अनुभव नहीं किया था।
 - 2007 में, चीन ने अपने पुराने मौसम उपग्रहों में से एक पर एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, जो अब तक ट्रैक किए गए अंतरिक्ष मलबे के सबसे बड़े बादल का उत्पादन करती है।
 - बाद में 2009 में, एक गैर-कार्यात्मक रूसी संचार ऑर्बिटर इरिडियम सैटेलाइट द्वारा संचालित एक कार्यशील ऑर्बिटर से टकरा गया, जिससे कम से कम 4 इंच व्यास वाले लगभग 2,000 मलबे का निर्माण हुआ।
 - तब से, स्थिति और अधिक अनिश्चित हो गई है

तो क्या कर सकते हैं?

- अंतरिक्ष कबाड़ के मुद्दे से निपटने के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग की आवश्यकता है।
- 1967 की बाहरी अंतरिक्ष संधि, जिसे चीन से कम इनपुट के साथ पहले की अंतरिक्ष दौड़ के दौरान बातचीत की गई थी, को अद्यतन करने की आवश्यकता है।
- विशेष रूप से, प्रावधान जो देशों को अंतरिक्ष में उनकी वस्तुओं के लिए स्थायी संपत्ति अधिकार प्रदान करते हैं, मलबे को साफ करने के प्रयासों को जटिल बना सकते हैं।
- इसके बाद, नासा को मलबा हटाने वाली तकनीकों में अनुसंधान के लिए धन देना चाहिए - जैसे कि हाल ही में एस्ट्रोस्केल द्वारा प्रदर्शित, एक जापानी स्टार्टअप, जो वादा करता है- और उन्हें विकसित करने वाली कंपनियों के साथ साझेदारी पर विचार करना चाहिए।
- अमेरिका को आर्टेमिस समझौते का भी विस्तार करना चाहिए, अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक ढांचा जिसमें (अब तक) 11 अन्य देश शामिल हैं।
- जैसे-जैसे अधिक राष्ट्र शामिल होते हैं, मलबे-शमन प्रोटोकॉल, जैसे कि यह निर्दिष्ट करने की आवश्यकता कि मिशन के अंत की योजना के लिए किस देश की जिम्मेदारी है, नियमित हो जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- राष्ट्रों को अंतरिक्ष को ऐसी जगह बनाने में मदद करनी चाहिए

जहां देश और कंपनियां सहयोग करें, न कि टकराएं।

भारत की आरक्षण प्रणाली को पुनर्जीवित करने की कुंजी

संदर्भ: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) परीक्षाओं के अखिल भारतीय कोटा में OBCs के लिए आरक्षण की शुरुआत।

आरक्षण क्यों?

- भारतीय समाज की गहरे असमान और दमनकारी सामाजिक व्यवस्था में, समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए किसी प्रकार के राज्य समर्थन (जैसे आरक्षण) की आवश्यकता है।
- आरक्षण के माध्यम से, हाशिए के समूह - जो पीढ़ियों से उत्पीड़न और अपमान का सामना कर रहे हैं - सत्ता के बंटवारे और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जगह पाने में सक्षम होंगे।
- हालांकि, आरक्षण ने हमारे विषम समाज में कई समूहों के लिए जीवन के अवसरों के बराबरी में अनुवाद नहीं किया है।

मुद्दे

- **इंट्रा-ग्रुप मांगें:** जो लोग हाशिए के वर्गों के भीतर से आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाए हैं, उनसे अब नीति में संशोधन की जोरदार मांग है।
- **आरक्षण का विषम वितरण:** केंद्रीय ओबीसी कोटे का 97 प्रतिशत लाभ उसकी 25 प्रतिशत जातियों को ही जाता है। 983 ओबीसी समुदायों - कुल का 37% - का केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश दोनों में शून्य प्रतिनिधित्व है। (G.Rohini Commission report)

- **डेटा की कमी:** राज्य और स्थानीय स्तर पर विभिन्न सामाजिक समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर शायद ही कोई पढ़ने योग्य डेटा है। साथ ही, हम यह नहीं जानते कि उदारीकरण ने उन जातियों के साथ क्या किया है जो आय के अधिक पारंपरिक स्रोतों से बंधी हुई हैं।

आगे की राह :

- संयुक्त राज्य अमेरिका या यूके के समान अवसर आयोग जैसे संस्थान की आवश्यकता है जो निम्नलिखित कार्य कर सके:
- विभिन्न समुदायों की सामाजिक-आर्थिक-आधारित जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके पृथक्करण सूचकांक बनाएं और प्रत्येक वंचित समुदाय के लिए विशिष्ट नीतियां बनाने के लिए उन्हें रैंक करना।
- गैर-भेदभाव और प्रदान किए गए समान अवसर पर नियोक्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों के प्रदर्शन पर एक ऑडिट करना।
- विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे अभ्यास के कोड जारी करना।

बिडेन की विदेश नीति सिद्धांत

संदर्भ: अफगानिस्तान युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हो गया है। इसके अंत ने अमेरिका के लिए एक नई विदेश नीति सिद्धांत को जन्म दिया है। अपने हालिया भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन ने सिद्धांत के प्रमुख घटकों को रखा।

बिडेन अफगान नीति की आलोचनाएँ क्या हैं?

- जब बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस लेने का फैसला किया, तो उसने अफगान सेना और सरकार को तैयार किए बिना अचानक ऐसा किया।
- आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका के पास अफगानिस्तान में एक छोटी सेना रखने और अफगान राष्ट्रीय सेना के लिए हवाई समर्थन बनाए रखने का विकल्प था। यह कम से कम गतिरोध को जारी रखता, और तालिबान को कब्जा नहीं करने देता।
- साथ ही, अफगानिस्तान का हस्तक्षेप नाटो समर्थित सैन्य उद्यम था। यह स्पष्ट नहीं है कि बिडेन ने पीछे हटने का फैसला करने से पहले यूरोपीय सहयोगियों से सलाह ली थी। बिडेन

की एकतरफा वापसी बहुपक्षवाद के उनके समर्थन के साथ अच्छी तरह से नहीं बैठती है।

- हजारों अफगान सहयोगी ऐसी स्थिति में पीछे छूट गए, जो तालिबान के आक्रमण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थी। इससे ताइवान और जापान में भारी बेचैनी होना लाजमी है।
- ताइवान की सुरक्षा एक अमेरिकी छत्र के नीचे कार्य करती है। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी और युद्ध से उसकी थकान को देखते हुए ताइवान में संदेह है कि क्या अमेरिका चीनी आक्रमण का सामना करने के लिए उसे दृढ़ समर्थन प्रदान करेगा।

नए सिद्धांत के प्रमुख घटक क्या हैं?

- चीन और रूस को शामिल करना उसके अधीन अमेरिकी विदेश नीति का फोकस होगा।
- साइबर सुरक्षा युद्ध का एक नया तरीका है और इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

- जमीन पर सैनिकों के माध्यम से अमेरिका की आतंकवाद विरोधी परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके बजाय, "क्षितिज के ऊपर (over the horizon)" क्षमताएं, जिसका अर्थ है उपग्रह और मानव रहित ड्रोन इसके प्रमुख उपकरण होंगे।
- बाहरी सैन्य तैनाती का उद्देश्य राष्ट्र-निर्माण या लोकतंत्र-निर्माण का उद्देश्य नहीं होगा। यह बिल्कुल भी तैनात है, इसके स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य सुरक्षा तक सीमित होंगे, बड़ी राजनीति तक नहीं।
 - सुरक्षा में उग्रवाद का विरोध शामिल नहीं होगा, जिसका अर्थ है गृहयुद्ध में दीर्घकालिक सैन्य भागीदारी।
- लोकतंत्र और मानवाधिकार विदेश नीति के प्रमुख चालक बने रहेंगे, लेकिन ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक उपकरण और कूटनीति मुख्य तरीके होंगे। सैन्य साधनों के

माध्यम से देशों को स्वतंत्र और लोकतांत्रिक होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

यह सिद्धांत पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से किस प्रकार भिन्न है?

- डोनाल्ड ट्रम्प के लिए, अमेरिकी सेना को घर वापस लाना, गठबंधनों से पीछे हटना और एकतरफावाद महत्वपूर्ण लक्ष्य थे।
- वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन गठबंधनों को मजबूत करेंगे, लेकिन सशस्त्र बल को उन क्षेत्रों से वापस लाएंगे जहां उन्होंने "महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित" की सेवा करना बंद कर दिया है।
- इसका तात्पर्य यह है कि जापान और दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सैन्य तैनाती जारी रहेगी, क्योंकि इनका उद्देश्य चीन को संतुलित करना है।

तालिबान और चीन

संदर्भ: अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की अचानक वापसी बीजिंग के लिए अवसर और चुनौती दोनों बनकर उभरी। अवसर इसलिए, क्योंकि चीन आंशिक रूप से पश्चिम द्वारा खाली की गई शक्ति शून्य को भर सकता है।

क्या आप जानते हैं?

- 2001 से, अमेरिका ने अफगानिस्तान में 2.26 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए हैं, जिसमें से 1.53 ट्रिलियन डॉलर रक्षा पर खर्च किए गए थे।
- अफगान अर्थव्यवस्था फली-फूली नहीं थी, इसकी 90% आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, जिसकी प्रतिदिन 2 डॉलर से भी कम है।

चीन और तालिबान

- तालिबान की वापसी को चीनी कूटनीति की जीत और संयुक्त राज्य अमेरिका की विफलता के रूप में देखा जाता है। चीन (रूस भी) ने काबुल में अपने दूतावास चालू रखे हैं जबकि पश्चिमी दूतावास हट गए हैं।
- अफगानिस्तान में दुर्लभ-मृदा धातुएं और तांबे के विशाल भंडार हैं। चीनी इन संसाधनों में रुचि रखते हैं क्योंकि उनके पास खुदाई करने की तकनीक है।
- इसके अलावा, चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) की सफलता सुनिश्चित करने के लिए तालिबान के साथ उलझ रहा है। यह एक बहुत बड़ा निवेश होने के कारण लाभ प्राप्त करने के लिए कई वर्षों के सफल संचालन की आवश्यकता होती है। इसलिए तालिबान का समर्थन चीन के लिए जरूरी है।

BRI (विशेष रूप से CPEC में) में चीन की निवेश रणनीति के इरादे क्या हैं?

- इस क्षेत्र में उत्पादन की लागत कम है इसलिए चीनी कंपनियां अपने उत्पादन फर्मों को चीन से इन क्षेत्रों में स्थानांतरित करके लाभ उठा सकती हैं।
- इन क्षेत्रों में निवेश का मतलब चीनी फर्मों के लिए बड़े बाजारों तक पहुंच था।
- यह चीन के लिए अधिक समान क्षेत्रीय विकास को भी सक्षम बनाता है (चीन का पश्चिमी अविकसित हिस्सा आर्थिक केंद्र के रूप में उभर सकता है)
- चीनी कंपनियां जब यहां से निर्यात करना शुरू करती हैं तो चीनी वस्तुओं पर लक्षित उच्च-टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों से बच सकती हैं।
- अफ्रीका और एशिया में निवेश ने चीन की कुछ ऊर्जा आवश्यकताओं को भी कम कर दिया है, जिससे चीन को सस्ती विदेशी ऊर्जा (तेल और बिजली) और खनिजों तक पहुंचने में मदद मिली है।

चीन के लिए चुनौतियां

- आतंकवाद की मौजूदगी में कोई भी व्यवसाय फल-फूल नहीं सकती। तालिबान के सत्ता में आने के साथ, अल कायदा, दाएश और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी समूहों के पुनरुत्थान की चिंता है।
- तालिबान को पूर्वी तुर्कस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर के रूप में भी जाना जाता है - चीन के उइघुर प्रांत (मुस्लिम बहुल प्रांत) में सक्रिय एक उग्रवादी समूह।
- चीन द्वारा दिए गए ऋण या परियोजनाओं को चुकाने की आर्थिक क्षमता पर संदेह है। पाकिस्तान BRI के तहत बनी

चीन द्वारा वित्त पोषित ऊर्जा परियोजना को चुकाने में असमर्थ है।

- तालिबान के शासक समूह एकजुट नहीं हैं, जिससे कोई भी विश्वसनीय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत भविष्यवाणियां करना असंभव हो गया है। यह चीन जैसी स्थिर निरंकुशता के अनुकूल नहीं है।
- विद्रोह, गुटिय युद्ध, तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान में संभावित घटनाएँ होंगी। ये मुद्दे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान,

बाजरा की खेती का महत्व

संदर्भ: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया, जैसा कि भारत द्वारा खाद्य और कृषि संगठन (FAO) को प्रस्तावित किया गया था।

बाजरा के बारे में

- बाजरा मोटे अनाज और प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों का भंडार है।
- इनमें ज्वार (सोरघम), रागी (फिंगर बाजरा), कोरी (फॉक्सटेल बाजरा), अर्क (कोदो बाजरा), समा (थोड़ा बाजरा), बाजरा (मोती बाजरा), चना/बार (प्रोसो बाजरा) और सानवा (बार्नयार्ड बाजरा) शामिल हैं।
- बाजरा मनुष्यों के लिए ज्ञात सबसे पुराने खाद्य पदार्थों में से एक था। लेकिन शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के साथ उन्हें गेहूं और चावल के पक्ष में छोड़ दिया गया।
- 41% बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत उनका सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है, और आने वाले दशक में वैश्विक बाजरा के लिए 4.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान है।

बाजरा के क्या फायदे हैं?

1. जलवायु अनुकूल

- मोठे फसल होने के कारण, वे अत्यधिक तापमान, बाढ़ और सूखे का सामना कर सकते हैं।
- वे गेहूं और चावल की तुलना में 3,968 किग्रा और 3,401 किग्रा के साथ प्रति हेक्टेयर 3,218 किग्रा कार्बन डाईऑक्साइड के समकक्ष कार्बन फुटप्रिंट के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में भी मदद करते हैं।

2. पारिस्थितिक तंत्र की बहाली और स्थिरता:

- भारत में भूमि क्षरण एक बड़ी समस्या रही है, जिससे साल दर साल बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होता है। सूखा-सहिष्णु फसलें, जैसे- बाजरा, रासायनिक इनपुट पर कम निर्भरता के साथ पारिस्थितिक तंत्र पर बहुत कम दबाव डालता है।
- अन्य फसलों के साथ बाजरा की अंतर-फसल विशेष रूप से फायदेमंद है क्योंकि बाजरा के पौधों की रेशेदार जड़ें मिट्टी की

तुर्की और BRI श्रृंखला में अन्य आवश्यक रिंगों तक फैलेंगे। इसलिए BRI में नकदी प्रवाह लगातार रुकावट के जोखिम का सामना करेगा।

निष्कर्ष

- शतरंज के खेल में, अफगानिस्तान को खाली करने का यू.एस. का कदम वास्तव में चीन के लिए महंगा साबित हो सकता है।

गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती हैं, ये पानी के बहाव को रोककर रखती हैं और कटाव वाले क्षेत्रों में मिट्टी के संरक्षण में सहायता करती हैं, जिससे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को बहाल किया जा सके।

3. जैव ईंधन और इथेनॉल सम्मिश्रण

- जून 2021 में, सरकार ने 2025 तक पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
- भारत में अधिकांश जैव-इथेनॉल का उत्पादन चीनी के शीरे और मक्का का उपयोग करके किया जाता है।
- हालांकि, मध्य प्रदेश में किसानों के बीच किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि ज्वार और बाजरा का उपयोग करके बायो-एथेनॉल बनाया जाता है, और यह ईंधन कार्बन उत्सर्जन को लगभग आधा कर देता है।
- अनुमान यह भी बताते हैं कि प्रसंस्करण में 40% कम ऊर्जा का उपयोग करते हुए बाजरा मक्का की तुलना में अधिक लाभ देता है। बाजरा जैव-इथेनॉल उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के रूप में मक्का पर एक महत्वपूर्ण लागत लाभ भी प्रदान करता है।

4. एक सांस्कृतिक संबंध:

- बाजरा की खेती की जड़ें भारतीय संस्कृति में गहरी हैं।
- डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी जैसे संगठनों ने तेलंगाना में महिला समूहों का गठन किया है और संस्कृति-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से बाजरा को बढ़ावा दे रहे हैं।
- इस तरह की फसल संवेदीकरण शहरी सेटिंग्स में भी फिल्टर किया गया है। 2018 में, बेंगलुरु में #LetsMilletCampaign ने रेस्टोरेंट्स द्वारा रिसोर्टो और पिज्जा जैसे व्यंजनों में बाजरा का उपयोग देखा गया।

5. स्थायी DGs को संबोधित करने में मदद करता है:

- बाजरा भारत की स्थिरता नीति के हस्तक्षेप में भूमिका निभाता है। समकालीन अनुसंधान विकास ने ऊर्जा अनुकूलन, जलवायु लचीलापन और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर बाजरा के प्रभाव पर प्रकाश डाला है।

- बाजरा की खेती से महिला सशक्तिकरण भी हुआ है। उदाहरण के लिए ओडिशा बाजरा मिशन ने 7.2 मिलियन महिलाओं को 'कृषि-उद्यमियों' के रूप में देखा।

बाजरा की वृद्धि को लेकर चिंताएं क्या हैं?

- आय में वृद्धि और शहरीकरण ने बाजरा की मांग को कम कर दिया है
- अपर्याप्त सरकारी नीतियां।
- बिचौलियों के कारण किसानों के लिए अनुचित मूल्य निर्धारण।
- इनपुट सब्सिडी और मूल्य प्रोत्साहन का अभाव।
- PDS के माध्यम से चावल और गेहूं की खरीद और सब्सिडी वाली आपूर्ति ने किसानों को बाजरा से इन फसलों की ओर स्थानांतरित कर दिया है।

- बाजरा का उपयोग उपभोग के अलावा अन्य विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है।

आगे की राह

- बाजरा के साथ अंतर-फसल को अपनाने को प्रोत्साहित करना (दो या दो से अधिक फसलें साथ-साथ लगाई गई) और फसल बीमा तथा भंडारण सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान करने से आय और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
- क्षमता से भरपूर, बाजरा देश के सतत विकास चक्र में एक महत्वपूर्ण दल के रूप में कार्य करता है यदि उनके उत्पादन को बढ़ावा देने, किसानों को प्रोत्साहित करने और बाजार संबंधों को मजबूत करने वाली नीतियों द्वारा समर्थित हो।

सेमी-कंडक्टर की कमी

संदर्भ: सेमीकंडक्टर चिप्स की वैश्विक कमी ने भारत में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SME) क्षेत्र में अपना प्रभाव महसूस करना शुरू कर दिया है।

- मूल उपकरण विनिर्माता (OEM) के कारण उत्पादन धीमा हो गया है, छोटे कारोबारियों को उनके व्यावसायिक आदेशों के रूप में प्रभावित किया जा रहा है और इसलिए राजस्व में कमी आ रही है।

सेमीकंडक्टर की कमी के कारण

- आपूर्ति करने वाले देशों में, विशेष रूप से एशिया में, कोविड - 19 मामलों में वृद्धि के कारण उत्पादन में व्यवधान (कारखानों का बंद होना) हुआ, जिससे वर्तमान कमी हुई।
- टेक्सास में भयंकर सर्दी के तूफान ने सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, और जापान में एक संयंत्र में आग लगने से भी इसी तरह की देरी हुई।
- इसके अलावा, सब्सट्रेट निर्माण के अपेक्षाकृत कम मार्जिन ने इसके निवेश को कम कर दिया है और वैश्विक चिप की कमी के खलन को बढ़ा दिया है।
 - सबस्ट्रेट्स चिप्स को सर्किट बोर्ड से जोड़ते हैं जो उन्हें पर्सनल कंप्यूटर और अन्य उपकरणों में रखते हैं।
 - राल (resin) में सैंडविच किए गए पतले तांबे के तार से बने, सबस्ट्रेट्स उपयोगकर्ता के निर्देशों को कंप्यूटर के चिप्स तक पहुंचाने में मदद करते हैं और उसके उत्तरों को रिले करते हैं।
 - वे आवश्यक हैं क्योंकि चिप्स से निकलने वाली अल्ट्राथिन वायरिंग एक सर्किट बोर्ड से सीधे सोल्डर किए गए कनेक्शन को सहन नहीं कर सकती है
 - इसलिए सबस्ट्रेट निर्माण को वैश्विक चिप आपूर्ति श्रृंखला के बैकवाटर के रूप में देखा जाता है।

- सबस्ट्रेट्स की आपूर्ति बहुत तंग है और इस कम निवेश वाले क्षेत्र में छोटा व्यवधान चिप निर्माताओं के लिए बड़ी चिंता का कारण बन रहा है।

- हाल ही में इंटेल (Intel) और आईबीएम (IBM) दोनों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने कहा है कि चिप की कमी दो साल तक रह सकती है।

सेमीकंडक्टर चिप्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर

- सेमीकंडक्टर चिप्स पावर ट्रेन, चैसिस, सुरक्षा प्रणालियों, उन्नत चालक सहायता प्रणालियों और ऑटोमोबाइल के अन्य भागों के अभिन्न अंग हैं।
- वाणिज्यिक या दोपहिया वाहनों की तुलना में यात्री वाहनों में इनका अधिक उपयोग किया जाता है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ने से चिप्स की मांग में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, फोर्ड फोकस आमतौर पर लगभग 300 चिप्स का उपयोग करता है, जबकि फोर्ड के नए इलेक्ट्रिक वाहनों में से एक में 3,000 चिप्स तक हो सकते हैं।
- सेमीकंडक्टर चिप्स की आपूर्ति धीमी होने से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर चिप की कमी के परिणाम:

- लंबे समय तक चलने के कारण - ऑर्डर देने और शिपमेंट की डिलीवरी के बीच का समय - ऑटोमोबाइल क्षेत्र को अपने उत्पादन में कटौती करने के लिए मजबूर किया गया है।
- बड़े ऑटोमोटिव खिलाड़ियों द्वारा उत्पादन में कमी के कारण MSMEs विक्रेताओं (जो पुर्जों की आपूर्ति करते हैं) को दिए जा रहे नए ऑर्डर में कमी आई है।
- MSMEs जो ऑटोमोबाइल उद्योग के विक्रेता और उप-विक्रेता हैं, वे अब सामान्य रूप से 12 घंटे के बजाय केवल 8

घंटे काम कर रहे हैं। इससे न केवल उनकी कमाई प्रभावित हुई है, बल्कि उन्हें दूसरे क्षेत्रों में पलायन करने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है।

- जबकि स्थानीय MSMEs औद्योगिक क्षेत्र कोविड -19 की दूसरी लहर के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो रहा था, कच्चे माल की उच्च कीमत और कम ऑर्डर से वसूली में बाधा उत्पन्न हुई है।

स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है?

- सैमसंग, टाटा समूह जैसी कंपनियां सेमी-कंडक्टर उत्पादन में भारी निवेश कर रही हैं।
- अमेरिका, यूरोप और चीन ने ऑन-शोरिंग उत्पादन के लिए अरबों की सब्सिडी देने की प्रतिबद्धता जताई है।
- वाहन निर्माताओं द्वारा लंबी अवधि के आपूर्ति अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।

भारत अपनी भूमिका कैसे निभा सकता है?

उच्च शिक्षा के सपनों के लिए वास्तविकता की जाँच

संदर्भ: UGC जल्द ही अपने दो हालिया नियमों - एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स और मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट को लागू करेगा।

इन दो नियमों का महत्व

- पाठ्यचर्या ढांचे के लचीलेपन को बढ़ावा देता है।
- उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के लिए अंतःविषय और शैक्षणिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है।
- मल्टीपल एंट्री-मल्टीपल एक्जिट विकल्पों के साथ डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणन प्राप्त करने के लिए छात्रों को अपना स्वयं का सीखने का रास्ता चुनने की सुविधा देता है।
- शिक्षा छात्र-केंद्रित लर्निंग होगी, जिसे प्रत्येक छात्र की स्ट्रेंथ, जरूरतों, कौशल और रुचियों के लिए अनुकूलित किया जाएगा।
- इस आलोचना को संबोधित करता है कि भारतीय शिक्षा बहुत अधिक संरचित, कठोर और महंगी है।
- छात्र प्रतिधारण और नामांकन बढ़ाने में मदद करता है। प्रासंगिकता की कमी और अपनी रुचि बनाए रखने में असमर्थ होने के कारण छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं।
- इसलिए, विनियमों को NEP की स्टार सिफारिशों और उच्च शिक्षा के लिए गेम-चेंजर के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। सैद्धांतिक स्तर पर ये अच्छे लगते हैं, लेकिन इसे साकार करने में चुनौतियां हैं।

चिंताओं

- छात्र की परिपक्वता:** 15 या 16 साल की एक युवा छात्र अपनी योग्यता के अनुरूप सर्वोत्तम पाठ्यक्रमों या पाठ्यक्रमों

- चूंकि, चिप निर्माण में पूंजी-गहन (औसत आकार की सुविधा की लागत \$7-10 बिलियन है) लंबी अवधि और तीव्र प्रौद्योगिकी के साथ है, इसलिए भारत के लिए चिप निर्माण पर आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास करना कठिन है।
- लेकिन, इसरो और डीआरडीओ द्वारा पहले से संचालित सरकारी स्वामित्व वाली सेमी-कंडक्टर सुविधाओं का विस्तार और उन्नयन किया जा सकता है।
- सरकार अनुसंधान एवं विकास में कुशल प्रतिभा पूल, कम श्रम लागत, बड़े बाजार और नीति समर्थन (उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना) का प्रदर्शन करके वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित कर सकती है।

के संयोजन का अर्थपूर्ण रूप से चयन करने की स्थिति में नहीं हो सकती है।

- डिग्री का नामकरण:** भले ही वह पाठ्यक्रमों का चयन करती है, हो सकता है कि वह अपनी इच्छानुसार अपनी डिग्रियों को तैयार न कर पाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिग्री के नामकरण पर नियंत्रण पूरी तरह से UGC के पास है।
- पूर्ण फ्लेक्सिबिलिटी नहीं:** विषयों के चुनाव में फ्लेक्सिबिलिटी, यदि पाठ्यक्रम का 50 प्रतिशत डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान के भीतर किया जाये, तो वास्तव में छात्र के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बचा है।
- पिछला अनुभव:** 2012 में "मेटा यूनिवर्सिटी" की इसी तरह की अवधारणा का प्रयास किया गया था, जो यूजीसी विनियमन के बावजूद, मुख्य रूप से मूक मानसिकता और संस्थानों के बीच समन्वय की कमी के कारण विफल रही।
 - राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) में व्यावसायिक शिक्षा के लिए समान सक्षम प्रावधान (मल्टीपल एंट्री और एक्जिट) हैं, लेकिन इसके लिए दिखाने के लिए कुछ भी ठोस नहीं है।
- सीमित विकल्प:** यदि गुणवत्ता के साथ लचीलापन आधार था, तो सरकार को क्रेडिट ट्रांसफर और क्रेडिट संचय के लिए केवल SWAYAM, NPTEL, V-Lab, आदि पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों को सीमित नहीं करना चाहिए। विदेशी ऋणों का भी दोहन किया जा सकता है।
- रोजगार कारक:** यदि कोई छात्र डिग्री कार्यक्रम में एक या दो वर्ष छोड़ने का विकल्प चुनता है, तो उसकी रोजगार योग्यता का मुद्दा अनसुलझा रहता है। 2014 में दिल्ली विश्वविद्यालय

के पंचवर्षीय यूजी कार्यक्रम को रद्द करते समय इसी तरह के तर्क का इस्तेमाल किया गया था।

- **नौकरशाही की बाधाएँ:** नौकरशाही प्रक्रियाओं के कारण प्रवास प्रमाण पत्र या प्रतिलेख प्राप्त करने में एक छात्र के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए, इन पहलों के सुचारू कार्यान्वयन के साथ आशाकाएँ हैं।
- **प्रशिक्षण जनशक्ति:** केवल शिक्षकों से मार्गदर्शक और संरक्षक बनने के लिए संकाय को पुनः उन्मुख करने की आवश्यकता होगी।

- **राशि (Funds):** इन पहलों के कार्यान्वयन के लिए आईटी अवसंरचना और जनशक्ति (शिक्षकों) दोनों के लिए धन की आवश्यकता होती है। हालांकि, 2014-15 में कुल केंद्रीय शिक्षा बजट में लगातार 4.14 फीसदी, 2019-20 में 3.4 फीसदी की गिरावट आई है।

आगे की राह

- इन नवोन्मेषी विचारों को सफल बनाने के लिए केंद्र और UGC से लेकर VCs, फैकल्टी और गैर-संकाय कर्मचारियों तक प्रत्येक हितधारक से बड़ी प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी।

उच्च शिक्षा नामांकन का विस्तार करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए

संदर्भ: अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) 2019-20 के अनुसार, उच्च या तृतीयक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) पिछले वर्ष में 26.3% (37.4 मिलियन) से बढ़कर 27.1% (38.5 मिलियन) हो गया।

- यह इंगित करता है कि 18-23 आयु वर्ग की शेष 72.9% आबादी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) में नामांकित नहीं है।

NEP और HEI नामांकन लक्ष्य

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने 2035 तक 50% GER का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, GER को 3.53% प्रति वर्ष की दर से बढ़ाने की आवश्यकता है।
- यह लक्ष्य प्राप्त करने योग्य है क्योंकि 2011-12 और 2019-20 के बीच GER की चक्रवृद्धि विकास दर 3.58% थी।

उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए एक बहुस्तरीय रणनीति की आवश्यकता है।

- सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी और फिर HEI में ट्रांजिशन रेशियो में सुधार की जरूरत है। उदाहरण के लिए: 2018-19 में उच्च माध्यमिक स्तर पर शुद्ध नामांकन अनुपात केवल 30.8% था, जो HEI में वृद्धि की संभावना को सीमित करता है।
- भूगोल भी HEI के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, शहरी क्षेत्रों में कॉलेज घनत्व अत्यधिक है। नामांकन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ भीतरी इलाकों में HEI का विस्तार करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप अत्यावश्यक है।
- नीति जो बड़े उच्च शिक्षा संस्थानों के पक्ष में है: इससे पहले, राधाकृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1949) और कोठारी आयोग (1964-66) ने छोटे, उच्च गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों का पक्ष लिया था। यह चीन, अमेरिका और यूरोप की नीति के बिल्कुल विपरीत है।
 - 2016 में, भारत के 51,649 HEI में 35.7 मिलियन छात्र थे, जबकि चीन के 2,596 संस्थानों में 41.8 मिलियन छात्र थे।

- उच्च नामांकन वाले उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रबंधित करना आसान और अधिक संसाधन-अनुकूल होता है।

- **मुक्त शिक्षा का विस्तार (Expanding Open Learning) :** भारत में दूरस्थ और मुक्त शिक्षा का हिस्सा कई वर्षों से लगभग 11% पर स्थिर है। स्वयं के माध्यम से बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ओपन कोर्स (MOOCs) एक अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन केवल 10.7 फीसदी भारतीय परिवारों के पास 23.8% इंटरनेट के साथ कंप्यूटर तक पहुंच है।

- **शिक्षक की कमी और गुणवत्ता में सुधार:** भारत को शिक्षक-छात्र अनुपात को 1:28 से आदर्श 1:15 तक सुधारने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.3 मिलियन अधिक शिक्षकों की आवश्यकता है। इसके लिए एक स्थिर और महत्वपूर्ण कैरियर प्रक्षेपवक्र सुनिश्चित करके शिक्षण को एक पेशे के रूप में चुनने के लिए सर्वोत्तम माइंड मिलने तथा मदद करने के प्रयासों की आवश्यकता है।

- भारत फिनलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में शिक्षा प्रणालियों से सीख सकता है, जहां शिक्षण एक प्रतिष्ठित पेशा है।

- **रोजगार में सुधार:** विभिन्न सर्वेक्षणों में पाया गया है कि स्नातकों के पास कुशल कार्य के लिए आवश्यक तकनीकी और संचार कौशल दोनों की कमी है। स्थानीय नियोक्ताओं के सहयोग से उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम इन स्तरों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

- **अधिक छात्रवृत्तियाँ:** छात्रवृत्ति के माध्यम से दी जाने वाली वित्तीय सहायता वर्तमान में अपर्याप्त है। "जन शिक्षा" से "सार्वभौमिक शिक्षा" में संक्रमण सबसे कमजोर लोगों को वित्तीय सहायता के माध्यम से है।

निष्कर्ष

- पिछले कुछ वर्षों में भारत का जीईआर लगातार बढ़ा है। इस वृद्धि ने महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के GER में भी पर्याप्त वृद्धि देखी है। यह वृद्धि

जारी रहनी चाहिए। इसलिए, भविष्य उपसमूहों को सशक्त बनाने में निहित है, जिससे GER में तेजी आएगी।

- इसे NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित अधिक से अधिक सामाजिक समावेशन की नीति को मजबूत करने के भारत के प्रयासों के साथ मिलना चाहिए।

9/11 के दो दशक

9/11 की घटनाओं ने पुराने के के साथ-साथ नई भू-रणनीतिक धाराओं की शुरुआत को भी चिह्नित किया।

आशय

- **आतंकवाद पर:** भारत 1989 से कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी विद्रोह का सामना कर रहा था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्लामी आतंकवादी लहर को गंभीरता से नहीं लिया गया क्योंकि पश्चिम ने इस मुद्दे को कम करके आंका। लेकिन 9/11 की घटनाओं ने इस कमजोर प्रतिक्रिया को समाप्त करने के लिए मजबूर किया और वैचारिक उग्रवाद का पर्दाफाश किया जो इन आतंकी ताकतों को चला रहा था।
- **नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए दुरुपयोग:** 9/11 दो युद्ध (अफगानिस्तान और इराक) शुरू करने का बहाना बन गया, पश्चिम एशिया क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्थायी युद्ध मशीन को प्रस्ताव में रखा, कार्यकारी शक्ति के गैर-जिम्मेदार अभ्यास को वैध बनाया, निगरानी राज्य की स्थापना की जो प्रतिकूल रूप से नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित किया। इसने अमेरिका की भू-राजनीतिक विश्वसनीयता और अधिकार को कमजोर कर दिया।
- **यूएस-पाक संबंधों पर:** पाकिस्तान 9/11 के हमलों के बाद शुरू हुए आतंक के खिलाफ युद्ध के लिए एक महत्वपूर्ण (और अविश्वसनीय) अमेरिकी सहयोगी बना रहा।
 - 2011 में, ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तानी सेना के अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से दूर, पाकिस्तानी धरती पर अमेरिकी सेना द्वारा समाप्त कर दिया गया था।
- **अमेरिका-भारत संबंधों पर:** 9/11 भारत और अमेरिका को करीब लाने में एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक था, क्योंकि भारत के पश्चिमी पड़ोस से उजागर होने वाले आतंकवाद की आम समस्या थी। बाद में चीन के उदय ने भारत और अमेरिका को बहुत करीब ला दिया है।
- **यूनिपोलर टू बाइपोलर (Unipolar to Bipolar):** 9/11 के बाद के दो दशकों ने दुनिया को एकध्रुवीयता से हटते हुए देखा है, जिसमें चीन अमेरिका के नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था को चुनौती देने वाले नए पोल (Pole) के रूप में उभर रहा है। महामारी से प्रेरित आर्थिक और स्वास्थ्य संकट ने केवल उन प्रवृत्तियों को गति दी।

पिछले कुछ वर्षों में भारत का आतंकवाद से निपटने का तरीका कैसे बदला है?

- 2008 में 26/11 के जघन्य मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद भी, भारत ने "रणनीतिक संयम" का प्रयोग करना चुना। इसका कारण यह था कि सरकार चिंतित थी कि इसे युद्ध के स्तर तक ले जाने से आर्थिक विकास बहुत अधिक लाभ प्राप्त किए बिना पटरी से उतर सकता है।
 - इसके बजाय, उसने पाकिस्तान पर आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने की रणनीति अपनाई।
- हालांकि, हाल के वर्षों में सत्ता में आने वाली एकल पार्टी के साथ दृष्टिकोण में बदलाव आया है जिसने राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित की है और मजबूत कार्रवाई करने के लिए आवश्यक लोकतांत्रिक महत्व दिया है।
- इसके अलावा, भारत की अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास हासिल करके ऊंचाई हासिल की है। इसने भारत को सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने सैन्य और राजनयिक विकल्पों का विस्तार करने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसे बाकी दुनिया ने भी एक गंभीर मुद्दे के रूप में मान्यता दी है।
 - उदाहरण के लिए, 2016 के उरी हमले और 2019 के पुलवामा हमले के बाद, भारत दृढ़ विश्वास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा और अपने हितों के लिए खड़ा हुआ तथा सैन्य कार्रवाई की जिसने रणनीतिक गणना को फिर से स्थापित कर दिया।
- आज, आर्थिक विकास उन देशों को आकर्षित कर रहा है जो भारत में निवेश और व्यापार करना चाहते हैं, जो लोकतांत्रिक भारत की राजनयिक बास्केट में तीर जोड़ रहे हैं।
- उदारीकरण और आर्थिक सुधार जो विकास को बढ़ावा देते हैं, न केवल गरीबी उन्मूलन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, बल्कि यकीनन यह अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रमुख रणनीति है।

निष्कर्ष

9/11 की 20वीं बरसी पर तालिबान की जीत से नई अज्ञात समस्याएं पैदा होने की संभावना है। हालांकि, दुनिया को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सतर्क रहना चाहिए कि आतंकवाद फिर से अपना सिर न उठाए।

खाता एग्रीगेटर: वित्तीय डेटा साझा करने के लिए नया दांचा

संदर्भ: 2 सितंबर को RBI ने वित्तीय डेटा को अधिक आसानी से सुलभ बनाने के उद्देश्य से खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क लॉन्च किया।

- इसके तहत, कई फिन-टेक संस्थाओं को खाता एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है।
- आठ बड़े बैंक भी अकाउंट एग्रीगेटर्स के साथ अपने ग्राहकों के बारे में विभिन्न वित्तीय डेटा साझा करने के लिए सहमत हुए हैं।

अकाउंट एग्रीगेटर कैसे काम करेगा?

- ढांचा डेटा धारकों और उसके उपयोगकर्ताओं के बीच वित्तीय डेटा का आदान-प्रदान करने की अनुमति देगा।
- RBI ने PhonePe जैसी कई कंपनियों को इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है।
- अकाउंट एग्रीगेटर बिचौलियों के रूप में कार्य करेंगे जो एक वित्तीय इकाई से डेटा एकत्र करेंगे और दूसरे के साथ उसका आदान-प्रदान करेंगे।
- उदाहरण के लिए, एक बैंक जो संभावित उधारकर्ता से ऋण आवेदन संसाधित कर रहा है, वह उधारकर्ता के बारे में विभिन्न प्रकार के वित्तीय डेटा तक पहुंच बनाना चाहता है। उधार देने वाला बैंक एक अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से उधारकर्ता की बचत, पिछले ऋण चुकौती रिकॉर्ड, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स और बीमा होल्डिंग्स के विवरण तक पहुंच सकता है।
- हालांकि, उधारकर्ता को अपने डेटा को उधार देने वाले बैंक के साथ साझा करने के लिए सहमति देनी होगी।

इसके फायदे क्या हैं?

- फिलहाल, किसी व्यक्ति के विभिन्न वित्तीय डेटा कई वित्तीय संस्थानों के डेटाबेस में बिखरे हुए हैं। तो एक व्यक्ति की बचत और ऋण डेटा बैंक के पास हो सकता है, उसका निवेश डेटा म्यूचुअल फंड के पास हो सकता है, जबकि उसका बीमा डेटा किसी अन्य वित्तीय इकाई के पास हो सकता है।
- अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत, इस सभी डेटा को आसानी से एकत्र किया जा सकता है और व्यक्ति की सहमति से अकाउंट एग्रीगेटर्स के माध्यम से साझा किया जा सकता है।
- ढांचे के समर्थकों का मानना है कि डेटा की आसान उपलब्धता से अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण लाभ होंगे।
- उनका मानना है कि यह ढांचा वित्तीय संस्थानों को व्यक्तियों की साख का बेहतर मूल्यांकन करने में मदद करेगा, और इस प्रकार बेहतर ऋण निर्णय लेने में मदद करेगा।

- भले ही व्यक्तिगत उधारकर्ताओं की साख का आकलन करने के लिए सिबिल जैसे तंत्र पहले से मौजूद हैं, उनका दायरा सीमित है।
- उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का पैन नंबर केवल सीमित संख्या में लेन-देन को कैप्चर करता है, जो एक निश्चित न्यूनतम सीमा राशि से अधिक मूल्य के होते हैं।
- ऐसा कहा जाता है कि यह ढांचा वित्तीय फर्मों को डेटा की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करेगा, जिससे वे क्रेडिट योग्य आबादी की सेवा करने के लिए और अधिक इच्छुक हो जाएंगे जिन्हें उन्होंने पहले अनदेखा किया था।
- ऐसा माना जाता है कि अकाउंट एग्रीगेटर क्रेडिट योग्य ग्राहकों के लिए अपने वित्तीय डेटा को आसानी से डिजिटल रूप से साझा करने की अनुमति देकर उनके जीवन को आसान बना सकते हैं।
- व्यापक वित्तीय डेटा की उपलब्धता से वित्तीय संस्थानों को व्यक्तिगत ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर उत्पाद पेश करने में मदद मिल सकती है।

क्या सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए गए हैं?

- डेटा चोरी के जोखिम को देखते हुए, व्यक्तियों के वित्तीय डेटा की सुरक्षा का मुद्दा आगे चलकर एक गंभीर चिंता का विषय होगा।
- व्यक्तियों की गोपनीयता की रक्षा के लिए, खाता एग्रीगेटर्स को एन्क्रिप्टेड रूप में वित्तीय डेटा प्राप्त करना और साझा करना चाहिए।
- आरबीआई ने यह भी कहा है कि डेटा का स्वामित्व व्यक्तियों के पास रहेगा।

आगे की राह

- डेटा तक पहुंच के लाभों को देखते हुए और अधिक वित्तीय फर्मों के ढांचे में शामिल होने की उम्मीद है।
- समय के साथ, वित्तीय संस्थान व्यक्तियों को ऋण और अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए एक शर्त के रूप में खाता एग्रीगेटर से डेटा अनिवार्य कर सकते हैं।
- कुछ लोगों का मानना है कि किसी व्यक्ति का पैन नंबर उसके वित्तीय डेटा तक पहुंचने का एक बेहतर तरीका हो सकता है क्योंकि यह एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए कई खातों के बीच एक सामान्य लिंक के रूप में कार्य करता है।
- हालांकि, रूपरेखा की अंतिम सफलता कई कारकों पर निर्भर करेगी। वित्तीय फर्म किस हद तक अपने ग्राहकों से व्यापक, सूक्ष्म-स्तरीय वित्तीय डेटा चाहते हैं और ग्राहकों में अपने डेटा को साझा करने के लिए उत्साह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

वैश्विक तापन एवं स्थायी तुषार

संदर्भ: हाल ही में, आईपीसीसी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने चेतावनी दी है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि होने से आर्कटिक स्थायी तुषार (पर्माफ्रॉस्ट) में कमी आएगी एवं भूमि के हिम द्रवण से मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हरितगृह गैसों के मुक्त होने की संभावना है।

पर्माफ्रॉस्ट क्या है?

- इसे भूमि – मृदा, चट्टान एवं कोई भी जिसमें हिम या कार्बनिक पदार्थ सम्मिलित हो- जो निरंतर न्यूनतम दो वर्षों तक शून्य डिग्री सेल्सियस पर अथवा उससे नीचे रहता हो, के रूप में परिभाषित किया गया है।
- स्थायी तुषार (पर्माफ्रॉस्ट) 23 मिलियन वर्ग किमी से अधिक के क्षेत्र में विस्तृत है, जो विश्व के लगभग 15% भूमि क्षेत्र को आच्छादित करता है।

बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने पर तत्काल प्रभाव क्या होंगे?

- **भौतिक अवसंरचना खतरे में:** पहला प्रभाव जो बहुत तेजी से होता है, उन देशों को प्रभावित करेगा जहां सड़कों या इमारतों का निर्माण पर्माफ्रॉस्ट पर किया गया था।
 - रूसी रेलवे एक उदाहरण है।
 - कनाडा के उत्तर-पश्चिम में, सड़क का एक छोटा सा हिस्सा है जहां सड़क की नींव को शीतलित करने हेतु भूमि को ठंडा करना आवश्यक है, ताकि पर्माफ्रॉस्ट को संरक्षित किया जा सके।
- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन:** यदि पर्माफ्रॉस्ट ग्राउंड पिघलना (पिघलना) शुरू हो जाता है, तो जमे हुए कार्बनिक पदार्थ माइक्रोबायोटा के टूटने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। कुछ वातावरणों में, बायोटा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन छोड़ेगा।

पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने के त्वरित प्रभाव

- पर्माफ्रॉस्ट में अब अन्तर्हित (दबे) कार्बन की कुल मात्रा लगभग 1500 अरब टन अनुमानित है एवं भूमि के शीर्ष तीन मीटर में लगभग 1000 अरब टन है।
- विश्व इस समय वातावरण में प्रतिवर्ष लगभग 10 अरब टन कार्बन का उत्सर्जन करती है।

- इस परिदृश्य में, यदि पर्माफ्रॉस्ट द्रवित हो जाता है एवं किसी एक वर्ष में हिमीभूत हुए कार्बन का 1% भी मुक्त करता है, तो यह औद्योगिक उत्सर्जन के संबंध में हमारे द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य को निष्प्रभावी कर सकता है।

तो, क्या हमें इन उत्सर्जनों को समझने के लिए और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है जो हो सकते हैं?

- हाँ, हम करते हैं। अब तक का अधिकांश प्रयास यह अनुमान लगाने में रहा है कि पर्माफ्रॉस्ट में कितना कार्बन है। वहीं वैज्ञानिक प्रयास किया गया है।
- वर्तमान में, कुछ प्रमाण हैं, कि कुछ पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्र कार्बन स्टोराइस से कार्बन के शुद्ध उत्सर्जक स्थान बन गए हैं।
- एक और बात, जिसका अध्ययन किया जाना है, वह है जंगल की आग की संख्या में वृद्धि। इस वर्ष रूस में वनों में आग लगी जिसका कुल क्षेत्रफल पुर्तगाल के आकार के बराबर था।
- सामान्य तौर पर, आग लगने के बाद, अगले 50-60 वर्षों में वनों के वापस विकास करने की उम्मीद की जाती है।
- किंतु टुंड्रा में, पीट वह स्थान है जहां कार्बनिक पदार्थ होते हैं और इसे संचित होने में अत्यंत लंबा समय लगता है। इसलिए, जब पीट को जलाया जाता है एवं पुनः वायुमंडल में मुक्त किया जाता है, तो उस कार्बन स्टॉक को जमीनी स्तर पर पुनः स्थापित करने में सदियां लगेगी।

क्या पर्माफ्रॉस्ट को पिघलाने से नए बैक्टीरिया या वायरस निकल सकते हैं? क्या यह एक और महामारी का कारण बन सकता है?

- इसका उत्तर है कि पर्माफ्रॉस्ट के कई रहस्य हैं। हाल ही में, रूस में पर्माफ्रॉस्ट में मैमथ (mammoths) शव पाए गए थे।
- और इनमें से कुछ विशाल शव जब वे फिर से सड़ने लगते हैं तो उनमें बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगते प्रकट हैं जो हजारों साल पहले जमे हुए थे। ये बैक्टीरिया और वायरस घातक हो सकते हैं।
- जब हजारों साल पहले पर्माफ्रॉस्ट का गठन किया गया था, उस क्षेत्र में बहुत से इंसान नहीं रहते थे जो बहुत ठंडा था। हालाँकि, अब पर्यावरण न केवल मानव जीवन के लिए, बल्कि वायरस और बैक्टीरिया के विकास के लिए हिमयुग की तुलना में बहुत अधिक उपयुक्त है।

इंटरनेट शटडाउन

संदर्भ: जनवरी 2020 में, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इंटरनेट के माध्यम से सूचना तक पहुंच भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है।

- यह माना गया कि सरकार द्वारा इंटरनेट एक्सेस पर कोई भी प्रतिबंध अस्थायी, सीमित दायरे, वैध, आवश्यक और आनुपातिक होना चाहिए।
- साथ ही, इंटरनेट एक्सेस को प्रतिबंधित करने वाले सरकार के आदेश न्यायालयों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं।

- अपेक्षा यह थी कि इंटरनेट निलंबन का आदेश केवल उन्हीं असाधारण स्थितियों में दिया जाएगा जहां सार्वजनिक आपात स्थिति या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है।

इंटरनेट शटडाउन की आलोचना उत्तर कुंजी

- **सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दरकिनार:** सरकार ने अनुराधा भसीन मामले में निर्देश को वैधानिक मान्यता देने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। वास्तव में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के वर्ष में, भारत में पिछले वर्ष की तुलना में इंटरनेट बंद होने के अधिक मामले देखे गए।
- **आदेशों का प्रकाशन न होना:** अधिकारियों द्वारा इंटरनेट निलंबन आदेश सरकार की वेबसाइटों पर अपलोड नहीं किए जाते हैं, जैसा कि अनुराधा भसीन मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य किया गया था।
- **न्यायिक सहारा में बाधाएं:** जब तक इन आदेशों को प्रकाशित नहीं किया जाता है, तब तक पीड़ित नागरिक कानून की अदालत में नहीं जा सकते हैं।
- **विश्वास की कमी:** सार्वजनिक रूप से प्रकट किए गए कारणों के बिना प्रतिबंध विश्वास की कमी पैदा करते हैं और सरकार में जनता के विश्वास को कम करते हैं।

- **जागरूकता की कमी:** आईटी अधिनियम की धारा 66ए के अनुभव से पता चला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को वैधानिक रूप से मान्यता नहीं दी जाती है, तो अधिकारी जागरूकता की कमी के कारण कानून को गलत तरीके से लागू करते हैं।
- **आर्थिक नुकसान:** 2020 में, इंटरनेट निलंबन के 129 अलग-अलग उदाहरणों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को 2.8 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, जिससे 10.3 मिलियन लोग प्रभावित हुए।
- **व्यापक प्रभाव:** इस तरह के निलंबन से होने वाले नुकसान - आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और पत्रकारिता इस निलंबन के किसी भी लाभ से अधिक है।

निष्कर्ष

- दुनिया के "इंटरनेट शटडाउन कैपिटल" के टैग से खुद को मुक्त करने और डिजिटल इंडिया की क्षमता को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अधिक वफादार अनुपालन की आवश्यकता है।

स्थानीय आरक्षण और उसका क्रियान्वयन

संदर्भ: हाल ही में विधानसभा ने 'झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक, 2021' को पारित कर दिया, जो आंध्र प्रदेश और हरियाणा के बाद देश का तीसरा राज्य बन गया, जहां निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला कानून है। जिसके तहत निजी क्षेत्र में 40 हजार रुपये प्रतिमाह तक के वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

स्थानीय आरक्षण क्यों?

- स्थानीय आरक्षण का विचार रोजगार की कमी और सरकारों द्वारा अपने घरेलू मतदाताओं को संतुष्ट करने की आवश्यकता के मुद्दों से प्रेरित है

ऐसे कानून लाने का सरकार का क्या औचित्य है?

- पर्याप्त समानता प्राप्त करने के लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता है: सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में सभी नौकरियों का केवल एक छोटा हिस्सा होता है, विधायकों ने सभी नागरिकों के लिए समानता के संवैधानिक जनादेश को प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की बात की है।
- **निजी क्षेत्र को बोझ साझा करने के लिए कहने का वैध अधिकार:** चूंकि निजी उद्योग कई तरह से सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हैं (बुनियादी ढांचे, सब्सिडी वाली भूमि और ऋण, आदि) राज्य के पास आरक्षण नीति का पालन करने की आवश्यकता का वैध अधिकार है।

- **शिक्षा में इसी तरह के आरक्षण को बरकरार रखा गया था:** निजी स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन करने की आवश्यकता में एक समान तर्क दिया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था।
- **अन्य देशों में इसी तरह की सकारात्मक कार्रवाई:** हालांकि, अमेरिका में नियोक्ताओं के कोटा रखने के लिए कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है, अदालतें भेदभाव के शिकारियों के लिए मौद्रिक क्षति और निषेधाज्ञा राहत का आदेश दे सकती हैं (अमेरिकी नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 के आधार पर रोजगार भेदभाव को प्रतिबंधित करता है) जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, धर्म और लिंग)। कनाडा में एम्प्लॉयमेंट इक्विटी एक्ट भी अल्पसंख्यक समूहों, विशेष रूप से आदिवासियों को संघीय रूप से विनियमित उद्योगों में, यहां तक कि निजी क्षेत्र में भी भेदभाव से बचाता है।
- राज्य स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण की घोषणा करते हैं, लेकिन इसे लागू करने में विफल हुए
- हालांकि इसने राजनीतिक कर्षण प्राप्त किया है, स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण कानूनी चुनौतियों और उद्योग प्रतिरोध दोनों के साथ मिला है, और किसी भी राज्य में मुश्किल से लागू किया गया है।

आंध्र प्रदेश के बारे में

- आंध्र प्रदेश उद्योग और कारखानों में स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम 17 जुलाई, 2019 को पहली बार राज्य विधानसभा में पारित किया गया था।
- कानून मौजूदा और आगामी दोनों उद्योगों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण को अनिवार्य देता है।
- कानून में प्रावधान हैं कि एक कंपनी को छूट दी जाती है यदि वह सरकार को बताती है कि उसे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध विशेष जनशक्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए राज्य के उद्योग विभाग द्वारा एक परीक्षा की आवश्यकता होगी।
- सरकार ने उद्योगों से यह भी पूछा है कि उन्हें कौन से कौशल सेट की आवश्यकता है, ताकि वे लोगों को प्रशिक्षित कर आवश्यकताओं की आपूर्ति भी कर सकें।
- उद्योग नाराज है क्योंकि यह उन पर प्रतिबंध लगाता है और निवेशकों के लिए कोई छूट नहीं है।
- कानून को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह संविधान के अनुच्छेद 16(2) और 16(3) का उल्लंघन करता है।
- कानून अभी भी प्रभावी है, हालांकि अप्रभावी तरीके से न्यायपालिका की ओर से कोई रोक नहीं है, जिसे अभी अंतिम फैसला देना बाकी है।

हरियाणा में बहस

- हरियाणा सरकार ने एक कानून पारित किया जो निजी क्षेत्र की नौकरियों में निवास प्रमाण पत्र (अधिवास) रखने वालों को 75% आरक्षण प्रदान करता है।
- यह कानून 10 साल की अवधि के लिए लागू होगा।
- कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि नया कानून न्यायिक जांच के दायरे में नहीं आएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हरियाणा में रहने वाले स्थानीय उम्मीदवारों को नौकरियों में वरीयता संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)(g) के उल्लंघन में थी।
- भारत एक राष्ट्र है और केवल एक ही नागरिकता है। किसी व्यक्ति को केवल इसलिए बाहरी व्यक्ति मानना क्योंकि वह एक राज्य का निवासी नहीं है, राष्ट्र की अनिवार्य अखंडता के विरुद्ध है।

निष्कर्ष

- हालांकि यह जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों की है, लेकिन उद्योग/श्रम विभागों के पास कर्मचारियों की कमी के कारण कोई सख्त कार्यान्वयन नहीं किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये आरक्षण मुश्किल से भूमि पर आएंगे।

दूरसंचार राहत पैकेज: AGR बकाया पर 4 साल की मोहलत

संदर्भ: हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत उपायों को मंजूरी दी जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के लिये राहत पैकेज के तहत कंपनियों को स्पेक्ट्रम और AGR बकाये के भुगतान को लेकर चार साल के लिये मोहलत का विकल्प दिया है।
- **AGR की सरलीकृत परिभाषा:** संभावित आधार पर (अब से) दूरसंचार कंपनियों के गैर-दूरसंचार राजस्व को छोड़कर AGR की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाया गया है।
 - दूरसंचार ऑपरेटरों को सरकार को 'राजस्व हिस्सेदारी' के रूप में लाइसेंस और स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।
 - इस राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली राजस्व राशि को समायोजित सकल राजस्व या AGR कहा जाता है।
- **FDI में छूट:** स्वतः मार्ग के माध्यम से दूरसंचार में 100 प्रतिशत FDI को मंजूरी दी गई है (पहले 49% थी।)
- प्रभागों को युक्तिसंगत बनाया गया: लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम शुल्क और सभी प्रकार के शुल्कों के भुगतान पर भारी ब्याज, जुर्माना और जुर्माना पर ब्याज की व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाया गया है।

- **ब्याज कम किया गया :** केंद्र मासिक के बजाय वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज करेगा। यह ब्याज MCLR की 'उचित' दर प्लस 2% पर लगाया जाएगा।
 - MCLR का तात्पर्य उस न्यूनतम ऋण दर से है जो बैंकों को देने की अनुमति है - निधियों की सीमांत लागत-आधारित उधार दर।
- स्पेक्ट्रम उपयोग की लंबी अवधि: स्पेक्ट्रम नीलामी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में आयोजित की जाएगी। स्पेक्ट्रम की नीलामी 20 साल के बजाय 30 साल के लिए की जाएगी। 10 साल की लॉक-इन अवधि पूरी करने के बाद, खरीदार के पास सरेंडर शुल्क का भुगतान करके आत्मसमर्पण करने का विकल्प होगा।
- **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस:** स्पेक्ट्रम शेयरिंग को पूरी तरह से अनुमति देकर इसे मुफ्त कर दिया गया है। इसके अलावा, प्रीपेड, पोस्ट-पेड के बीच स्थानांतरण के लिए नए केवाईसी की आवश्यकता नहीं होगी।

इन सुधारों की पृष्ठभूमि क्या है?

- अक्टूबर 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार ऑपरेटरों को दूरसंचार विभाग को लंबित AGR-बकाया के रूप में 1.47 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था।

- हालांकि, सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगभग 1.47 लाख करोड़ रुपये के अपने AGR बकाया को चुकाने के लिए दूरसंचार कंपनियों को 10 साल का समय दिया था।
- इन AGR बकाया (जियो के प्रवेश के कारण व्यवधान के साथ) ने विभिन्न दूरसंचार कंपनियों के नकदी प्रवाह को प्रभावित किया, जिसका दूरसंचार क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा। केवल दो प्रमुख दूरसंचार खिलाड़ियों - भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के साथ एकाधिकार के उभरने की आशंका थी।
- हालांकि, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए इच्छुक थी कि इस क्षेत्र में अधिक प्लेयर हों और ग्राहक बनाए रखने के विकल्प हों। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा हमेशा बेहतर कीमतों और तकनीक की ओर ले जाएगी।

महत्व

- **कई दूरसंचार कंपनियों को राहत:** पैकेज कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया के लिए राहत प्रदान करता है, जिस पर अभी भी AGR बकाया के रूप में सरकार का लगभग 50,000 करोड़ रुपये है। यह टाटा समूह (12,601 करोड़ रुपये का बकाया) और एयरसेल (12,389 करोड़ रुपये) को भी राहत प्रदान करता है।
- **नकदी की कमी वाले दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत:** AGR बकाया पर अधिस्थगन उद्योग के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए की वार्षिक नकदी प्रवाह राहत प्रदान करता है, जबकि स्पेक्ट्रम बकाया पर अधिस्थगन समग्र रूप से 32,000 करोड़ रुपए वार्षिक नकदी प्रवाह राहत देता है।

चिंता

- इसलिए सुधार पैकेज दूरसंचार कंपनियों को अपने नकदी प्रवाह को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने की सुविधा प्रदान करता है और दूरसंचार उद्योग में विकास को बढ़ावा देता है।
- **सुरक्षा स्वास्थ्य बैंकिंग :** दूरसंचार कंपनियों के लिए बैंकिंग क्षेत्र का जोखिम 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। दूरसंचार पैकेज बैंकों के लिए एक राहत के रूप में है क्योंकि यह कमजोर दूरसंचार (वोडाफोन) द्वारा डिफॉल्ट की संभावना को रोकता है। इससे इस क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करने में मदद मिलेगी।
- **डिजिटल भविष्य को बढ़ावा :** ये नए सुधार भविष्य की डिजिटल प्रौद्योगिकियों में निवेश करने और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए दूरसंचार प्रयासों को बढ़ावा देंगे।
- **पिछले बकाया बने रहेंगे:** AGR की परिभाषा में बदलाव जो दूरसंचार कंपनियों पर बोझ को कम करेगा, केवल संभावित रूप से लागू होता है, इसलिए वे पिछले बकाया देय बने रहेंगे।
- **अस्थायी उपाय:** हालांकि यह उनके घर को व्यवस्थित करने के लिए समय प्रदान करता है, दूरसंचार कंपनियों की समग्र देयता कम नहीं होती है और अंततः उन्हें पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करने के लिए टैरिफ बढ़ाना होगा। AGR का बकाया ब्याज सहित देना होगा।
- **अधूरी मांगें:** टेलीकॉम फ्लोर टैरिफ निर्धारित करने में सरकार के हस्तक्षेप की लंबे समय से चली आ रही मांग, जैसा कि प्रतिस्पर्धा की रक्षा के लिए नागरिक उड्डयन क्षेत्र में किया गया है, को राहत पैकेज में जगह नहीं मिली।

आईडिया - 'इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर'

संदर्भ: हाल ही में सरकार ने इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एग्रीकल्चर (IDEA) नामक एक पहल शुरू की है जो ओपन डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाते हुए किसान को कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के केंद्र में रखेगी।

आईडिया की मुख्य विशेषताएं

- इसमें एक राष्ट्रीय किसान डेटाबेस शामिल होगा, जो किसानों के लिए एक तरह का 'सुपर आधार (super Aadhaar)' होगा।
- डेटाबेस में किसानों के डिजिटलीकृत भूमि रिकॉर्ड और आधार डेटाबेस के साथ क्रॉस-लिंकड शामिल होंगे ताकि एक अद्वितीय FID या किसानों की ID बनाई जा सके।
 - सितंबर 2021 तक 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के डेटा को राष्ट्रीय डेटाबेस में शामिल किया गया है।
- इसके अलावा, यह पीएम किसान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना आदि जैसी योजनाओं से जानकारी प्राप्त करेगा।

- डेटाबेस का निर्माण Microsoft द्वारा कृषि और किसान कल्याण विभाग (DoAFW) के तत्वावधान में किया जा रहा है।
- यह डेटाबेस किसी को भी इस तक पहुंच बनाने में सक्षम करेगा-
 - विशिष्ट रूप से भूमिधारक की पहचान करना।
 - उसकी पकड़ की सीमा जानना।
 - मिट्टी की स्थिति।
 - फसल पैटर्न और औसत उपज।
 - और ऐसी अन्य जानकारी बारीक स्तर पर।

आईडिया का बड़ा उद्देश्य क्या है?

- **एग्री-स्टैक:** FID का निर्माण भव्य आईडिया का केवल एक हिस्सा है। योजना 'इंडिया स्टैक' के बराबर कृषि बनाने की है - APIs (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) का एक सेट। ये ऐप हितधारकों किसानों को सक्रिय और व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान

करने और कृषि क्षेत्र की दक्षता में सुधार करने में सक्षम बनाता है।

- **सहयोग के माध्यम से नवाचार:** यह एग्रीकल्चरल इंडिया स्टैक सरकारों, व्यवसायों, स्टार्ट-अप्स और डेवलपर्स को एक अद्वितीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने की अनुमति देगा ताकि भारत की उपस्थिति-कम, कागज रहित और कैशलेस सेवा वितरण की कठिन समस्याओं को हल किया जा सके।
- **गवर्नेंस डिलीवरी:** FID किसानों को दी जाने वाली सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंच के लिए 'सिंगल साइन-ऑन' को सक्षम करेगा।
- **साक्ष्य आधारित नीति निर्माण:** कृषि क्षेत्र के लिए ऐसा डेटाबेस, बड़े डेटा और विश्लेषण द्वारा तथा सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित, अधिकारियों को निर्बाध ऋण और बीमा सेवाएं, बीज, उर्वरक, कीटनाशकों, बाजार की जानकारी और मूल्य पूर्वानुमान आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
- 'एग्रिस्टैक', जिसे सरकार उम्मीद कर रही है, अंततः किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी।

चुनौतियों

बैड बैंक: NARCL-IDRCL

संदर्भ: हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स' की पुनर्प्राप्ति के लिये 'नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड' (NARCL) को शामिल किया है।

- NARCL एक नई बैड बैंक संरचना का हिस्सा है, जिसकी घोषणा बजट 2021 में की गई थी।
- NARCL विभिन्न चरणों में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों से लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की दबाव वाली संपत्ति का अधिग्रहण करेगी।
- **IDRCL:** एक अन्य संस्था 'इंडिया डेब्ट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड' (IDRCL) बाजार में तनावग्रस्त संपत्तियों को बेचने की कोशिश करेगी।
- NARCL-IDRCL संरचना एक नई 'बैड बैंक' संरचना है।
- इसे काम करने के लिए, सरकार ने गारंटी के रूप में 30,600 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

एक बैड बैंक क्या है?

- हर देश में, वाणिज्यिक बैंक जमा स्वीकार करते हैं और ऋण देते हैं।
- जमा एक बैंक की "दायित्व" है क्योंकि यह वह पैसा है जो उसने एक आम आदमी से लिया है, और जमाकर्ता द्वारा मांगे जाने पर उसे वह पैसा वापस करना होगा।

- भारत में 14 करोड़ से अधिक कार्यरत फार्म हैं जो डिजिटलीकरण प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं।
- सामान्य रूप से भारत के भूमि रिकॉर्ड और ग्रामीण, विशेष रूप से कृषि भूमि रिकॉर्ड जटिल और सामान्य मानक नहीं हैं।
- लगभग 12% कृषि परिवार पट्टे पर दी गई भूमि पर संचालित होते हैं - दूसरे शब्दों में, वे काश्तकार किसान हैं। हालांकि, भारत में भूमि काश्तकारी समझौतों की कोई कानूनी मान्यता नहीं है, ऐसे अधिकांश समझौते अनौपचारिक और मौखिक होते हैं। ऐसे मामले में, एफआईडी इन किसानों को लाभ प्राप्त करने से बाहर कर देगा, क्योंकि वे डेटाबेस में बिल्कुल भी नहीं हैं।
- फिर महिला किसानों की समस्या है क्योंकि अधिकांश भूमि का मालिकाना हक पुरुषों के पास है।
- इस बात की चिंता है कि एग्रीस्टैक कृषि को दी जाने वाली सरकारी सेवाओं के पूर्ण निजीकरण का अग्रदूत है।
- डेटा गोपनीयता पर भी बड़ी चिंता है। डेटा गोपनीयता कानून के अभाव में इस तरह की संवेदनशील, वित्तीय और जमीन से जुड़ी जानकारी देना संभावित दुरुपयोग पर कई समस्याएं पैदा करता है।

- इसके अलावा, अंतरिम में, जमाकर्ता को उन जमाराशियों पर ब्याज दर का भुगतान करना होगा।
- इसके विपरीत, बैंक जो ऋण देते हैं, वे उनकी "संपत्ति" होते हैं क्योंकि यह वह जगह है जहां बैंक ब्याज कमाते हैं और यह वह धन है जिसे उधारकर्ता को बैंक को वापस करना होता है।
- संपूर्ण व्यवसाय मॉडल इस विचार पर आधारित है कि बैंक जमाकर्ताओं को वापस भुगतान करने की तुलना में उधारकर्ताओं को ऋण देने से अधिक धन अर्जित करता है।
- एक लोन बैड हो सकता है जब उधारकर्ता इसे वापस चुकाने में असमर्थ हो। ऐसे में दो चीजें होती हैं।
 - एक, संबंधित बैंक कम लाभदायक हो जाता है क्योंकि उसे अन्य ऋणों से अपने कुछ लाभ का उपयोग जमा ऋणों पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए करना पड़ता है।
 - दो, यह अधिक जोखिम-प्रतिकूल हो जाता है। दूसरे शब्दों में, इसके अधिकारी ऋण देने से हिचकिचाते हैं।
- अगर बैंक में ऐसे "बैड लोन" खतरनाक रूप से बढ़ते हैं, तो बैंक बंद हो सकता है।

- जब एक अर्थव्यवस्था में कई बैंक उच्च स्तर के जमा ऋणों का सामना करते हैं और सभी एक ही समय में, यह पूरी अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए खतरा होगा।
- करदाता के दृष्टिकोण से, सबसे चिंताजनक तथ्य यह था कि खराब ऋणों का एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के पास था, जो सरकार के स्वामित्व में थे और इसलिए जनता के पास थे।
- ऐसे पीएसबी को व्यवसाय में रखने के लिए, सरकार को उन्हें पुनर्पूजीकरण करने के लिए मजबूर किया गया था - अर्थात् करदाताओं के पैसे का उपयोग PSB के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए किया गया था ताकि वे आर्थिक गतिविधियों को उधार देने और वित्त पोषण के व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें।
- पुनर्पूजीकरण के बावजूद जमा ऋणों की समस्या कम नहीं हुई। इसलिए कई लोगों द्वारा यह तर्क दिया गया कि सरकार को एक बैड बैंक बनाने की आवश्यकता है - यानी, एक ऐसी संस्था जहां सभी बैंकों के सभी बैड लोन पार्क किए जा सकें।

बैड बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी?

बैड बैंक होने का फायदा था

- वाणिज्यिक बैंकों को उनकी "तनावग्रस्त संपत्तियां" से राहत देना और उन्हें सामान्य बैंकिंग परिचालन, विशेष रूप से उधार देने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देना है।
- जबकि वाणिज्यिक बैंक उधार देना फिर से शुरू करते हैं, तथाकथित बैड बैंक, या बैड लोन का बैंक, इन "परिसंपत्तियों" को बाजार में बेचने की कोशिश करेगा।

NARCL-IDRCL की कार्यप्रणाली और गारंटी की पेशकश:

- सर्वप्रथम NARCL बैंकों से बैड लोन की खरीद करेगा। यह सहमत मूल्य (Agreed Price) का 15% नकद में भुगतान

करेगा और शेष 85% "सुरक्षा रसीद" (Security Receipts) के रूप में होगा।

- जब संपत्तियां बेची जाती हैं तो IDRCL की मदद से वाणिज्यिक बैंकों को बाकी का भुगतान किया जाएगा।
- यदि बैड बैंक बैड लोन को बेचने में असमर्थ है, या उसे घाटे में बेचना है, तो सरकारी गारंटी लागू होगी। वाणिज्यिक बैंक को क्या मिलना चाहिये था और बैड बैंक क्या जुटाने में सक्षम था, इसके मध्य का अंतर सरकार द्वारा प्रदान किये गए 30,600 करोड़ रुपये से पूरा किया जाएगा।

क्या एक बैड बैंक मामलों को सुलझाएगा?

- वाणिज्यिक बैंक उच्च NPA स्तर के कारण परेशान हैं, बैड बैंक की स्थापना से इससे निपटने में मदद मिलेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंक अपनी सभी ऐसी संपत्तियों से छुटकारा पा लेगा, जो एक त्वरित कदम में उसके मुनाफे को कम कर रहे थे।
- जब वसूली का पैसा वापस भुगतान के रूप में दिया जाएगा, तो यह बैंक की स्थिति में सुधार करेगा। इस बीच यह फिर से उधार देना शुरू कर सकता है।
- सरकार और करदाता परिप्रेक्ष्य: चाहे डूबे हुए ऋणों से ग्रसित PSB का पुनर्पूजीकरण हो या सुरक्षा रसीदों की गारंटी देना हो, पैसा करदाताओं की जेब से आ रहा है।
- अगर बैड बैंक बाजार में ऐसे बैड एसेट्स को बेचने में असमर्थ रहते हैं तो वाणिज्यिक बैंकों को राहत देने की योजना ध्वस्त हो जाएगी। इसका भार वास्तव में करदाता पर पड़ेगा।

निष्कर्ष

- जबकि पुनर्पूजीकरण और इस तरह की गारंटी को प्रायः "सुधार" के रूप में नामित किया जाता है, वे एक अच्छे रूप में बैंड अनुदान/सहायता (Band Aids) हैं। PSBs में ऋण देने की प्रक्रिया में सुधार करना ही एकमात्र स्थायी समाधान है।

ई-श्रम पोर्टल

संदर्भ: 26 अगस्त, 2021 को श्रम और रोजगार मंत्रालय (MOLE) ने ई-श्रम की शुरुआत की।

- यह असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW) बनाने के लिए वेब पोर्टल है, जिसे आधार के साथ जोड़ा जाएगा।
- यह अनुमानित 398-400 मिलियन असंगठित कामगारों को पंजीकृत करने और उन्हें 12 अंकीय विशिष्ट संख्या वाला ई-श्रम कार्ड जारी करने की इच्छा रखता है।
- पोर्टल पर पंजीकरण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति 2 लाख रुपये प्रति वर्ष के दुर्घटना कवरेज का पात्र होगा जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के अंतर्गत वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है।

मुद्दे

- **ढीली प्रक्रिया:** प्रत्येक कार्यकर्ता को पंजीकृत करने की बड़ी प्रकृति को देखते हुए, यह एक लंबी प्रक्रिया होगी।
- **डेटा-सुरक्षा संबंधी मुद्दे:** कड़े डेटा संरक्षण कानून के अभाव में, पोर्टल की प्रमुख चिंताओं में से एक डेटा-सुरक्षा और इसका संभावित दुरुपयोग है क्योंकि यह एक वृहत आकार का डेटाबेस है। केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ डेटा साझा करना होगा जिनकी डेटा सुरक्षा क्षमता अलग-अलग है।
- **निश्चित मुद्दे:** EPF और ESI के दायरे में शामिल कामगारों के बहिर्वेशन से लाखों संविदा कामगार (contract workers) असंगठित कामगारों के दायरे से बाहर कर दिये जाएंगे।

- **हमेशा बदलती पहचान:** असंगठित की जटिल और हमेशा बदलती पहचान हो सकती है जहां वे औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों के बीच चलते हैं।
- **‘गिग’ कामगारों के बारे में अस्पष्टता:** हालांकि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ‘गिग’ कामगारों (Gig Workers) को इस प्रक्रिया में शामिल किया है, अन्य तीन श्रम संहिताएं उन्हें कामगार के रूप में शामिल नहीं करतीं, न ही सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code) उन्हें विशेष रूप से शामिल करती हैं, जब तक कि वे ‘self-employed’ या ‘wage workers’ घोषित नहीं हों।
- **संघीय चुनौतियाँ:** संघ योजना बनाता है लेकिन राज्यों को इसे लागू करना होता है। राज्य की क्षमताओं में अंतर कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

- भ्रष्टाचार - इंटरनेट प्रदाता जैसी मध्यम सेवा एजेंसियां ई-श्रम कार्डों को पंजीकृत करने और प्रिंट करने के लिए अत्यधिक शुल्क ले सकती हैं।

आगे की राह

- भ्रष्टाचार के मुद्दों के समाधान के लिए निगरानी एजेंसियों की भागीदारी महत्वपूर्ण है।
- पंजीकरण प्रणाली की दक्षता का आकलन करने के लिए सरकार को पंजीकरण के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर आंकड़े प्रकाशित करने चाहिए।
- एक राष्ट्र-एक-राशन कार्ड, ई-श्रम कार्ड (विशेष रूप से बैंक खाता सीड) और चुनाव आयोग कार्ड का ट्रिपल लिंकेज, कुशल और रिसाव-रहित वितरण के लिए किया जा सकता है।

AUKUS

संदर्भ: 15 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के शासनाध्यक्षों ने एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते के गठन की घोषणा की, जिसे औक्स के नाम से जाना जाएगा।

AUKUS के प्रमुख पहलू

- AUKUS समझौता ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को तैनात करने की तकनीक और क्षमता प्रदान करेगा।
 - इसका मतलब होगा कि कम से कम आठ परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया में बनी हैं, और यह पहली बार होगा जब यूके और यूएस ने किसी अन्य देश के साथ परमाणु क्षमता साझा की है।
 - ये पनडुब्बियां संभावित रूप से उन्नत अमेरिकी हथियारों जैसे मार्क-48 टॉरपीडो, हार्पून एंटी-शिप मिसाइलों और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से पूरी तरह सुसज्जित होंगी।
- अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर युद्ध, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि जैसे क्षेत्रों में खुफिया और उन्नत तकनीकों को साझा करेंगे।

AUKUS का महत्व

- ऑस्ट्रेलिया हिंद-प्रशांत में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में और अधिक मजबूत भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया के पास अब अपने संप्रभु हितों की रक्षा के लिए स्वयं का एक अधिक सार्थक नौसैनिक प्रतिरोध होगा।
- AUKUS समझौता भी यू.एस.-ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा संधि की प्रासंगिकता का दावा है।
- ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने वाला AUKUS पनडुब्बी सौदा सामरिक रक्षा सहयोग का एक उदाहरण है, और भारत-प्रशांत की समुद्री सुरक्षा वास्तुकला में एक गेम-चेंजर है।

- त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया अब चीन के साथ अपने पहले के विशुद्ध आर्थिक विचारों पर काबू पाने के लिए रणनीतिक लेंस के माध्यम से चीन का आकलन करता है।
- AUKUS यूनाइटेड किंगडम को इंडो-पैसिफिक में खुद को सीधे तौर पर फिर से स्थापित करने का एक नया अवसर प्रदान करता है।
 - यूके पहले से ही फाइव आईज (FVEY) का सदस्य है, जो एंग्लो-सैक्सन एकजुटता (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यू.एस.) पर निर्मित एक खुफिया-साझाकरण गठबंधन है।
- ऑस्ट्रेलिया की परमाणु पनडुब्बियां भारत-प्रशांत में, विशेष रूप से यू.एस. और यू.के. के साथ मिलकर शक्ति का एक नया संतुलन बनाने में मदद करेंगी।

सीमाओं

- चीन ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में अस्थिरता और हथियारों की होड़ को बढ़ावा देने के रूप में औक्स और पनडुब्बी सौदे की कड़ी आलोचना की है।
- **एंग्री फ्रांस:** 2016 से फ्रांस 12 पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों (\$90bn सौदा) का एक बेड़ा बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत कर रहा है। AUKUS की घोषणा ने ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस के साथ अपने अनुबंध को रद्द कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप फ्रांस के लिए निवेश और नौकरी के अवसरों का नुकसान हुआ है।
 - फ्रांस का कहना है कि वह "धोखा (betrayed)" महसूस कर रहा है और उसने अपने अमेरिकी राजदूतों को वापस लेने का अभूतपूर्व कदम उठाया।

- क्वाड सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, हालांकि व्यापक रूप से यह महसूस किया जाता है कि मजबूत सुरक्षा आधार के बिना यह चीन के सैन्यीकरण की वास्तविक चुनौती से निपटने में एक सीमित भूमिका निभाएगा।
- मालाबार अभ्यास एक नौसैनिक गठबंधन नहीं है, भले ही सहयोग की आदत जरूरत के समय संचार और अंतःक्रियाशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार की गई हो।

निष्कर्ष

- फ्रांस क्षेत्रीय सुरक्षा गणना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह झटका भारत जैसे भागीदारों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के लिए फ्रांस को प्रोत्साहित कर सकता है।
- अपनी खुद की लड़ाई लड़ने की तैयारी करते समय, भारत को बाहरी संतुलन की तलाश करनी होगी। यदि वास्तविक राजनीति ऐसी मांग करती है, तो उसे नई साझेदारियों पर प्रहार करना होगा - जहाँ भी हितों का अभिसरण हो।

फेडरल रिजर्व का रुख और भारत

संदर्भ: हाल ही में अमेरिकी केंद्रीय बैंक (Federal Reserve) ने दोहराया है कि जब तक मुद्रास्फीति और रोजगार के लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते, तब तक वह एक 'समायोजनवादी रुख (accommodative stance)' बनाए रखेगा।

उदार रुख क्या है?

- उदार रुख का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में विकास और मांग को पुनर्जीवित करने के लिए भविष्य में ब्याज दरों को कम करने की गुंजाइश है।
- उदार मौद्रिक नीति, जिसे ढीले ऋण या आसान मौद्रिक नीति के रूप में भी जाना जाता है, यह तब होती है जब एक केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समग्र मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करने का प्रयास करता है जब विकास धीमा होता है (जैसा कि जीडीपी द्वारा मापा जाता है)।
- राष्ट्रीय आय और मुद्रा की मांग के अनुरूप मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करने की अनुमति देने के लिए नीति लागू की गई है।

फेडरल रिजर्व ने क्या कहा?

- यूएस फेड ने महामारी के कारण आर्थिक दृष्टिकोण के लिए जोखिमों को रेखांकित किया और कहा कि यह "मौद्रिक नीति का एक उदार रुख बनाए रखना" जारी रखेगा, जब तक कि यह मुद्रास्फीति को मामूली रूप से 2 प्रतिशत से ऊपर प्राप्त नहीं कर लेता।
- फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC), जो अमेरिकी मौद्रिक नीति निर्धारित करती है, ने फेडरल फंड रेट (भारत की रेपो दर के बराबर) के लिए लक्ष्य सीमा 0 - 0.25 प्रतिशत पर रखने का फैसला किया है।

infusion of liquidity पर फेड ने क्या कहा?

- फेड ने पहले (जुलाई 2021) में कहा था कि वह संपत्ति खरीद की गति को कम (मंदी) करेगा।
 - सेंट्रल बैंक द्वारा बांड/संपत्ति खरीदने का अर्थ है बाजार में मुद्रा आपूर्ति का प्रवाह यानी तरलता में वृद्धि। फेड वर्तमान में कम से कम \$ 80 बिलियन की ट्रेजरी सिक्योरिटीज और कम से कम \$ 40 बिलियन प्रति माह की बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों की खरीद करता है।

- अमेरिका में कम ब्याज दरें और उच्च तरलता विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) से भारतीय इक्विटी में निरंतर फंड प्रवाह सुनिश्चित करेगी। अगस्त 2021 में भारतीय इक्विटी में FPI का प्रवाह 2,083 करोड़ रुपये था।
- संपत्ति खरीद में मंदी (जिसे टेपरिंग के रूप में भी जाना जाता है) का अर्थ यूएस फेड द्वारा liquidity infusion को धीमा करना है।

- अपनी हाल की बैठक में, यूएस फेडरल रिजर्व ने संकेत दिया कि उसके बांड खरीद कार्यक्रम की टेपरिंग धीरे-धीरे होगी और 2022 के मध्य में फैल जाएगी।

फेड के फैसले का मतलब क्या है?

- संपत्ति की खरीद में प्रति माह \$15 बिलियन की गिरावट आ सकती है, और 2022 के मध्य तक संपत्ति की खरीद समाप्त होने से 2023 में दरें बढ़ाने के मामले को मजबूती मिलेगी।
- इसे मजबूती के संकेत के रूप में देखा जाता है कि अमेरिकी आर्थिक सुधार सही रास्ते पर है।
- विश्लेषकों का कहना है कि वित्तीय बाजारों के लिए टेपरिंग (बॉन्ड खरीद की मंदी) को कैलिब्रेट किया जा सकता है और गैर-विघटनकारी होने की संभावना है - जिसका अर्थ है कि विदेशी निवेशकों के अचानक भारत से बाहर निकलने की संभावना नहीं है।
- अमेरिका ने मुद्रास्फीति और रोजगार के दरों, वृद्धि कम करने के संबंध में कठोर शर्तें रखीं, इसका मतलब है कि फेड के कामकाज में अनुमान लगाया जा सकता है।

भविष्य का दृष्टिकोण क्या है?

- सहभागियों के बीच एक आम सहमति है कि भारत में उस तरह के घरेलू बाजार, आगे चलकर स्थानीय कारकों पर अधिक निर्भर होंगे।
- ऐसी आशा है कि यदि तेजी से टीकाकरण होता है तो कोविड की तीसरी लहर कम होगी और अर्थव्यवस्था फिर से खुल जाएगी और खपत-संचालित विकास में तेजी आएगी।

- दिवाली के करीब खपत बढ़ने की उम्मीद है और अगले दो

महीनों में ऋण वृद्धि में तेजी आएगी।

साइबर सुरक्षा और बैंक

संदर्भ: वित्तीय संस्थानों के लिए डिजिटलीकरण पर जोर देने के साथ-साथ साइबर सुरक्षा खतरों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- इसलिए डिजिटल बैंकिंग के लिए कड़े साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

खतरे

- **मैलवेयर (Malware) :** डिजिटल लेनदेन आम तौर पर मोबाइल, कंप्यूटर आदि जैसे एंड-टू-एंड उपयोगकर्ता उपकरणों पर किए जाते हैं। यदि एक्सेस के लिए उपयोग किए जा रहे उपकरण मैलवेयर से संक्रमित हैं, तो जब भी इससे जुड़ते हैं, वे बैंक के साइबर सुरक्षा नेटवर्क के लिए एक गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं।
- **तृतीय-पक्ष (Third-party) सेवाएं :** कई बैंक अपने ग्राहकों को बेहतर तरीके से सेवा देने में सक्षम होने के लिए Third-party विक्रेताओं की सेवाओं का उपयोग करते हैं। हालांकि अगर विक्रेता सक्रिय साइबर सुरक्षा उपाय नहीं करते हैं, तो बैंक को इसके नतीजों का सामना करना पड़ सकता है।
- **स्पूफिंग (Spoofing):** साइबर अपराधी बैंक के URL को एक वेबसाइट के साथ प्रतिरूपित करने का प्रयास करते हैं जो कि मूल वेबसाइट के समान है और इसमें समान कार्य भी हैं। जब भी कोई उपयोगकर्ता नकली वेबसाइट में तनाव के कारण लॉगिन करता है, तो अपराधियों द्वारा क्रेडेंशियल (जानकारी) चुरा लिए जाते हैं।
- **फ़िशिंग (Phishing) :** इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से अपने आप को एक प्रामाणिक, भरोसेमंद इकाई के रूप में प्रच्छन्न करके, धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए क्रेडिट कार्ड विवरण आदि जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना।

- **अनएन्क्रिप्टेड डेटा (Unencrypted data):** यह अनिवार्य है कि जो भी डेटा कंप्यूटर या बैंकों के सर्वर पर संग्रहीत है, उसे पूरी तरह से एन्क्रिप्ट करने की आवश्यकता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि डेटा चोरी होने की स्थिति में भी, साइबर अपराधियों द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

चुनौतियाँ

- **जागरूकता की कमी:** ऐसी बहुत सी कंपनियां नहीं हैं जो लोगों के बीच साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण और समग्र जागरूकता बढ़ाने में निवेश करती हैं।
- **सोशल मीडिया का बढ़ता उपयोग:** कई बार जो ग्राहक साइबर सुरक्षा उपायों से अच्छी तरह वाकिफ नहीं होते हैं, वे अंत में किसी को भी देखने के लिए डेटा फीड कर देते हैं।
- **अपर्याप्त बजट और प्रबंधन की कमी:** बजट आवंटन में अक्सर साइबर सुरक्षा की उपेक्षा की जाती है, जहां फर्म को इन खतरों के बड़े प्रभाव का एहसास नहीं होता है।

समाधान

- **एकीकृत सुरक्षा:** BFSI के रूप में विनियमित क्षेत्र में, एकीकृत सुरक्षा भविष्य है।
- **मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स:** साइबर लचीलापन का लाभ उठाने के लिए ये आवश्यक हैं।
- अपडेट किए गए एंटीवायरस और एंटी-मैलवेयर एप्लिकेशन उन हमलों से सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रदान करते हैं जो संभावित रूप से विनाशकारी हो सकते हैं।
- **Endpoint सुरक्षा (Endpoint protection):** वित्तीय संस्थानों को ऐसी तकनीकों में निवेश करने की आवश्यकता है जो Endpoint सुरक्षा को बढ़ा सकें।

नगा समझौते के लिए शांति प्रक्रिया अटकी

संदर्भ: आर एन रवि (जो पहले नागालैंड के राज्यपाल भी थे) ने नागा शांति वार्ता के वार्ताकार के रूप में इस्तीफा दे दिया है।

- नागा सूत्रों ने कहा है कि NSCN(IM) रवि को नागालैंड के राज्यपाल और वार्ताकार के पद से हटाने को एक जीत के रूप में देखता है।

नागा शांति प्रक्रिया क्या है?

- यह 1997 से नागा शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के उद्देश्य से भारत सरकार और नागा विद्रोही समूहों, विशेष रूप से

NSCN(IM) के बीच चल रही बातचीत को संदर्भित करता है।

- नागा राष्ट्रवाद में निहित नागा विद्रोह देश के सबसे पुराने विद्रोहों में से एक है।
- पूर्वोत्तर के नागा-बसे हुए क्षेत्रों ने कभी भी खुद को ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं माना और 14 अगस्त, 1947 को अंगामी ज़ापू फ़िज़ो के नेतृत्व में नागा नेशनल काउंसिल (NNC) ने नागालैंड के लिए स्वतंत्रता की घोषणा की।

- फ़िज़ो ने 1952 में एक भूमिगत नागा संघीय सरकार (NFG) और एक नागा संघीय सेना (NFA) का गठन किया, जिसके जवाब में केंद्र ने सेना को भेजा और सशस्त्र बल (विशेष) शक्ति अधिनियम, या AFSPA अधिनियमित किया।
- वर्षों की बातचीत के बाद, 1976 में नागालैंड के भूमिगत समूहों के साथ शिलांग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन NNC के कई शीर्ष नेताओं ने इसे इस खारिज कर दिया कि यह नागा संप्रभुता के मुद्दे को संबोधित नहीं करता है।
- पांच साल बाद, इसाक चिशी स्वी थुइंगलेंग मुइवा और एस एस खापलांग NNC से अलग हो गए और सशस्त्र संघर्ष जारी रखने के लिए नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN) का गठन किया।
- 1988 में, NSCN फिर से इसाक और मुइवा के नेतृत्व में NSCN(IM) और खापलांग के नेतृत्व में NSCN(K) में विभाजित हो गया।
- 1997 में, NSCN(IM) ने भारत सरकार के साथ युद्धविराम में प्रवेश किया, जिसने अंतिम समाधान की आशा को जन्म दिया।

तब से क्या हुआ है?

- लगभग 100 दौर की बातचीत हो चुकी है। अगस्त 2015 में, NSCN (IM) समूह ने नागा शांति समझौते के लिए भारत सरकार के साथ एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए। वार्ता को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए रवि को वार्ताकार नियुक्त किया गया था।
- लेकिन जब सरकार और नागा समूहों दोनों ने कहा कि सरकार की 31 अक्टूबर, 2019 की समय सीमा पर बातचीत सफलतापूर्वक संपन्न हुई, तो किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।
- वार्ता समाप्त होने के बाद रवि और NSCN (IM) के बीच संबंध खुल गए। जनवरी 2020 में, सरकार ने आईबी के विशेष निदेशक अक्षय मिश्रा ने कदम रखा और वार्ता जारी रखी।

चीजें कैसे गलत हुईं?

- जब आर एन रवि ने महसूस किया कि NSCN(IM) और भारत सरकार के बीच फ्रेमवर्क समझौते की उनकी समझ में अंतर होने के बाद चीजें खराब होने लगीं। समूह नागा संविधान पर और वर्तमान नागालैंड राज्य की सीमाओं से परे एक ग्रेटर नागालिम (Nagalim) के लिए जोर दे रहा था।
- नवंबर 2017 में, रवि ने सात समूहों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो नागा राष्ट्रीय राजनीतिक समूहों (NNPGs) के बैनर तले एक साथ आए थे, जिसमें NSCN (IM) शामिल नहीं था।

- NSCN (IM) जो खुद को नागा आकांक्षाओं का प्रमुख प्रतिनिधि मानता है, कई NNPG समूहों का प्रतिद्वंद्वी रहा है। 2020 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में, IM ने रवि पर "नागा नागरिक समाज को अलग करने" का प्रयास करने का आरोप लगाया।
- 2019 में नागालैंड के राज्यपाल बनने के बाद, आर एन रवि ने सौदे के समापन में देरी पर बेचैनी व्यक्त की। उन्होंने NSCN (IM) पर अलग नागा राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के विवादास्पद प्रतीकात्मक मुद्दों को उठाकर समझौते में देरी करने का आरोप लगाया।
- रवि ने नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो को एक पत्र लिखा, जिसमें NSCN(IM) को एक "सशस्त्र गिरोह" कहा, और उस पर "समानांतर सरकार" चलाने और जबरन वसूली में शामिल होने का आरोप लगाया।
- आर एन रवि की खुली आलोचना ने NSCN(IM) को सार्वजनिक रूप से अपनी स्थिति सख्त कर दी। इसने मांग की कि नागा ध्वज और नागा संविधान पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।
- NSCN(IM) ने दावा किया कि रूपरेखा समझौते में असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में सभी नागा बसे हुए क्षेत्रों के एकीकरण का विचार शामिल है। इसने रवि पर उन प्रमुख शब्दों को हटाकर दस्तावेज़ को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया, जो यह सुझाव देते थे कि नागालैंड एक संप्रभु के रूप में भारत के साथ सह-अस्तित्व में रहेगा।
- रवि द्वारा काउंटर कि "राष्ट्र को विघटित करने के लिए किसी भी दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा" ने NSCN (IM) को नाराज कर दिया और राज्यपाल तथा वार्ताकार के रूप में उन्हें हटाने का आह्वान किया।

इन सबके बीच असल मुद्दे क्या हैं?

- नागा मुद्दा बहुत जटिल और NSCN(IM) नाजुक स्थिति में है। इसका नेतृत्व मणिपुर का एक तंगखुल (Tangkhu) कर रहा है, जिसके लिए ग्रेटर नागालिम की मांग को छोड़ना मुश्किल है। लेकिन भारत उस मांग को स्वीकार नहीं कर सकता, और एक बीच का रास्ता निकालना होगा, जिसमें कुछ समय लग सकता है।
- दूसरी ओर, नागा ध्वज और नागा संविधान जो NSCN (IM) की मुख्य मांगों में से एक है, को अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
- जिस उत्साह के साथ 2015 में फ्रेमवर्क समझौते की घोषणा की गई, उससे अंतिम समझौते की अनुचित उम्मीदें पैदा हुईं।

आगे की राह

- सरकार ने IB के पूर्व अधिकारी अक्षय कुमार मिश्रा को बातचीत के लिए नए सूत्रधार के रूप में नियुक्त किया है। सूत्रों का कहना है कि मिश्रा, जिन्हें औपचारिक रूप से नया वार्ताकार नियुक्त किया जा सकता है, एक शांत कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, और जनवरी 2020 से नागा समूहों से बात कर रहे हैं।
- यह समझना महत्वपूर्ण है कि NSCN (IM) के बिना कोई समझौता नहीं हो सकता क्योंकि इसमें युवा भर्तियां जारी हैं और इस क्षेत्र में इसका काफी प्रभाव है।
- विचार यह है कि भारत जो दे सकता है उसे स्वीकार करने के लिए NSCN (IM) को धीरे-धीरे लाया जाए।

- कुछ मांगें जिन्हें समाप्त करने की आवश्यकता है उनमें शामिल हैं
 - विभिन्न जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कम से कम 40 मनोनीत सदस्यों वाली द्विसदनीय सभा;
 - स्थानीय सशस्त्र बलों या भारतीय अर्धसैनिक बलों में संवर्गों का समावेश;
 - पड़ोसी राज्यों के नागा बहुल क्षेत्रों में स्वायत्त परिषदों की स्थापना;
 - कम से कम प्रथागत आयोजनों के लिए नागा ध्वज का प्रयोग।

विवाह पंजीकरण

संदर्भ: हाल ही में राजस्थान ने विवाह अधिनियम, 2009 के अनिवार्य पंजीकरण में संशोधन किया, जो बाल विवाह सहित विवाह के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करता है।

नया संशोधन किस बारे में है?

- संशोधन में प्रावधान है कि यदि दुल्हन ने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और दूल्हे ने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, तो उनके माता-पिता या उनके अभिभावकों को 30 दिनों के भीतर विवाह का पंजीकरण कराना चाहिए।
- विपक्ष का आरोप था कि यह नाबालिग बच्चों को प्रमाण पत्र देने के लिए राज्य के लिए बाल विवाह को सही ठहराता है।
- लेकिन सरकार का तर्क है कि यह बिल शादी को वैध नहीं बनाता है और जिला कलेक्टर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
- 2015-16 में एकत्र किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 15 से 19 वर्ष की आयु की 16.2% लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले कर दी गई थी,
- कई लोगों का दावा है कि बाल विवाह के पंजीकरण से बाल विवाह को बढ़ावा मिलेगा/वैध होगा। क्या ये सच है?
- बाल विवाह का पंजीकरण उन्हें वैध बनाने के लिए नहीं है। प्रत्येक नाबालिग को अभी भी यह अधिकार है कि वह बालिग होने पर अपनी शादी को रद्द करवा सकता है।
- सरकार ने तर्क दिया है कि संशोधित प्रावधान नाबालिगों के वैवाहिक संबंधों की स्थिति को बदले बिना केवल पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेंगे।
- पंजीकरण संकेत देता है कि शादी हो चुकी लड़की के लिए एक स्थिति को सुरक्षित करता है।
- यह बाल विवाह करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने और उस लड़की के भरण-पोषण और निवास से संबंधित प्रावधानों

को लागू करने में भी मदद करता है, जिसका विवाह बाद में अमान्य हो गया है।

- इसके अलावा, सीमा बनाम अश्विनी कुमार, 2006 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश द्वारा, बाल विवाह सहित सभी विवाहों को पंजीकृत किया जाना है, और यह कोई नया विकास नहीं है। SC ने कहा है कि बाल विवाह, या किसी भी विवाह को 'पंजीकृत' करने का कारण दुल्हन के अधिकारों को सुनिश्चित करना है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही पंजीकरण स्वयं वैध विवाह का प्रमाण नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चों की कस्टडी, दो व्यक्तियों के विवाह से पैदा हुए बच्चों के अधिकार के मामलों में इसका बहुत महत्व होगा, जिनकी शादी पंजीकृत है।
- इसलिए, पंजीकरण लड़की को लाभ प्रदान करता है क्योंकि यह उसके वैवाहिक अधिकारों को सुरक्षित करता है जिससे उसके लिए अदालत में इन अधिकारों का दावा करना संभव हो जाता है।

भारत में बाल विवाह की वैधता

- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 बाल विवाह के अनुष्ठापन के निषेध के लिए अधिनियमित किया गया है।
- एक पुरुष जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी और एक महिला जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए 'बच्चे' है।
- कानून के तहत, बाल विवाह शून्य नहीं हैं, लेकिन केवल एक पक्ष के कहने पर शून्यकरण योग्य हैं, जो वयस्क होने के दो साल के भीतर विवाह को रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

निष्कर्ष

- इस विवाद के परिणाम के रूप में, संसद को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन करने के लिए विधि आयोग की सिफारिश पर विचार करना चाहिए, ताकि 16

साल से कम उम्र के बाल विवाह को शून्य बनाया जा सके और जब दोनों में से कोई भी पक्ष 16 और 18 के बीच था, तो वे अमान्य हो गए।

कार्टेलाइजेशन: बीयर कंपनियों पर CCI जुर्माना

संदर्भ: हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पाया कि तीन बीयर कंपनियों - यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड (UBL), कार्ल्सबर्ग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (CIPL) और Anheuser Busch InBev India (AB InBev) ने देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गुटबाजी कर 2009 से लेकर अक्टूबर 2018 के दौरान बीयर की बिक्री और आपूर्ति करने में शामिल थे।

- नतीजतन, CCI ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीयर की बिक्री और आपूर्ति में कार्टेलाइजेशन के लिए कंपनियों के साथ-साथ ऑल इंडिया ब्रूअर्स एसोसिएशन (AIBA) और 11 व्यक्तियों पर 873 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
- एबी इनबेव (AB InBev) को जुर्माने से 100% राहत मिली क्योंकि इसके अधिकारियों ने कार्टेल के कामकाज की CCI जांच में मदद की थी।
- अजीब तरह से, कंपनियों ने सरकारी नियमों को दोषी ठहराया, जिसके लिए उन्हें कार्टेल बनाने के मुख्य कारण के रूप में किसी भी मूल्य संशोधन के लिए राज्य के अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

कार्टेल क्या है?

- कार्टेल को परिभाषित करना मुश्किल हो सकता है। CCI के अनुसार, "कार्टेल में उत्पादकों, विक्रेताओं, वितरकों, व्यापारियों या सेवा प्रदाताओं का एक संघ शामिल होता है, जो आपस में समझौते द्वारा, माल के उत्पादन, वितरण, बिक्री या मूल्य, व्यापार को सीमित या नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क (ICN), जो प्रतिस्पर्धा कानून को लागू करने के लिए समर्पित एक वैश्विक निकाय है, की एक सरल परिभाषा है। कार्टेल के तीन सामान्य घटक हैं:
 - एक समझौता;
 - प्रतियोगियों के बीच;
 - प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने के लिए।
- एक कार्टेल बनाने वाला समझौता औपचारिक लिखित नहीं होना चाहिए। कार्टेल में लगभग हमेशा गोपनीयता शामिल होती है।

कार्टेल कैसे काम करते हैं?

- ICN के अनुसार, आचरण की चार श्रेणियां आमतौर पर क्षेत्राधिकारों (देशों) में पहचानी जाती हैं। ये हैं:

- दर तय करना;
- आउटपुट प्रतिबंध;
- बाजार आवंटन और
- बोली में हेराफेरी

- कुल मिलाकर, हार्ड-कोर कार्टेल में प्रतिभागी प्रतिस्पर्धा के लिए सहयोग को प्रतिस्थापित करते हुए, प्रतिस्पर्धी बाजार की कठोरता से खुद को बचाने के लिए सहमत होते हैं।

कार्टेल कैसे हर्ट (hurt) करते हैं?

- उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाता है क्योंकि कार्टेल प्रतिस्पर्धी स्तर से ऊपर कीमत बढ़ाता है और उत्पादन कम करता है।
- दूसरे शब्दों में, आपूर्ति को कृत्रिम रूप से रोककर या समन्वित तरीके से कीमतें बढ़ाकर, कंपनियां या तो कुछ उपभोक्ताओं को कमोडिटी (जैसे-बीयर) को और अधिक दुर्लभ बनाकर बाजार से बाहर करने के लिए मजबूर या ऐसा मुनाफा कमाती हैं जो मुक्त प्रतिस्पर्धा की अनुमति नहीं देता।
- उपभोक्ता की लाचारी और बेहतर कीमतों के लिए सौदेबाजी करने की शक्ति की कमी कार्टेल ऑपरेटरों को धन का हस्तांतरण सुनिश्चित करती है।
- कार्टेल के बीच गैर-प्रतिस्पर्धा और लाभ की गारंटी के स्पष्ट समझौते के कारण, किसी के उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए कोई भी प्रोत्साहन हटा दिया जाता है। इसलिए, कार्टेलिजेशन नवाचारों और समग्र आर्थिक दक्षता को कमजोर करता है।

कार्टेलिजेशन के प्रसार को कैसे रोकें?

- कार्टेल का पता लगाना और पहचानना आसान नहीं है। हालांकि, दोषी पाए जाने वाले कार्टेल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आमतौर पर, यह एक मौद्रिक दंड का रूप लेता है जो कार्टेल द्वारा अर्जित लाभ से अधिक होता है।
- जुर्माना इतना अधिक होना चाहिए कि कार्टेल द्वारा प्राप्त किसी भी लाभ की भरपाई की जा सके।
- जुर्माने के साथ-साथ, फर्मों और उनके कार्यों को उजागर करने वाले व्हिसलब्लोअर्स (whistleblowers) को प्रोत्साहित करने के लिए फर्मों को उदारता प्रदान की जानी चाहिए (जैसे एबी इनबेव के लिए 100% राहत)।

लेखा परीक्षकों के लेखा परीक्षक: NFRA

संदर्भ: राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) 1 अक्टूबर से नेतृत्वहीन हो जाएगा यदि सरकार मौजूदा अध्यक्ष को उत्तराधिकारी या किसी अन्य कार्यकाल की घोषणा नहीं करती है।

NFRA क्या है?

- IL & FS वित्तीय घोटाले के मद्देनजर NFRA 2018 के अंत में अस्तित्व में आया।
- NFRA कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित लेखा परीक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय नियामक है।
- NFRA का जन्म भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा लेखा परीक्षा पेशे के स्व-विनियमन की विफलता के कारण हुआ था।
- यह विशेष रूप से सूचीबद्ध और बड़ी जनहित संस्थाओं में धोखाधड़ी में लेखा परीक्षकों की भूमिका की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था।
- यह 2018 के अंत में IL&FS वित्तीय घोटाले के मद्देनजर अस्तित्व में आया।
- संरचना - NFRA में एक अध्यक्ष होगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और अधिकतम 15 सदस्य होंगे।
- NFRA का एक महत्वपूर्ण कार्य कंपनियों या कंपनियों के वर्ग या उनके लेखा परीक्षकों द्वारा अपनाने के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियों तथा मानकों के निर्माण और निर्धारण पर केंद्र सरकार को सिफारिश करना है।
- NFRA की स्थापना के साथ, इस तरह के गंभीर इरादे से लेखापरीक्षा प्रथाओं को जांच के दायरे में रखा गया था।

क्या आप जानते हैं?

- भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अद्वितीय है, जो सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य रूप से अनिवार्य ऑडिट करता है, चाहे उनका आकार और विशेषता कुछ भी हो।

- विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को केवल छोटी कंपनियों के लिए वैधानिक लेखा परीक्षा की आवश्यकता होती है, जब सार्वजनिक हित के कुछ न्यूनतम मानदंड संतुष्ट होते हैं।
- भारत में भी आय कर लेखा परीक्षा अब अनिवार्य नहीं है जहां कारोबार 10 करोड़ या उससे कम बशर्ते कि 5% से अधिक लेन-देन नकद में न हो। GST ऑडिट को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।

NFRA के प्रभावी कामकाज में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **सीमित स्टाफ के साथ कार्य करना:** अध्यक्ष के अलावा बोर्ड में केवल एक पूर्णकालिक निदेशक होता है, और तीन अंशकालिक निदेशक होते हैं जो ICAI के नामित होते हैं।
- **हितों का टकराव:** NFRA बोर्ड इस मायने में अद्वितीय है कि उसके पास उस निर्वाचन क्षेत्र (ICAI के नामिती) का प्रतिनिधित्व है जिसे वह विनियमित करना चाहता है। यह सेबी के बोर्ड में स्टॉक ब्रोकरों या आरबीआई द्वारा अभ्यास करने वाले बैंकों को डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त करने जैसा है।

आगे की राह

- अंशकालिक निदेशकों के रूप में अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति के माध्यम से नियामक निकाय पर कब्जा करने के ICAI के प्रयासों को खारिज कर दिया जाना चाहिए।
- NFRA अब महत्वपूर्ण टेक-ऑफ चरण में है और इसे एक स्वतंत्र प्रमुख की आवश्यकता है जो ICAI का पूर्व या वर्तमान पदाधिकारी नहीं है।
- शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों की अधिक भागीदारी और शेयरधारक की बढ़ती सक्रियता के साथ, हमें एक मजबूत, स्वायत्त नियामक की आवश्यकता है जो लेखा परीक्षकों को नियंत्रण में रख सके और लेखा परीक्षा पेशे को विकसित करने में मदद कर सके।

Q.1) हाल ही में लद्दाख द्वारा निम्नलिखित में से किसे राज्य पशु के रूप में अपनाया (adopted) गया था?

- जंगली भैंस
- हिम तेंदुआ
- मिथुन
- एक सींग वाला गैंडा

Q.2) बायोलुमिनसेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- यह केवल समुद्री प्रजातियों में ही पाया जाता है।
- यह एक प्रकार का रक्षा तंत्र है यह दबाव, समुद्र की गति और लहरों के कारण होता है।

सही कथनों का चयन करें:

- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2

Q.3) शोला वन पाया जाता है:

- हिमालय
- पश्चिमी घाट
- विंध्य
- पूर्वी घाट

Q.4) तूफान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

- हरिकेन एक हिंसक तूफान है जो उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जल से उत्पन्न होता है।
- यह एक कम दबाव केंद्र, एक बंद निम्न-स्तरीय वायुमंडलीय परिसंचरण और तेज हवाओं के गठन द्वारा होता है।
- आंधी की एक सर्पिल व्यवस्था है जो भारी बारिश या तूफान उत्पन्न करती है।
- ये सभी

Q.5) राष्ट्रीय चंबल नदी घड़ियाल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस प्रजाति की पर्याप्त आबादी वाला एकमात्र क्षेत्र है?

- लेदरबैक कछुआ
- लाल मुकुट वाला कछुआ
- उत्तरी नदी भूभाग
- काला सॉफ्टशेल कछुआ

Q.6) संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं?

- राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति
- राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.7) वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- यह FSDC अधिनियम, 2009 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है
- यह वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है
- वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर उर्जित पटेल समिति (2008) ने सबसे पहले FSDC के निर्माण का प्रस्ताव रखा।

गलत कथनों का चयन करें:

- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- 1, 2 और 3

Q.8) 'बैरा सिडल पावर स्टेशन' भारत के किस राज्य में स्थित है?

- हिमाचल प्रदेश
- उत्तराखंड
- झारखंड
- पंजाब

Q.9) अधिकतर खबरों में देखा जाने वाला 'कार्बी आंगलोंग विद्रोह' निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?

- नगालैंड
- अरुणाचल प्रदेश
- मिजोरम
- असम

Q.10) अकाउंट एग्रीगेटर्स (AAs) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- यह ग्राहक के सभी डिजिटल पदचिह्नों को एक ही स्थान पर संकलित करेगा और उधारदाताओं के लिए इसे एक्सेस करना आसान बना देगा।
- AAs के लिए लाइसेंस वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है

सही कथनों का चयन करें:

- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2

Q.11) SIMBEX भारत और _____ के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है।

- सेशल्स (Seychelles)
- सिंगापुर
- दक्षिण कोरिया
- दक्षिण अफ्रीका

Q.12) 'इनर लाइन परमिट' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कोई भी व्यक्ति प्रत्येक एक वर्ष में अपने परमिट को नवीनीकृत करने का हकदार है यदि वह इन राज्यों में मूल निवासी नहीं है, इस तथ्य के बावजूद कि वह एक दीर्घकालिक निवासी है।
2. यह भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास स्थित कुछ क्षेत्रों में आवाजाही को भी नियंत्रित करता है।
3. यह गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।

सही कथनों का चयन करें:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q.13) निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित हैं?

1. टाइफून: चीन सागर और प्रशांत महासागर।
2. हरिकेन : कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर।
3. विली-विलीज (Willy-willies) : उत्तर-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में।
4. उष्णकटिबंधीय चक्रवात: हिंद महासागर क्षेत्र में।

सही उत्तरों का चयन करें:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2
- c) केवल 3 और 4
- d) 1, 2, 3 और 4

Q.14) सामान्य सेवा केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. CSC इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) का एक विशेष प्रयोजन वाहन है।
2. CSC भारत सरकार की ई-सेवाओं को ग्रामीण और दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने के लिए भौतिक सुविधाएं हैं जहां कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता नगण्य थी या अधिकतर अनुपस्थित थी।

सही कथनों का चयन करें:

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.15) निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए ग्रीन वीजा लॉन्च किया है?

- a) अमेरिका
- b) जापान
- c) संयुक्त अरब अमीरात
- d) इजराइल

Q.16) निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मीठे पानी के नदी द्वीपों की सबसे बड़ी संख्या है?

- a) माजुलिक
- b) डिब्रू सैखोवा

- c) श्रीरंगमी
- d) भवानी द्वीप

Q.17) निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला 'डुगोंग संरक्षण रिजर्व' स्थापित करेगा

- a) गुजरात
- b) तमिलनाडु
- c) उड़ीसा
- d) पश्चिम बंगाल

Q.18) ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है
2. न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक संगठन की वित्तीय संरचना के घटक हैं।

सही कथनों का चयन करें:

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.19) नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत भारत रैंकिंग 2021 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है?

- a) नीति आयोग
- b) अजीम प्रेमजी फाउंडेशन
- c) शिक्षा मंत्रालय
- d) दोनों (A) और (C)

Q.20) परागणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. परागण मादा जैविक संरचनाएं हैं जिनमें निषेचन की प्राथमिक भूमिका होती है।
2. हवा में निलंबित पाया गया पराग अस्थमा, मौसमी राइनाइटिस और ब्रोन्कियल जलन जैसी अभिव्यक्तियों के साथ व्यापक ऊपरी श्वसन पथ और नासोब्रोन्कियल एलर्जी का कारण होता है।

सही कथनों का चयन करें:

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.21) जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED) निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?

- a) जनजातीय मामलों के मंत्रालय
- b) वाणिज्य मंत्रालय
- c) पर्यावरण मंत्रालय
- d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.22) 'गुज्जर बकरवाल आदिवासी समुदाय (Gujjar Bakerwal tribal communities)' निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं?

- a) मणिपुर

- b) जम्मू और कश्मीर
- c) गुजरात
- d) राजस्थान

Q.23) GST परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. यह एक वैधानिक निकाय है।
2. इसकी अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट सचिव करते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.24) मुद्रास्फीति से लाभ किसे होता है?

- a) फिक्स्ड इनकम अरनर (Fixed income earners)
- b) ऋणदाता / लेनदार
- c) कर्जदार/देनदार
- d) बैंक जमाकर्ता

Q.25) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?

- a) शहरी विकास मंत्रालय
- b) गृह मंत्रालय
- c) यह एक स्वतंत्र एजेंसी है
- d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.26) PLI योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उत्पाद लिंकड प्रोत्साहन (PLI) योजना का उद्देश्य सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
2. यह योजना आयात बिलों को कम करने और स्थानीय वस्तुओं की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कंपनियों को अपने घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.27) निम्नलिखित में से कौन क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है?

- a) भारत
- b) चीन
- c) ऑस्ट्रेलिया
- d) यूनाइटेड किंगडम

Q.28) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बैड बैंक एक वित्तीय संस्थान को संदर्भित करता है जो उधारदाताओं की बैड संपत्तियों को लेकर समाधान करता है।

2. नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक बैड बैंक है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.29) निम्नलिखित में से कौन भारत के कुछ हिस्सों में पीने के पानी में प्रदूषक के रूप में पाया जाता है?

1. आर्सेनिक
2. फ्लोराइड
3. फॉर्मलडिहाइड
4. सोरबिटोल
5. यूरेनियम

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2, 4 और 5
- c) केवल 1, 2 और 5
- d) 1, 2, 3, 4 और 5

Q.30) निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ग्लोबल मीथेन प्लेज लॉन्च किया है?

- a) अमेरीका
- b) चीन
- c) सिंगापुर
- d) भारत

Q.31) निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित हैं?

1. पृथ्वी: कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल।
2. अग्नि: विभिन्न रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें।
3. त्रिशूल: कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल।
4. नाग: तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइल।
5. आकाश: मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल।

नीचे दिए गए उद्धरणों में से सही उत्तर का चयन करें:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 1, 2 और 5
- c) 1, 2, 3, 4 और 5
- d) केवल 2 और 4

Q.32) मानव पूंजी सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है?

- a) विश्व आर्थिक मंच
- b) विश्व बैंक
- c) आसियान
- d) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

Q.33) उदयगिरी की गुफाएँ कहाँ स्थित हैं?

- a) महाराष्ट्र
- b) उत्तर प्रदेश
- c) मध्य प्रदेश
- d) राजस्थान

Q.34) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यान्वित की जाती है?

- a) शिक्षा मंत्रालय
- b) अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय
- c) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
- d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.35) निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा है?

- a) मन्नारी की खाड़ी
- b) पाक खाड़ी
- c) पाक जलडमरूमध्य
- d) मलक्का जलडमरूमध्य

Q.36) केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह एक संवैधानिक निकाय है जिसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
2. इसकी स्थापना सरकार ने 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की थी।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.37) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSS अधिनियम) के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है।
2. यह कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.38) मुद्रा योजना के शिशु उत्पाद के अंतर्गत अधिकतम ऋण सीमा क्या है?

- a) 5 लाख रुपये
- b) 1 लाख रुपये
- c) 50,000 रुपये
- d) 10 लाख रुपये

Q.39) भारत में जनगणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है?

- a) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
- b) गृह मंत्रालय
- c) नीति आयोग
- d) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

Q.40) सुप्रीम कोर्ट द्वारा फास्टर सिस्टम (FASTER System) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित उपकरण है जो प्रासंगिक तथ्यों और कानूनों को एकत्र करता है तथा उन्हें एक न्यायाधीश को उपलब्ध कराता है
2. यह जीवन के मौलिक अधिकारों, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.41) राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसके तहत लोगों को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान की जाएगी, जिसमें व्यक्ति के सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड होंगे
2. इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.42) अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

- a) गुरुग्राम
- b) मास्को
- c) पेरिस
- d) बीजिंग

Q.43) आयातित माल पर लागू डंपिंग रोधी शुल्क _____.

- a) विश्व व्यापार संगठन द्वारा समाप्त कर दिया गया है
- b) घरेलू परिवारों के लिए उपभोक्ता अधिशेष में कमी का परिणाम
- c) औद्योगिक देशों द्वारा लगाया जाता है लेकिन विकासशील देशों द्वारा नहीं
- d) घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कम कीमत वाले सामान में परिणाम

Q.44) हाल ही में जुडिमा, डिमासा समुदाय द्वारा बनाई गई शराब को भौगोलिक संकेत (GI) टैग से सम्मानित किया गया है। यह समुदाय भारत के किस राज्य से संबंधित है?

- a) छत्तीसगढ़
- b) असम
- c) उड़ीसा
- d) मेघालय

Q.45) XENON1T प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. XENON1T प्रयोग दुनिया का सबसे संवेदनशील डार्क मैटर प्रयोग है।
2. इसे इटली में INFN Laboratori Nazionali del Gran Sasso में गहरे भूमिगत रूप से संचालित किया गया।

सही कथनों का चयन करें:

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.46) वर्तमान में निर्माणाधीन 14.15 किमी लंबी जोजिला सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ेगी?

- a) श्रीनगर से लेह
- b) लद्दाख से लेह
- c) सिक्किम से दार्जिलिंग
- d) कुल्लू से स्पीति

Q.47) सेबी के प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल हैं:

- a) प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए
- b) प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के लिए

- c) प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने के लिए
- d) ये सभी

Q.48) ट्यूनीशिया के उत्तर में कौन सा समुद्र है?

- a) काला सागर
- b) भूमध्य - सागर
- c) एड्रियाटिक समुद्र
- d) लाल सागर

Q.49) निपाह वायरस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से सत्य है/हैं:

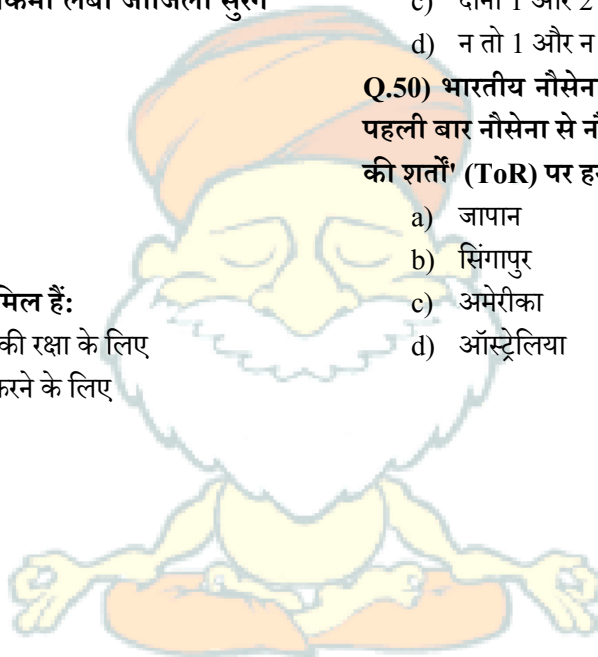
1. यह एक जूनोटिक वायरस है।
2. फ्रूट बैट्स , जिसे आमतौर पर उड़ने वाली लोमड़ी के रूप में जाना जाता है, को वायरस का प्राकृतिक भंडार माना जाता है।

सही कथनों का चयन करें:

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.50) भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ पहली बार नौसेना से नौसेना की वार्ता के संचालन के लिए 'संदर्भ की शर्तों' (ToR) पर हस्ताक्षर किए हैं?

- a) जापान
- b) सिंगापुर
- c) अमेरिका
- d) ऑस्ट्रेलिया



उत्तर कुंजी

1. b
2. b
3. b
4. d
5. b
6. c
7. c
8. a
9. d
10. a
11. b
12. b
13. d
14. c
15. c
16. a
17. b
18. d
19. c
20. b
21. c
22. b
23. d
24. c
25. b



26. c
27. b
28. c
29. c
30. a
31. c
32. b
33. c
34. c
35. a
36. b
37. a
38. c
39. b
40. b
41. a
42. a
43. b
44. b
45. c
46. a
47. d
48. b
49. c
50. d



Available In
English &
हिन्दी

INTEGRATED LEARNING PROGRAM (S-ILP) – 2022

Road to Mussoorie...



Detailed Study Plan
With Daily Targets



Essay Guidance



63 Prelims & 66
Mains Tests



CSAT Tests



Value Add Notes- For
Prelims & Mains



Strategy Classes



Babapedia - One Stop
Destination for Current Affairs
- Prelims + Mains



Mind Maps For GS Mains

ADD-ONS

Mentorship, Mains Evaluation, Current Affairs Classes



The Program Begins On November 12th

ENROLL NOW

Scan here to



know more